



LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Friday, February 2, 2024 / Magha 13, 1945 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. Kirit P. Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Shrirang Appa Barne

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Friday, February 2, 2024 / Magha 13, 1945 (Saka)

<u>CONTENTS</u>	<u>PAGES</u>
...	1
ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 1 – 7)	1A – 30
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 8 – 20)	31 – 50
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 1 – 230)	51 – 280



सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Friday, February 02, 2024 / Magha 13, 1945 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Friday, February 02, 2024 / Magha 13, 1945 (Saka)

<u>C O N T E N T S</u>	<u>P A G E S</u>
RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	281
...	282
PAPERS LAID ON THE TABLE	283 - 89
ASSENT TO BILLS	290
COMMITTEE ON ESTIMATES 32 nd to 34 th Reports	291
STATEMENTS RE: CORRECTING ANSWER GIVEN TO UNSTARRED QUESTION NO. 1109 DATED 08.12.2023 RE: (i) DATA OF AYUSH COLLEGES AND (ii) GIVING REASONS FOR DELAY – LAID Shri Sarbananda Sonowal	291
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 19 TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN AFFAIRS – LAID Shri Hardeep Singh Puri	292
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 350 TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON EDUCATION, WOMEN, CHILDREN, YOUTH AND SPORTS – LAID Dr. (Prof.) Mahendra Munjapara	292
BUSINESS OF THE HOUSE	293

ELECTION TO COMMITTEE	294
All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Bhopal	
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	295 - 307
Shri Jamyang Tsering Namgyal	295
Shrimati Keshari Devi Patel	296
Shri Vishnu Dayal Ram	296
Shri Naranbhai Kachhadiya	297
Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo	297
Shri Chhedi Paswan	298
Dr. Nishikant Dubey	298
Dr. Heena Vijaykumar Gavit	299
Shri Raju Bista	299
Shri Ravi Kishan	300
Dr. Sukanta Majumdar	300
Shri Janardan Singh Sigriwal	301
Shri Bhola Singh	301
Shri Krishnapalsingh Yadav	302
Dr. Shashi Tharoor	302
Shri C. N. Annadurai	303
Prof. Sougata Ray	303
Shri Raghu Rama Krishna Raju	304
Shri Dileshwar Kamait	304
Shri Bhartruhari Mahtab	305
Shri Ritesh Pandey	305
Dr. G. Ranjith Reddy	305
Choudhary Mehboob Ali Kaiser	306

Shrimati Supriya Sadanand Sule	306
Kunwar Pushpendra Singh Chandel	307
Shri Ravneet Singh	307
...	308
MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS (Inconclusive)	309 - 41
Dr. Heena Vijaykumar Gavit	309 - 21
Prof. S.P. Singh Baghel	322 - 41
ANNOUNCEMENT RE: AMENDMENTS TO MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS	342
...	343
MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS (Contd. - Inconclusive)	344 - 474
Shri Gaurav Gogoi	344 - 51
TEXT OF AMENDMENTS	352 - 54
Shri T.R. Baalu	355 - 60
...	361
Dr. Kakoli Ghosh Dastidar	362 - 67
Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki	368 - 72
Dr. Beesetti Venkata Satyavathi	373 - 76
@Shri Chandra Sekhar Sahu	377
Shri Malook Nagar	378 - 80
Dr. Amol Ransing Kolhe	381 - 82
Shri Saptagiri Sankar Ulaka	383 - 87
Shri Sudheer Gupta	388 - 94

Dr. Kalanidhi Veeraswamy	395 - 401
Shri E.T. Mohammed Basheer	402 - 04
Shri Rajendra Agrawal	405 - 09
Adv. Dean Kuriakose	410 - 13
Shri Tejasvi Surya	414 - 22
Shri Asaduddin Owaisi	423 - 26
Shri Ramcharan Bohra	427 - 28
Shri Karti P. Chidambaram	429 - 32
Shrimati Supriya Sadanand Sule	433 - 38
Shri Ramesh Bidhuri	439 - 46
Shri Bhartruhari Mahtab	447 - 50
Shri Vincent H. Pala	451 - 53
Shri Santosh Pandey	454 - 56
Shri Abdul Khaleque	457 - 60
Dr. DNV Senthilkumar S.	461 - 63
Shri Sanjay Seth	464 - 68
Shri Girish Chandra	469 - 70
Shrimati Locket Chatterjee	471 - 74
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	475
48th Report	
MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT ADDRESS	476 - 79
(Contd. - Inconclusive)	
Shri Jasbir Singh Gill	476 - 77
Dr. Arvind Kumar Sharma	478 - 79

(1100/YSH/RP)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

... (व्यवधान)

श्री बी. मणिकम टैगोर (विरुधुनगर): सर, झारखंड में अत्याचार हो रहा है।...
(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जोशी जी, क्या आपको कुछ बोलना है?

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, इन्होंने देश को तोड़ने की बात की है। इन्होंने कल देश को तोड़ने की बात की है।... (व्यवधान)
बजट के बारे में जो रिएक्शन दिया है, उस बात को हम यहां पर रखना चाहते हैं।...
(व्यवधान) देश को तोड़ने की बात हुई है। इन्होंने यह बहुत बड़ी गलती की है। मेरे हिसाब से तो यह बहुत बड़ा क्राइम है। इसलिए इस बात को उठाने की इजाजत दी जाए।...
(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, नो। क्वेश्चन आवर के बाद बोलिएगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जोशी जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : सर, मैं 12 बजे के बाद बोलूंगा।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल।

प्रश्न संख्या – 1, श्री कृष्णपालसिंह यादव जी।

... (व्यवधान)

1102 hours

(At this stage, Shri T.R. Baalu, Shri B. Manickam Tagore, Prof. Sougata Ray and some other hon. Members left the House.)

... (Interruptions)

(प्रश्न 1)

श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं सबसे पहले हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूँ, जिन्होंने एक सर्व समावेशी और आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के लिए जन कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है। साथ ही आयुष मंत्रालय का बजट भी 3700 करोड़ रुपये का कर दिया है, जो वर्ष 2014 में सिर्फ 691 करोड़ रुपये का था। प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में आयुष प्रणाली को पूरे विश्व में प्रसिद्धि मिल रही है।

मेरे संसदीय क्षेत्र 'गुना' के अंतर्गत तीन जिले आते हैं, जिनमें 30 प्रतिशत वन क्षेत्र है, जहां पर 35 से अधिक प्रकार के आयुष और वन औषधियां जैसे अश्वगंधा, आंवला, भृंगराज और गिलोय जैसी औषधियां मेरे क्षेत्र के जंगलों में पाई जाती हैं। इनकी गुणवत्ता खेतों में उगाए जाने वाली औषधियों से अधिक होती है, लेकिन इन पर शोध की कमी के कारण इनका ठीक से उपयोग नहीं किया जा रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन प्राकृतिक औषधियों की गुणवत्ता एवं उपलब्धता और इनके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सरकार द्वारा मेरे लोक सभा क्षेत्र में आयुष रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेंटर शुरू करने की कोई योजना है? इसके अतिरिक्त क्या इन औषधियों को मंडियों में बेचने के लिए कोई निर्धारित खरीदी केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना बनाई जा रही है, जिससे वहां के लोगों को इन औषधियों का उचित मूल्य मिल सके?

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे साथी सांसद डॉ. कृष्णपालसिंह यादव जी ने जो सवाल किया है, उसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ। आज आयुष सेक्टर को जिस हिसाब से देश और दुनिया में मान्यता मिली है, उसका एक ही मूल कारण है कि पिछले 10 सालों में परम आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में इस विभाग को मंत्रालय बनाया गया है, चूँकि यह पहले विभाग हुआ करता था तथा इसके साथ ही बजटरी सपोर्ट के साथ-साथ इंस्टीट्यूट मैकेनिज्म, रिसर्च सेन्टर इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने सहयोग किया है। उनकी निरंतर कोशिशों की वजह से आज आयुष ने दुनिया में मानव समाज को अलग-अलग रोगों से राहत देने का काम किया है। इस वजह से चाहे प्रोडक्ट हो या प्रैक्टिस हो, आज आयुष की क्रेडिबिलिटी बढ़ चुकी है, इसलिए देश की जनता जानना चाहती है कि आयुष से देश के अंदर किसान और हर प्रांत के लोग कैसे जुड़ सकते हैं। इसके जरिए चाहे हमारी नई पीढ़ी हो या किसान हो, वे जानना चाहते हैं कि हम उत्पादन के साथ-साथ उपार्जन के लिए क्या उपाय कर सकते हैं?

(1105/RAJ/NKL)

इस सिलसिले में मैं इतना ही कहूंगा कि हमारा नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है। हम इस नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के जरिए स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड को सहयोग करते हैं और ग्रुप ऑफ किसान को क्वालिटी मेडिसिनल प्लांटिंग के लिए सहयोग करते हैं और इसके साथ-साथ ट्रेनिंग भी दी जाती है। आफ्टर हार्वेस्टिंग उनके प्रोडक्ट्स को कैसे स्टोरेज किया जाएगा, कैसे उसमें वैल्यू एडिशन किया जाएगा, मार्केट लिंकेज दिया जाएगा और बायर्स-सेलर्स मीट का भी आयोजन किया जाता है। हम उसी हिसाब से किसानों को इस विषय पर बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम के द्वारा हमेशा मदद करते आए हैं।

श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना): अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। आयुष प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए अच्छे डॉक्टरों की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत इसके लिए प्रावधान भी है, लेकिन आज भी बहुत सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो रही है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या सरकार आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति करने के लिए कोई विशेष अभियान शुरू करने पर विचार कर रही है और साथ ही आयुष प्रणाली की चिकित्सा शिक्षा बेहतर बनाने के लिए जिस प्रकार से दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद खोला गया है, उसी तर्ज पर अन्य प्रदेशों में, देश की हृदयस्थली मेरे मध्य प्रदेश में भी ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद खोलने का कोई विचार है?

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : अध्यक्ष महोदय, हमारा जो हेल्थ वेल्नेस सेंटर है, अगर इस पर कोई नई व्यवस्था जोड़नी हो, तो राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव आए, स्टेट एनुअल ऐक्शन प्लान के जरिए प्रस्ताव भेजे, तो निश्चित रूप से मंत्रालय इस विषय पर विचार करेगा।

श्री उन्मेश भैयासाहेब पाटिल (जलगाँव): सर, आपने मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने वर्ष 2014 में आयुष के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया। यह हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। हमारा देश महर्षि चरक की भूमि है। मैं महाराष्ट्र के जिस जिले से चुन कर आया हूँ, पाल से लेकर पाटना देवी तक हेल्थ प्लस वेल्थ का जोन कहा जाता है। हमारे यहां एरोमैटिक्स एंड मेडिसिनल प्लांट का बड़ा प्लांटेशन है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आयुष मंत्रालय के द्वारा यह जानना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री जी का डबलिंग इनकम का जो संकल्प है, उसके लिए ट्रेडिशनल क्रॉप्स, कॉटन एवं शुगरकेन के अलावा मेडिसिनल एंड एरोमैटिक्स प्लांट्स को बढ़ावा देने के लिए किसानों को भी ऑप्शंस मिलेंगे और उसके लिए क्या आयुष मिनिस्ट्री और मेडिसिनल बोर्ड की ऐसी कोई योजना है जिसके द्वारा हमारे किसानों की आय बढ़े और आयुष प्रोडक्ट्स के लिए भी रॉ मैटेरियल अवेलेबल हो सके?... (व्यवधान)

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा है कि हमारा जो सेंटर सेक्टर स्कीम है, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, इसके जरिए हम ग्रुप ऑफ किसानों को इस विषय पर प्रोत्साहित करते हैं। वह स्कीम हमारे पास है। स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की तरफ से अगर वह हमें प्रस्ताव भेजे तो निश्चित रूप से इस विषय पर हम मदद करते हैं। इस स्कीम के तहत अधिकतम एक करोड़, 20 लाख तक ग्रुप ऑफ किसान एक साथ आएँ, वे स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के जरिए प्रस्ताव भेजें, तो हम शुरुआत में उनकी क्वालिटी मेडिसिनल प्लांटिंग के लिए में 60 लाख रुपए तक दे सकते हैं। उसके बाद हम उनको अलग-अलग स्कीम के लिए भी हार्वेस्टिंग के बाद, वैल्यू एडिशन, ट्रेनिंग इत्यादि-इत्यादि के लिए फिर से 27 लाख रुपए दे सकते हैं। कुल मिला कर सारी स्कीम्स में किसान निष्ठापूर्वक शामिल हो जाएँ, तो वे निश्चित रूप से उपार्जन के लिए एक बढ़िया रास्ता ढूँढ सकते हैं।

(इति)

(प्रश्न 2)

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे (रावेर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं सबसे पहले अपने प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद चाहूंगी कि उन्होंने कोविड के समय से टेली मेडिशन और टेली कंसल्टेंसी की सुविधा को बढ़ावा दिया है और उसके माध्यम से हमारे देश के 20 करोड़ से भी अधिक लोगों को उसका फायदा हुआ है।

(11110/KN/VR)

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इस सुविधा को बढ़ाने के लिए क्या सरकार आगे कुछ और कदम उठा रही है? उसके साथ ही हमारे महाराष्ट्र में खासकर मेरे जलगांव और बुलढाणा जिले में इसके कितने सेंटर्स हैं?

डॉ. भारती प्रवीण पवार : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हमारे अनेक प्रयास आरोग्य मंत्रालय में चलाए जा रहे हैं। हमारा जो टेली कंसल्टेशन है, टेलीमेडिसिन सर्विसेज हैं, जो डॉक्टर टू डॉक्टर भी दिया जाता है और डॉक्टर टू पेशेंट भी दिया जाता है। इसमें स्पेशलिस्ट्स और सुपर स्पेशलिस्ट्स का कंसल्टेशन गांव के पेशेंट को भी मिले, ताकि उसके समय की भी बचत हो और पैसे की भी बचत हो तथा ईजी एक्सेस डॉक्टर का मिले। माननीय सांसद महोदया ने जैसे कहा कि आज तक कितना कंसल्टेशन हुआ है तो मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छा टेली कंसल्टेशन आज तक हुआ है। कोविड के बाद टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा भारत हम देख रहे हैं। इसमें 20 करोड़ से ज्यादा टेली कंसल्टेशन सक्सेसफुली हुए हैं। मैं महाराष्ट्र के बारे में बताना चाहूंगी कि 68 लाख पेशेंट्स ने टेली कंसल्टेशन के माध्यम से सुविधा ली है। माननीय सांसद महोदया ने पूछा है कि महाराष्ट्र में कितने ऐसे हब एंड स्पोकस हैं तो मैं बताना चाहती हूँ कि हब की संख्या 2 हजार से ज्यादा है और स्पोकस 9 हजार से ज्यादा उसमें जुड़े हैं। सांसद महोदया के क्षेत्र से जुड़ी डिटेल्स मैं उनको भेज दूंगी। यह हब एंड स्पोकस मॉडल है, जिसमें लगातार संख्या बढ़ाई जा रही है। उन्होंने जो चिंता जताई है कि क्या स्ट्रेंथन करेंगे तो बिल्कुल करेंगे। टेली कंसल्टेशन सुविधा को स्ट्रेंथन करने के लिए हर स्टेट को इमरजेंसी कोविड रिलीफ पैकेज (ईसीआरपी-2) के माध्यम से बजट दिया गया था। हरेक राज्य व हरेक जिले में इसे स्ट्रेंथन किया गया है, जिसमें आज हम देख रहे हैं कि 4 लाख पेशेंट्स पर डे इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : ऑनरेबल मैम्बर, क्या आप सप्लीमेंट्री पूछना चाहती है?

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे (रावेर): जी सर।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने आयुष, हमारे देश का जो ट्रेडिशनल मैथड है, उसको काफी बढ़ावा दिया है। मैं जानना चाहती हूँ कि इस टेली कंसल्टेशन के माध्यम से क्या हम आयुष की कंसल्टेशन भी शुरू कर सकते हैं?

डॉ. भारती प्रवीण पवार : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह टेली कंसल्टेशन का सवाल इमरजेंसी लेवल पर गांव के पेशेंट को डॉक्टर की सुविधा जल्द उपलब्ध करवाने के बारे में है। जैसे माननीय सदस्या ने कहा कि क्या इसमें आयुष मिनिस्ट्री जुड़ सकती है, तो इस बारे में हमारे दोनों कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग भी हुई है, चर्चा भी हुई है। टेली कंसल्टेशन के लिए हम दोनों क्षेत्रों पर जोर देने का विचार कर रहे हैं। टेली कंसल्टेशन के माध्यम से हरेक को जोड़ने का प्रयास हमारे मंत्रालय से लगातार हो रहा है।

DR. T. SUMATHY ALIAS THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Thank you very much, hon. Speaker, Sir. Through you, I would like to ask the hon. Minister whether she has taken any steps to encourage inter-State cooperation in terms of televised advices regarding medical health and partnership for the exchange of best practices and advancement in healthcare, particularly in the field of telemedicine.

I would also like to ask whether the hon. Minister has explored the possibility of creating a collaborative framework to address the regional health disparities of other States. Thank you.

डॉ. भारती प्रवीण पवार : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सांसद महोदया ने हरेक स्टेट को इंटीग्रेटेड करने के बारे में कहा है, हम लोग अभी जैसे लेवल 1, 2 और 3 पर काम कर रहे हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज एक हब रहेगा, टर्शियरी केयर एक हब रहेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक हब रहेगा। हम स्पोकस के माध्यम से प्राइमरी सेंटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं।

We are connecting the tertiary care with the primary care. हरेक जिले में यह प्रयास हो रहा है। In your State, the tertiary care is going to connect with the primary care. हम लोग इसमें मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को पीएचसी से जोड़ रहे हैं। Again, the second level PHC is going to connect with the sub-centres. माइक्रो लेवल पर यह प्लान हो रहा है। So far as numbers are concerned, about 20 crore teleconsultations have been completed.

(1115/VB/SAN)

हम लोग इसमें सही दिशा में कनेक्टिविटी कर रहे हैं। मैं कहूंगी कि फॉलो-अप ऑफ द पेशेंट के लिए यह ज्यादा उपयोगी हो रहा है। डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए भी यह ज्यादा उपयोगी हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें महिलाओं का कंसल्टेशन सबसे ज्यादा हुआ है। टर्शियरी केयर के लिए महिलाएं गांव से ज्यादा प्रवास नहीं कर पाती हैं, इसलिए यह महिलाओं के लिए ज्यादा लाभदायी हुआ है। आपके सजेशन के माध्यम से, इसे और इंटीग्रेटेड वे में बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील (सतारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने का मौका दिया।

मैं महाराष्ट्र के एक छोटे-से गांव से आता हूँ मैं जानना चाहता हूँ कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले पेशेंट्स को ऑनलाइन चिकित्सा सलाह मिलने पर ई-संजीवनी के तहत उन्हें घर पर दवाई उपलब्ध कराने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है? आजकल डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में दवाइयाँ मिलनी मुश्किल है। दूर-दराज के गांवों में रहने वाले पेशेंट्स ने सलाह ले ली, लेकिन उन्हें औषधि नहीं मिलती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर ऐसी कोई योजना है, तो अच्छा होगा और यदि ऐसी कोई योजना नहीं है, तो सरकार ऐसी योजना लाने की कृपा करे।

धन्यवाद।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि दूर-सुदूर गांवों में मुफ्त इलाज मिले, मुफ्त दवाई मिले।

भारत सरकार की ओर से नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 60 परसेंट राशि प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स को दिये जाते हैं। यानी आयुष्मान आरोग्य मन्दिर में कोई भी स्वास्थ्य लाभ के लिए जाएंगे, ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, तो उनको मुफ्त मेडिसिन मिले, इसके लिए भारत सरकार की ओर से 60 परसेंट राशि दिये जाते हैं। इसमें 40 परसेंट राशि राज्य सरकार देती है और उनको मुफ्त मेडिसिन उपलब्ध कराई जाती है।

दूसरा प्रश्न यह है कि टेली-कंसल्टेशन गांवों तक कब पहुंचेंगे। मैं पहले के प्रश्न का भी रिप्लाई देना चाहूंगा। हेल्थ एक्सेसिबल हो, हेल्थ एफोर्डेबल हो, लास्ट माइल के व्यक्ति तक हेल्थ की सुविधा उपलब्ध हो, उसके लिए टेली-कंसल्टेशन बहुत महत्वपूर्ण है। उसको हब और स्पोक के रूप में डेवलप किया गया है।

आयुष्मान आरोग्य मन्दिर, जो पूरे देश में 1 लाख 64 हजार की संख्या में हैं, वे स्पोक के रूप में काम कर रहे हैं एवं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेज और एम्स हब के रूप में काम कर रहे हैं। हब के रूप में काम करना यानी वहाँ पर स्पेशल डॉक्टर का एक रूम होता है। यदि नीचे से कोई भी कॉल आएगी, तो तुरन्त वह रिसीव करेगा और वे वर्चुअली कनेक्ट हो जाएंगे। जब स्पोक के रूप में किसी ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ आयुष्मान आरोग्य मन्दिर है, वहाँ गांव का कोई पेशेंट आएगा, तो वहाँ के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या कोई एमबीबीएस डॉक्टर से मिलेंगे। वहाँ उसका कंसल्टेशन होगा। अगर वहाँ के डॉक्टर को ऐसा लगे कि उसको टर्शियरी केयर की आवश्यकता है या किसी सीनियर डॉक्टर से पूछने की आवश्यकता है, किसी स्पेशियलिस्ट डॉक्टर से पूछने की आवश्यकता है, तो वह तुरन्त टेली-कंसल्टेशन के माध्यम से, किसी मेडिकल कॉलेज या एम्स या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्पेशियलिस्ट डॉक्टर के

साथ जुड़ जाएंगे। पेशेंट की बात डॉक्टर से होगी, डॉक्टर की बात स्पेशियलिस्ट डॉक्टर से होगी और वहाँ से ही उसको सलाह मिल जाएगी। वे वहाँ से सीएचओ को रेकमेंड भी कर देंगे कि आप इस तरह की मेडिसिन लिख दो। इससे यह फायदा होगा कि आज तक हमारे सामने जो स्टडी आई है कि एक सामान्य और गरीब व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसी प्राइमरी ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो या प्राइमरी स्टेज पर कोई सिम्टम दिख जाए, तो रोग आगे बढ़ने से रुक सकता है। इसका यह नतीजा हुआ है कि आज एवरेज लगभग तीन से चार लाख लोग टेली-कंसल्टेशन का लाभ ले रहे हैं।

महोदय, उसका यह फायदा हुआ है कि गरीब व्यक्ति जब अस्पताल जाता है, तो उसकी एक दिन की कमाई जाती है। यदि कोई मरीज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जाता है, तो उसके रिश्तेदार भी उसके साथ जाते हैं। उसके रिश्तेदार को भी उसके साथ न जाना पड़े, इसलिए एवरेज एक टेली-कंसल्टेशन के माध्यम से, एक पेशेंट पर 914 रुपये की बचत हुई है। आज तक 20 करोड़ से अधिक टेली-कंसल्टेशन हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 18 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए की बचत गरीब लोगों की जेब से हुई है। उनके पॉकेट का खर्च बचा है। इसलिए मोदी सरकार ने टेली-कंसल्टेशन के माध्यम से ट्रीटमेंट कराने की जो सुविधा दी है, आज उसका लाभ दूर-सुदूर गांव के लोग ले रहे हैं। इससे हेल्थ एक्सेसिबल और एफोर्डेबल हो रहा है।

(इति)

(1120/PC/SNT)

(प्रश्न 3)

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने के लिए समय दिया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से स्वास्थ्य मिशन पर चर्चा, ईको सिस्टम कार्यक्रम के बीच में जो दूरी कम हुई है, इसके बारे में माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे कि बीस हजार लोग अब तक इससे जुड़े हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूँगा कि राजस्थान में कितने रोगियों को इसका लाभ मिला और कितने आयुष्मान भारत कार्ड और आभा कार्ड बने हैं?

डॉ. भारती प्रवीण पवार : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सवाल है कि हमने टेक्नोलॉजी से जुड़े क्या न्यू इनीशिएटिव्स लिए हैं? जैसे अभी टेली कन्सल्टेशन पर चर्चा हुई, तो उसके साथ ही इन फोर पिलर्स पर मोदी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। यदि हम प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इनफ्रास्ट्रक्चर की बात कहें, तो उसको स्ट्रेन्डन करने का काम शुरू हुआ है।

हमारे हैल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के काम, जो कि अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहे जाते हैं, वे लगभग 1 लाख 64 हजार से ज्यादा फंक्शनल हुए हैं। तीसरा, प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके बारे में माननीय सांसद ने पूछा है कि कितने कार्ड बने हैं और खासकर राजस्थान के बारे में उनका सवाल है। प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के भारत में लगभग 55 करोड़ बेनिफिशरीज हैं। इसमें से टोटल कार्ड की जनरेशन को देखा जाए, तो 31 करोड़ के लगभग कार्ड्स जनरेट हुए हैं और इनमें से राजस्थान में लगभग दो करोड़ कार्ड्स जनरेट हुए हैं। मैं इस सदन के माध्यम से सभी माननीय सांसदों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब अपने-अपने क्षेत्रों में ये कार्ड्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करें, ताकि पांच लाख रुपए का जो इश्योरेंस उन्हें ट्रीटमेंट के लिए मिलता है, वह उन्हें मिल सके। आयुष्मान भारत आभा आईडी कार्ड के बारे में भी उन्होंने पूछा है। यह भी डिजिटल हैल्थ मिशन के माध्यम से हमारी नई पहल है। राजस्थान में लगभग तीन करोड़ आभा कार्ड्स जनरेट हुए हैं।

मुझे खुशी है कि आज आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में डिजिटल क्रांति के साथ हैल्थ इनफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम ट्रीटमेंट की सुविधा भी आगे लेकर जा रहे हैं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहूँगा कि जो विकसित भारत संकल्प योजना चली है, उसे विकसित भारत की यात्रा में कैम्पस लगाकर रजिस्ट्रेशन हुए हैं और रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्ड्स बनाने का आग्रह किया है। इसके लिए लोगों के फॉर्म भी भरवाए हैं। कितने दिनों में इन लोगों के कार्ड्स बन जाएंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो परिवार रहते हैं, जो असहाय लोग हैं, उन लोगों को

भी माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत जो पांच लाख रुपए तक का इलाज करने का प्रावधान है, उन परिवारों को भी जल्द से जल्द लाभ मिल सके।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण पूरक प्रश्न पूछा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दरम्यान ज्यादा से ज्यादा कार्ड्स बनाए जाएं, ताकि गरीब लोगों को पांच लाख रुपए के मुफ्त इलाज की गारंटी मिले।

अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण विषय यह है कि देश में आज 60 लाख आयुष्मान भारत योजना के बेनिफिशरीज हैं, यानी कि 12 करोड़ फैमलीज को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। माननीय सदस्य के लिए यह महत्वपूर्ण विषय है कि आज कार्ड बनाने के लिए वहां कार्यक्रम के स्थान पर जाएं, वहां उसको कार्ड बनाकर दें, तो यह सरकार की ओर से होगा ही, लेकिन आयुष्मान भारत एप पर हमने व्यवस्था की है कि कोई भी लाभार्थी स्वयं अपना केवाईसी करके अपने आयुष्मान भारत कार्ड को डाउनलोड कर सकता है। कोई भी माननीय सदस्य लोगों की मदद करना चाहें, सभी एमपीज के पास अपना कार्यालय होगा। अपने कार्यालय के द्वारा, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, आप जिसका भी उपयोग करना चाहें, उनका उपयोग करके आयुष्मान भारत योजना की वेबसाइट पर जाएंगे, तो वहां लाभार्थियों की सूची है। इन लाभार्थियों की सूची के अनुसार आप केवाईसी करके स्वयं आयुष्मान भारत योजना के कार्ड को क्रिएट कर सकते हैं।

(1125/CS/AK)

लाभार्थी भी क्रिएट कर सकते हैं। बिहाफ ऑफ लाभार्थी आप भी उसे क्रिएट करके दे सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे। गरीब व्यक्ति को पता चलेगा कि मैं आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी हूँ। किसी की जिन्दगी बचाने के लिए, किसी की मदद करने से आपको संतोष भी होगा। उसका फायदा भी होगा और हमारा जनाधार भी बढ़ेगा। इसलिए सभी जनप्रतिनिधियों से मेरा अनुरोध है कि आयुष्मान भारत योजना के साथ जुड़कर अपने क्षेत्र में रह रहे गरीब लोगों का आयुष्मान भारत कार्ड बनवाने में सहयोग करें।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): महोदय, आपने मुझे अहम सवाल पूछने की इजाजत दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जनाब, नेशनल हेल्थ केयर पॉलिसी का यह लक्ष्य है कि एक क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड हो।

माननीय अध्यक्ष : आप थोड़ा माइक के पास आकर बोलिए।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): जनाब, जम्मू-कश्मीर में हेल्थ केयर सिस्टम को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पर इक्विपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन मैनपावर नहीं है। मैंने गुजारिश की थी कि साउथ कश्मीर में, जहाँ करीब 25 लाख लोग निर्भर हैं, वे जहाँ रिपोर्ट करते हैं, जो हमारा आउटडोर है, चार जिलों में, कि वहाँ पर एमआरआई और एक पैट स्कैन मशीन लगायी जाए। अगर हम डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज की सुविधा न करें तो जो हमारा लक्ष्य है, वह लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है।

जनाब, दूसरी बात यह है कि अब यह कहा जा रहा है कि श्रीनगर मुल्क की लंग कैंसर कैपिटल है। लंग कैंसर के इंसिडेंट्स और बाकी जो कैंसर इंसिडेंट्स हैं, वे वहाँ बहुत ज्यादा लेवल तक बढ़ चुके हैं। इस हालत में डायग्नोस्टिक सिस्टम को मजबूत करना और खासकर साउथ कश्मीर में एक भी एमआरआई और पैट स्कैन मशीन नहीं है। अन्य व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जाना चाहिए।

जनाब, सबसे बड़ी बात यह है, जो मैंने कहा है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में करीब 40 परसेंट का मैनपावर क्राइसिस है। सारे ब्लॉक में कहीं भी एक भी एक्स-रे टेक्नीशियन नहीं है। अगर मशीन लगाई भी गई है, इक्विपमेंट है, लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं है। जनाब, मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके बारे में इंतजामात किए जाएं... (व्यवधान) वहाँ पर एक एमआरआई और एक पैट स्कैन की व्यवस्था की जाए ताकि डायग्नोस्टिक सिस्टम अच्छा हो सके।

डॉ. मनसुख मांडविया : महोदय, माननीय सदस्य ने डायग्नोस्टिक के लिए एमआरआई मशीन की बात की है, वह तो हम अवश्य लगा ही देंगे। सवाल केवल जम्मू-कश्मीर के एक ब्लॉक में एमआरआई मशीन एक अस्पताल में लगाना, इतने तक सीमित नहीं है, बल्कि हेल्थ को एक्सेसेबल करने के लिए, हेल्थ को एफोर्डेबल करने के लिए भारत सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने जो काम्प्रिहेंसिव एक्शन लिया है, वह महत्वपूर्ण है। जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष बात मैं यह कहना चाहूँगा कि वहाँ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिया गया है। 5 लाख रुपये के मुफ्त इलाज की गारंटी सभी कश्मीरी नागरिकों को दी गई है। इतना ही नहीं, केवल बोलने से उसको 5 लाख रुपये के मुफ्त इलाज की गारंटी मिल गई, ऐसा नहीं है। जम्मू-कश्मीर में दो एम्स बन रहे हैं। श्रीनगर में भी एम्स बन रहा है और जम्मू में भी एम्स बन रहा है। एक स्टेट में रीजनल दोनों, हिली एरिया में यानी कि घाटी में भी हेल्थ की सुविधा मिले, जम्मू में भी हेल्थ की सुविधा मिले। वहाँ नेशनल हेल्थ मिशन के तहत रिक्रूटमेंट करने के लिए भी 60 परसेंट पैसा भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। मैं विज्ञापन देख रहा था, बार-बार वहाँ हेल्थ वर्क फोर्स के लिए विज्ञापन हो रहा है। डॉक्टर्स के लिए विज्ञापन निकल रहा है। लैब टेक्नीशियन के लिए विज्ञापन निकल रहा है। इतना मैनपावर वहाँ उपलब्ध हो रहा है। मैनपावर लगाकर जम्मू-कश्मीर के लोगों को हेल्थ की एक्सेसिबिलिटी मिले, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you very much, Mr. Speaker.

Sir, we all have to be very concerned about the rising incidents of violence in the workplace against doctors and healthcare professionals. In India, 75 per cent of doctors have experienced violence and this is much more than most other countries in the world. In fact, younger and less experienced doctors are particularly vulnerable. In Kerala, we had a young 23-year-old doctor being murdered by a patient who was brought in by the police for her to treat. A recent survey by the Indian Medical Association showed that 82.7 per

cent of Indian doctors feel stressed out by the profession; 62.8 per cent fear violence; and 46.3 per cent say that violence is the main cause of their stress. Now, I had raised this issue in the Private Member's Bill. I got a very good reply from the Health Minister saying that we cannot have any legislation to protect doctors because if we do it for doctors, then tomorrow Chartered Accountants would want special laws and others would want special laws.

The doctors are working in life and death matters. They are working with patients and they are saving life. Risking their own life should not be part of their profession.

(1130/UB/IND)

I urge the Government to reconsider this stand and to kindly introduce legislation that will actually protect doctors and other healthcare professional in the workplace. At the same time, I would urge the Government to produce some financial or legal support to medical professionals who become victims of violence while performing their duties at the Central level. Dr. Vandana Das was killed in a Government Taluk hospital in Kerala. This kind of incidents should not be allowed to happen. The Government has a responsibility. Therefore, I would urge the Minister to change his policy on this matter.

डॉ. मनसुख मांडविया : अध्यक्ष जी, डॉ. शशि थरूर जी ने जो प्रश्न किया है, उसके संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में डाक्टर को भगवान के रूप में माना जाता है। डाक्टर्स के ऊपर देश की जनता की श्रद्धा है। यदि डाक्टर से कोई छोटी-मोटी गलती भी हो जाती है तो भी मरीज या उसके रिश्तेदार बोल देते हैं कि उसका आयुष पूरा हुआ होगा, इसलिए हमें डाक्टर को दोष नहीं देना चाहिए। हमारे देश की ऐसी रीति-नीति रही है लेकिन डाक्टर का प्रोफेशन ही ऐसा है कि कई बार एलिंगेशन्स लग जाते हैं और कई बार लोग इरिटेशन में उसके सामने एक्शन कर देते हैं। यदि किसी कारण मरीज की मृत्यु हो जाती है तो डाक्टर को दोषी भी ठहरा देते हैं। ऐसी स्थिति में डाक्टर को प्रोटेक्शन मिलना बहुत वाजिब है और बहुत आवश्यक है। इसके लिए कोविड के समय पेनडेमिक एक्ट में भी हमने सुधार किया कि ऐसी स्थिति में यदि कोई भी डाक्टर के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का प्रावधान किया था। पहले जब कोई डाक्टर के साथ हिंसा करता है तो आईपीसी एक्ट के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही होती थी और इस बार माननीय गृह मंत्री जी ने जो नया कानून पारित किया है, उसमें भी डाक्टर्स के लिए विशेष प्रावधान किया है। उन्होंने अपने भाषण में उल्लेख किया है कि नेशनल डाक्टर्स एसोसिएशन द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया था और मेरे पास भी बार-बार आते थे और ऐसी हिंसा करने वाले लोगों के सामने कार्यवाही करने का प्रावधान किया गया है। यदि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति होती है तो समय-समय पर कानून में बदलाव होना आवश्यक होता है। आज के समय में कानून में जो प्रावधान किया गया है, उससे डाक्टर्स को प्रोटेक्शन मिलेगा।

(इति)

(प्रश्न 4)

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदय, मेरा प्रश्न स्मार्ट हेल्थ सेंटर के बारे में है। मैं सबसे पहले माननीय प्रधान मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा रिफॉर्म वे लेकर आए हैं। दुनिया में पहले भारत की पहचान बीमार देश के रूप में थी, गरीब देश के रूप में थी। आज उसी देश को दुनिया में माना जाता है कि हेल्थ सेक्टर में सबसे बड़ा कोई सुविधा देने वाला देश है तो भारत है। देश में अब तक आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 30 करोड़ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं तथा मेरे मध्य प्रदेश में अभी तक 3,86,49,628 कार्ड्स जारी हुए हैं, जिनमें 3504161 लोगों की बीमारी का इलाज भी हुआ है। मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना में लगभग 1079872 कार्ड जारी हुए हैं, जिनमें 90844 लोगों की बीमारी का इलाज भी हुआ है। इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या स्मार्ट हेल्थ सेंटर का उद्देश्य लोगों को सस्ती दरों पर विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है? देश में कुल 164043 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें मध्य प्रदेश के किन-किन शहरों को शामिल किया गया है तथा मेरा लोक सभा क्षेत्र सतना इसमें शामिल है या नहीं? यह मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ।

डॉ. भारती प्रवीण पवार : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चिंता जतायी है कि मध्य प्रदेश हो या पीएचसी लेवल में क्या-क्या सुविधा नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी है। जैसा पहले ही सवाल में बात हुई कि टेली कंसल्टेशन हर स्टेट में, हर जिले में शुरू हुई है जिससे पैसा बचे, समय बचे और पेशेंट को ईजी एक्सेसेबिलिटी डाक्टर्स के साथ मिले। उसके साथ ही प्रीडाइग्नोस्टिक सर्विस सेंटर का इनिशिएटिव भी लिया है जिसमें हम डायग्नोस्टिक सर्विसेज को बढ़ा रहे हैं जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को पेशेंट के हिसाब से कम करेगा और जिसमें हम 14 टेस्ट्स सब-सेंटर में, 63 पीएचसी में, 97 सीएचसी सेंटरों में और सब-डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में 111 और 134 डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में करके अलग-अलग लेवल पर प्रीडाइग्नोस्टिक को हम बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जनारोग्य का विषय है जिसमें हम पांच लाख रुपये की सुविधा पेशेंट को दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात कही गई है कि वहां कितने आरोग्य मंदिर आज फंक्शनल हैं, जिनमें यह सुविधा है। टोटल 11 हजार से ज्यादा आयुष्मान मंदिर फंक्शनल हैं, जिनमें आज यह सुविधा बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में भी काम जारी है।

(1135/RV/SRG)

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में क्या-क्या इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल किए गए हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से केन्द्र सरकार ने सतना में जो मेडिकल कॉलेज दिया था, उसका अभी तक अस्पताल नहीं बन पाया है। क्या पन्द्रहवें वित्त आयोग में 350 करोड़ रुपये की इसकी सिफारिश हो सकती है?

वैसे सतना जिले में प्रधानमंत्री ए.बी.एच.आई.एम. के तहत 448.84 लाख रुपये की लागत से चार बी.पी.एच.यू. और एक आई.पी.एच.एल. की स्थापना के लिए सिफारिश की गयी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि यह पर्याप्त नहीं है। जिला अस्पताल, जो मेडिकल कॉलेज के परिसर में बनना है, क्या उसके लिए पन्द्रहवें वित्त आयोग में 350 करोड़ रुपये की स्वीकृति देने पर विचार किया जाएगा?

डॉ. भारती प्रवीण पवार : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सांसद महोदय ने विशेष चिंता जताई है और कुछ मांगें भी की हैं कि उनके क्षेत्र में क्या-क्या सुविधाएं मिलें। माननीय सदस्य ने सतना के बारे में जो सवाल उठाया है, उसकी डिटेल्स उन तक पहुंचायी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का काम एक ऐसे मिशन मोड पर शुरू हुआ है, जिसमें 64,000 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि के माध्यम से हम प्राइमरी, सेकेन्डरी, और टर्शियरी लेवल को मजबूत कर रहे हैं। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि हम जैसे पैन्डेमिक को देखते हैं, वैसे इसे देखें। इसकी बेसिक सुविधाओं के लिए हमें अभी काफी काम करना बाकी है। अगर भविष्य में कोई भी डिजास्टर या पैन्डेमिक आता है तो इसके लिए बेसिक सुविधाएं, जैसे लैब बनना हो, तो हम लगभग 730 जिलों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बना रहे हैं, जो यहां बैठे हुए हर सांसद महोदय के जिले में बन रही है। उसे एक करोड़ रुपये से भी ज्यादा का बजट प्रोवाइड किया गया है। आप सभी माननीय सदस्य इसकी डिटेल ले लें। आप वहां जाएं और अगर आपके यहां इस लैब का काम शुरू नहीं हुआ है तो आप उसके लिए प्रोपोजल भी भेजें। सरकार उसे जरूर एप्रूव करेगी। जैसे इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेवल पर यह लैब बनाई जा रही है, उसके ही आधार पर चाहे रीजनल लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर हो या ब्लॉक लेवल हो, हमने क्लिनिकल मैनेजमेंट और सर्विलेंस को मजबूत करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यह कदम उठाया है।

महोदय, इसके पहले, पन्द्रहवें वित्त आयोग ने इतना बजट नहीं दिया था, जितना अभी पाँच सालों के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपये का बजट हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया गया है। मैं माननीय मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पन्द्रहवें वित्त आयोग के माध्यम से यह राशि उपलब्ध कराई है।

महोदय, बी.पी.एच.यू. भी एक ऐसा लैब है जिसमें हम सर्विलेंस करेंगे और अगर किसी बीमारी का आउटब्रेक होगा तो उसे देखेंगे। ये बी.पी.एच.यू. तालुका लेवल पर बन रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो कहा है कि इसे और बढ़ाया जाए तो मैं सभी माननीय सदस्यों से यह कहती हूँ कि आप प्रोजेक्ट्स भेजिए। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के माध्यम से यह

सुविधा पहुंचायी जा रही है। अगर आपके माध्यम से, स्टेट के माध्यम से यह प्रपोजल आएगा तो हम यहां से उसे जरूर एप्रूव करेंगे।

महोदय, मैं माननीय सदस्य को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत बेसिक प्रश्न पूछा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सभी के लिए बहुत जरूरी है।

DR. M.K. VISHNU PRASAD (ARANI): Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity. Actually I asked to speak on the previous question, but that issue is related to this question also.

Setting up of smart health centres is mandatory because smart health centres immediately diagnoses certain diseases, and screening is essential for every people. At the same time, I would like to ask the Government this. Any child is a gift of the God. At the same time, some children are born with some genetic disorder, especially a special child or an autistic child. But unfortunately, I am very sorry to say that now-a-days I am unable to understand that there is no insurance cover for autistic children for either medical treatment or supporting treatment because it is not a curable one. We have to keep supporting the child. So, Will the Government consider an insurance cover for autistic children also?

(1140/GG/RCP)

डॉ. भारती प्रवीण पवार : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ऑटिज़्म के बारे में स्पेसिफिक प्रश्न उठाया है। जैसे स्मार्ट पीएचसी, स्मार्ट आरोग्य मंदिर की बात हो रही है तो सदन के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि प्राइमरी, सैकेंडरी और टर्शरी केयर सेंटर को आप कृपया ध्यान से समझिए। प्राइमरी लैवल पर हम स्क्रीनिंग करते हैं, वहां पर ऑपरेशंस नहीं होते हैं। उसके बाद वे सैकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए रेफर होते हैं। आज सरकार का प्रयास है कि वहां तक डॉक्टर की सुविधा पहुंचे, टेलिकंसल्टेशन हो। जैसा आपने कहा है कि बच्चों में ऑटिज़्म पाया जाता है या कम सुनाई देने की समस्या होती है, तो इसके लिए स्क्रीनिंग प्राइमरी और सैकेंडरी लैवल पर होते हैं और ऑपरेशन टर्शरी सेंटर में होते हैं। इसके लिए सरकार मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से लगातार स्ट्रक्चर बढ़ा रही है। वर्ष 2014 से पहले जिन मेडिकल कॉलेजिस की संख्या मात्र 350 थी, आज वह संख्या 750 से पार हो गई है। यह उसका एक सॉल्युशन है। पहले टर्शरी लैवल पर एम्स की संख्या एक ही थी, वहीं आज हम 23 एम्स की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही, माननीय सदस्य की जो चिंता है कि क्या ऑटिज़्म के केसेज़ ढूँढने में कोई कमी है तो मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। Rashtriya Bal Swasthya Karyakram (RBSK) की एक स्कीम है, जिसमें हम बच्चों की स्क्रीनिंग करते हैं, उसमें उनको ऑपरेशन के लिए डेट दे कर रेफर करते हैं। हरेक जिले में आरबीएसके का कैंप चलाया जाता है।

मैं आपके माध्यम से सदन से फिर एक बार अनुरोध करती हूँ कि ऐसे केसेज़ हैं तो आप उस माध्यम से रेफर भी करें। इसका फ्री इलाज और फ्री ऑपरेशन टर्शरी लैवल पर किया जाता है और जिसमें हम मेडिकल कॉलेज और एम्स की मदद लेते हैं।

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न काल चल रहा है और बहुत ही अच्छे उत्तर आ रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में सरकार ने आयुष्मान भारत से ले कर जेनरिक मेडिसिन तक बहुत बड़ा बदलाव किया है। मरीजों के आरोग्य में तो बदलाव आया ही है, लेकिन पिछले साढ़े नौ सालों में देश के आरोग्य में भी बहुत बदलाव आया है। इसके साथ-साथ मेरी चिंता यह भी है, भारत सरकार के इतना अच्छा काम करने के बावजूद, महाराष्ट्र की सरकार भी इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन शहरी भागों में कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे हैं कि जहां पर मरीज चला जाता है तो 20-25 लाख रुपये के बिल सात-आठ दिन के इलाज में बन जाते हैं। शिकायत करने पर उसका कोई परिणाम नहीं आता है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इस प्रकार की कितनी शिकायतें आई हैं और कितनों पर क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में जब कई बार कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल ज्यादा बिल चार्ज कर देते हैं तो उसके लिए नेशनल मेडिकल कमिशन में एक एथिक्स बोर्ड है। एथिक्स बोर्ड में ऐसी कोई शिकायत आती है तो उस पर कार्यवाही भी होती है और कई बार मरीज को पैसा वापस भी देने के लिए कहा जाता है। सामान्यतः अस्पताल से अपेक्षा रखी जाती है, इस देश का मॉडल ही अलग है, दुनिया के लिए हेल्थ एक कॉमर्स हो सकता है, लेकिन इंडिया के लिए हेल्थ कॉमर्स नहीं है, हेल्थ सेवा है। यह मैंने कोविड क्राइसिस के समय में देखा है। दुनिया में यह स्थिति भी हमने देखी है कि जब कोविड पीक पर था, तब दुनिया के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ मेरी बात होती थी, तब वे मुझसे पूछते थे कि आपके यहां डॉक्टर्स और नर्सिज़ की प्रेज़ेंस कैसी है, तो मैं कहता था कि फुल प्रेज़ेंस है। वे मुझे कहते थे कि हमारे यहां डॉक्टर्स नहीं आते हैं, नर्सिज़ नहीं आती हैं, पैरा मेडिक स्टॉफ नहीं आता है, क्योंकि वहां कॉमर्स हो सकता है। हमारे देश में यह सेवा है। हम अपेक्षा करते हैं कि आवश्यक रूप से किसी डॉक्टर या अस्पताल के लिए वह आजीविका का माध्यम हो सकता है, लेकिन इंडिया में यह कभी भी लूट का स्थान नहीं होता है। इसलिए डॉक्टर एथिकली ज्यादा पैसा न ले और ज्यादातर लेते भी नहीं हैं, लेकिन अगर लेते हैं तो उसके लिए भी इस्टैब्लिशमेंट और व्यवस्था है। नेशनल मेडिकल कमीशन के एथिक बोर्ड में उसकी शिकायत की जा सकती है।

(इति)

(प्रश्न 5)

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे प्रश्न का उन्होंने बहुत ही विस्तार से उत्तर दिया है। अध्यक्ष जी, मैं यह महसूस कर रहा हूँ कि इस समय देश में एक बड़ी चर्चा है कि मोदी जी का यह प्रयास है कि चाहे आम हो या खास, सभी 100 साल जिएं। इसमें आयुष मंत्रालय अच्छा काम कर रहा है। बहुत ही सार्थक कार्य हुआ है। इसका हमने एक उदाहरण देखा, जब विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही थी, तब सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन आयुष के प्लेटफॉर्म पर होते थे।

(1145/MY/PS)

अध्यक्ष जी, हमारे दिल्ली में भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र का एक सेंटर है। नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली हमारा क्षेत्र है। इस क्षेत्र से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा सटे हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि अगर हमारे क्षेत्र में दिल्ली का एक और भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र बन जाए तो इसका लाभ सभी को मिलेगा। क्या ऐसा हो सकता है? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. (प्रो.) महेन्द्र मुंजपरा): माननीय अध्यक्ष जी, यह क्वेश्चन नेशनल आयुष मिशन से रिलेटेड था। सबसे पहले मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारी सिस्टम का एक ही टाइप का जो साइन, सिम्टम्स एंड डिजीज हैं, उसको अलग-अलग पैथी में अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है, इसलिए रिसर्च स्कॉलर को टीचिंग में सब जगह दिक्कत आती है। मोदी जी ने अपने 'मन की बात' के लास्ट एपिसोड में उसका जिक्र किया, launch of ICD-11, Traditional Medicine Chapter Module 2 version for Country Implementation, इसके द्वारा रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट को बहुत ही फायदा होगा। इसके लिए मोदी जी ने पहल की है, इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

अध्यक्ष जी हमारे माननीय संसद सदस्य जी का क्वेश्चन है कि दिल्ली में All India Institute of Ayurveda का एक और सेंटर बनाया जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के सरिता विहार में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का सेंटर बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। इसके फेज-2 का इन्फॉर्मेशन भी हम within a short time करने जा रहे हैं। वहाँ पर हम उनको भी बुलाएंगे। वह वहाँ पर जरूर आएँ, ऐसा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ।

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। माननीय मंत्री जी से मेरा एक और अपेक्षा होगी कि आयुष की तरफ लोगों का जो झुकाव हो रहा है, उनके झुकाव का लोगों में और भी संदेश जाए, इसका भी हमें प्रयास करना चाहिए। इसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? यह भी मैं जानना चाहूँगा।

डॉ. (प्रो.) महेन्द्र मुंजपरा: अध्यक्ष जी, हमारे माननीय संसद सदस्य जी यह जानना चाहते हैं कि आयुष प्रचार और प्रसार कैसे हो। इसके लिए आईसीडी एक्टिविटी है, उसके माध्यम से सभी लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव और इक्विटेबल आइज ट्रीटमेंट मिले। Prevention is better than cure.

आप में कोई बीमारी न आए, इसलिए 'Preventive and Promotive Aspects' हेल्थ केयर के लिए एक holistic wellness model आयुष बेस पर खड़ा किया गया है। इससे सब लोगों को आयुष की ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कॉस्ट इफेक्टिव मिल जाएगी।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। वर्ष 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आयुष का एक अलग मंत्रालय बना और इंटरनेशनल योगा डे भी हुआ। इसके कारण आयुष के बारे में पूरी दुनिया को जानकारी मिली, सोच-समझ मिली और भारत सरकार का एक फोकस आयुष मंत्रालय की तरफ गया।

अध्यक्ष महोदय, अभी जो जी-20 सम्मेलन संपन्न हुआ, उसमें लीडरशिप का जो रिजोलुशन हुआ, उसमें भी आयुष और इस तरह की पद्धति को शामिल किया गया। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है।

सर, हमारा मूल प्रश्न है कि झारखंड और बिहार में डॉक्टर्स की कमी है। खासकर झारखंड में राज्य सरकार के कारण डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं। उस कारण से लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन पर, खासकर आयुष मंत्रालय का जो होम्योपैथ, आयुर्वेद, युनानी पद्धति है, उसके ऊपर लोग निर्भर करते हैं। हमारे लोक सभा क्षेत्र गोड्डा में होम्योपैथ का एक कॉलेज है। वह कॉलेज माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण चल रहा है। आज वह डॉक्टर्स की कमी के कारण नहीं चल पा रहा है। उसमें भारत सरकार फंड देती है।

सर, हमने सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के लिए भी काम किया है। देवघर में देवों के देव हैं, बाबा बैद्यनाथ हैं और कई एक कंपनियाँ उन्हीं के नाम से चलती हैं। उसके लिए भी पिछले चार साल से भारत सरकार ने प्रपोजल दिया है। वह राज्य सरकार के कारण नहीं बन पाया है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से स्पेशल प्रश्न है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फोकस है और उसमें ईस्टर्न इंडिया के लुकिंग ईस्ट पॉलिसी के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा है। हमारे यहां ये जो दो इंस्टीट्यूट्स हैं, गोड्डा में होम्योपैथ कॉलेज और देवघर में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट खुलना था, उन दोनों के बारे में अगर माननीय मंत्री जी जानकारी दे दें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद।

डॉ. (प्रो.) महेन्द्र मुंजपरा: अध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय संसद सदस्य जी ने कहा कि उनके यहां डॉक्टर की कमी है और स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, जिसके कारण दो नए कॉलेज ऑपरेट नहीं हो पा रहे हैं।

(1150/CP/SMN)

प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी वर्ष 2014 के बाद जब प्रधान मंत्री बने, उस वक्त आयुष मिनिस्ट्री का बजट 691 करोड़ रुपये था, अभी यह 2023-24 में बढ़कर 3,647 करोड़ रुपये हो गया है। आयुष कॉलेज में बच्चे पढ़कर डॉक्टर बनते हैं और सारे देश, विदेश में जाकर प्रैक्टिस करते हैं। वर्ष 2014-15 में आयुष कॉलेजों की संख्या 512 थी, वह संख्या 2023-24 में बढ़कर 782 हो गई है। अंडर ग्रेजुएट सीट्स में 80 पर्सेंट की बढ़ोत्तरी हुई है और पोस्ट ग्रेजुएशन सीट्स में 41 पर्सेंट की

बढ़ोत्तरी हुई है। आपने जो दोनों इंस्टीट्यूट्स के बारे में पूछा है, वह हम आपके स्टेट में चालू करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं आपको यह आश्वासन देता हूँ।

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, Kerala has always been in the forefront of medical facilities in terms of treatment, in terms of setting primary healthcare centres in every Panchayat. AYUSH centres are also working quite well.

My question is this. The National Health Mission is doing a huge discrimination against the State of Kerala where the outlay for 2023-24 was Rs. 2521.99 crore and the resource envelope was Rs. 1,376 crore.

Sir, only Rs. 154 crore have been allotted to Kerala so far. The National Health Mission is doing work for rural and urban areas. The contract doctors, nurses, technicians and staff are being supported using the National Health Mission's fund. During the UPA regime, 90 per cent was given by the Centre as the Central share and 10 per cent was given as the State share. Now, it is 60:40. There has been a huge discrimination against the State of Kerala and the Director, National Health Mission has sent a letter to the Central Government requesting to release the rest of the funds to make sure that the State healthcare of Kerala works quite well.

Thank you, Sir.

डॉ. (प्रो.) महेन्द्र मुंजपरा: माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार सभी राज्यों को बराबरी से फंड एलोकेट करती है। यह क्वैश्चन नेशनल हेल्थ मिशन से रिलेटेड है। बेसिकली हमारी आयुष मिनिस्ट्री में नेशनल आयुष मिशन आता है। फिर भी, उसके स्टेट एनुअल एक्शन प्लान में हमारे आयुष मिनिस्ट्री के बारे में जो कुछ प्रपोजल में आयेगा, उस पर हम जरूर विचार करेंगे और केरल के साथ पूरा न्याय करने का प्रयत्न करेंगे... (व्यवधान)

(इति)

(Q.6)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, this question relates to a very important issue regarding the Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers.

Sir, you may kindly see that the Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers are being given meagre salary, not even salary, only honorarium. In that too, the Government of India's contribution according to the answer supplied by the hon. Minister, is just Rs. 4500 per month for Anganwadi workers and Rs. 2700 per month for Anganwadi Helpers.

Sir, the work and responsibilities given to the Anganwadi Workers and Helpers is very huge. It is very disproportionate. The honorarium provided to the Anganwadi Workers and Helpers is very meagre and it is disproportionate to the work given to them.

The honorarium was revised last on 1st October, 2018 when Rs. 3000 was enhanced to Rs. 4500 per annum as the contribution of the Government of India.

Sir, I am not detailing the work done by the Anganwadi Workers and Helpers. The three-page answer submitted by the hon. Minister itself suggests that numerous works and numerous responsibilities is being entrusted with them but the salary or the honorarium is very meagre.

The pre-schooling activities of the children in the age group of 3-6 years, the growth monitoring of children, mother's nutrition and the health programme between 15 and 49 years, and take home ration for the pregnant women and lactating mother and this Amrutham Nutrimix programme, community based meeting twice in one month, all these works are being done by these workers.

(1155/SM/NK)

My specific question to the Minister is, whether the Government proposes to increase the honorarium of the Anganwadi workers and helpers. As far as the workers are concerned, long-term agreement is there for five years. Already five years are over.

I want to know whether the Government will consider the demand to enhance the honorarium of Anganwadi workers in line with the Government of India employees and also as per the long-term agreement. SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, the three-page answer which the hon. Member refers to does not describe the volume of duties of Anganwadi workers. In fact, it describes the volume of benefits given by the Government of India to Anganwadi workers.

Having said that, I would, through you, Sir, applaud the passion with which the hon. Member speaks about the honorarium of Anganwadi workers. I, in fact, was hopeful that in the year 2008 when UPA was in power and an Anganwadi helper would get a mere Rs.750, the same House would have witnessed the exhibition of such passion.

From Rs.750 in UPA era, today the Anganwadi workers and mini Anganwadis, which are now to be upgraded to full-fledged Anganwadis, are receiving Rs.4,500. That is already illustrated in the answer given.

Additionally, what the answer also contains is the per community-based event that Anganwadi workers do. Rs.250 is given per community-based event for Angagwaid for engaging with community. Additionally, Rs.500 is given which encompasses if the Anganwaid worker visits the house of a beneficiary or, for that matter, measures a child as per WHO standards.

I am hopeful that the detail that is illustrated in the answer given is reflected upon by the hon. Member. I am sure that the hon. Member, given the passion with which he speaks about Anganwadi workers, would also applaud the announcement yesterday, courtesy the Prime Minister of India, of now ensuring that the benefits of Ayushman Bharat Yojana are now made available to Anganwadi workers and helpers across the country including ASHA workers who have our gratitude for their service.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I fully agree with the hon. Minister that yesterday's announcement is very good as far as Anganwadi

workers are concerned by extending Ayushman Bharat Scheme to Anganwadi workers and helpers.

My second supplementary question is about the Employees State Insurance Scheme. It is beneficial to the workers and they are getting better treatment. In the State of Kerala, we are having a pension scheme for them as per the Anganwadi Workers (Regularisation of Service and Welfare) Act of 2018.

My question is whether the Government will consider extending the benefits of Employees State Insurance Medical Benefit Scheme to the Anganwadi workers and helpers.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, I was hopeful that the hon. Member reflects on the response given. The answer itself says that the Government of India, under the leadership of Prime Minister Modi Ji, has extended the benefits of life insurance and accidental coverage up to Rs.2 lakh each for every Anganwadi worker and helper. Every State Government has been informed about the same.

Additionally, the pension scheme under Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana is something that is already extended to Anganwadi workers and helpers.

(ends)

(pp.23-30)

(Q.7)**माननीय अध्यक्ष :** श्रीमती पूनम महाजन-उपस्थित नहीं।

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Sir, through you, I thank the hon. Minister of Health and Family Welfare for giving an elaborative reply about the measures taken by the Union Government to increase the medical colleges and under-graduate and post-graduate seats in the country to meet the medical standards as recommended by WHO.

My supplementary question to the Minister is whether the Ministry has looked into the issue of new notice issued by National Medical Commission, limiting the number of medical seats in the States. How would it affect the State of Andhra Pradesh especially? By his visionary leadership, our hon. Chief Minister, Shri YS Jagan Mohan Reddy himself has sanctioned 17 new medical colleges in 2021.

(1200/RP/SK)

He sanctioned them for each district to ensure the availability of, at least, one medical college in each of the districts in the Government sector. It is because the Government has limited 100 seats for 10 lakh population. I request the Government through you, Speaker, Sir, to look into this matter so that there will be justice for the medical students of the State of Andhra Pradesh.

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप एक मिनट में उत्तर दें क्योंकि बारह बज गए हैं।

... (व्यवधान)

डॉ. भारती प्रवीण पवार : माननीय अध्यक्ष जी, आंध्र प्रदेश के बारे में जो डिटेल है, माननीय सदस्य को पहुंचा दी जाएगी। जो रिक्मेंडेशन आती हैं, एनएमसी उसे विजिट करती है और स्ट्रक्चर देखती है, अगर वह कैपेबल है तभी उसे परमिशन मिलती है।

महोदय, हमने आंध्र प्रदेश को आज तक 37 कॉलेजेज दिए हैं और रिसेंटली फेज़-3 में चार कॉलेजेज दिए हैं। मुझे लगता है कि हम डिटेल दे देंगे लेकिन सरकार का विज़न आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में यही है कि हर जिले को हम मेडिकल कॉलेज से जोड़ें। इसके लिए कल घोषणा भी हुई है कि समिति बनेगी जिसमें आपके सुझाव अपेक्षित हैं। धन्यवाद। (इति)

प्रश्न काल समाप्त

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1202 बजे

माननीय अध्यक्ष : मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: जोशी जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): माननीय अध्यक्ष जी, कल कांग्रेस के इसी सदन के सदस्य, जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के भाई भी हैं, श्री डी.के. सुरेश ने मीडिया के सामने एक स्टेटमेंट दी है और स्टेटमेंट देते हुए देश के विभाजन की बात कही है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने इस रेवेन्यू और बजट एलोकेशन का झूठा बेस बनाते हुए देश के विभाजन की जो बात कही है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और खंडन करता हूं। ... (व्यवधान) कांग्रेस के नेता ने संविधान का भी अपमान किया है। देश के विभाजन को लेकर कांग्रेस की परंपरा अभी भी बरकरार है। ... (व्यवधान)

मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को इस विषय का स्पष्टीकरण करना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि संविधान का जो आश्रय है उसका घोर अपमान किया गया है। ... (व्यवधान)

मैं अध्यक्ष जी से मांग करता हूं और निवेदन करता हूं कि जिस संविधान के तहत हम सब लोग शपथ लेते हैं, उस संविधान का अपमान किया गया है, घोर अपमान किया गया है, इसलिए कृपया आप इस विषय को एथिक्स कमेटी में भेजिए। ... (व्यवधान)

मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं कि आपका रुख क्या है? आपका रवैया क्या है? क्या आप इस स्टेटमेंट के साथ हैं? अगर आप इसके साथ नहीं हैं तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस को उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ... (व्यवधान)

जिन्होंने अपमान किया गया है, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और कांग्रेस को इसके बारे में माफी मांगनी चाहिए। ... (व्यवधान) देश तोड़ने की बात कभी-भी देश स्वीकार नहीं करता। उन्होंने दक्षिण भारत के एक सैपरेट देश की मांग की है। ... (व्यवधान) मैं बोलना चाहता हूं कि मैं भी दक्षिण भारत से आता हूं। जय शंकर जी भी इधर बैठे हैं, वह भी दक्षिण भारत से आते हैं। हम भारत की अखंडता में पूरी निष्ठा रखते हैं, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। ... (व्यवधान) पूरा देश एक है, यह हम मानते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोनिया गांधी जी से मांग करता हूँ कि उनको ऐक्शन लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ... (व्यवधान) मैं बार-बार यही आग्रह करता हूँ कि जो शपथ ली है, उसका उल्लंघन हुआ है। ... (व्यवधान)

डॉ. बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर रचित संविधान के तहत हम और सब लोग जो शपथ लेते हैं, एक तरफ उस शपथ का अपमान किया गया है और दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी अपमान किया गया है।... (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस विषय को एथिक्स कमेटी में भेजिए।... (व्यवधान)

दूसरी बात, मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूँ। ... (व्यवधान) बालू जी आप क्यों उठ गए हैं? ... (व्यवधान) मैं कांग्रेस से आग्रह करता हूँ कि उनके ऊपर ऐक्शन लेना चाहिए।

(1205/KDS/NKL)

अगर ऐक्शन नहीं लेते हैं, तो देश यह मानेगा कि ये लोग भी देश के टुकड़े-टुकड़े करने में लगे हुए हैं। ... (व्यवधान) अतः मैं सोनिया गांधी जी से आग्रहपूर्वक डिमांड रखता हूँ कि ऐक्शन लिया जाए और माफी मांगनी चाहिए। यह मेरा आग्रह है। ... (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1205 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे।

आइटम नंबर 2, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :-

- (1) भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम, 2019 की धारा 32 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को संदेय, वेतन और भत्ते तथा निबंधन और शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 2023, जो दिनांक 27 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 560(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (समितियों की संरचना और कृत्य) नियम, 2023, जो दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 717(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (माध्यस्थम का संचालन) विनियम, 2023, जो दिनांक 1 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. ए-60011/96/2023-प्रशासन (एआर)-IIएसी में प्रकाशित हुए थे।
 - (चार) भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की रीति और शक्तियां तथा कृत्य) विनियम, 2023, जो दिनांक 5 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. ए-60011/117/2023-प्रशासन (एआर)-IIएसी में प्रकाशित हुए थे।
- (2) (एक) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) (एक) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I rise to lay on the Table of the House:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
- (a) (i) Review by the Government of the working of the Shipping Corporation of India Limited, Mumbai, for the year 2022-2023.
- (ii) Annual Report of the Shipping Corporation of India Limited, Mumbai, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (b) (i) Review by the Government of the working of the Shipping Corporation of India Land and Assets Limited, Mumbai, for the year 2022-2023.
- (ii) Annual Report of the Shipping Corporation of India Land and Assets Limited, Mumbai, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

- (2) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Paradip Port Authority, Paradip, for the year 2022-2023.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Paradip Port Authority, Paradip, for the year 2022-2023.
- (iii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Paradip Port Authority, Paradip, for the year 2022-2023, together with Audit Report thereon.
- (iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Paradip Port Authority, Paradip, for the year 2022-2023.
- (3) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Chennai Port Authority, Chennai, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Chennai Port Authority, Chennai, for the year 2022-2023.
- (4) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Tariff Authority for Major Ports, Mumbai, for the year 2022-2023, together with Audit Report thereon.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Annual Accounts of the Tariff Authority for Major Ports, Mumbai, for the year 2022-2023. ...
(Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (ADV. AJAY BHATT): Hon. Speaker Sir, with your kind permission, I rise to lay on the Table of the House:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
 - (a) (i) Review by the Government of the working of the Yantra India Limited, Nagpur, for the year 2022-2023.

- (ii) Annual Report of the Yantra India Limited, Nagpur, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (b)
 - (i) Review by the Government of the working of the India Optel Limited, Dehradun, for the year 2022-2023.
 - (ii) Annual Report of the India Optel Limited, Dehradun, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (c)
 - (i) Review by the Government of the working of the Munitions India Limited, Pune, for the year 2022-2023.
 - (ii) Annual Report of the Munitions India Limited, Pune, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (2)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Land Warfare Studies, New Delhi, for the years 2020-2021 to 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Land Warfare Studies, New Delhi, for the years 2020-2021 to 2022-2023.
- (3) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at Item No. (2) above. ...
(Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (DR. R.K. RANJAN SINGH): Hon. Speaker Sir, with your permission, I rise to lay on the Table of the House:-

- (1) A copy of the Indian Council of World Affairs, Recruitment (Amendment) Regulations, 2023 (Hindi and English versions) published in Notification No. F.No. ICWA/Admn/551/10/2023 in Gazette of India dated 7th November, 2023, under Section 27 of the Indian Council of World Affairs Act, 2001.

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Nalanda University, Nalanda, for the year 2022-2023.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Nalanda University, Nalanda, for the year 2022-2023, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Nalanda University, Nalanda, for the year 2022-2023.
- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of World Affairs, New Delhi, for the year 2022-2023.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Council of World Affairs, New Delhi, for the year 2022-2023, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of World Affairs, New Delhi, for the year 2022-2023. ...
(Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AYUSH (DR. (PROF.) MAHENDRA MUNJAPARA): Hon. Speaker Sir, with your kind permission, I rise to lay on the Table of the House:-

- (1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 56 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020:-
- (i) The National Commission for Homoeopathy (General) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No.1-93/2023-NCH in Gazette of India dated 4th December, 2023.
- (ii) The National Commission for Homoeopathy (Medical Research in Homoeopathy) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No.3-36/2021/NCH/HEB/R.C. in Gazette of India dated 4th December, 2023.

- (iii) The National Commission for Homoeopathy (National Examinations in Homoeopathy) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No.3-104/2023/NCH/HEB/Exam Regulation in Gazette of India dated 28th November, 2023.
- (2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 56 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020:-
 - (i) The National Commission for Indian System of Medicine (General) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. Sec/NCISM/Regulations/2023-1 in Gazette of India dated 6th December, 2023.
 - (ii) The National Commission for Indian System of Medicine (Procedure for Engagement of Experts and Professionals) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. Sec/NCISM/Regulations/2023-1 in Gazette of India dated 6th December, 2023.
- (3)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Commission for Protection of Child Rights, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Commission for Protection of Child Rights, New Delhi, for the year 2022-2023.
- (4)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Commission for Women, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Commission for Women, New Delhi, for the year 2022-2023.
- (5) A copy of the Institute of Teaching and Research in Ayurveda (Amendment) Regulations, 2023 (Hindi and English versions) published in Notification No. F.No. L-12015/18/2021-AS in Gazette of

India dated 31st October, 2023, under Section 29 of the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Act, 2020.

- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar, for the year 2022-2023.
- (7) A copy of the Special Report (Hindi and English versions) on the Child Protection in the State of West Bengal by National Commission for Protection of Child Rights.
- (8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Social Welfare Board, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Social Welfare Board, New Delhi, for the year 2022-2023. ... (*Interruptions*)

ASSENT TO BILLS

1207 hours

SECRETARY-GENERAL: Sir, I lay on the Table the following eight Bills passed by the Houses of Parliament during the Fourteenth Session of Seventeenth Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on the 05th December, 2023:-

- (i) The Advocates (Amendment) Bill, 2023;
- (ii) The Appropriation (No. 3) Bill, 2023;
- (iii) The Appropriation (No. 4) Bill, 2023;
- (iv) The Post Office Bill, 2023;
- (v) The Central Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2023;
- (vi) The Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023;
- (vii) The Provisional Collection of Taxes Bill, 2023; and
- (viii) The Press and Registration of Periodicals Bill, 2023.

I also lay on the Table a copy each, duly authenticated by the Secretary General, Rajya Sabha, of following eleven Bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President:

- (i) The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023;
- (ii) The Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023;
- (iii) The Central Universities (Amendment) Bill, 2023;
- (iv) The Repealing and Amending Bill, 2023;
- (v) The Jammu and Kashmir Reorganisation (Second Amendment) Bill, 2023;
- (vi) The Government of Union Territories (Amendment) Bill, 2023;
- (vii) The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2023;
- (viii) The Telecommunications Bill, 2023;
- (ix) The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023;
- (x) The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023; and
- (xi) The Bharatiya Sakshya Bill, 2023. ... (*Interruptions*)

COMMITTEE ON ESTIMATES**32nd to 34th Reports**

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Sir, I beg to present present the following Reports (Hindi and English versions) of the Committee on Estimates (2023-24):-

- (1) Thirty-second Report on the subject 'Review of Performance of National Rural Development Agency (NRIDA) w.r.t. Implementation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)' pertaining to the Ministry of Rural Development.
- (2) Thirty-third Report on the subject 'Assessment of various projects including Green Highways under National Highways Development Project (NHDP)' pertaining to the Ministry of Road Transport and Highways.
- (3) Thirty-fourth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their 26th Report (17th Lok Sabha) on the subject 'Evaluation of Electric Vehicle (EV) Policy' pertaining to the Ministry of Heavy Industries. ... *(Interruptions)*

STATEMENTS CORRECTING ANSWER GIVEN TO UNSTARRED**QUESTION NO. 1109 DATED 8.12.2023****RE: (i) DATA OF AYUSH COLLEGES AND
(ii) GIVING REASONS FOR DELAY – LAID**

THE MINISTER OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS AND MINISTER OF AYUSH (SHRI SARBANANDA SONOWAL): Hon. Speaker Sir, I rise to lay statements correcting the reply given on 8.12.2023 to Unstarred Question No. 1109 (Hindi and English versions) by Shrimati Queen Oja, MP regarding 'Data of AYUSH Colleges' and the reasons for delay. ... *(Interruptions)*

**STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF
RECOMMENDATIONS IN 19TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON
HOUSING AND URBAN AFFAIRS – LAID**

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, with your permission, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 19th Report of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs on action taken by the Government on the recommendations contained in the 18th Report of the Committee on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs. ... (*Interruptions*)

(1210/VR/MK)

**STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF
RECOMMENDATIONS IN 350TH REPORT OF
STANDING COMMITTEE ON EDUCATION, WOMEN,
CHILDREN, YOUTH AND SPORTS -- LAID**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AYUSH (DR. (PROF.) MAHENDRA MUNJAPARA): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 350th Report of the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Demands for Grants (2023-24) pertaining to the Ministry of Women and Child Development.(*Interruptions*)

BUSINESS OF THE HOUSE

1212 hours

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): With your permission Sir, I rise to announce that Government Business for the remaining part of the 15th Session of 17th Lok Sabha will consist of:-

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's order paper:- [it contains discussion on the Motion of Thanks on the President's Address]
2. General Discussion on Interim Union Budget 2024-25.
3. Discussion and voting on:
 - a) Demands for Grants on Account 2024-25 and introduction, consideration and passing of the related Appropriation Bill; and
 - b) Supplementary Demands for Grants 2023-24 and introduction, consideration and passing of the related Appropriation Bill.
4. Consideration and passing of the Finance Bill, 2024
5. General Discussion on Interim Budget of Union Territory of Jammu and Kashmir 2024-25.
6. Discussion and voting on:
 - a) Demands for Grants on Account of Union Territory of Jammu and Kashmir 2024-25 and introduction, consideration and passing of the related Appropriation Bill; and
 - b) Supplementary Demands for Grants of Union Territory of Jammu and Kashmir 2023-24 and introduction, consideration and passing of the related Appropriation Bill.
7. Consideration and passing of the following Bills, *after their introduction*:-
 - a) The Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2024;
 - b) The Public Examination (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024;
 - c) The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2024;
 - d) The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2024; and
 - e) The Jammu and Kashmir Local Bodies Laws (Amendment) Bill, 2024.

1213 hours

(At this stage, S/ Shri Gaurav Gogoi, T. R. Baalu, N. K. Premachandran and some other hon. Members left the House.)

ELECTION TO COMMITTEE

All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Bhopal

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. MANSUKH MANDAVIYA): Sir, I beg to move the following:-

"That in pursuance of Section 4(9) read with Section 6(3) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one member from amongst themselves to serve as member of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Bhopal vice Shri Uday Pratap Singh resigned from Lok Sabha w.e.f. 6.12.2023 subject to the other provisions of the said Act."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6(3) के साथ पठित धारा 4(छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन, श्री उदय प्रताप सिंह, जिन्होंने 6.12.2023 से लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भोपाल के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कहां गए? पेपर लेड पूरा हो गया है, क्या अब वे नहीं बोलना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1213 बजे

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है।

Re: Withdrawal of SROs issued by the State Board for Wildlife in J&K and delineation of wildlife sanctuaries in Ladakh

SHRI JAMYANG TSERING NAMGYAL (LADAKH): In 1987, the intent to establish the Hemis, Changthang, and Karakorum as Protected Areas, covering 12,350Sq/Km, was notified under Sections 17 & 35 of the J&K Wildlife Act 1978 through SRO 158, 155, 152. However, crucial subsequent processes, such as Proclamation, Settlement of Rights, and the Final Declaration of the Protected Area under Section 26A-1, remain incomplete due to gross errors in the initial notification. Presently, the restrictions are being arbitrarily applied to approximately 38,755Sq/Km, encompassing 87% of Leh District, far exceeding the initially designated area. Alarming, over 98% of residents in this expanded area are Tribals. To address these critical issues, the following interventions are urgently requested: 1. The Ministry of Home Affairs is urged to intervene and withdraw SRO 158, 155, 152, issued by the State Board for Wildlife of erstwhile J&K State, on the Demand for the Withdrawal of Wildlife Sanctuary Notifications in Ladakh and grounds of unresolved errors persisting for 36 years and the improbable rectification of these errors in the future.

2. Additionally, the Ministry of Home Affairs is implored to facilitate a fresh proposal from the State Board for Wildlife of the Union Territory of Ladakh in consultations with LAHDCs to delineate Wildlife Sanctuaries in Ladakh, excluding Human Habitations.

(ends)

Re: Starting of flight services between Prayagraj and Delhi

श्रीमती केशरी देवी पटेल (फूलपुर): प्रयागराज से दिल्ली तथा दिल्ली से प्रयागराज हेतु सुबह 7 से 9 बजे एवं सांय 7 से 9 बजे के आसपास सेवा शुरू की जाये। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकार के कई मुख्यालय, उच्च न्यायालय तथा कई विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थान स्थित हैं तथा यह शहर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का प्रमुख केंद्र है। प्रयागराज में 2025 में महाकुम्भ होना है, इसलिए भी यह होना जरूरी है। प्रयागराज एअरपोर्ट पर आवक कार्गो की अस्थाई सुविधा दी गई है, परन्तु कार्गो भेजने और स्टोर करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि एअरपोर्ट की भविष्य की विस्तार योजना में कार्गो कोम्प्लेक्स का प्रावधान है। कार्गो सुविधा होने पर यहाँ के किसानों व छोटे व्यवसायियों को लाभ होगा। अत मैं माननीय उड्डयन मंत्री जी से मांग करती हूँ कि प्रयागराज से दिल्ली एवं दिल्ली से प्रयागराज हेतु सुबह 7 से 9 बजे एवं सांय 7 से 9 बजे के आसपास उड़ान सेवा शुरू की जाये एवं प्रयागराज एअरपोर्ट से कार्गो सेवा और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें तथा हज के लिये विमान की शुरुआत की जाए।

(इति)

Re: Need to expedite the construction of new railway line from Gaya to

Daltonganj via Rafiganj

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): गया-शेरघाटी, इमामगंज, डालटनगंज वाया रफीगंज स्वीकृत नई रेलवे लाइन निर्माण कराना आवश्यक है। पलामू जिला देश के 112 आकांक्षी जिलों में से एक है, स्वभावतया प्रगति के पथ पर पिछड़ा हुआ है। इसके बहुत सारे इलाके की जनता आजादी के 75 वर्ष के बावजूद रेल की सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसे ही एक क्षेत्र में हरिहरगंज, पाटन, छतरपुर, नौडीहा बाजार प्रखंड है। इस क्षेत्र को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए एवं यहाँ की जनता को रेल सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए गया-शेरघाटी, इमामगंज, डालटनगंज वाया रफीगंज रेल लाइन की स्वीकृति कई वर्ष पूर्व दी गई थी। परन्तु आज तक उक्त परियोजना पर धरातल पर काम नहीं हो सका है। वर्ष 2023-2024 के बजट में उक्त रेलवे लाइन के निर्माण हेतु सर्वे कार्य के लिए 20 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी को बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ। परन्तु इस कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता है।

अतः माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि इस रेल खंड के निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारम्भ कराएं ताकि बिहार एवं झारखंड दोनों राज्यों के निवासियों को रेल से आवागमन की सुविधा मिल सके।

(इति)

**Re: Need to run a daily train between Veraval (Somnath) in Gujarat and
Bandra in Maharashtra**

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): वर्तमान में गुजरात के वेरावल (सोमनाथ) से बांद्रा के बीच गाड़ी संख्या 19204 सप्ताह में केवल एक दिन (शुक्रवार) को चलती है और यह एकमात्र गाड़ी है जो मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों (वडिया, कुंकावाव, लुनिधार, चीतल, खिजडिया एवं लाठी) से बांद्रा की ओर जाती है और इस गाड़ी का संचालन सप्ताह में केवल एक दिन होने से मेरे संसदीय क्षेत्र से मुंबई महानगर की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रतिदिन मुंबई तक सीधी ट्रेन की सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती है। उन्हें यात्रा हेतु काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। यदि वेरावल से बांद्रा तक वन्दे भारत ट्रेन या एक सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन इसी रूट पर प्रतिदिन कर दिया जाए तो यात्रियों को मुंबई यात्रा करने में एक सुखद एवं आरामदायक यात्रा का लाभ मिल सकेगा।

अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है की गुजरात के वेरावल (सोमनाथ) से बांद्रा के बीच इसी रूट पर प्रतिदिन एक वन्दे भारत ट्रेन या एक सुपरफास्ट ट्रेन की सुविधा प्रदान करने की कृपा करें, जिससे जनता को इसका लाभ मिल सके।

(इति)

**Re: Construction of new Holiday Home, Guest Houses and Touring
Officers' Hostels in Ayodhya**

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): The Directorate of Estates under the Ministry of Housing and Urban Affairs administers the Holiday Homes/Guest Houses/Touring officers' Hostels which are maintained by Central Public Works Department. These Guest Houses are booked by serving/retired employees of Central/ State PSUs/Autonomous Bodies/Statutory Bodies.

As the newly constructed Shri Ram Janm bhoomi Teerth Kshetra at Ayodhya has already been inaugurated. Lakhs of devotees from various parts of our country are planning to visit the Shri Ram Temple for darshan and puja.

I request the Hon'ble Minister of Housing and Urban Affairs to arrange for construction of new Holiday Homes/Guest Houses/Touring offices' Hostels in Ayodhya at the earliest keeping the religious sentiment of devotees of all over the country including Odisha.

(ends)

Re: Need to expedite irrigation project for channelizing water of Telhar Kund to Jagdahwah dam in Kaimur district

श्री छेदी पासवान (सासाराम): बिहार के कैमूर जिलान्तर्गत सुवारा नदी के बायां दायं तटबंध पर ग्राम-पड़री-पंचकुइयों के पास बांध बनाकर अधौरा प्रखण्ड के तेलहार कुण्ड के पानी को जगदहवां बांध में गिराने की शीघ्र आवश्यकता है। इस असिंचित एवं पिछड़े क्षेत्र में सिंचाई का एक मात्र स्रोत जगदहवां बान्ध ही है। इस संबंध में अनेकों पत्राचार द्वारा आग्रह किया गया है, जिसके आलोक में मुझे अवगत कराया गया है कि बाँध के निर्माण हेतु कंसल्टेंट की नियुक्ति की जा चुकी है। एस0जी0ई0 कंसल्टेंसी को डी0पी0आर0 तैयार कर तीन माह के भीतर समर्पित करना था तथा वन विभाग से अनापति प्राप्त कर एवं भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की कार्यवाही शुरू की जा चुकी है, परन्तु विलम्ब के कारण किसानों में निराशा नजर आने लगी है। वर्षों से सूखाग्रस्त क्षेत्र को जितनी जल्दी सिंचाई का साधन उपलब्ध होगा उतना ही किसानों को राहत मिलेगी। अतः सदन के माध्यम से मेरा जल शक्ति मंत्री जी से अनुरोध है कि यथाशीघ्र उक्त सिंचाई परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र कार्यान्वित करने हेतु मंत्रालय को निर्देशित करने की कृपा की जाए।

(इति)

Re: Setting up of a Sainik School in Godda/Deoghar, Jharkhand

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): I wish to draw your kind attention towards the backwardness of Santhal Pargana region in general and the area(s) of Godda and Deoghar, in particular which happens to be my Lok Sabha constituency. The overall condition of Education in this region is a subject-matter of utter neglect inspite of the fact that since time immemorial, the entire region was considered to be a harbinger of ancient education practices and dissemination of social norms and mores. There has been a vociferous demand of establishing a Sainik School in Godda/Deoghar so that this area could also share the pride of having quality education to their children. In February 2016, the then Honourable Minister of Defence, visited my constituency and after acknowledging the backwardness of the region, he was kind to announce the setting up of a Sainik School in Godda/Deoghar. Further, as a consequence to the said announcement, the Project for establishing a Sainik School was immediately sanctioned by the Ministry of Defence. However, it is a matter of concern that since then, more than five years have elapsed, but the entire Project has not witnessed any visible progress.

(ends)

**Re: Operationalisation of Post Office Passport Seva Kendra (PoPSK) at
Nandurbar Parliamentary Constituency**

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Currently, 93 PSKs and 434 POPSKs have been set up in the country and are operational to cater to the needs of passport seekers. The MEA and Department of Posts had announced to utilise the Head Post Offices (HPO) in various states as Post Office Passport Seva Kendra (POPSK). I represent the Nandurbar Parliamentary constituency which is amongst the 51 Lok Sabha constituencies which have no Passport Seva Kendra or Post Office Passport Seva Kendra. Nandurbar is a tribal dominated region having a low human development index indicator. The people of Nandurbar have to travel to Dhule or Nasik in order to get an appointment for a passport which causes inconvenience. The Government had sanctioned a POPSK for Nandurbar Parliamentary constituency and the required land/space was also made available and POPSK was scheduled to be inaugurated in 2023, but due to absence of necessary equipments to operationalize the POPSK, the inauguration and subsequent operationalization of passport related services has been delayed. I request the Government to intervene and take necessary steps to address the delay in operationalizing the POPSK in Nandurbar by providing necessary equipment for starting POPSK at the earliest which will benefit the people of my constituency.

(ends)

Re: A constitutional solution to the demands of people of Darjeeling

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): The people of Darjeeling hills, Terai and Dooars have been demanding a separate administrative unit in the form of Gorkhaland state for long. This has led to numerous Andolan in the past. The andolan in 1986-1988 led to the formation of the Darjeeling Gorkha Hill Council. Andolan from 2007-2011 led to the establishment of the Gorkhaland Territorial Administration (GTA). The GTA which was supposed to be semi-autonomous body was also not allowed to function because of which, there was andolan for Gorkhaland again in 2017. GTA has failed to fulfil the aspirations of the people completely. Our region is critical from the National Security Perspective. We share border with four nations – Bangladesh, Nepal, Bhutan and China is nearby. In this past decade, hundreds of thousands of Rohingyas and illegal Bangladeshis have been settled in our region. This is causing massive demographic changes in the region. The indigenous Gorkha, Adivasi, Rajbangshi, Bengali, Hindi Bhasi community are under threat today. I therefore request the Ministry of Home Affairs to provide Constitutional solution to the demands of the people.

(ends)

Re: Establishment of IIM in Gorakhpur, Uttar Pradesh

श्री रवि किशन (गोरखपुर): गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का सबसे बड़ा महानगर है। गोरखपुर शिक्षा, व्यापार और पर्यटन का एक बड़ा केंद्र भी है। पूर्वांचल का गोरखपुर, बस्ती मण्डल, आजमगढ़ मण्डल एवं बिहार का सीमावर्ती क्षेत्र एवं सघन जनसंख्या को कवर करता है तथा पूर्वांचल व बिहार के लगभग 20 जिले अपने विभिन्न जरूरतों के लिए गोरखपुर पर निर्भर है। यहां रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है तथा यहां एयरपोर्ट भी है। गोरखपुर और इसके आसपास के जिलों के छात्र बड़े मेधावी हैं जो शिक्षा के लिए गोरखपुर आते हैं तथा उनमें अपार संभावनाएं हैं। वे प्रबंधन की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन गोरखपुर व उसके आसपास के किसी भी जिले में प्रबंधन संस्थान ना होने के कारण उन्हें काफी दूर जाना पड़ता है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर, दलित और वंचित वर्ग के छात्र संसाधनों की कमी की वजह से अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। गोरखपुर में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) की स्थापना हो जाने से यहां के छात्र-छात्राओं को अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होगा जिससे इस क्षेत्र का चहुंमुखी विकास होगा।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि गोरखपुर में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने की दिशा में तत्काल निर्णय लेकर इस क्षेत्र के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण योगदान देने की कृपा करें।

(इति)

Re: Introduction of New Guaranteed Pension Scheme for Central Government employees

DR. SUKANTA MAJUMDAR (BALURGHAT): I demand for New Guaranteed Pension Scheme (NGPS) in place of NPS for Central Government Employees (CGEs) on the pattern of Andhra Pradesh Guaranteed Pension Scheme, being a hybrid model between NPS and OPS. As reversal to the non-contributory OPS is not financially feasible, the guaranteed pension system is a middle path wherein with the provision of guaranteed monthly pension of 50% of last drawn basic salary along with an additional dearness relief twice a year to CGEs will address the long pending demand of CGEs for restoration of OPS to a large extent. Under the NGPS, all CGEs will get guaranteed monthly pension of 50% of their last drawn basic salary with DA. The government can make a matching contribution to the employee's NPS account, with the option to choose from different investment options by the CGEs. Any shortfall in the pension amount from the NPS corpus may be borne by Employer ensuring that employees are getting guaranteed 50% pension of their last drawn salary, even if their NPS investment returns are lower. Therefore, in view of the 'impossibility' of going back to OPS, the new guaranteed pension system model may be launched at the earliest by the Government.

(ends)

Re: Need to install rooftop solar panels under Pradhan Mantri Suryodaya Yojana in Maharajganj Parliamentary Constituency

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 'प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना' जैसी प्रमुख और कल्याणकारी योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत एक करोड़ लोगों के घरों पर 'रूफटॉप सोलर पैनल' लगाया जाएगा। घरों पर सोलर पैनल लगाने से कम खर्चे में लोगों को ऊर्जा उपलब्ध होगी। ऊर्जा के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बनेगा। अतः महोदय के माध्यम से मेरा आग्रह है कि भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री हमारे संसदीय लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज बिहार की जनता के घरों पर भी 'प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना' के शुभारंभ के समय अधिक से अधिक रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करेंगे।

(इति)

Re: Alleged illegal extension work carried out in DDA/CGHS flats in Delhi

SHRI BHOLA SINGH (BULANDSHAHR): A big chunk of DDA land parcels have been encroached by land Mafias including IP Extension. Slum colonies have erected with many commercial shops/establishments around Mandawali, Joshi Colony, Madhu Vihar, Chander Vihar, West Vinod Nagar, etc. and illegal business activities are operating from there causing big losses to DDA as many DDA Shopping Complexes are vacant/unutilized. DDA is not conducting any anti-encroachment drive which has encouraged encroachment practices and now even half of the public roads are encroached at Madhu Vihar crossing causing great inconvenience to local residents who are usually stuck in the traffic due to these encroachments as roads/streets remain full of vehicles. DDA has no control over the illegal construction in the CGHS Societies here and in absence of any guidelines/Rules/Regulations, illegal construction has grown up in the vicinity. I request the DDA to take urgent action against the mushrooming of extension of additional floor/room/balconies/permanent sheds in existing DDA/CGHS flats in Delhi. If extension is allowed, bring the policy in public. These CGHS flats are in depleted condition but DDA has not approved any redevelopment proposal of CGH Societies while it is the need of the hour and I urge upon the Government to take urgent action in this regard at the earliest.

(ends)

Re: Redevelopment of 'Masala Park', in Guna Parliamentary Constituency

श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना): वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले मसाला बोर्ड ने 45 करोड़ रुपये की लागत से 2013 में गुना के मावन गाँव में मसाला पार्क का संचालन शुरू किया था, जिसका उद्देश्य किसानों को बेहतर सुविधाएं देना था। जिससे धनिया की खेती करने वाले किसानों को बेहतर दाम मिले। यह पार्क 100 एकड़ में फैला हुआ है और यह देश का पहला मसाला पार्क था, जो Public Private Partnership Model पर शुरू किया था और इसमें आधुनिक सुविधाएं जैसे processing, quality evaluation, Cold Storage, Steam Sterilizer, Warehousing का प्रावधान भी किया गया था, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर अपेक्षा अनुसार कार्य नहीं हो रहा और बहुत ही कम निर्यात यूनिट की स्थापना हुई है एवं अनुमानित रोजगार भी नहीं मिले है। मेरे गुना लोक सभा में धनिया, लहसुन, प्याज और हल्दी की खेती होती है और मसाला पार्क के सुचारु संचालन से छोटे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा तथा मसाले का निर्यात भी बढ़ेगा। मेरा सरकार से निवेदन है कि गुना में स्थित मसाला पार्क को पुनर्विकसित किया जाए और इसकी क्षमता के अनुसार यहाँ पर परियोजनाएं शुरू की जाए, जिससे मेरा क्षेत्र जो आकांक्षी जिले में आता है, उसका समग्र विकास हो और मसालों के उत्पादन और निर्यात में हम आत्मनिर्भर बने जो हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है।

(इति)

Re: Increase in the number of unreserved and sleeper coaches in Passenger trains passing through Thiruvananthapuram Railway division.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I wish to draw the attention of the Honourable Minister of Railways towards the recent media reports regarding the Indian Railways introducing AC train coaches by replacing either Sleeper or Second-Class coaches. With relatively smaller share of people being able to afford the higher costs of AC coaches; general ticket holders invading reserved compartments has become common. Many of my constituents have raised demand to increase the number of unreserved and sleeper coaches on various trains passing through Thiruvananthapuram Railway division. According to the Annual Statistical Statements of the Indian Railways, of all passengers carried by Indian Railways in 2019-20, 7.8% were in AC coaches, a sharp jump from 3.6% a decade back. Media reports claim an 80 paise difference per passenger per km between AC 3-tier coaches and reserved Sleeper Class in 2019-20. The fare of AC 3-tier has increased by 33 paise per passenger per km in the past decade, while that of reserved Sleeper Class increased only by 17.4 paise. Given that these concerns impede the ease of travel and convenience of many commuters, I would be grateful if you could kindly examine this issue urgently and increase the number of unreserved and sleeper coaches on passenger trains.

(ends)

Re: Extension of passenger train No. 06034 operating between Chennai and Vellore upto Tiruvannamalai

SHRI C.N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): There is a demand by large number of public for extension of Passenger Train No. 06034 (VLR to MSB DEP FRM VLR 0600 Hrs. Daily) operating between Chennai and Vellore, which could be extended upto Tiruvannamalai. The Temple city of Tiruvannamalai attracts lakhs of visitors for Darshan of Lord Arunachaleswarar and Girivalam. Needless to say that there is no direct train running between Chennai to Tiruvannamalai. A large number of Passengers avail the service of the said train to reach Vellore whose destiny is Tiruvannamalai, therefore, facing a lot of problem in undertaking different modes of transportation. I urge upon the Hon'ble Minister of Railways to take necessary action to extend the service of the said train upto Tiruvannamalai to facilitate huge number of passengers to reach their ultimate destiny.

(ends)

Re: Release of the pending dues of MGNREGA to West Bengal

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): The total central dues to West Bengal in MGNREGA is above Rs 7,000 crore and in PMAY is above Rs. 8,000 crore. The total dues towards West Bengal from the Central Government pertaining to various schemes is above Rs. 1,50,000 crores. The West Bengal Government has formed a committee comprising six secretaries to discuss with Central Government for the early release of dues in various central schemes. West Bengal appeals to the Union Government to release the funds for payment of MGNREGA. Despite being deprived of the Central Funds under the MGNREGA, State Government had been able to create 10 lakh Man-days. As regards housing scheme, Union Government wants to take the sole credit of the scheme. "But the reality is that both the Union and the State Governments have their shares of contribution under this scheme. Despite the Union Government's reluctance to release Central Funds, the State Government is determined to go ahead with its project for developing the rural road network in the state. I urge upon the Government to release the pending dues of MGNREGA to the State of West Bengal with immediate effect.

(ends)

Re: Need to provide additional stoppage of train no. 20833/84 Vande Bharat Express at Tadepalligudem Railway Station, Andhra Pradesh

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): I would like to draw the attention of Hon'ble Minister of Railways regarding Vande Bharat Express Train having the best modern safety Kavach system along with wide range of modern features and amenities running between Secunderabad and Visakhapatnam stations in Andhra Pradesh. Presently, this train is having 4 stops at Rajahmundry, Vijayawada in Andhra Pradesh and Khammam and Warangal in Telangana.

I request you to kindly provide one more stop to Train No.20833/84 Vande Bharat Train at Tadepalligudem Railway Station in Andhra Pradesh which is the well-known hub for commercial and industrial activities, surrounded with 4 municipalities in the Godavari district and also well-connected with many historical and tourism places.

Keeping in view its importance, I urge upon the Government to kindly consider for providing an additional stop to train No.20833/84 Vande Bharat Express Train at Tadepalligudem railway station which will fetch considerable revenue to the railways.

(ends)

Re: Need to include supaul district of Bihar in the list of Aspirational districts

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): मेरा संसदीय क्षेत्र सुपौल, बिहार राज्य का सीमावर्ती बाढ़ग्रस्त तथा अति पिछड़ा क्षेत्र है। जिसकी वजह से संसदीय क्षेत्र सुपौल संसाधनों से वंचित है एवं इसका प्रभाव यहाँ की जनता पर पड़ता है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने की वजह से कई प्रकार की बीमारी एवं महामारी होती है, जिससे आम जन-जीवन अस्त व्यस्त रहता है। मूलभूत सुविधाओं का काफी अभाव रहता है। खासकर के स्वास्थ्य सुविधा एवं रेल यातायात की सुविधा। स्वास्थ्य सुविधा का लाभ लेने के लिए एवं गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई तथा अन्य दूर के शहरों में जाना पड़ता है जिसके लिए सुपौल से दिल्ली अथवा बम्बई के लिए कोई भी रेल सुविधा नहीं है। रोजगार के भी साधन पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ में बड़े पैमाने पर जान एवं माल का नुकसान होता है। अतः मैं सरकार से यह मांग करता हूँ कि सुपौल को भारत के आकांक्षी जिला में जोड़ा जाय, जिससे सुपौल संसदीय क्षेत्र की जनता को लाभ मिले।

(इति)

Re: Prevalence of Dementia among the elderly population of the country

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Recently a pan-India study has found that dementia is prevalent among an estimated 7.4% of the country's elderly people, which means 8.8 million individuals aged 60 years and older suffer from the debilitating ailment that affects memory and cognitive function. As we know, Dementia adversely affects not only the individual but also his/her family (significant carer burden and poor quality of life) and society (economic and social costs), and is a significant cause of disability in late - life. Although there have been no significant national level programmes focusing on dementia.

Dementia should be acknowledged not only as a national public health priority but also as a social care priority. I request the Government that there should be a National Dementia Plan with allocated funds to see it through has to be in place so elderly Indians can be saved at an age where they require more care. With the help of Academicians, Researchers and NGOs, Government should launch a national level campaign for the increasing awareness about Dementia.

(ends)

Re: Road connectivity in Ambedkar Nagar Parliamentary Constituency

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): मेरे लोक सभा क्षेत्र अम्बेडकर नगर के अकबरपुर ब्लॉक की अरिया दलित बस्ती सभी मुख्य मार्गों से कट चुकी है। शारदा नहर पर एक मात्र पैदल पुल के २ साल पहले टूटने के कारण यह दलित बस्ती संचार के सभी माध्यमों से वंचित है। बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते और मरीजों को जैसे-तैसे अस्पताल पहुँचाया जाता है। मैंने नहर विभाग चीफ़ अयोध्या को फ़ोन और पत्र के माध्यम से कई बार समस्या का निस्तारण करने के लिए कहा, किंतु विभाग ने इन दलितों के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई। इसे लेकर जनता अत्यंत ही पीड़ित है और आंदोलन पर उतारू है। मेरा माननीय संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस समस्या का निस्तारण करने के लिए तुरंत प्रबंधन करवाने हेतु पहल की जाये।

(इति)

**Re: Shifting the site for construction of radar station in Vikarabad district,
Telangana**

DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): There is no doubt that development has to take place and when it comes to security, we have to be accommodative. But, at the same time, when we have alternative location for setting up of radar station, we should consider constructing radar station in the premises of 400 years old Sri Ramalingeswara Swamy Temple in Damagundam in Pudur Mandal of Vikarabad district, Telangana. Indian Navy's proposal to set up Indian Navy Radar Station in the above Lord Shive temple premises is being opposed by the local residents for years as it impacts the holy premises, health of local people and also the environment in that area. The local people are demanding for shifting this Indian Navy's Radar Station to some other place.

Hence, I appeal to the Hon'ble Minister of Defence to consider their request and shift this radar station to other suitable location.

(ends)

Re: Alleged irregularities in implementation of development schemes sponsored by Central Government in Khagaria district, Bihar

चौधरी महबूब अली कैसर (खगड़िया): मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत खगड़िया जिला एक आकांक्षी जिला होने के साथ-साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है। उक्त जिले में भारत सरकार द्वारा बहुत सारी महत्वकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिसके अन्तर्गत मनरेगा से उक्त जिले में करोड़ों रुपये की महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन हो रहा है। खगड़िया जिले में सभी केंद्रीय योजनाओं जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिला परिषद् के अन्तर्गत योजनाओं एवं अन्य इनके अधीनस्थ केन्द्रीय योजनाओं में व्यापक पैमाने पर अनियमितताएं बरती जा रही हैं जिस कारण स्थानीय जनप्रतिनिधि काफी परेशान हैं एवं जनता में काफी रोष है।

अतः मेरी आप के माध्यम से भारत सरकार से मांग है कि उपरोक्त परियोजनाओं से संबद्ध पदाधिकारियों की संपत्ति की जांच प्रवर्तन निदेशालय से कराई जाए तथा साथ ही साथ इनके कार्यकाल के माध्यम से हुई सभी केन्द्रीय योजनाओं की जांच केन्द्रीय एजेंसी से कराई जाए।

(इति)

Re: Unemployment scenario in the Country

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): India's unemployment rate surged to a two-year high, reaching 10.09% in October 2023. Despite a growing population, the nation's workforce has stagnated over the last five years. The Azim Premji University's State of Working India 2023 report shows a disturbing trend in employment of women showing a shift towards self-employment rather than secure jobs. Youth unemployment, alarmingly, was at 23.22% in 2022, higher than our neighbours Pakistan (11.3%), Bangladesh (12.9%), and Bhutan (14.4%), according to World Bank data. Despite India's economic growth, expected to exceed 6% annually, there exists a paradox—growth without job creation. In IT Park, Hinjewadi of my constituency there is a job crunch for youth. I urge upon the Government to push for the creation of high-quality, dignified job opportunities, to ensure a productive workforce. Achieving this imperative requires structural change, with a focus on increasing university seats, improving Government schools, and upgrading curriculum to create an employable and skilled workforce with transferable skills.

(ends)

Re: Need to create a separate State of Bundelkhand

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, गोवा, उत्तराखंड, झारखण्ड, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना इत्यादि राज्यों का निर्माण स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हुआ और आंकड़े बताते हैं कि इन राज्यों के निर्माण के उपरांत इन राज्यों ने काफी प्रगति भी की है। परन्तु देश में नए राज्यों की मांग अभी भी जारी है। इन नए राज्यों की मांग में बुंदेलखंड राज्य की मांग भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग का प्रमुख आधार विकास है। यद्यपि वर्तमान की उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा विकास के अनेक कार्य किये जा रहे हैं, परन्तु यदि बुंदेलखंड राज्य बन जाता है तो नई उर्जा के साथ इसका विकास बहुत तेज गति से संभव हो सकेगा और यह विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकेगा। इसके अतिरिक्त जहाँ अन्य राज्यों का विभिन्न आधार पर निर्माण हुआ और उन्होंने न सिर्फ आर्थिक प्रगति की वही अपनी संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन भी किया, परन्तु बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बुन्देली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में भी जगह नहीं मिल पाई है। इस हेतु आपके माध्यम से मेरी सरकार से यह मांग है कि पृथक बुंदेलखंड राज्य का निर्माण किया जाये।

(इति)

Re: Immediate release of Rural Development Fund (RDF) dues to Punjab

SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA): The Government has withheld the Rural Development Fund (RDF) to the Government of Punjab to the tune of Rs.5637 crore. The RDF has not been released for the last many Kharif and Rabi marketing seasons. The RDF is the legitimate right of the Government of Punjab. The RDF is to be utilized by the Government for the welfare of farmers of the state and development of rural infrastructure including maintenance and creation of rural mandis and rural link roads for enabling easy access in transporting agricultural produce to the nearest mandis. If RDF of Punjab is not cleared in time, the rural infrastructure will be hit and the Government will have no resources to maintain the rural and mandi infrastructure. I urge upon the Government that in the larger interest of the development of rural infrastructure in the State of Punjab, the entire pending amount of Rural Development Fund (RDF) which is the legitimate right of Punjab may be released immediately. The Government may also develop a robust system of checks and balances to check any leakage or misuse and ensure complete transparency in the utilization of RDF funds by the Government of Punjab.

(ends)

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आप सभी को पेपर लेड के बाद बोलने का मौका देता, लेकिन आप पहले ही बायकॉट करके चले गये। अब आप राष्ट्रपति के अभिभाषण में अपनी बात रख दीजिएगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको बोलने का मौका देता। पेपर लेड चल रहा था। मैंने पेपर लेड के बाद बोलने के लिए कहा था। मैंने आपको इशारा करके कहा था कि पेपर लेड के बाद बोलने का मौका दूंगा।

... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष महोदय, हम आपका आदर करते हैं। आप सब कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मैंने कहा था कि पेपर लेड चल रहा है, आप इसके बाद बोलिएगा।

... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष महोदय, यदि आप चाहें तो हम अभी भी बोल सकते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब आप राष्ट्रपति अभिभाषण में बोल लीजिएगा।

... (व्यवधान)

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

1214 बजे

माननीय अध्यक्ष: राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत ।

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (नन्दुरबार): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ:

“कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए –

‘कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 31 जनवरी, 2024 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।’

अध्यक्ष महोदय, आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा दिये गये अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की अगुवाई करने का मुझे अवसर और सौभाग्य मिला है, इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी और अपनी पार्टी का आभार व्यक्त करती हूँ।
(1215/SJN/SAN)

अध्यक्ष महोदय, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि 31 तारीख को एक महिला राष्ट्रपति ने इस सदन में अभिभाषण दिया। 1 फरवरी को एक महिला वित्त मंत्री ने यहां पर बजट पेश किया और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर एक आदिवासी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद को यानी मुझे बोलने का सौभाग्य मिला है। यह उस नई संसद में हुआ है, जिस संसद की पहली बैठक में महिलाओं के लिए ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पास हुआ था। यह एक ऐसा बिल है, पिछले तीन दशकों से महिला आरक्षण का यह बिल लंबित था, उसे इस सदन में पारित किया गया है। यह विधेयक महिलाओं को सशक्त करने वाला है। इस बिल के माध्यम से लोक सभा और विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

अध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति जी ने हमारे सामने 75 मिनट का अभिभाषण दिया था। उसमें उन्होंने हमारे देश की 75 वर्ष की यात्रा के बारे में बताया। इन 75 मिनट्स में उन्होंने आने वाले 25 वर्षों का विजन भी हम सबके सामने रखा है। मैं अभिभाषण के दौरान हमारे विपक्ष के साथियों का चेहरा देख रही थी। मुझे उनके चेहरे पर मिक्सड इमोशंस दिख रहे थे। जब एक तरफ महामहिम राष्ट्रपति जी हमारी सरकार की अनेक उपलब्धियों के बारे में बता रही थीं, तो उनके चेहरे पर एक हैरानी दिखाई दे रही थी कि इस सरकार की इतनी सारी उपलब्धियां हैं। दूसरी तरफ यह भी दिखा कि वे थोड़े कन्फ्यूज्ड लग रहे थे कि हम सरकार को किस विषय पर कटाक्ष करें या उन पर किस विषय पर आरोप लगाएं। यह जायज़ भी है,

क्योंकि हमारी सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के सिद्धांत पर देश में निरंतर विकास के काम शुरू किए हैं।

हमारे देश में जो विकास हो रहा है, उसको देखने के बाद मुझे तो यह लगता है कि धीरे-धीरे 'इंडिया अलायंस' के कई सारे साथी उधर से इधर अर्थात् हमारे साथ आने लगेगा। अभी 'इंडिया अलायंस' का जो हाल है, उस पर मैं यहां एक शेर बोलना चाहूंगी, जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2018 में अविश्वास प्रस्ताव के समय बोला था।

“न मांझी, न हमसफ़र, न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है”।

महोदय, आज 'इंडिया अलायंस' की हालत एक ऐसी क्रिकेट टीम की तरह हो चुकी है, जहां 11 के 11 प्लेयर्स खुद कैप्टन बने हुए हैं। कोई एक-दूसरे की बात नहीं सुनता है। मैं तो यह बताना चाहूंगी कि जैसे पश्चिम बंगाल में ममता दीदी वहां की कैप्टन हैं, वे वहां पर कांग्रेस पार्टी को अपनी टीम में नहीं लेना चाहती हैं। पंजाब के कैप्टन केजरीवाल जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी को 12वें प्लेयर या एक एक्सट्रा प्लेयर की तरह वहां पर रख रहे हैं। 'इंडिया अलायंस' अब बिग बॉस के कार्यक्रम की तरह लगने लगा है। जहां सभी एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन सबकी नजर प्रधानमंत्री की ट्रॉफी पर है कि वह किसे मिलेगी।

जैसे कल हमारी वित्त मंत्री जी ने बजट पेश करते समय कहा था कि वर्ष 2024 का जो फुल बजट आएगा, वह हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ही लाएगी। मुझे यह विश्वास है कि जिस तरह से हमारी सरकार की नीतियां हैं और जिस तरह से हमारी सरकार विकास का काम कर रही है, इस देश की जनता पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को ही वह अवसर देगी और वर्ष 2024 का फुल बजट हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार में ही आएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि “सपने नहीं, हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी जी को ही चुनते हैं”।

अभी कुछ दिनों में चुनाव होगा और सभी देशवासियों के सामने एक सवाल आएगा कि उनको किस दल को वोट करना है। यह इलेक्शन बाकी चुनावों से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि यह विचारधारा पर आधारित नहीं, बल्कि लोग डिलिवरी वर्सेज डिले की लड़ाई पर वोट देंगे। जहां एक तरफ हमारी सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के कारण लोगों को जो लाभ मिल रहा है, हम जिन योजनाओं की डिलिवरी कर रहे हैं, वह एक तरफ है। दूसरी तरफ यूपीए के 10 सालों में जहां पॉलिसी पैरालिसिस और डिले के कारण लोगों का विकास नहीं हो पाया है। (1220/SPS/SNT)

इस बार का चुनाव एफिशिएंसी वर्सेस डेफिशिएंसी का चुनाव होगा। एक तरफ भाजपा सरकार है, जहां एफिशिएंट पॉलिसी के कारण पासपोर्ट दो दिनों में लोगों को मिलता है और यूपीआई के माध्यम से सब्जी से लेकर सोने की खरीदारी तक ट्रांसपेरेंसी से व्यवहार होता है तथा दूसरी तरफ यूपीए के कार्यकाल में 2G जैसी टेक्नोलॉजी में घोटाला हुआ। ऐसी चीजें भी

लोग जानते हैं, इसलिए यहां एफिशिएंसी वर्सेस डेफिशिएंसी विषय पर लोग वोटिंग करेंगे। हाल ही में एक सांसद के यहां इतनी धनराशि प्राप्त हुई है कि एजेंसीज तीन दिन तक वहां पर राशि गिनती रहीं। जब इलेक्शन की वोटिंग होती है तो वोटिंग के बाद भी काउंटिंग एक दिन में पूरी हो जाती है, लेकिन इनका भ्रष्टाचार इतना है कि तीन-तीन दिन तक वहां पर गिनती चलती रही। राजनीति में हम कई बार यह कहते हैं कि विपक्ष एकजुट है और सरकार अस्थिर या अनस्टेबल है, लेकिन आज यहां पर बिल्कुल विपरीत देखने को मिल रहा है। यहां पर हमारी सरकार एकजुट है और विपक्ष अनस्टेबल है और हर दिन कोई न कोई पार्टी समर्थन वापस ले रही है। इसी परिस्थिति को देखकर मुझे पूरा यकीन है कि वर्ष 2024 में आएंगे तो मोदी जी ही।

हमारे प्रधान मंत्री जी ने जिस तरह पृथ्वी पंचतत्व पर बनी हुई है, उसी तरह से हमारे देश का विकास पंचतत्व एरियाज पर फोकस करके काम किया है। पहला महिला, दूसरा किसान, तीसरा वंचित और गरीब, चौथा युवा और पांचवा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं एक महिला हूं, इसलिए मैं अपनी बात महिलाओं के विषय से शुरू करूंगी। वर्ष 2014 से पहले हमारे देश में ऐसी स्थिति थी और उस समय मैं खुद एक स्टूडेंट थी। हमारे देश में वर्ष 2014 से पहले महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ ऐसी घटनाएं घटीं कि हमारे देश की महिलाओं के मन में एक डर बैठ गया और वे अपने आप को असुरक्षित मानने लगीं। वर्ष 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आई तो उस सरकार के आने के बाद जो पहला कदम हमारी सरकार ने लिया, जब हम लोग सांसद बनने के बाद ओथ लेते हैं, उससे भी पहले हमारे सदन का जो सबसे बड़ा पद होता है, वह स्पीकर का पद होता है, उस स्पीकर के पद पर हमारी संसद की आठ बार चुनकर आई हुई एक महिला सांसद को मोदी जी ने बैठने का मौका दिया। महिला सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन जी का चयन इस वरिष्ठ पद के लिए किया गया। उनकी इसी पॉलिसी से पता चलता है कि महिलाओं के प्रति उनका विश्वास है।

सर, महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमारी सरकार ने कई सारी पॉलिसीज बनाई हैं, मैं उनके बारे में यहां पर बताना चाहूंगी। हर तबका, हर वर्ग, हर क्षेत्र की महिलाओं के लिए पॉलिसीज हमारी सरकार ने बनाई हैं। महिलाओं की भागीदारी में चन्द्रयान-3 हो या कोविड-19 महामारी हो हर जगह महिलाओं का योगदान बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि पहले महिलाओं में प्रतिभा नहीं थी। पहले भी हमारे देश में महिलाओं में बहुत प्रतिभा थी, लेकिन महिलाओं के लिए अवसर की कमी थी और उस अवसर को देने का काम हमारे प्रधान मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस कारण आज हम हर क्षेत्र में हम महिलाओं को देख रहे हैं। सरकार की जो लॉ एंड ऑर्डर और पॉलिसीज हैं, उनके कारण महिलाओं का योगदान हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए और आत्मनिर्भर करने के लिए आज देश में 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए हैं और उन्हें 8 लाख करोड़ रुपए का बैंक लोन और 40 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक

सहायता दी गई है। आत्मनिर्भर भारत का उत्कृष्ट उदाहरण ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वर्ष 2014 के पहले भी बनते थे, लेकिन उन्हें सही तरह से ट्रेनिंग, स्किलिंग और मार्केटिंग हमारी सरकार ने दी। इसके कारण एसएचजीज आज जो चीजें बना रहे हैं, वे केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी हमारी महिला एसएचजीज उन चीजों को एक्सपोर्ट कर रही हैं।

सर, रूरल इकोनॉमी में हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का आज बहुत बड़ा योगदान देखने को मिल रहा है। आर्थिक उन्नति के लिए दो करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अभियान हमारी सरकार चला रही है। टेक्नोलॉजी के साथ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जोड़ने के लिए 'नमो ड्रोन दीदी' जैसी बहुत अच्छी योजना हमारी सरकार लेकर आई है, जिसके कारण आज 15 हजार ड्रॉन्स ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को दिए जा रहे हैं, जिससे वे खेतों में जाकर फर्टिलाइजर की स्प्रींग कर सकें और फर्टिलाइजर कैमिकल के कारण कई बार जो अलग-अलग बीमारियां होती हैं, उससे हमारी माताएं और बहनें बच सकें।

(1225/MM/AK)

मेटरनिटी लीव के बारे में यहां मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगी। एक डॉक्टर होने के नाते और एक महिला होने के नाते इस सदन को मैं बताना चाहूंगी कि जब कोई महिला प्रेगनेंट होती है और उसकी डिलिवरी होती है तो प्रेग्नेंसी के समय और डिलिवरी के बाद भी उसे रेस्ट की जरूरत होती है, क्योंकि डिलिवरी के तुरंत बाद वह रिकवर नहीं हो पाती है। हमारे देश में पहले उसको 12 हफ्तों की मेटरनिटी लीव दी गयी, लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी ने महिलाओं को मेटरनिटी लीव बढ़ाकर क्यों देनी चाहिए, इस पर विचार किया और केवल पॉलिसी ही नहीं, बल्कि कानून में बदलाव करके 12 हफ्तों से 26 हफ्तों तक की मेटरनिटी लीव हमारी सरकार ने महिलाओं को, हमारी माताओं को यहां पर दी है।

हम लोग हमेशा से महिलाओं को, नारी शक्ति को दुर्गा का रूप कहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि पिछले 60 वर्षों में देश की रक्षा का अवसर महिलाओं को नहीं मिल पाया? हम तो उस देश की बात कर रहे हैं, जहां झांसी की रानी की वीरता और शौर्य का उदाहरण हम बच्चों को देते हैं। अभी हमारे प्रधान मंत्री जी ने हमारे देश की महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सैनिक स्कूल्स में आज तक केवल लड़कों का ही एडमिशन होता था, लेकिन अब सैनिक स्कूल्स और नेशनल डिफेंस अकेडमी जैसी संस्थाओं में महिलाओं को भी महिला केडेट्स के रूप में प्रवेश मिलेगा। हम लोग तो नेचुरली कहते हैं कि महिला में फाइटर स्पिरिट होती है। लेकिन आज सही मायने में हमारी महिलाओं को फाइटर प्लेंस और नेवी के जहाज के कमांडेंट के रूप में महिलाओं की जो फाइटर स्पिरिट है और देश की सुरक्षा के लिए आज उनका जो योगदान है, सही मायने में हम देख पा रहे हैं।

हमारे प्रधान मंत्री जी हमेशा विमन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। हमारे देश की राष्ट्रपति एक महिला हैं। हमारे देश की वित्त मंत्री एक महिला हैं और पहली फुल टाइम वित्त मंत्री इस देश को जो मिली है, वह हमारी सरकार ने दी है। हमारी वित्त मंत्री जी देश की पहली ऐसी महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 6 बजट लगातार इस सदन में पेश किए हैं। हमारी पूर्व एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर स्वर्गीय सुषमा जी भी इस देश की पहली फुल टाइम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रही हैं। इस तरह के रोल्स में हमें महिलाओं की लीडरशिप को इसी सरकार ने दिखाया है।

आज जमीन से लेकर आसमान तक हर क्षेत्र में महिलाएं अपना झंडा लहरा रही हैं। यदि हम पॉलिटिकल बात करें तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर 33 परसेंट महिलाओं को आरक्षण दिया गया और आने वाले समय में महिलाओं का योगदान, विमन लेड डेवलपमेंट, इस प्रिंसिपल के आधार पर प्रधान मंत्री जी यहां बिल लाए थे, जिसके कारण आने वाले समय में 33 परसेंट महिला सांसद हमें इस सदन में दिखेंगी। यह सभी कदम जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने उठाए हैं, ये सब कांग्रेस ने क्यों नहीं किए? कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष महिला थी। हमेशा वे महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी महिलाओं के लिए इस तरह नहीं सोचा। आज इतनी सारी चीजें जो महिलाओं के बारे में हमारी सरकार ने की हैं, ये सब हमें नयी क्यों लग रही हैं? ये लोग हमेशा कहते हैं कि 60 साल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसके बारे में हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन इन 60 सालों में इन्होंने यह चीजें यदि की होतीं तो हमें यह करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने जो दस साल में किया, 60 साल में भी इनकी सरकारें वह नहीं कर पायीं। क्योंकि हमारे पास नीति भी है और नीयत भी है। हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण को नयी परिभाषा दी है, नये आयाम दिए हैं, नया विस्तार दिया है। पहले प्रतिनिधित्व पर बल दिया जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की और अब उससे भी आगे बढ़कर महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में आ रही हैं। यह परम्परा से परिवर्तन तक की यात्रा है। यही महिलाओं की सच्ची प्रगति है और यही सच्चा सशक्तिकरण है। महिलाओं के बारे में मैं यहां कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी-

नारी शक्ति है, सम्मान है। नारी गौरव है, अभिमान है।

नारी ने ही रचा है विधान ये और नारी के योगदान को मोदी सरकार का प्रणाम है।

(1230/YSH/UB)

मैं यहां पर अगले तत्व यानी कि किसान पर बोलना चाहूंगी। एक पुराना गाना हमेशा सब लोग सुनते हैं, वह है – 'मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती', अर्थात् हमारे देश की इकोनॉमी हमेशा एग्रीकल्चर ड्रिवन रही है। आज भी हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का मेन ऑक्यूपेशन खेती ही है। यूपीए के समय ऐसा होता था कि कई किसान कर्ज में

डूब जाते थे और फिर सरकार आकर उनका कर्ज माफ करती थी, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि किसान कर्ज में क्यों डूबते थे? किसान कर्ज में इसलिए डूबते थे, क्योंकि इनके द्वारा किसानों के लिए बनाई गई नीतियां फेलियर थीं, उसके कारण हमारे देश के किसान सक्षम नहीं हो पाए। उनकी आय नहीं बढ़ पाई और इसलिए हमारे देश के किसान कर्ज में डूबते चले गए।

हमारी सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक एजेंडा सामने लेकर आई और उसी आधार पर योजनाएं बनाई गईं। सबसे पहले हमारी सरकार फार्म टू फूड पॉलिसी को बनाकर अलग-अलग स्कीम्स लेकर आई। जब किसान को उसके खेत में बीज बोने होते हैं तो हमारी सरकार 'प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि' जैसी महत्वपूर्ण योजना लेकर आई, जिसके अंतर्गत 6,000 रुपये प्रतिवर्ष किसानों को दिए जा रहे हैं। इससे आज देश के करीब 12 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिल रहा है और इस योजना के अंतर्गत किसानों को 2,80,000 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।

किसान को अपने खेत में एक बार बीज बोने के बाद पानी की जरूरत होती है। हमारे किसानों को पानी उपलब्ध करवाने के लिए हमारी सरकार ने 'प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना', 'हर खेत को पानी' तथा 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' के बेस पर योजनाएं लाकर हमारे देश के किसानों को समृद्ध करने का काम किया है। इसी तरह से 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' है। यदि किसान अपने खेत में कुछ बोता है, वह उगता है, लेकिन किसी कारणवश उसका नुकसान हो जाता है तो हमारी सरकार ने किसान को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मदद करने का काम भी किया है।

अध्यक्ष महोदय, इससे पहले भी हमारे देश में बीमा योजनाएं थीं, लेकिन उन योजनाओं में और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में एक बहुत बड़ा फर्क है। उस समय की फसल बीमा योजनाएं इंश्योरेंस कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए थीं, लेकिन हमारी सरकार के द्वारा लाई गई प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना किसानों के हित के लिए है। इससे किसानों को फायदा होता है। इसके आँकड़े बता देते हैं कि कितने किसानों को इससे फायदा हुआ है। 30 हजार करोड़ रुपये का प्रीमियम हमारी सरकार ने इस योजना के अंतर्गत दिया है और 1.5 लाख करोड़ क्लेम्स किसानों को दिए गए हैं। इतनी बड़ी मात्रा में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को मदद दी गई है।

अगर किसानों के खेतों से कोई फसल आई और वह उसको मार्केट में बेचने से पहले यदि कहीं पर स्टोर करना चाहता है तो भंडारण योजना भी हमारी सरकार लेकर आई है। अगर कोई किसान उसके खेत की उपज को एक्सपोर्ट करना चाहता है तो हमारी सरकार एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी भी लेकर आई है और इस पॉलिसी के अंतर्गत अभी तक हमारे

देश से एग्रीकल्चर में 4 लाख करोड़ रुपये तक का एक्सपोर्ट हुआ है। हमारे देश से यह अभी तक का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट है।

यदि किसानों की खेती की उपज खराब हो जाए या बहुत अच्छी क्वालिटी की न हो और यदि उस पर वह प्रोसेसिंग करना चाहे तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के माध्यम से अलग-अलग फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स भी ग्रामीण क्षेत्रों में सेटअप करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इतना ही नहीं हमारी सरकार ने फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों का एक बड़ा संगठन तैयार करने का काम भी किया है। अभी तक 8 हजार फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में बन चुके हैं।

खेती के साथ-साथ मत्स्यपालन, पोल्ट्री व्यवसाय, बकरी पालन जैसी अनेक योजनाओं से किसानों को लाभ मिल रहा है। इतना ही नहीं 'किसान क्रेडिट कार्ड' जैसी योजना से भी हमारे यहां मत्स्यपालन, पोल्ट्री तथा बकरी पाजन जैसी योजनाओं के लिए ऋण दिया जा रहा है। मत्स्य पालन में तो पिछले 10 सालों में 95 लाख मिट्रिक टन से बढ़कर 175 लाख मिट्रिक टन तक का प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है।

हमारा जो तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है, वह गरीब और पिछड़ा वर्ग है। मोदी जी खुद एक गरीब परिवार से आते हैं और इसलिए वे जानते हैं कि गरीबों की क्या समस्याएं हैं और उन्हें किस तरीके से दूर किया जा सकता है। मैं खुद एक आदिवासी परिवार से आती हूँ और मैं यहां पर आपको बता सकती हूँ कि यदि कोई गरीब घर का हो या आदिवासी परिवार का हो, उन सबकी एक ही सबसे महत्वपूर्ण अड़चन है और वह उनकी मूलभूत सुविधाओं की है।

जब कांग्रेस की यूपीए सरकार बनी तो उन्होंने कई बार गरीबी हटाने का नारा दिया। गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन गरीब ही मुख्य धारा से हट गए और वे कैसे हटे, उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊँगी।

(1235/RAJ/SRG)

गांवों में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी पूरी जिंदगी यह सोचते हुए निकल गई कि उनके सपनों का आवास कब मिलेगा, उनको अपने हक का घर कब मिलेगा? जब प्रधान मंत्री जी प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर आए, तो अभी तक उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दो करोड़ लोगों को आवास दिया है। मैं एक आदिवासी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूँ। मैं आपको यह बता सकती हूँ कि जब मैं अपने क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों में जाती हूँ तो 70 वर्ष, 80 वर्ष और 90 वर्ष के बुजुर्ग गांवों में मिलते हैं और हाथ जोड़ कर प्रधान मंत्री जी को आशीर्वाद देते हैं कि उनका पूरा जीवन निकल गया, लेकिन उनको आवास नहीं मिला था। उनको बुढ़ापे में उनका आवास मिला है, उनको अधिकार मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के साथ-साथ दूसरी बड़ी समस्या यह होती है कि गंदा पानी पीने से लोग बीमार होते हैं या कई गांवों में तो पानी ही नहीं होता है। आज देश

में हमारे प्रधान मंत्री जी ने इस अड़चन को समझा और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'हर घर जल से नल' जैसी महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना ला कर 11 करोड़ लोगों के घरों में पहली बार पाइप से पानी पहुंचाया है। आज गांवों में रहने वाली हमारी माताएं-बहनें बहुत खुश हैं। क्योंकि जब घर में पानी नहीं होता है, तो इन माताओं-बहनों को हंडे में पानी भर कर दूर-दूर से पैदल पानी लाना पड़ता था। आज प्रधान मंत्री जी की इस योजना के कारण हमारी महिलाओं का यह टेंशन दूर हो गया है।

महिलाओं की दूसरी बड़ी टेंशन खाना पकाने की होती थी। क्योंकि उन्हें चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां लानी पड़ती थी, लेकिन प्रधान मंत्री मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना जैसी योजना ला कर, आज देश की 10 करोड़ महिलाओं और बहनों के घरों में गैस कनेक्शन पहुंचाया। हमारी माताएं-बहनों को चूल्हे से निकलने वाले धुएं के कारण आंखों की बीमारियां होती थी, सांस की बीमारियां होती थीं। आज हमारी सभी माताएं-बहनें इस टेंशन से मुक्त हो गई हैं कि आने वाले समय में उन्हें किसी भी प्रकार की बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह से कोई बेटा अपनी बुजुर्ग मां की सेवा करता है, प्रधान मंत्री जी हमारी माताओं और बहनों की उसी तरह की सेवा कर रहे हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी ये सभी योजनाएं लाए हैं, इनसे हमारी माताओं और बहनों का जीवन पूरी तरह से बदल गया है। जो कठिनाइयां उनको आती थी, आज वे कठिनाइयां दूर हो गई हैं। प्रधान मंत्री जी देश का नेता नहीं बल्कि देश का बेटा बन कर काम कर रहे हैं। इसीलिए सभी लोग कहते हैं कि घर-घर मोदी, घर-घर मोदी।

अध्यक्ष जी, कोरोना काल में हमारी सरकार के 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन देने का काम किया। इसे केवल कोरोना काल तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि आने वाले पांच सालों तक हमारी सरकार यह मुफ्त राशन 80 करोड़ लोगों को देने का काम कर रही है। प्रधान मंत्री मोदी जी एक महत्वपूर्ण योजना हमारे देश में लेकर आए हैं - हर घर बिजली योजना, सौभाग्य योजना।

अध्यक्ष जी, महलों में रहने वालों को गांवों और गरीबों के घर का अंधेरा नहीं दिखता है। हमारे प्रधान मंत्री जी खुद एक गरीब घर से आते हैं, इसलिए घरों में बिजली न रहने के कारण कितनी तकलीफें उन घरों में रहने वाले लोगों को सहनी पड़ती है, यह पूरी तरह से प्रधान मंत्री जी जानते हैं। इसलिए वे हर घर बिजली योजना लेकर आए हैं। मैं अपने क्षेत्र का एक उदाहरण यहां पर दूंगी। मेरे क्षेत्र में एक आदवासी क्षेत्र में धड़गांव नाम का एक तालुका है। वह पूरा पहाड़ में बसा है। इस योजना के आने से पहले कहां घर है, क्या है, वहां कुछ नहीं दिखता था, क्योंकि वहां बिजली ही नहीं थी। वहां लोग छोटा लालटेन जला कर रहते थे। आजादी के 75 साल हो गए लेकिन उन गांवों में बिजली नहीं पहुंची। जब उन गांवों में सौभाग्य योजना, हर घर बिजली योजना दी गई, तो आज जब हम उस क्षेत्र में जाते हैं, तो दिवाली में

घर के बाहर जैसे दिए जलते हैं, उस तरह से पूरा पहाड़ा रोशनी से चमकता है। जब मैं एक गांव में इस योजना का उदघाटन करने गई थी, तो वहां लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। क्योंकि उन्होंने यह कल्पना ही नहीं की थी कि कभी उनके घर में बिजली आ सकती है। हमारे प्रधान मंत्री जी यहां पर इस तरह की योजनाएं लेकर आए हैं।

आज हर ब्लॉक में आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जैसे अच्छे स्कूल्स बनाए गए हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र के एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग में मेरिट से एडमिशन ले रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि आदिवासी क्षेत्र में भी जो बहुत ही पिछड़ा वर्ग है, जिसको हम पीवीटी गुप्स कहते हैं, जो आज भी मुख्यधारा से वंचित हैं, उनके लिए हमारी सरकार प्रधानमंत्री जनमन योजना जैसी एक बहुत अच्छी योजना लेकर आई है, ताकि पीवीटी गुप्स भी आज मुख्यधारा में आ सकें। आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों से लोग ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं। अभी तक देश में सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेशन के लिए कोई डेडिकेटेड मिशन, कोई डेडिकेटेड प्रोग्राम नहीं था।

(1240/KN/RCP)

लेकिन हमारी सरकार सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेशन के लिए एक नेशनल मिशन लाकर आज देश के एक करोड़ से ज्यादा आदिवासी लोगों की सिकल सेल एनीमिया में टेस्टिंग कर चुकी है। इसके कारण आने वाले समय में सिकल सेल धीरे-धीरे आदिवासी क्षेत्रों में पूरी तरह से इरेडिकेट हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

प्रधान मंत्री जी ने जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके डेवलपमेंट में भी 5 प्रमुख इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई करके उन इंडिकेटर्स पर काम शुरू किया है। जब प्रधान मंत्री मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने तो देश के गरीबों के मन में एक विश्वास जागृत हुआ। उन्हें यह विश्वास जागृत हुआ कि यदि हमें कोई गरीबी से बाहर निकाल सकता है तो यही इंसान निकाल सकता है, यही व्यक्ति निकाल सकता है। अगर आज हम नीति आयोग की रिपोर्ट देखें तो देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं और सही मायने में आज इस गरीब वर्ग को, वंचित वर्ग को न्याय देने का काम इस सरकार ने किया है।

अगला मेरा तत्व जिस पर मैं बोलना चाहूंगी, वह युवा है। हम हमेशा कहते हैं कि युवा देश का भविष्य है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि युवा देश का वर्तमान भी है। हमारे युवाओं के अचीवमेंट्स को प्रधान मंत्री मोदी जी हमेशा अपने सोशल मीडिया या अपने वक्तव्य में हाइलाइट्स करते रहते हैं, चाहे वह ओलंपिक्स हो, चाहे वह एशियन गेम्स हों या चाहे वह स्टार्ट-अप इंडिया के अंतर्गत किसी युवा ने कोई अच्छा काम किया हो या कोई युवा गायक हो, जिसने कोई नया गीत गाया है या कोई धार्मिक गीत गाया हुआ है। हर क्षेत्र में युवा जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी सराहना हमारे प्रधान मंत्री जी करते हैं।

देश की युवा शक्ति की शिक्षा और कौशल विकास के लिए हमारी सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई और उसका फास्ट इम्प्लिमेंटेशन भी हमारी सरकार ने किया। एजुकेशन के बारे में जब भी हमारे विरोधी पक्ष के साथी यहां बोलते हैं तब वह हमेशा एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बोलते हैं। मुझे उनसे यह सवाल पूछना है कि जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी, वह वर्ष 2002 में आई थी। नई एजुकेशन पॉलिसी आने में 20 साल लग गए, तो आप लोगों ने इन 20 सालों में एजुकेशन के क्षेत्र में क्यों काम नहीं किया? आज यहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने के बाद केवल राष्ट्र भाषा में ही नहीं, बल्कि भारत की जितनी अलग-अलग भाषाएं हैं, आज उन भाषाओं में मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ के कोर्सेस में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। सही मायने में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इक्वल अपॉर्च्युनिटीज देने वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बन चुकी है।

स्कूल एजुकेशन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमारे देश में 'प्रधान मंत्री श्री विद्यालय' की स्थापना की जा रही है। करीब 14 हजार इस तरह के विद्यालय हमारे देश में बन रहे हैं, जिनमें से 6 हजार विद्यालय यहां पर बन चुके हैं। हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसके कारण आज स्कूल ड्रॉप आउट रेट भी बहुत बड़ी मात्रा में कम हुआ है। इतना ही नहीं, आज हमारे यहां हायर एजुकेशन में एडमिशन का रेट बढ़ते हुए दिख रहा है। आज एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी हायर एजुकेशन ले रहे हैं। एससी वर्ग का यहां पर 44 परसेंट एडमिशन रेट बढ़ गया है। एसटी कैंडीडेट्स का 65 परसेंट एडमिशन रेट बढ़ गया है। ओबीसी कैंडीडेट्स का 44 परसेंट एडमिशन रेट हायर एजुकेशन में बढ़ा हुआ है।

एजुकेशन के साथ-साथ इनोवेशन पर भी हमारी सरकार फोकस कर रही है। अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत 10 हजार अटल टिकरिंग लैब्स के माध्यम से एक करोड़ से ज्यादा युवकों को इनोवेशन के साथ जोड़ने का काम हमारी सरकार कर रही है।

यदि हम वर्ष 2014 के पहले मेडिकल कॉलेजेज की संख्या देखें तो 7 एम्स और 390 मेडिकल कॉलेजेज हमारे देश में थे। वर्ष 2014 से अभी तक हमारे देश में 16 एम्स बन चुके हैं और 315 नए मेडिकल कॉलेजेज बन चुके हैं, जिससे एमबीबीएस की सीट्स भी डबल हो गई है। 167 नर्सिंग कॉलेजेज नए खोले गए हैं। युवाओं को कौशल और रोजगार से जोड़ने के लिए हमारी सरकार स्पोर्ट्स इकोनॉमी पर बहुत फोकस कर रही है। खिलाड़ियों को हर तरह की मदद की जा रही है। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सेट-अप कर ली है। कई शहरों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज बना कर युवाओं के लिए स्पोर्ट्स एक प्रोफेशन हो सकता है, इस तरह का अवसर युवाओं को देने का काम हमारी सरकार कर रही है।

'मेरा युवा भारत, माई भारत' जैसा संगठन बना कर एक करोड़ युवाओं को 'माई भारत' के साथ जोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। युवाओं के बारे में एक मुहावरा है, जब हम भी छोटे थे तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि—

खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब।

लेकिन आज जिस तरह के अवसर हमारे युवाओं को दिए जा रहे हैं, तो मैं यह मुहावरा थोड़ा सा बदल कर यहां पर बोलूंगी—

खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब।

(1245/VB/PS)

आज हमारे देश के युवा केवल जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब क्रिएटर और जॉब गिवर बनें, हमारी सरकार इस पॉलिसी पर काम कर रही है।

कांग्रेस पार्टी हमेशा उद्योगपतियों को गालियाँ देती है। मैं उसे याद दिला दूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर के साथ ही प्राइवेट सेक्टर भी जॉब क्रिएशन का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। आज एक तरफ जब कांग्रेस पार्टी उद्योगपतियों को गालियाँ देती है, तो उसी पार्टी के एक मुख्यमंत्री दावोस में जाकर उन्हीं उद्योगपतियों के साथ एमओयू साइन करते हैं ताकि उनके यहाँ के युवाओं को भी रोज़गार मिल सके। यह है कांग्रेस का दोहरा चरित्र। एक तरफ वे यहाँ पर उद्योगपतियों को गालियाँ देते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के साथ एमओयू साइन करके रोज़गार निर्मिती के लिए काम करते हैं।

इस सरकार के विकास का आखिरी तत्त्व है- इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे देश की इकॉनमी को सबसे ज्यादा बूस्ट जिससे मिलता है, वह है इंफ्रास्ट्रक्चर।

माननीय अध्यक्ष जी, दस वर्ष पहले भारत को फ्रेजाइल फाइव इकॉनमीज में माना जाता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी नीतियों के कारण आज हम लोग टॉप फाइव इकॉनमीज में पहुंच चुके हैं। वह समय ज्यादा दूर नहीं है, जब हमारा देश दुनिया की थर्ड लार्जस्ट इकॉनमी बनेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, दस-बारह वर्ष पहले जब मैं स्वयं किसी देश में जाती थी, तो वहाँ के रोड्स, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आदि देखने के बाद मैं यह विचार करती थी कि क्या ये सब कभी हमारे देश में भी आएगा? यहाँ मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज जब हम वंदे भारत जैसी ट्रेन्स देखते हैं, जब स्टेशंस रिडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स देखते हैं, नये एयरपोर्ट्स बनते हुए देखते हैं, मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि मेरे संसदीय क्षेत्र के सबसे निकट का एयरपोर्ट सूरत एयरपोर्ट है, जिसका कुछ दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी लोकार्पण किया है। उस एयरपोर्ट पर जाने के बाद विश्वास नहीं होता है कि यह हमारे भारत का एयरपोर्ट है। हमारे यहाँ इतना सुन्दर, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण एयरपोर्ट का निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं महाराष्ट्र राज्य से आती हूँ। वहाँ पर समृद्धि महामार्ग के नाम से एक बहुत बड़ा नैशनल हाइवे बना है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने अटल सेतु, जो

भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल है, उसका भी लोकार्पण उन्होंने किया। ये सब केवल प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के विज़न के कारण पॉसिबल है।

पहले हम कहते थे कि भारत में यूएस जैसे रोड्स क्यों नहीं हैं, यूरोप जैसी ट्रेन्स क्यों नहीं है, लेकिन आज हमारे देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जिस तरह के रोड्स और रेलवेज बने हैं, इससे आज कई देश यह कहने लगे हैं कि हमारे देश में भी भारत जैसे रोड्स और भारत जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है, हमें भी भारत जैसे रोड्स और रेलवेज हमारे देश में बनाने हैं।

आज भारत दुनिया को दिशा दे रहा है। बाकी कंट्रीज को किस दिशा में डेवलपमेंट करना है, भारत उनको यह भी गाइड कर रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, यूपीआई के माध्यम से आज ट्रांजैक्शन्स किये जा रहे हैं। पिछले महीने यूपीआई के माध्यम से रेकॉर्ड 1200 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए। इसके तहत 18 लाख करोड़ रुपए का रेकॉर्ड लेनदेन हुआ है। सिंगापुर एवं कतर जैसे देश आज हमारे देश का यूपीआई एडॉप्ट करना चाह रहे हैं।

हमारे देश में कोविड महामारी के कारण वैक्सिनेशन प्रोग्राम चलाया गया। उस समय जो कोविन ऐप था, वह दुनिया का पहला ऐसा ऐप है, जिसमें एक सौ करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कोविड के समय हुआ, जिनको पूरी तरह से उसमें डिजिटाइज किया गया। आज यूएस जैसे देश में भी इस तरह का कोई ऐप नहीं है। आज वहाँ भी कोविड वैक्सिनेशन का सर्टिफिकेट लोग कागज पर लेकर जाते हैं। एक सौ करोड़ से ज्यादा लोगों का डिजिटली डाटा और रेकॉर्ड हमारे देश में कोविन ऐप में बनाया गया है।

मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश रूल फॉलो करने वाला नहीं, बल्कि हमारा देश आज एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा हुआ है।

हमने जी-20 के आयोजन में प्रधानमंत्री जी का विज़न तो देखा ही है। अभी तक हमारे देश में जितनी भी डिप्लोमैटिक मीटिंग्स होती थीं, वे केवल नई दिल्ली में होती थीं। यहाँ मीटिंग होकर खत्म हो जाता था और देश में किसी को पता नहीं चलता था कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जब जी-20 की अध्यक्षता भारत को मिली, तो मोदी जी ने जी-20 की मीटिंग्स कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक हुई। हर राज्य में जी-20 की मीटिंग्स आयोजित हुई। जी-20 की मीटिंग्स केवल डिप्लोमैटिक मीटिंग्स तक ही सीमित नहीं हुई, बल्कि जिस शहर में मीटिंग हो रही थी, वहाँ जनभागीदारी भी सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार ने किया है।

(1250/PC/SMN)

आज हमारी सरकार पर्यटन स्थलों के डेवलपमेंट पर भी विशेष रूप से ध्यान दे रही है। पर्यटन स्थल डेवलप होने से केवल उतना एरिया ही डेवलप नहीं होता है, बल्कि पूरे क्षेत्र का

डेवलपमेंट होता है। इससे पूरे शहर का और आसपास के शहरों का भी डेवलपमेंट होता है। इससे रोजगार की अपॉर्च्युनिटीज भी मिलती हैं। कुछ दिन पहले, 22 तारीख को हमारे प्रधान मंत्री जी ने अयोध्या में प्रभु श्रीराम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, कुछ साल पहले तक अयोध्या में सिर्फ चार-पांच होटल्स थे। आज अगर आप वहां जाएंगे, तो देखेंगे कि देश के सबसे बड़े होटल्स, सबसे बड़े नाम की कंपनियां, सब वहां पर हैं। इसके कारण वहां के लोगों के लिए और परिसर के लोगों के लिए हजारों की संख्या में रोजगार निर्मिति हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखें, महाकाल कॉरिडोर देखें, सब तरफ इसी तरह से डेवलपमेंट करने का काम हमारी सरकार कर रही है। इससे वहां की लोकल इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है। ये पांच तत्व ही आगे जाकर विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे। विकसित भारत का मतलब केवल जीडीपी ग्रोथ ही नहीं है। इसका मतलब विकसित महिला, विकसित किसान, विकसित युवा, विकसित पिछड़ा वर्ग और विकसित समाज भी है।

अध्यक्ष जी, विकसित भारत केवल किसी पार्टी की विचारधारा नहीं है, यह देश के हर नागरिक की विचारधारा है। मैं अपना भाषण कुछ पंक्तियों से समाप्त करूंगी। वैसे तो हमारी सरकार ने इतनी सारी योजनाएं, इतनी सारी पॉलिसीज बनाई हैं कि हम हफ्ते भर, पूरे एक हफ्ते से ज्यादा तक उन पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो समय आवंटित किया गया है, उसकी मर्यादा ध्यान में रखते हुए मैं कुछ पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी।

कशती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें,
लहर-लहर तूफान मिले और मौज-मौज मझधार हमें,
फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको,
विपरीत हालत में भी आता है दरिया पार करना हमें।

अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1252 बजे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉ. हिना जी द्वारा रखे गए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं आपको और पार्टी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस अंतिम कालखंड के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया।

अध्यक्ष महोदय, डॉ. हिना जी ने बहुत सिलसिलेवार रूप से सरकार की योजनाओं को बताया है। लेकिन मैं इसकी शुरुआत यहां से करना चाहूँगा कि जैसे गुप्तकाल भारत का स्वर्ण युग था, वैसे ही मोदी जी का यह दस साल का कार्यकाल इस शताब्दी का स्वर्ण युग है।

अध्यक्ष महोदय, मैं योजनाओं के बारे में बताने से पहले पहली उपलब्धि यह बताना चाहूँगा कि यह जो लुटियन्स जोन है, यह काजल की कोठरी है। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई प्रधान मंत्री अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ इस काजल की कोठरी में दस सालों से रह रहा है और न कपड़े पर कालिख आई है और न चेहरे पर कालिख आई है।

1253 बजे

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

मेरे पैदा होने से पहले कृष्णा मेनन का जीप का घोटाला हो गया था। मेरी जवानी के दिनों में बोफोर्स हुआ था और जब मैं एमपी था, तो 2जी, 3जी, कोयला और कॉमनवेलथ घोटाला हुआ था। मैं डॉ. हिना जी के शेर को थोड़ा सुधारता हूँ। ऐसा कोई नेता बड़ी मुश्किल से होता है, जो दस सालों तक कोठरी में रहे और उस पर कालिख न लगे। ... (व्यवधान) ऐसा तो कोई फकीर कर सकता है, कोई हरफनमौला कर सकता है, कोई साधु-संत कर सकता है, कोई परमहंस कर सकता है। इसलिए, उस शेर को मैं ऐसे पढ़ना चाहूँगा –

न मांझी, न रहबर, न हक में हवाएं,
है कश्ती भी टूटी, यह कैसा सफर है,
फकीरी का अपना अलग ही मजा है,
न पाने की चिंता, न खोने का डर है।

मोदी जी को यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करनी है। वे झोला उठाकर कभी भी हिमालय पर जा सकते हैं, लेकिन देश में अन्याय के साथ, अत्याचार के साथ, भ्रष्टाचार के साथ, परिवारवाद के साथ वे कभी समझौता नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इस लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे बड़ी घटना ये दस साल हैं, जो विकास युक्त और भ्रष्टाचार मुक्त रहे हैं। इसीलिए, मैं आपके चेहरे देख रहा हूँ।

तमाम चेहरों पर खौफ जारी है,

एक चिराग अंधेरों पर कितना भारी है।

(1255/CS/SM)

प्रधानमंत्री जी एक दूरदृष्टा हैं। जैसे ही वे वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला काम जीरो बैलेंस में जन धन खाता खुलवाने का किया। कांग्रेस के एक बहुत नामदार राजकुमार, खासदार, जो आजकल अमेठी से हार गए हैं, दीदी के द्वारा, इसलिए केरल जाना पड़ा। वे भाँप गए थे। उन्होंने एक बात कही थी कि रात-रात भर बैंक खुलवा रहे हो, गरीबों को लाइन में लगा रहे हो, चवन्नी नहीं डाल रहे हो, तो मैंने कहा था कि ट्यूबलाइट देर में जलती है। उसे देर में समझ में आता है। उन्हीं के पिताजी स्वर्गीय राजीव गाँधी ने कहा था, जो इतिहास में दर्ज है, कि वे यहाँ से एक रुपया भेजते हैं और गाँव आते-आते 15 पैसे पहुँचते हैं। जब नोट गिनकर देने का अधिकार रखोगे, तो एडीओ, बीडीओ, सीडीओ, डीडीओ, डीएम, जिला कृषि अधिकारी और उस समय के कांग्रेसी नेता जब कहते थे कि 85 परसेंट खा रहे हो तो मेरा भी हिस्सा दो। यहाँ से मोदी जी ने कहा कि जीरो बैलेंस में जन धन खाते खुलेंगे।

महोदय, मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री हूँ, लेकिन आजकल मुझे डब्ल्यूएचओ से अच्छा डीबीटी लग रहा है। यह शताब्दी का सबसे अच्छा एब्रीवीएशन है। यह डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर है। अब एक रुपया जाता है तो 15 पैसे नहीं पहुँचते हैं। किसान सम्मान निधि में अगर दो हजार रुपये भेजने के लिए एक बटन दबाते हैं तो 1,999 रुपये 99 पैसे किसान के पास नहीं पहुँचता है, सीधे 2,000 रुपये पहुँचते हैं। बोलो यह 85 परसेंट करप्शन को रोकने का काम किया है या नहीं किया है। 51.5 करोड़ लोगों ने बैंक की शकल ही नहीं देखी थी। जिन्होंने यह बयान दिया था कि वे एक रुपया भेजते हैं और 15 पैसे पहुँचते हैं, मैं उनको इनोसेंट प्रधानमंत्री कहता हूँ, लेकिन मैं उनको इन्काम्पिटेन्ट भी कहूँगा। मेघवाल जी, जब देश के प्रधानमंत्री को पता चल गया कि उनके द्वारा भेजे गए पैसे में से 15 पैसे पहुँच रहे हैं, 85 परसेंट पैसे मारे जा रहे हैं तो क्या उसे संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव रोकेगा? जो भेज रहा है, यह उसकी जिम्मेदारी है। इसीलिए मोदी जी चौकीदार हैं। वे चोरी नहीं होने दे रहे हैं। बताइए 85 परसेंट की चोरी वर्षों तक हुई। आपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन खाते नहीं खुलवाए। यह नियम बना देते कि जो गरीब लोग हैं, वे जीरो बैलेंस पर खाता खोलेंगे तो यह 85 परसेंट की चोरी नहीं होती।

महोदय, डीबीटी तो सबसे अच्छा है ही, लेकिन इस देश में किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने अगर इस देश को... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

है तो उनका नाम ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) हैं, जिन्होंने कहा था कि गरीबी हटाओ... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): महोदय, सदन में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए... (व्यवधान)

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : इस देश के एक कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): आप बैठिए। आप बोलिए।

... (व्यवधान)

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : इस देश में कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने इस देश के गरीबों को ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया) का काम किया था... (व्यवधान) उन्होंने एक नारा देकर कहा था कि गरीबी हटाओ और इस देश के गरीबों ने इस प्रत्याशा में कि अगर हम गाय बछड़े पर मोहर लगा देंगे तो उनके घर से गरीबी दूर हो जाएगी... (व्यवधान) गरीबी दूर नहीं हुई... (व्यवधान) यदि गरीबी दूर हो गई होती तो ये 80 करोड़ लोग कौन हैं, जो हमें विरासत में मिले हैं, जिन्हें 5 किलो गेहूँ और चावल मोदी जी दे रहे हैं... (व्यवधान)

माननीय सभापति : हम देख लेंगे। आप बोलिए।

... (व्यवधान)

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : महोदय, यदि गरीबी हट गई होती तो ये 4.5 करोड़ लोग कौन हैं, जिन्हें मोदी जी प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास बनाकर दे रहे हैं... (व्यवधान)

मेरे भाई गोगोई साहब, यदि गरीबी हट गई होती तो स्वनिधि योजना के तहत 10 हजार रुपये की राशि लेने वाले लोग हमें विरासत में क्यों मिलते?... (व्यवधान)

माननीय सभापति : एक सेकेंड रुकिए। मैंने कहा है कि मैं चेक करा लूँगा। आप बैठ जाइए। मैं देख लूँगा। आप बैठ जाइए। नीतियों के विषय में, संसद के अंदर जिन नीतियों का उल्लेख हुआ है, उनकी चर्चा हो सकती है। नामोल्लेख के बारे में मैं देख लूँगा। आप कृपया बैठ जाइए।

कृपा करके आप नाम मत लीजिए।

... (व्यवधान)

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : मैं रटकर नहीं आया हूँ, जो भूल जाऊँगा... (व्यवधान) हमले जारी रहेंगे... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, कृपया आप चेयर को संबोधित कीजिए।

... (व्यवधान)

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : महोदय, मैं चेयर को संबोधित करते हुए कह रहा हूँ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप किसी भी माननीय सदस्य का नाम लेकर संबोधित मत कीजिए।

... (व्यवधान)

(1300/IND/RP)

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : सभापति जी, मैं चेयर को संबोधित करते हुए कह रहा हूँ कि कांग्रेस के एक प्रधान मंत्री ने कहा था कि गरीबी हटाओ और गरीबों ने गाय-बछड़े पर मुहर लगा दी, लेकिन गरीबी नहीं हटी... (व्यवधान) तुम गरीबी हटा नहीं सकते हो क्योंकि गरीबों का लहु तुम्हारी कारों का डीजल है और गरीबी मिट जाएगी तो तुम क्या रिकशा चलाओगे?... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): मैंने व्यवस्था दे दी है, आप बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : सभापति जी, अगर गरीबी हट गई होती तो हमें विरासत में 80 करोड़ गरीब लोग न मिलते, जिन्हें हम गेहूँ और चावल दे रहे हैं। यदि गरीबी हट गई होती तो ये साढ़े चार करोड़ लोग कौन हैं, जो हमसे घर ले रहे हैं? यदि गरीबी हट गई होती तो ये करोड़ों लोग कौन हैं, जो दस हजार रुपये स्वनिधि योजना में मांग रहे हैं? यदि गरीबी हट गई होती तो ये मुद्रा योजना में 50 हजार रुपये का लोन लेने वाले आखिर गरीब कहां से आ गए? यदि गरीबी हट गई थी तो केवल 12 हजार रुपये का शौचालय लेने के लिए हम लोगों के घर गरीब लोग नहीं आते। यदि गरीबी हट गई होती तो पांच लाख रुपये प्रति व्यक्ति प्रति साल का आयुष्मान का कार्ड देने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। यदि गरीबी हट गई होती, तो आपको टेली लॉ लाने की जरूरत नहीं होती। यदि गरीबी हट गई होती तो मेघवाल जी, आपको न्याय बंधु नहीं लाना पड़ता। यदि गरीबी हट गई होती, तो ई-कोर्ट नहीं बनाने पड़ते। यदि गरीबी हट गई होती तो टेली लॉ और न्याय बंधु आपको लाने की जरूरत न पड़ती... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मंत्री जी, कृपया आप चेयर को संबोधित कीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : विपक्ष को बोलने का मौका मिलेगा, अभी आप बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : काका वंदनीय, कांग्रेसियों के लिए पूजनीय नेता वंदनीय, वे गरीबी नहीं हटा पाईं। मैं एक बार फिर शेर सुना दूँ कि गरीबों का लहु तुम्हारी कारों का डीजल है। यदि गरीबी मिट जाएगी तो तुम क्या रिकशा चलाओगे। ये मोदी जी हैं, जिनके 10 साल के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग बहु आयामी गरीब लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। इसे कहते हैं गरीबी हटाओ। क्या आप लोग कालाहांडी को भूल गए हैं? भूख से लोग मरते थे। बिना एक्सरे के पसलियां दिखाई पड़ती थीं। विदेशी लोग फोटो लेने आते थे। राष्ट्रीय शर्म की बात थी। कालाहांडी से एक बार खबर आई थी कि लोग भूख से मरे हैं। आपकी पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। मैं पुलिस में रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा था कि पोस्टमार्टम करा दो। इनकी बड़ी आंतों में पिछले 72 घंटों में कच्चा या पक्का अनाज यदि मिलता है तो भूख से नहीं मरे हैं, बीमारी से मरे हैं लेकिन आपने पोस्टमार्टम नहीं कराया, क्योंकि पता चल जाता कि वे भूख से मरे हैं।

सभापति जी, हम सभी को मरना है लेकिन पिछले 10 साल से 140 करोड़ लोगों में से एक भी आदमी भूख से नहीं मरा है क्योंकि पांच किलो गेहूँ और चावल उसे निशुल्क मिल रहा है। कल

बजट में यह भी कह दिया गया है कि अगले पांच सालों की भी गारंटी ले ली गई है। क्या सड़क पर शौच करती महिला को आप लोगों ने नहीं देखा था? मैं यदि नाम ले लूंगा तो मिर्ची लग जाएगी। पहले प्रधान मंत्री ने ज्यादा देखा क्योंकि तब हम महागरीब थे। फिर दूसरे प्रधान मंत्री ने देखा। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। फिर तीसरे प्रधान मंत्री ने देखा और कई बार देखा क्योंकि वे कई बार प्रधान मंत्री रही हैं। फिर चौथे ने देखा, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें ने देखा और यह भी देखा कि जब वह महिला शौच कर रही होती थी और कोई बड़ा-बूढ़ा आता था या रोशनी वाली फटफटिया आ जाती थी, तो वह महिला अचानक खड़ी हो जाती थी। इस देश में कहा जाता है कि खाना खाते हुए यदि कोई लाट साहब आ जाए तो भी नहीं उठना है लेकिन मैं कहता हूँ कि खाना खाते हुए उठने से न तो कपड़े खराब होते हैं और न ही पेट खराब होता है। क्या यह कोई बिजली का स्विच है कि महिला शौच के लिए बैठी तो स्विच ऑन कर दिया, मोशन हो गया और अचानक खड़ी हो गई तो स्विच ऑफ हो गया। उसमें पेट भी खराब होता था और कपड़े भी खराब होते थे। इस दर्द को मोदी जी ने समझा और शौचालय बनाने का काम किया। लाल किले की प्राचीर से इस शब्द को बोला... (व्यवधान)

सभापति जी, मैं आपके जिले में ही पुलिस में था। बलात्कार की रिपोर्ट आती थी। मैं थाना इंचौली, लालपुरतिनी, सरदना में रहा। जब बलात्कार की एफआईआर आती थी, तो उसमें लिखा होता था कि मेरी पत्नी, बहन या बेटा शौच करने के लिए गई थी तो बदमाशों ने बुरा किया क्योंकि हमारी बहनें सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद शौच के लिए जाती थीं, इसका बदमाशों ने फायदा उठाया। जब से ये इज्जत घर बने हैं, बलात्कार की संख्या में कमी आ गई है और यह बड़ा काम मोदी जी ने करने का किया है... (व्यवधान) उज्ज्वला योजना के लिए 11 करोड़ ऐसे ही मत बोला कीजिए। कंडे पर रोटी बनाते हुए, रेयर के खांडू पर रोटी बनाते हुए, सरसों की तोई पर रोटी बनाते हुए, ढेंचा पर रोटी बनाते हुए और गीले कंडे पर रोटी बनाते हुए किस प्रधान मंत्री ने नहीं देखा था।

(1305/RV/NKL)

शहर वालों, हमें आपकी भी हैसियत पता है - पत्थर के कोयले पर, लकड़ी के कोयले पर, लकड़ी के बुरादे पर, बत्ती वाले स्टोव पर, फिर पीतल के स्टोव पर, फिर लोहे के स्टोव पर खाना बनने लगा - ऐसे ही तो हुआ।

सभापति महोदय, मैं आपको अपनी एक घटना सुनाता हूँ। यह आपके शहर से संबंधित है। मैं छुट्टी में अपने घर गया। मेरी माँ का आदेश हुआ कि दिवाली पर पूरे खानदान को आना पड़ेगा। मैंने अपनी माँ को रात में पाँच बार उठ कर चूल्हा जलाकर दूध गर्म करते देखा। सुबह मैंने उनसे कहा कि माँ, आप तो सोयी नहीं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी सरकार ने गैस नहीं दी। मेरी सरकार नहीं थी। मैं पुलिस में था। मेरठ में पुरी गैस एजेंसी है। जब मैं छुट्टी से वापस लौटा तो मैं वहाँ वर्दी पहनकर गया और कहा कि मुझे गैस चाहिए। उन्होंने कहा कि फॉर्म भर दो। मैंने कहा कि इसके लिए फिर मैं कब आऊँ तो उन्होंने कहा कि पाँच साल बाद इसके लिए पूछने आना। मैंने कहा कि मुझे तो अभी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मदत्त से लिखवाकर ले आओ। मैंने कहा कि ब्रह्मदत्त कौन हैं तो

उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मंत्री हैं। फिर मैंने कहा कि इतनी मेरी औकात नहीं है। मैंने उनकी कार का नम्बर नोट कर लिया। तब वर्ष 1984 में उनके पास चार मारुति कार थीं। मैंने मोटर वेहिकल्स एक्ट के नियमों के अनुसार गाड़ी का चालान किया। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि इतवार को गैस दे देंगे। मैंने कहा कि मैं चूल्हा नहीं खरीदूंगा, क्योंकि उसमें उसकी इनकम है। जब मुझे गैस सिलिन्डर मिला और जब मैं छुट्टी लेकर संगम एक्सप्रेस से भरा हुआ सिलिन्डर और रेगुलेटर लेकर अपनी माँ से मिलने पहुंचा तो वहां के तीन पुलिस अफसरों की माँ ने यह कहा था कि इससे अच्छा गिफ्ट कोई और हो नहीं सकता है, क्योंकि धुएँ में फूँकते-फूँकते उन्हें मोतियाबिन्द हो गया है। अभी मोदी जी अंतिम आदिवासी महिला को गैस का सिलिन्डर दे रहे हैं, पाइपलाइन से गैस पहुंचा रहे हैं और उस पर सब्सिडी भी दे रहे हैं... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): अब कनेक्शन लेने के लिए किसी को डराने की जरूरत नहीं है।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : सभापति महोदय, मजेदार बात यह है कि मैंने माँ से कहा कि गैस भरवाने में दिक्कत होती होगी तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसे अमृत की तरह इस्तेमाल कर रही हूँ।

महोदय, उसके बाद वर्ष 1998 में मैं एम.पी. हो गया। आपकी चेयर ने 120 गैस सिलिन्डर्स देने का अधिकार दिया, लेकिन उसमें यह प्रावधान था कि इसे आप अपनी कंस्टीट्यून्सी में ही देंगे। मेरा एक भतीजा मैनपुरी लोक सभा क्षेत्र में करहल में रहता है। उसने मुझे एक चिट्ठी लिखी कि चाचा, मुझे गैस चाहिए। मैंने कहा कि स्पीकर साहब ने कहा कि इसे मैं अपनी कंस्टीट्यून्सी में ही दे सकता हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे एम.पी. बलराम सिंह यादव जी हैं। मैंने उन्हें एक चिट्ठी लिखी कि मेरा सगा भतीजा आपकी लोक सभा कंस्टीट्यून्सी में रहता है, कृपया उसे एक गैस कनेक्शन दें। फिर उस एम.पी. साहब ने उस चिट्ठी में लिखा कि मेरा सगा साढ़ू तुम्हारे लोक सभा क्षेत्र में राजा का ताल में रहता है, पहले तुम उन्हें एक गैस कनेक्शन दो, तब मैं तुम्हारे भतीजे को गैस कनेक्शन दूंगा। उस समय एक एम.पी. दूसरे एम.पी. से इसके लिए बारगेनिंग कर रहा था और अब 11 करोड़ गैस कनेक्शंस मोदी जी ने दिये। अब अंतिम गरीब आदिवासी महिला को भी गैस कनेक्शन देने का काम मोदी जी ने किया है। काश! मोदी जी मेरी दादी और मेरी अम्मा के जमाने में पैदा हो जाते, तो फिर मेरे घर में फूँकनी नहीं होती, फिर मेरी दादी और मेरी माँ का धुएँ से मोतियाबिन्द नहीं होता, इसलिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

साढ़े चार करोड़ प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास देने के लिए मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि कल दो करोड़ और आवास देने का वादा कर दिया गया है। पॉलिथीन में, छप्पर में, खपरैल में, यहां तक झुग्गी-झोपड़ी में और दिल्ली में सीमेंट की पाइप में मैंने लोगों को रहते हुए देखा है।

सभापति महोदय, तब नवम्बर के महीने में भैंस को बाहर रखा करते थे और दिसम्बर आते-आते झूल ओढ़ाते थे और पूस आते-आते भैंस को कमरे में बाँधना पड़ता था। कमरे के आधे में भैंसिया बंधती थी और आधे में हमारी खटिया बिछी रहती थी। भैंस पेशाब करके पूँछ हिलाती थी।

हमारे मुँह पर तो वह बहुत बार गिरा है। इसलिए इथेन, मिथेन सूँघते हुए जवान हुए हैं। आज कई करोड़ आवास बना दिए गए हैं। कल दो करोड़ आवास और बनाने के लिए वादा किया गया है। मैं गरीबों की तरफ से फिर एक बार इस सदन के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करूँगा।

महोदय, मैं एक घटना सुनाता हूँ। मैं अपनी कंस्टीट्यून्सी में घूम रहा था तो एक महिला ने कहा कि रुको। तब मैंने कहा कि मैं जल्दी में हूँ। उन्होंने कहा कि अरे, तुम्हें रुकना पड़ेगा, क्योंकि आजकल मैं अपनी कंस्टीट्यून्सी में एक्स.ई.एन. नहीं रहा, बल्कि अब मैं गार्जियन हो गया हूँ। छः बार जीतने के बाद अब रिश्ते बन गए हैं। वह महिला अपने घर में घुसी और मिट्टी के दीये में सरसों के तेल से दीपक जलाकर आरती की। यू.पी. में ऐसी आरती नहीं होती है। मैंने कहा कि क्यों खुश हो तो उसने कहा कि प्रधान मंत्री ने मुझे एक आवास दिया है। उसने कहा कि मैं छप्पर के नीचे बाहर सोती थी, रात में कपड़े ऊँचे-नीचे होने का डर लगा रहता था, शराबी लोगों से डर लगता था, मैं जिन्दगी में झिक्के नहीं सोयी हूँ। ट्रांसलेशन वालों, झिक्का मतलब होता है - साउण्ड स्लीपा फिर उसने कहा कि जबसे मोदी जी ने मुझे मकान दिया है, मैं कुंडी बंद करके सोती हूँ और वर्षों के बाद मैं झिक्के आठ घंटे सोयी हूँ। यह इस आवास का महत्व है। संख्या का नहीं, आवास का ऐसा महत्व है।

(1310/GG/VR)

सर, इसलिए मुझे एक शेर याद आ रहा है कि
“हमने तो खानाबदोश की जिंदगी काट ली है रब,
अगली नस्लें तो न भटके, उन्हें घर भी देना”

इसलिए मोदी जी ने इस शेर को चरितार्थ किया है।

“सौ में सत्तर अदमी फिलहाल जब नाशाद हैं,
दिल पर रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है।
कोठियों से मुल्क के मेआर को मत आँकिए,
असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है।”

उस फुटपाथ पर रहने वाले, झुग्गी में रहने वाले, झोंपड़ी में रहने वाले, छप्पर में रहने वाले, खपरैल में रहने वाले, पॉलिथिन में रहने वाले, लोहे की टिन में रहने वाले और सीमेंट के पाइप में रहने वाले लोगों के लिए मोदी जी ने पुनः दो करोड़ घर स्वीकृत कर के उनके लिए छत बनाने का काम किया है। अस्सी करोड़ लोगों को पांच किलो गेहूँ और चावल देने का काम किया है। कालाहांडी के बार में दोबारा नहीं कहूँगा, एक्सरे की जरूरत नहीं पड़ती थी।

आप लोगों को गरीब कहते थे और मोदी जी उनको दरिद्र नारायण समझते हुए, ईश्वर तुल्य मानते हुए ये उद्द सौ योजनाएं ले कर आए हैं। इसलिए गरीबी हट रही है इसलिए 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। ... (व्यवधान)

प्रोफेसर साहब, मैं यह कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद अगर मुझसे कोई पत्रकार यह पूछे कि तुम्हारे छह कार्यकाल की सबसे अच्छी योजना क्या है, तो मैं कहूंगा कि छह कार्यकाल बड़े छोटे होते हैं, मैं तो इस युग की सबसे बड़ी योजना प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना को मानता हूँ, जिसमें 5 लाख प्रति व्यक्ति, प्रति साल, पूरे खानदान को इलाज मिलता है। 25 लाख आंगनवाड़ी बहनों और दस लाख आशा बहनों को इसमें जोड़ कर स्वास्थ्य का अंत्योदय करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कल के बजट में किया है। मैं एक नंबर ऐसे ही नहीं कहता हूँ। ये 80 करोड़ लोग अगर बीमार हो जाएं, ये 12 हजार रुपये में शौचालय बनवाने लोग अगर बीमार हो जाएं, पीएम स्वनिधि योजना में 10 हजार रुपये लेने वाले अगर बीमार हो जाएं, मनरेगा के मजदूर बीमार हो जाएं, तो क्या होगा? अगर ये लोग गलती से कॉर्पोरेट अस्पताल में घुस गए, तो इनके जेवर बिक जाएंगे, पूरी खेती बिक जाएगी और अगर वे पांच रुपये सैकड़े पर उधार लेंगे, तो भी इलाज नहीं हो पाएगा। एक दिन हम सबको मरना है, लेकिन मोदी के कार्यकाल में इलाज के अभाव में एक भी आदमी नहीं मरेगा।

साहब, मैं गांव में पैदा हुआ हूँ, 32 घरों के मकान में पैदा हुआ हूँ। जब गांव का आदमी बीमार होता है, तो पहले दिन वह बीमारी को नोटिस में नहीं लेता है। दूसरे दिन चाय में अदरक डाल कर कोल्ड एण्ड कफ को ठीक करने का प्रयास करता है। तीसरे दिन काढ़ा पीता है, चौथे दिन अपने जेब में डले हुए अपने रुपयों की औकात के अनुसार अपने डॉक्टर का चयन करता है। इलीट क्लास के लोग अपनी बीमारी के अनुसार अपने एक्सपर्ट का चयन करते हैं। वह गरीब डॉक्टर के पास जाता है, तब डॉक्टर कहता है कि पांच दिनों का एंटीबायोटिक का कोर्स चलेगा। तो मेरे गांव की भाषा में कि भाड़ में जाए डॉक्टर साहब तुम्हारा कोर्स, मेरी जेब में 45 रुपये पड़े हैं, इसमें जितनी दवाई आती है, उतनी दे दो। तब वह बिना रैफर के नीली-पीली गोली कागज़ की पुड़िया में लपेट के देता है। लेकिन अब उन गरीबों की जेब में पांच लाख रुपये प्रति व्यक्ति, प्रति साल का मोदी की गारंटी का कार्ड जेब में रखा हुआ है, जैसे हम सांसदों की जेबों में सीजीएचएस का कार्ड रखा हुआ है। यह मोदी की गारंटी की गारंटी है। मैंने आंगनवाड़ी का बोल दिया है कि 25 लाख आंगनवाड़ी बहनों और 10 लाख आशा बहनों को मिला कर 35 लाख को चार से गुणा कर दें तो एक करोड़ 40 लाख लोगों को कल ही आयुष्मान कार्ड देने का काम कर दिया गया है। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती गर्भवती महिला के टच में आती है, जो आशा बहनें तीन साल के बच्चे का स्वास्थ्य का ख्याल रखती हैं, अगर वे बीमार हो जाती हैं, उनमें से किसी की बाईपास होती है, अगर किसी का लीवर खराब हो जाता तो वह क्या करेगी? मोदी जी ने इसको ध्यान में रखा है और इसी को नारी सशक्तिकरण कहते हैं। असली नारी सशक्तिकरण यही है कि अंतिम पायदान पर खड़ी हुई महिला को 20 लाख रुपये, घर में चार सदस्य तो होते ही हैं, मियां-बीबी और दो बच्चे, इस तरह से 20 लाख रुपये आज से उसकी जेब में पड़े। अगर वह दिल्ली जा रही होगी और मथुरा में तबियत खराब हो जाएगी तो मथुरा में उतर कर किसी भी इम्पैनल्ड अस्पताल में घुस जाएगी और उस डॉक्टर को इलाज करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो मैं भी स्वास्थ्य राज्य मंत्री हूँ, फिर मैं देखूंगा।

सर, पीएम स्वनिधि मुझे बहुत अच्छी लगती है। It is very close to my heart. अंडे वाला, ठेले वाला, केले वाला, पास्ता वाला, पिज्जा वाला, बर्गर वाला, चाऊमीन वाला, मूंगफली वाला, गजक वाला, पंचर वाला, सब्जी वाला, ऑमलेट वाला, मुरमुरे वाला, पेठे वाला दस हजार रुपये की पीएम स्वनिधि से अपने घर का गुजारा कर रहा है। मुद्रा योजना मेरे बहुत क्लोज़ है, शिशु योजना, तरुण योजना, किशोर योजना है। इसके माध्यम से लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं।

महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इनके राज्य वाले हमारी आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं कर रहे हैं। पांच लाख रुपये, प्रति व्यक्ति, प्रति साल, इनकी अपनी योजना होगी, लेकिन हमारे पांच लाख रुपये क्यों छोड़ रहे हैं?

(1315/MY/SAN)

क्या कई बार लीवर ट्रांसप्लांट 15 लाख रुपये में होता है? क्या कई बार बाईपास सर्जरी पाँच लाख रुपये से ऊपर नहीं जाती है? क्या कैंसर का इलाज इससे ऊपर नहीं जाता है? क्या हार्ट का खर्च उससे ऊपर नहीं जाता है? आपको मालूम है कि ये लोग क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल में मोदी जी की फोटो आ जाएगी। मोदी जी शौचालय, आवास, पाँच किलो गेहूँ-चावल, स्वनिधि और मुद्रा से पहुंच गए हैं। आप इस आयुष्मान कार्ड योजना को लागू नहीं कर रहे हैं। आप गरीबों का नुकसान कर रहे हैं... (व्यवधान)

हाँ, यही से पूरा जा रहा है। 'मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन', तो भी नहीं घिस रहे हैं। भारत ने कोविड के दौरान टीकाकरण की 220.67 करोड़ खुराक हासिल की और एक दिन में लगा दी। आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य कोई जुमला नहीं है। हम 29.62 करोड़ आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं। इसे मैं पढ़कर आया हूँ। 6.15 करोड़ लोग अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करा चुके हैं। इसके लिए हम 75,000 करोड़ रुपये निर्गत कर चुके हैं। 10 हजार से ऊपर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुल गए हैं। आपने 60 सालों में क्या ... (*Expunged as ordered by the Chair*)

मचवाई थी?

सर, 30 परसेंट से लेकर 90 परसेंट तक बचत हो रही है। मैं देश के डॉक्टरों से इस लोकतंत्र के मंदिर से अपील करना चाहूंगा कि जब गरीबों का प्रिस्क्रिप्शन लिखें तो वे दवाइयाँ जरूर लिखें, जो जन औषधि केंद्र पर उपलब्ध होती हैं, जिससे उनका 30 परसेंट से 90 परसेंट पैसा बचे।

सर, मेडिकल कॉलेज की जो संख्या है, इसे आप क्या कहेंगे- 10 साल बनाम 67 साल। हाँ, ठीक है – 67 साल बनाम 10 साल। 67 सालों में आपने जो मेडिकल कॉलेज बनाए थे, उनकी संख्या 387 थी। इनको 82 परसेंट बढ़ाकर 706 कर दिया गया है। यहां दोगुने से कम करने में मजा ही नहीं आता है। विरासत में हमें 6 एम्स मिली थी। आज उनकी संख्या 22 हो गई है। एमबीबीएस की सीटें 112 परसेंट बढ़ गई हैं। यहां दोगुने से कम में मोदी जी को आनंद ही नहीं आता है। वर्ष 2014 से पहले 51,348 सीटें थीं। अब 1,08,940 सीटें हो गई हैं। पीजी की जो स्थिति है, दीवारों से इलाज नहीं होता है, आज पीजी से नीचे कोई हाथ नहीं दिखा रहा है। इसमें हमने 126 परसेंट की वृद्धि की है। वर्ष 2014 से पहले आपके राज्य में इनकी संख्या 31,118 थी,

अब यह बढ़कर 70,645 हो गई है। वर्ष 2014 में 6 एम्स थे। अब इनकी संख्या 22 हो गई है। मैं आश्चर्य करना चाहूंगा कि मद्रास और दरभंगा में भी एम्स तैयार हो जाएगी।

विकसित भारत संकल्प यात्रा – मोदी की गारंटी की गाड़ी पहली बार देश के हर राजस्व गाँव में गई है और केंद्र सरकार के विभागों ने बहुत मेहनत की है। इसके बाद मैं कहूंगा कि सरकार आपके द्वार है... (व्यवधान) हाँ, यह नहीं है। क्या आप ऐसे रोक लेंगे? क्या खुशबू को आज तक कोई रोक पाया है?

खुशबू को बहुत गरूर था अपने महकने पर
मुमकिन नहीं यह हवा से रिश्ता किए बगैरा

हवा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्होंने इस खुशबू को बूथ स्तर तक पहुँचा दिया। मनसुख भाई के मॉनिटरिंग में विभाग ने ठीक से काम किया है। हमने ग्राम पंचायत स्तर पर यूएलबी की संख्या 2,30,000 तक पहुँचायी है। शिविर में 7 करोड़ लोग पहुँचे हैं। टीबी की जाँच के लिए 3.76 करोड़ लोग गए हैं। टीबी से संदर्भित लोगों की संख्या 11,54,000 है। प्रधानमंत्री आभा में ली गई सहमति के अनुसार पंजीकृत नि-क्षय की संख्या 1,14,000 है। नि-क्षय पोषण योजना में 83,926 को कीट दे रहे हैं और नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने के लिए और जीवनशैली में बदलाव करने के लिए 2 करोड़ 88 लाख लोगों ने अपनी स्क्रीनिंग करायी है। हाई ब्लड प्रेशर की 2 करोड़ 72 लाख लोगों ने हमारे कैंपों में स्क्रीनिंग करायी है। ब्लड प्रेशर के लिए 19 करोड़ 97 लाख लोगों ने हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर पर स्क्रीनिंग करायी है। आजकल यहां पर आयुष्मान मंदिर है। डायबिटीज एक हिडेन बीमारी है। 2 करोड़ 61 लाख लोगों ने इसकी स्क्रीनिंग करायी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत यात्रा में हेल्थ विभाग के कैंप में 14 करोड़ 13 लोगों ने डायबिटीज चेक करायी है। एनसीडी और हायर पब्लिक फैसिलिटीज के लिए 30 करोड़ लोगों को संदर्भित किया गया है। सिकल सेल की भी बात आती है। इन्होंने कहा था कि हमारी आदिवासी बहनें 40 साल में मर जाती हैं। इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। अब उनका कार्ड बन गया है। दोनों कार्ड मैच करेंगे, यदि वह लाल हो जाएगा तो शादी नहीं होगी, क्योंकि अगर बच्चा पैदा होगा तो वह भी 99 परसेंट सिकल सेल से होगा।

(1320/CP/SNT)

मैं आपकी तरफ मुखातिब हूँ। हिना जी ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से कहा। सिकल सेल उन्मूलन का काम हो रहा है। एसईडी के लिए संदर्भित जांच लोगों की संख्या 70 हजार, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नया नाम 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर', लेकिन आप नीला नहीं पोत रहे हैं और हमसे 60 परसेंट पैसा ले रहे हैं। आप क्यों नहीं लिख रहे हैं 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर'? मोदी जी की फोटो लग जाएगी तो क्या आफत आ जाएगी? क्या आप रोक पायेंगे, क्या मेरे भाषण को रोक पायेंगे? पश्चिम बंगाल के लोग सुन रहे हैं कि हम 60 परसेंट पैसा देते हैं, लेकिन आप नाम नहीं लिखते हैं, रंग तक नहीं बदलते हैं। 50 करोड़ 97 लाख फिजिकल आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं और 100 परसेंट आयुष्मान कार्ड की संतति 1 करोड़ 30 लाख। यह बहुत लंबा है, चलो इतने में ही काम चलाते हैं। कल के बजट में स्वास्थ्य अंत्योदय हुआ है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ,

10 लाख आशा बहनें, 25 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का आयुष्मान कार्ड में पंजीकरण हो जाएगा। मैं नये मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति के लिए बधाई देना चाहूंगा।

चेयरमैन सर, जब आप चेयर पर बैठे थे, तो मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि महिलाओं को कौन-कौन से कैंसर होते हैं? मैंने जवाब दिया था, ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर। 17 पर्सेंट महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से मरती थीं। मैं बजट के लिए वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने एचपीवी वैक्सीन को प्रोत्साहन देने का कल वादा किया है। अगर 40 औरतें दुनिया में मरती थीं तो 27 भारत में मरती थीं। अब इस सर्वाइकल कैंसर का उन्मूलन आने वाले समय में हो जाएगा। मैं 9 साल से 14 साल की बच्चियों की तरफ से प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का आभार प्रकट करना चाहूंगा।

फर्टिलाइजर, यह अघोषित दूसरी हरित क्रांति हो रही है। नीम कोटेड यूरिया करते ही पेट में दर्द हो गया था। घटतौली बंद हो गई थी और तस्करी भी बंद हो गई थी। मैं किसानों के लिए इस बड़े अविष्कार को मानूंगा, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी। नैनो डीएपी में अगर आप एक बोरी डीएपी डालेंगे, उसकी जगह आप नैनो एक लीटर इस्तेमाल करेंगे तो 645 रुपये बच जाएंगे। हम तो आलू वाले लोग हैं। जहां तक निगाह पड़ती है, आलू, आलू। हम तो सैकड़ों बोरी छिड़क डालते हैं। प्रति बैग 645 रुपये मोदी जी ने नैनो डीएपी बनाकर बता दिया और नैनो यूरिया में 45 रुपये। ऊपर से अब मेटोडोर नहीं करनी पड़ेगी अब पीठ में बोरी नहीं लादनी पड़ेगी। दो जेबों में डालकर जाऊंगा, एक में नैनो डीएपी और एक में नैनो यूरिया। ड्रोन इस देश का भविष्य है। जब से ये तमाम योजनाएं आई हैं, थोड़ी मजदूरी में प्रॉब्लम आ रही है। एक एकड़ का, चाहे कीटनाशक का, चाहे डीएपी लिक्विड का, चाहे नैनो यूरिया का छिड़काव 5 मिनट में हो जाएगा। आप सोचिएगा, आने वाले समय में क्या होगा? अब तक 12 हजार लोगों ने ड्रोन खरीद लिया है। 12 हजार लोग और मात्र 500 रुपये, 500 रुपये तो मजदूर एक या डेढ़ दिन में ले लेगा।

मुझे याद है डीएपी और यूरिया के लिए लाइन लगती थी, लाठी चार्ज होता था। मैं मुकदमे झेल रहा हूँ, मुकदमे चल रहे हैं। खाद को लेकर लाठीचार्ज होता था। अब बताइए कि क्या कहीं 10 सालों में लाठीचार्ज हुआ? रेलवे टाइम पर रैक पहुंचा देती है और नैनो इस देश का भविष्य है। मैं फिर इस देश की बड़ी पंचायत से देश के किसानों से आग्रह करूंगा कि क्या हम नैनो यूरिया और डीएपी ऐसी बना सकते हैं, जो फसल खराब कर दे। हम पर विश्वास करो, मोदी जी पर विश्वास करो, कृषि वैज्ञानिकों पर विश्वास करो। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी इस्तेमाल करो। जो डीएपी सॉलिड और यूरिया दो पौधों के बीच में पड़ जाती है, वह बेकार हो जाती है। लेकिन, इसमें पत्ती के माध्यम से जड़ में पहुंचती है, इसलिए उसका 100 पर्सेंट यूटिलाइजेशन होता है। मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों नैनो पर आ जाओ। ऐसे ही बातें नहीं हुई हैं। 35 लाख नैनो डीएपी बिक गई है, 7 करोड़ नैनो यूरिया की बोटल बिक गई हैं... (व्यवधान) यह नैनो लिक्विड है। जैसे आपने नैनो कार का बहिष्कार किया था, वैसा मत करिए। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का बहिष्कार मत करिए... (व्यवधान) प्रोफेसर सब समझते हैं। ... (व्यवधान) 33 लाख नैनो डीएपी और 7 करोड़ नैनो यूरिया बिक चुकी है और 12 हजार सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ले चुके हैं। मैं देश के नौजवानों से कहना

चाहूंगा कि अगर एक ड्रोन खरीद लेंगे, तो पैडी में करिए, फिर व्हीट पर करिए, फिर जायद की फसल पर करिए, फिर रबी की फसल पर करिए, फिर खरीफ की फसल पर करिए, फिर दक्षिण भारत में नारियल पर चले जाओ, रबर पर चले जाओ। जेसीबी मशीन चलती थी तो बीस लोग देखते थे। हमारे ड्रोन को एक हजार लोग देखने आते हैं।

(1325/NK/AK)

जब उसे देखेंगे तो खरीदेंगे और इस्तेमाल भी करेंगे। प्रधानमंत्री किसानों की आय कैसे दोगुना कर देंगे? मुझे लगा कि न उत्पादन दोगुना होगा तो मूल्य दोगुना कैसे होगा? मैंने तब रात में घर आकर अखबार पढ़ा। प्रधानमंत्री जी की बात का किसानों ने अनुसरण किया। अब किसान पशु पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन और मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। ड्रीप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन में सब्सिडी है, एक्वाकल्चर, औषधि खेती, फूलों की खेती, फलों की खेती के द्वारा किसान इस समय अपनी आय दोगुना करने का काम कर रहे हैं इसीलिए 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं।

किसान सम्मान निधि के बारे में हम विस्तार से नहीं बताते हैं। हम केवल कह देते हैं कि 11 करोड़ लोगों के हिस्से में इतने करोड़ आ गए। इस बारे में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, न एकड़ तय किया, न हेक्टेयर तय किया, न बिगहा तय किया, न कूड़ तय किया। इस हाउस के अंदर बीच में जो टेबल है, यदि किसी किसान के रिकार्ड या खतौनी में एक कूड़ जमीन होगी तो यह हो सकता है कि फसल सौ रुपये की भी न हो, लेकिन दो-दो हजार रुपये की तीन किशतें उसके खाते में आएंगी और पन्द्रह किशतें आ चुकी हैं। हम लोग किसान के बच्चे हैं, ओला, पाला, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, गाय, नीलगाय, आग, बाढ़ और सूखाड़ से बच जाएं तब किसान की फसल होती है। यह हो सकता है कि खेती न हो तो भी फसल बीमा योजना है। छह हजार रुपये की गारंटी नरेन्द्र मोदी ने ले ली। दो हजार रुपये पूरे पहुंचते हैं और जिस दिन खाते में पहुंचता है, उस दिन किसान 1 किलो मिठाई लेकर घर जाता है। आपने सीकर और झूनझूनू में बटन दबाया था, मैं आपके राज्य चितौड़ में था, मैसेज आ गया कि दो हजार रुपये आ गए।

एक महिला ने मुझसे कहा कि मोदी जी को राम-राम कहना। मैंने कहा कि आप खुद ही कह देना। मैंने कहा कि आप चिट्ठी लिख दो, वह जवाब देते हैं। आप मोदी जी को क्यों राम-राम कह रहे हैं। उस महिला ने कहा कि जब मेरी विधवा पेंशन के एक हजार रुपये आते हैं, उसके तीन दिन पहले से मेरी बहू पैर दबाना शुरू कर देती है। मोदी जी ने बड़े-बूढ़ों का सम्मान करा दिया है।

महोदय, मुझे थोड़े दिन लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय भी देखने का मौका मिला। यह मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रही है, पेन्डेंसी कम हो रही है, टेली लॉ शुरू कर दिया, ई-कोर्ट शुरू कर दिया, ई-फाइलिंग कर दी है, वर्चुअल कोर्ट हो रहा है, स्क्रीन पर लोग अपनी बहस को सुन सकते हैं। गरीब, दलित, पिछड़े, महिलाएं, विडो और डिवोर्सी महिलाओं को आप निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। यह अच्छा काम कर रहे हैं।

अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कनैडी ने कहा कि अमेरिका पैसे वाला देश है इसलिए उसने सड़कें नहीं बनायीं, उसने पहले सड़कें बनायीं इसलिए वह पैसे वाला देश हो गया। रोड और

ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी साहब ने इसको अपना ब्रह्म वाक्य बनाते हुए इस देश में सड़कों का जाल बिछा दिया। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया था, इसके बाद अटल जी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गडकरी साहब ने रोड बनाए। ऐसे थोड़े न हवा में बोलते हैं। नेशनल हाईवे नेटवर्क की हाई स्पीड कॉरीडोर की लम्बाई वर्ष 2014 में केवल 93 किलोमीटर थी जो अब बढ़कर वर्ष 2023 में चार हजार किलोमीटर हो गई। 93 किलोमीटर बनाम 4000 किलोमीटर। मार्च, 2014 से दिसम्बर, 2023 तक के बीच एनएच नेटवर्क का 1.6 गुना यानी 91 हजार, 267 किलोमीटर से 1 लाख 46 हजार 145 किलोमीटर हो गया। आपने शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस चलायी थी, अब गतिमान चल रही है, वन्दे भारत चल रही है, दुरंतो चल रही है और बुलेट ट्रेन की तैयारी हो रही है। एक शेर याद आता है, तू किसी रेल सी गुजरती है मैं पुल सा थरथराता हूँ, आजकल इतनी स्पीड से ट्रेनें चल रही हैं।

चौधरी साहब ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से जाता है। मैं इसमें थोड़ा संशोधन करूंगा कि यदि देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से जाता है तो देश की खुशहाली का रास्ता एमएसएमई से होकर भी जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई में बहुत बड़ा काम करने का काम किया है।

सामाजिक न्याय और सोशल इंजीनियरिंग की चर्चा इस देश में बहुत होती है। संविधान के 103 संशोधन अधिनियम, 2019 में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 परसेंट आरक्षण की शुरुआत की। 103(सी ए) को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। मेडिकल एनईईटी, पीजी और यूजी में अखिल भारतीय कोटा में पहली बार ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण किया गया, इसके लिए धन्यवाद। उच्च वर्ग के गरीब की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया। मेरा मन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के बारे में बोलने का कर रहा है। पहले एससी कमीशन होता था, एसटी कमीशन होता था, माइनोंरिटी कमीशन होता था। बैकवर्ड के लोग बैकवर्ड कमीशन का नाम नहीं जानते थे क्योंकि वह दंतहीन और शक्तिहीन था, समन करने की भी ताकत नहीं थी। प्रजापति समाज की बच्ची मिट्टी का बरतन बनाने के लिए मिट्टी लेने जाती थी तो उसके साथ गलत काम नहीं होता था?

(1330/SK/UB)

तब कमीशन क्यों नहीं था? कमीशन था तो दंतहीन और शक्तिहीन था। भाई, जो नदी के किनारे बालू का काम, मछली या खेती का काम करते हैं, क्या बैकवर्ड्स के साथ एट्रोसिटीज नहीं होती थीं? क्योंकि तब कमीशन में जान नहीं थी। दंतहीन, शक्तिहीन कमीशन को माननीय मोदी जी ने कोबरा बना दिया है और इसे संवैधानिक दर्जा देने का काम कर दिया। यह बड़ा काम हो गया है।

आप हम पिछड़े, दलितों के बारे में पता है क्या सोचते थे कि ये बाईं तरफ का शून्य है, इनकी तो कोई औकात ही नहीं है। एक शेर है – जानिब का सफर हो, तुम्हारी हस्ती क्या है, चाहो तो घटा लो। अरे, मोदी जी ने कहा है कि दलित, पिछड़े, महिलाएं और जवान दाईं तरफ का शून्य हैं जिनके साथ जाते हैं, दस गुना कर देते हैं। स्टैंडिंग कमेटी जो पहले नहीं थी, बना दी और संवैधानिक दर्जा दे दिया, क्रीमी लेयर लिमिट बढ़ा दी। ओबीसी के जो लोग अपने बच्चों को जी.डी.

गोयनका, डी.पी.एस, दून, शेरवुड आदि में पढ़ा पाते थे, वे क्रीमी लेयर के चक्कर में आते थे और जो चुंगी के स्कूल में पढ़ाते थे, उनके लिए आरक्षण था, इसलिए क्रीमी लेयर को बढ़ाकर अच्छे घर के बच्चों को आरक्षण देने का काम कर दिया। यह अच्छी बात है, मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

महोदय, सबसे ज्यादा ओबीसी एमपीज़ इस पार्टी में हैं। सबसे ज्यादा एससी एमएलएज़, एमपीज़, राज्य सभा मैम्बर्स, मंत्री, जिला परिषद् अध्यक्ष, कोऑपरेटिव बैंक्स के अध्यक्ष, भूमि विकास परिषद् के अध्यक्ष हैं। आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा ओबीसी मिनिस्टर्स, एमपीज़, एमएलएज़, एमएलसीज़, राज्य सभा मैम्बर्स, मिनिस्टर्स, बैंकों के अध्यक्ष, भूमि विकास परिषद् के ब्लॉक प्रमुख हैं। अंतिम पायदान पर खड़ी कुछ जातियां हैं – पघेरे, ठठेरे, दर्जी, बुर्गी, तेली, तमोली, चौरसिया, प्रसाद, मल्लाह, बघेल, सुनार, कुर्मी, लोहार और विश्वकर्मा, ये सब अंतिम पायदान पर खड़े थे। मुझे और दीदी जी को माननीय मोदी जी ने मंत्री बनाया तो अब हमारी जाति के लोग भी शास्त्री भवन और निर्माण भवन में बैठने का काम कर रहे हैं। यह है उनके मन में पिछड़ों के लिए असली दर्द, वरना पिछड़ों के लिए बातें तो बहुत की गई हैं।

“संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावें सौ में साठा”

क्या दिया था साथ?

“अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा,
बड़े लोगों की क्या पहचान, गिटपिट अंग्रेजी टाई निशाना”

इस तरह के नारे देते रहे, अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते रहे, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई कराते रहे और हमारी कारों पर कीप डिस्टेंस की जगह, कृपया दूरी बनाकर रखें, लिखा, ऐसा दोहरा चरित्र। इसलिए मैं आज कहूंगा कि अंग्रेजी भी पढ़नी है और भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म और अध्यात्म को भी बचाकर रखना है।

महोदय, मैं भाजपा के नीति निर्धारकों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आजादी के बाद पहली बार ओबीसी तो छोड़ो मोस्ट बैकवर्ड क्लास में पैदा होने वाले हर ऋतु में, हर रेल पर चाय बेचने वाले, दस फुट के कमरे में छः भाइयों के साथ रहने वाले, दूसरों के घरों में चौका-बर्तन करने वाली मां के बेटे, महा अति पिछड़ी जाति वाले व्यक्ति को देश का प्रधान मंत्री बनाने का काम पहली बार देश ने किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।

महोदय, बचपन में सुना था कि तीसरा विश्वयुद्ध पानी पर होगा, लेकिन हो नहीं रहा है, मोहल्ला युद्ध हो रहे थे। मैं जहां पढ़ता था वहां हफ्ते में एक दिन में एक घंटे के लिए पानी आता था और मैं स्कूल छोड़कर पानी भरने आता था। 90 परसेंट बीमारियां दूषित पानी से होती हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में अरई, रजापुर, कुतुबपुर, नगलापार, चेलासली, रामगढ़, उमरगढ़, कैलाशपुर, बागई, मिलिख, गोतुआ, रेजुआ, बढालुई, सिलामुई, दुपरिया, दुसवा, कुसैत, चोरथरा, कठौता, हिनौना, नगलारूपी, नेगो, नगलारामजीत, रामनगर, जिठौली, रुदनू, वांदनू, नयाबास, फतलपुर, अगरपुर, सिखरा की जमीन में जो पानी था वही पीना पड़ता था। जल जीवन मिशन में ओवरहैड टैंक से

ट्रीटेड वाटर पिएंगे। राजस्थान में बहनें, दादियां और नानियां दिन में दो बार तीन घड़े से चार किलोमीटर दूर जाकर पानी लाती थीं और उन्होंने अपने जीवन का 40 परसेंट पानी लाने में गुजारा है। पहले क्या होता था, एक घंटे पानी आता था, बाल्टियों की लाइन लगी होती थी, गुंडे टाइप के लोग पहले आ जाते थे और पहले पानी लेते थे। मेरे जैसा आदमी खड़ा होता था और कहता था कि तुम पहले कैसे आ गए, मुझे पागल समझ रहे हो जो चार बजे से लाइन में लगा हूं। दोनों में झगड़ा हुआ, बाल्टियां चलीं, खून बहा फिर धारा 147, 148, 149, 323, 504, 306, 307 लगीं और मेरे लोकसभा क्षेत्र में धारा 302 भी पानी के कारण हो गई है। एक शेर है –

“खून इस दौरे-गरानी में बहुत सस्ता है, रात फिर गांव में कत्ल हुआ पानी परा”

दौरेगरानी का मतलब है महंगाई। पहले पानी पर मर्डर हो जाते थे लेकिन अब नल के द्वारा जल, ट्रीटेड वाटर लोग पिया करेंगे। मेरे लोकसभा क्षेत्र के लोग तो गंगाजल पिएंगे, बिस्लरी। माननीय मोदी जी की वजह से 70 किलोमीटर दूर से गंगा जल ला रहे हैं।

(1335/KDS/SRG)

जब तक सूरज-चांद रहेगा, गंगा में पानी रहेगा। आगरा और लोक सभा के लोग गंगाजल पिएंगे। मैं सपा और बसपा में चार बार एमपी रहा। मैं वहां क्या करता रहा? जिंदगी बरबाद हो गई। सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खड़जा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, शादी-ब्याह, तेरहवीं, भागवत कथा, रसिया, दंगल, कव्वाली, कुआं पूजन, एकादशी का व्रत करने में अपनी पूरी जवानी निकाल दी। पहली बार वर्ष 2019 में जब से भाजपा से जीतकर आया हूं, तो अगर अनुच्छेद 370 हटा है, तो उसमें मेरी भी भागीदारी है, दीदी की भी भागीदारी है। तीन तलाक हटा है, तो हमारा भी हाथ है। समान नागरिक आचार संहिता हमने भी हटाया है। पुरानी वाली आईपीसी, सीआरपीसी मैं पढ़ता था। अब तो धारा 302 भी नहीं पढ़नी है, धारा 301 पढ़नी है। यह अंग्रेजों ने बनाई थी। सन् 1861 से कूप मंडूक बने चले आ रहे थे। जो हमारे लिए इर-रिलेवंट कानून थे, ऐसे लगभग 1 हजार कानूनों में आपने मोदी जी के नेतृत्व में आग लगा दी है।

साहब, किसी ने तीन बार बोल दिया तलाक, तलाक, तलाक और तलाक दे दिया, जबकि हमारी एक जोड़ी चप्पल घिस जाती थी। क्या शादी जैसे बंधन को कोई तीन शब्दों में कहकर समाप्त कर देगा? अगर अपने-आप को आप 14-20 करोड़ की आबादी कहते हैं, तो उनमें से आधी आबादी को मोदी जी ने, अमित शाह जी ने तीन तलाक हटाकर न्याय देने का काम किया है। बताइए, बड़ा काम हुआ या नहीं हुआ? मियां, अब तीन बार कहकर तलाक नहीं हो पाएगा। आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, वकील करना पड़ेगा और सिद्ध करना पड़ेगा। आपकी एक जोड़ी चप्पल घिस जाएगी, तब जाकर बड़ी मुश्किल से तलाक ले पाओगे। एक बहुत अच्छा शेर है-

“तलाक दे तो रहे हो गुरुर और कहर से, मेरा हुस्न भी लौटा दो मेरी मेहर के साथ।”

मुस्लिम महिलाओं को यह सब झेलना पड़ता था और वे बेचारी सड़क पर पहुंच जाती थीं। चाणक्य जी ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हमारे दुश्मन के दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुरभि संधियां, दुरभि सम्मेलन

किया करेंगे। ऐसा ही एक 'इंडी' आकार ले रहा है तथा जो नेतृत्वविहीन, नीतिविहीन व सिद्धांतविहीन हो रहा है। ऐसी शादियां हनीमून नहीं मना पाती हैं, उसके पहले ही तलाक हो जाता है।

महोदय, मेरे और आपके लोक सभा क्षेत्र में ठंड में तापते हुए किसान आजकल एक चर्चा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि एक-दूसरे को गाली देने वाले आखिर क्यों साथ आ रहे हैं? आखिर मोदी जी ने ऐसा क्या बुरा काम किया है कि उसके लिए सब एक हो रहे हैं, तो जनता कह रही है कि अगर तुम गठबंधन करोगे, तो आग से तापने वाली सातों जातियां वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक का भी गठबंधन है कि हम मोदी जी को एक सुरक्षा कवच देने का काम करेंगे और तुम्हारी 'इंडिया' का कुछ नहीं हो पाएगा। भय, भगदड़, भ्रम चुनाव होने से पहले होता है। आधी हिंदी तो आपकी समझ में आ नहीं रही होगी, वर्ना आपको मजा आ जाता। यह भय, भगदड़ और भ्रम मोदी जी की लोकप्रियता के कारण है। जहाज के कप्तान मुल्ला ने 32 लोगों को बचाने के बाद जल समाधि ले ली थी, क्योंकि कैप्टन की परम्परा है कि वह नहीं भागता है, लेकिन इस भय, भगदड़ और भ्रम से अच्छे-अच्छे कप्तान भागेंगे। यह प्रधान मंत्री का सपना देखते थे। 6 बार चुनाव जीतने के बाद भी तेलंगाना वालों का चुनाव चिह्न नहीं पता है। वे अपने मोहल्ले में ही निपट गए। इस देश का प्रधान मंत्री बनने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और 100 परसेंट ईमानदार होना पहला गुण है, जो मैं दूरबीन लगाकर आपकी तरफ दूँड रहा हूँ, लेकिन आपकी तरफ दिखाई नहीं पड़ रहा है।

महोदय, यूपी में वे जमाने गए, जब सपा और बसपा का शासन हुआ करता था। समाजवादी पार्टी ने 16 टिकट घोषित कर दिए और इनके राजकुमार से पूछा ही नहीं, उसमें उन्होंने अपने घर के ही तीन टिकट कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों, डरने की जरूरत नहीं है। जब सपा के परिवार ने टॉप की 5 सीटें आजमगढ़, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कन्नौज और बदायूं चुनीं तथा बहन जी से डेढ़ लाख का चेक लिया, इसके बाद भी तीन लोग हारे हैं। अब वह गठबंधन भी नहीं है। सपा-बसपा, सपा-बसपा हुआ करता था। वर्ष 2014 में मोदी जी आ गए। पहले हुआ करता था-

... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

अब यूपी बारी-बारी नहीं लुटेगी।

सर, अगर आप मुझसे पूछें कि मैंने पहली बड़ी बात तो आयुष्मान कार्ड बता दिया, लेकिन दूसरी क्या है? मैं दूसरी बड़ी बात मानता हूँ केंद्र सरकार की समस्त नॉन गजटेड नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त होना। भारत सरकार न में ए, बी, सी और डी चार ग्रुप होते हैं। ए में इंटरव्यू होगा, बी में गजटेड होगा, सी और डी का इंटरव्यू नहीं होगा। भाजपा शासित राज्य यूपी में समूह क, ख, ग, घ होगा। गजटेड में इंटरव्यू होगा, नॉन गजटेड में इंटरव्यू नहीं होगा।

(1340/MK/RCP)

अब एक बच्चे ने कहा, चाचा इंटरव्यू समाप्त होने के बारे में बहुत बोल रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि इंटरव्यू लेने के लिए नहीं होते थे।

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): अब आप समाप्त कीजिए।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : महोदय, इनकी सरकार में इंटरव्यू निकालने के लिए होते थे। लेना है तो आगरा की स्पेलिंग बताओ और नहीं लेना है, तो चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताओ। चेकोस्लोवाकिया की बताने के बाद भी नहीं लगी थी, बंदरबांट हो जाती थी। हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट को हमारी पीढ़ी के लोग पॉलिथीन में मढ़वा के रखते थे, रोजगार कार्यालय जाते थे, लिखित परीक्षा पास करते थे, पिताजी के पास नोट नहीं थे और बराबरी पर बड़ा नेता नहीं था जो मुख्य मंत्री की सूची में हमारा नाम लिखा देता। इसलिए, हमारे बड़े भाई लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि सूची चलती थी। अब आ रहा है तो कोई ले नहीं पाएगा और कोई नहीं ले रहा है तो कोई आ नहीं पाएगा।

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, कृपया अब आप समाप्त कीजिए।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : महोदय, माननीय मोदी जी ने 10 लाख नौकरी का वादा किया था। 70 हजार हर महीने देते हैं। आप भी गये हैं, मैं भी गया हूँ, बहन जी, आप भी गई हैं। ... (व्यवधान) बिना पैसे के, बिना रिश्त के, बिना जाति को देखे हुए, बिना गोत्र को देखे हुए, बिना इटावा को देखे हुए, बिना जिले को देखे हुए, बिना अमेठी को देखे हुए, बिना रायबरेली को देखे हुए योग्यता के आधार पर सेलेक्ट होकर आ रहे हैं। आप भी अपने वर्कर से कह दीजिए कि बिना इंटरव्यू के नौकरी लग रही है। प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान मंजूषा, हिन्दी के अखबार, 'दि हिन्दू' अखबार, टेलीविजन की न्यूज और खन्ना-वर्मा की जी. के. की किताब अगर तुम्हारे बच्चे 8 घंटे पढ़ लेंगे तो मोदी जी की बिना इंटरव्यू की पचास हजार की रुपये नौकरी तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाएगी। मैं गारंटी ले रहा हूँ।

महोदय, पशुपालन हमेशा पैरेलल इकोनॉमी रही है। 70 परसेंट दुग्ध उत्पादन बढ़ गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी बहनों को बचाने के लिए और बकरियों को बचाने के लिए मोदी जी ने निःशुल्क गोट वैक्सीन और ब्रुसेलोसिस फ्री, शीप पॉक्स और गोट पॉक्स का इंतजाम किया है। फुट और माउथ डिजीज रोकने के लिए लगभग 12 करोड़ वैक्सीनेशन लगाने का काम किया है। इससे एक क्रांति आ जाएगी।

महोदय, मैं सेक्स सॉर्टेड सीमेन के बारे में देश को बताना चाहता हूँ। मोदी जी की सरकार वर्गीकृत वीर्य से गायों के बच्चे कृत्रिम गर्भाधान से पैदा कर रही है। आपको मालूम है रिजल्ट क्या आया है? 92 परसेंट बछिया पैदा हो रही है। मैंने सुना है दूध की नदियां बहती थीं। वे बह जाएंगी, अगर देश के किसान मेरी आज की बात को मानकर अपनी गाय का कृत्रिम गर्भाधान वर्गीकृत वीर्य से कराएंगे तो एक गारंटी है कि साहिवाल की बछिया पैदा होगी, थारपारकर की होगी, गिर की होगी और हरियाणवी गाय होगी तथा वह 12 साल तक जिन्दा रहेगी। अगर बछड़ा पैदा हो गया, तो अब न हल चलते हैं, न बैलगाड़ी चलती है और न दाईं चलती हैं, न रहट चलती है और दाईं तो तुम्हारा नेता जानता भी नहीं होगा कि दाईं किसे कहते हैं। इसलिए, बछिया पैदा होगी तो दूध की नदी बहेगी और बछड़ा पैदा होगा तो मशीन के आने से अभी जो यूजलेस है, वह प्राइसलेस हो गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि गोट, भेड़ और देसी गाय पालने के लिए 50 लाख रुपये की सब्सिडी है।

महोदय, नागरिक उड्डयन को ले लीजिए, एक दिन माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे। 517 नये रास्ते ढूँढ़ लिये हैं। एक हजार नये एयरक्रॉफ्ट आ रहे हैं। आगरा में सिविल एयरपोर्ट बन रहा है। पर्यावरण ने क्लीयरेंस दे दी है, टेंडर हो गया है और मोदी जी के कार्यकाल में, जो पहले एक भी नहीं चलती थी, अब आगरा से लखनऊ, आगरा से बैंगलोर, आगरा से अहमदाबाद, आगरा से जयपुर और एक-दो भूल रहा हूँ, इन सभी जगहों से फ्लाइट शुरू हो गई है। आपने पैसा दे दिया है, हमने जमीन इकट्ठी कर ली है, केंद्र ने पर्यावरण की स्वीकृति दे दी है और टेंडर भी हो गया है। देश का कोई भी व्यक्ति यदि भारत में पर्यटन की दृष्टि से आता है तो वह आगरा का ताजमहल देखने के लिए आता है और बाद में अन्य जगह जाता है। अब हम हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

महोदय, 'इसरो', अब चंदा मामा दूर के नहीं रहे। आपको पता है वर्ष 2013 में हॉलीवुड की एक फिल्म 'इंटरस्टेलर' बनी थी, जिस पर 1,300 करोड़ रुपये की लागत आई थी। रील की कीमत 1,300 करोड़ रुपये और रियल की कीमत 615 करोड़ रुपये आई है। 615 करोड़ रुपये में चंद्रयान पहुंच गया है। चलो आप तो अंतरिक्ष में भी ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) करते थे। हम विश्वगुरु थे, हम नहीं हैं, हम बन जाएंगे।

महोदय, वर्ष 1192 हमारे लिए बहुत खराब था। जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। भारत की सभ्यता-संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, हमारे अविष्कार, हमारे विश्वगुरु, हमारा साहित्य संगीत कला, लोक कला और लोक भाषा पर कुठाराघात हुआ है। उसके बाद मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक, सिकन्दर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायुं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद हुणों ने, यवनों, फ्रांसीसियों ने, डचेज ने और ब्रितानिया हुकूमत ने, हम विश्वगुरु थे, हमारे कर्ण के पास बुलेटप्रूफ जैकेट थी, जे. एल. बेयर्ड ने टेलीविजन बाद में बनाया, कुरुक्षेत्र के युद्ध को संजय हस्तिनापुर में सुना रहे थे। मॉर्कोनी ने रेडियो बाद में बनाया है, हमारे पास द्वापर में था। जब कंस अपनी प्यारी बहन को लेकर मेरी लोक सभा से गुजर रहा था तो आकाशवाणी हुई थी कि जिसको ले जा रहा है, उसका पुत्र तुम्हें मार देगा। मॉर्कोनी ने रेडियो बाद में बनाया है। हमारे पास पहले से था।

(1345/SJN/PS)

महोदय, सन् 1903 में राइट ब्रदर्स ने जहाज बनाया था। हमारे विश्वकर्मा जी ने पुष्पक जहाज बनाया था, जिसे रावण हाईजैक करके ले गया था। इसी प्रकार से फायरप्रूफ जैकेट की वजह से प्रह्लाद बच गया था और उसकी बुआ मर गई थी। कर्ण के पास बुलेटप्रूफ जैकेट थी। हम विश्व गुरु थे, अब हम नहीं हैं, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में हम विश्व गुरु जरूर बनेंगे... (व्यवधान) इसलिए मैं कहना चाहता हूँ... (व्यवधान)

मित्रों, आज की तारीख, स्थान और समय नोट कर लेना, हम रहें या न रहें, जब वर्ष 2047 में देश आज़ादी के 100 साल मना रहा होगा, तब हम नंबर एक सुपर पावर होंगे। हम नंबर वन

इकोनॉमी होंगे और हम विकसित राष्ट्र होंगे। मेरी भाषा में हमारी चौधराहट भी दुनिया के देशों में होगी। ये मेरे अपने शब्द हैं।

बाबासाहेब ने क्या था? शिक्षित बनो, संगठित रहो तथा संघर्ष करो। क्या कभी ऐसा कहा था कि संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो? जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता है। सत्ता वह चाबी है, जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है। मैंने भी 5-6 बार खोला है, लेकिन शिक्षा वह चाबी है, जिससे जंग लगे हुए ताले भी खुलते हैं। दीदी के कार्यकाल में कुछ ताले खुले थे, जब वह एचआरडी मिनिस्टर थीं। आपने जितने आईआईटीज़ बनाए हैं, हमने उससे पांच गुने ज्यादा बना दिए हैं। आपने जितने आईआईएम्स बनाए थे, हम 10 सालों से उससे चार गुने ज्यादा बना दिए हैं। आपने जितने एम्स बनाए थे, हमने उससे तीन गुने ज्यादा बना दिए हैं। आपने जितनी लॉ यूनिवर्सिटीज़ खोली थीं, हमने उससे चार गुनी ज्यादा खोल दी हैं।... (व्यवधान)

हमारी सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी जेएनयू मार्क नहीं है।... (व्यवधान) क्या जी-20 छोटी-मोटी बात थी? जब तुम्हें गांवों में अपनी पंचायत करनी पड़ती है, तो अपने आपको बहुत लाट साहब समझते हो कि हमें पंचायत करनी पड़ रही है। हमने तो 100 देशों के साथ पंचायत की है। जी-20 के द्वारा हमने भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म्य, गीता, पुराण, महाभारत, लोकभाषा, लोकभोजन, लोकभूषा, लोकनृत्य, लोकगीत, लोकसंगीत, हमने अपने विज्ञान और प्रगति को दुनिया के 100 देशों से ऊपर बताने का काम किया है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए अन्यथा अगले वक्ता का नाम बोल दिया जाएगा।

... (व्यवधान)

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : महोदय, आपने पहली बार टोका है। मेरी ससुराल आपके यहां है, थोड़ा-सा ख्याल रखिए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको उसी के कारण इतना समय मिल गया है।

... (व्यवधान)

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : महोदय, गरीब देश के नेता के आंखों में आंसू थे, उन्होंने मोदी जी को गले लगा लिया।

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

... (व्यवधान)

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : महोदय, काश मेरी अंग्रेजी अच्छी होती, क्योंकि मेरे मित्र जानते हैं कि मैं कितना अच्छा बोल रहा हूँ। ये सब कैसे हो गया? जो हिना जी और मैंने बताया है, अभी और भी 10-12 लोग बोलेंगे, ये कैसे हुआ? मोदी जी गरीब घर में पैदा हुए थे।

महोदय, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित 'पूस की रात' एक कहानी है, जिसको डनलप पिलो पर सोने वाले, एसी में रहने वाले, राडो की घड़ी पहनने वाले, लोड्डो का जूता पहनने वाले और मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा होने वाला तुम्हारा नेता उसको रटकर 90 प्रतिशत नंबर ला सकता

है, लेकिन उसके दर्द को वही समझ सकता है, जिसने पूस की एक ठंडी रात एक पिछौरा में काटी है, नरेन्द्र मोदी जी ने काटी है। वह 10 बाई 12 के कमरे में रहे हैं।

इसलिए मैं इस लोक सभा के माध्यम से भगवान से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक डेमोक्रेसी रहे, जब तक चुनाव हो, तब तक इस देश का प्रधानमंत्री महागरीब बनाना, लेकिन शर्त यह है कि दिल्ली आकर उसको गरीबी याद रहे। जैसे मोदी जी को याद है। इसलिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर बोलने के लिए एक घंटे का समय भी कम है। आप कल के बजट को विदाई कह रहे थे... (व्यवधान) ये दूसरी पारी का लास्ट इंटरिम बजट है... (व्यवधान)

माननीय सभापति : बघेल साहब, अपनी बात समाप्त कीजिए।

... (व्यवधान)

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : आप सुनिए तो... (व्यवधान) प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं, बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से नरेन्द्र मोदी जी मई की किसी तारीख में 400 एमपीज के साथ इस नए भवन को प्रणाम करते हुए ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) आएं... (व्यवधान)

माननीय सभापति : ऐसे शब्द मत बोलिए।

... (व्यवधान) ... (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

... (व्यवधान)

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : महोदय, 'होइहि सोइ जो राम रचि राखा'।... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर) : महोदय, ये लोक सभा की मर्यादा का अपमान कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

... (व्यवधान)

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : महोदय, हमारी अच्छी पैरवी से, हमारे अच्छे वकीलों से, हमारे धर्माचार्य, शंकराचार्य, आचार्य और प्रचारों से... (व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मंदिर के पक्ष में आया है। न्यास बना रहा है, लेकिन करोड़ों का हवाई अड्डा सरकार बना रही है। हम विश्वस्तर का काम कर रहे हैं और सरयू के घाट को पक्का कर रहे हैं। एक दिन में एक लाख लोग आ रहे हैं। मां शबरी के नाम पर डाक टिकट जारी किया है। हम अपने पुरखों को नहीं भूलते हैं। केवट महाराज के नाम पर डाक टिकट जारी करने के अलावा... (व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए –

‘कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 31 जनवरी, 2024 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।’

(1350/SPS/SMN)

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संशोधनों के बारे में घोषणा

1350 बजे

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : माननीय सदस्यगण, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जिन माननीय सदस्यों के संशोधन परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने संशोधनों को प्रस्तुत करने के इच्छुक हैं तो 15 मिनट के अंदर सभा पटल पर अपनी पर्चियां भेज सकते हैं, जिनमें उन संशोधनों की क्रम संख्या दर्शायी गई हो, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : केवल उन संशोधनों को ही प्रस्तुत किया गया समझा जाएगा, जिनके संबंध में पर्चियां विनिर्दिष्ट समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त होंगी। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए संशोधनों की क्रम संख्या को दर्शाने वाली सूची कुछ समय पश्चात् सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी। सदस्य यदि सूची में कोई विसंगति पाते हैं तो वे कृपया इसे तत्काल सभा पटल पर अधिकारियों के ध्यान में लाएं।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Chairman Sir, I am on a Point of Order.

माननीय सभापति : आप नियम बताइए।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Chairman Sir, I am on a Point of Order under Rules 17 and 20 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha and also Articles 86 and 87 of the Constitution of India.

Sir, I do agree that there is no rule specifically prohibiting the Minister in seconding the Motion expressing thanks to the Presidential Address. I do agree but if you go through Rule 17, it is very specific that the Motion of Thanks has to be moved by a Member and seconded by another Member. There also, I agree that the Minister is also a Member of the House. I have no dispute about it.

Now I come to Rule 20. In Rule 20, the Prime Minister or any other Ministers have a right to give explanation or reply to the discussions at the conclusion of the discussion. Further, it says that the Mover or the Seconder shall not have any right of reply after the Prime Minister or any other Minister has explained the position of the Government at the end of the discussion.

If you go through Rules 17 and 20, it is very clear that the Motion has to be moved by a Member and has to be seconded by another Member. Why I am saying is that the Presidential Address is approved by the Cabinet. So, the Cabinet has approved and that has to be moved. The Motion of Thanks has to be given by a Member and supported by another Member. This is a question of propriety also. The Minister coming and seconding the Motion of the House is not proper on the part of the Government. There is no convention also.

There is one convention of 2014. It is quite unfortunate that it is the right of the Member other than the Minister but unfortunately, the Minister coming and seconding the Motion is not proper. It is a question of propriety. I am seeking a ruling from the Chair.

माननीय सभापति : ठीक है, इसको देख लेंगे। हालांकि, ऑनरेबल स्पीकर के माध्यम से ही यह स्वीकृति हुई है और उन्हीं की अनुमति दी गई है, लेकिन तब भी आपकी आपत्ति को माननीय स्पीकर तक पहुंचाकर इसके संबंध में हम लोग स्पष्टीकरण करवा देंगे।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : प्रेमचन्द्रन जी, यह डिस्मिज़न परंपराओं और नियमों को देखकर ही हुआ है तथा इससे पहले भी यह होता रहा है। ...
(व्यवधान)

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव - जारी

1353 बजे

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर) : सभापति महोदय, धन्यवाद। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आज धन्यवाद प्रस्ताव के संदर्भ में मैं खड़ा हुआ हूँ। ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) ... (व्यवधान) इस सदन की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन हमने पहली बार संसद के अंदर आदरणीय राष्ट्रपति जी को देखा।

1354 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) आप पिछले ही सत्र का उदाहरण ले लीजिए। पिछले ही सत्र में सदन में हमने देखा कि... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सर, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है।

माननीय अध्यक्ष : आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है?

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सर, नियम 352 (6) के अंतर्गत है। इन्होंने राष्ट्रपति महोदया की बातों को तोड़-मरोड़कर पेश किया है। राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि वह पहली बार दोनों सदनों को संबोधित कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया साल में केवल एक बार संबोधित करती हैं और वह मौका उनको मिला।

(1355/MM/SM)

अब इसके उद्घाटन में वे आयीं या नहीं आयीं, इस पर डिबेट को वह जो इनफ्लूएंस कर रहे हैं, उसको एक्सपंज करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : इसको चैक कर लेंगे।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): हम इसी परम्परा की बात कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष के मंत्री, सत्ता पक्ष के सांसद, जब भी उनका मन चाहे खड़े होकर आरोप लगा सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं है, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के विषय के अनुसार मौका दिया है।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सर, विपक्ष जब अपनी बात रखना चाहे तो हमें चिट्ठी भेजनी पड़ती है, हमें रुकना पड़ता है। आज सुबह भी हमने यही देखा कि आदरणीय संसदीय मंत्री ने एक सांसद, जो आज नहीं हैं, उन्होंने सदन के बाहर कोई वक्तव्य रखा और उस पर उन्होंने मीडिया पर निर्धारित जो कुछ बातें आयीं, उस पर अपनी बातें रखीं। लेकिन हम उस पर अपना विरोध नहीं जता पाए। संसदीय मंत्री बार-बार कहते हैं और आप भी कहते हैं कि जो सदन के बाहर बातें कही जाती हैं, मीडिया के सूत्रों के आधार पर बातें हमें अंदर नहीं रखनी चाहिए। आप ही के निर्देश का उल्लंघन संसदीय मंत्री करते हैं और आपके संरक्षण में हम अपनी बात नहीं रख पाते हैं। यही हो रहा है, सर। पिछले सत्र में भी जब कुछ युवा बेरोजगारी के नारे लगाते हुए सदन के अंदर घुसे और हमने बात उठायी और हमने केन्द्रीय गृह मंत्री जी जानने की कोशिश की कि यह घुसपैठ कैसे हुई तो केन्द्रीय गृह मंत्री ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। ... (Expunged as ordered by the Chair)... (व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, यह आप पर भी आरोप लगा रहे हैं। संसद की व्यवस्था, लोक सभा की व्यवस्था को देखना स्पीकर के कार्यालय का काम है। यह आप पर भी आरोप लगा रहे हैं, चेयर को भी नहीं छोड़ रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप राष्ट्रपति के अभिभाषण के विषय पर, नीतियों पर और कार्यक्रमों पर अपनी बात बोलें।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सर, यह बहुत दुख की बात है, आप उस समय सदन में नहीं थे, जब पूर्व में वक्ता बोल रहे थे। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने जितना लंबा भाषण दिया, उससे दोगुना लंबा भाषण इन दोनों ने दिया। किन-किन विषयों पर दिया, आप उस समय नहीं थे, मैं आशा करता हूँ कि आप उसे सुनते। ... (*Expunged as ordered by the Chair*) ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से अपेक्षा करूँगा कि वे सदन के किसी भी निर्णय पर जो सदन ने लिया है, उस पर टिप्पणी न करें तो उचित होगा।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सर, हम इस सदन को लोकतंत्र का मंदिर कहकर सम्मानित करते हैं। लेकिन वर्ष 2014 के बाद धीरे-धीरे एक सुनिश्चित योजना सत्ता पक्ष के द्वारा देख रहे हैं। अब यह सदन या यह संसद ... (*Expunged as ordered by the Chair*) ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और आप संसद पर ही आरोप लगा रहे हैं। जिस संस्था में आप बैठे हैं, यह संस्था एक पवित्र सदन है। आपको सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं?

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): He is not alleging the House. His allegation is also not against the Chair. This Government is undermining the value of the House.

माननीय अध्यक्ष : आपने संसद पर सवाल उठाया है, पार्लियामेंटरी सिस्टम पर सवाल उठाया है।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सर, मैं सदन की मर्यादा और भारत के संसदीय इतिहास की मर्यादा के संरक्षण में बोल रहा हूँ। मैं सत्ता पक्ष की सुनिश्चित योजना की बात कर रहा हूँ। क्योंकि यहां पर जब भी ... (*Expunged as ordered by the Chair*) आते हैं तो सारे सांसद खड़े होकर ताली बजाते हैं, उनका जयकार होता है। जिस जिम्मेदारी के लिए हम आते हैं, उस जिम्मेदारी को हम भूल जाते हैं। ... (*Expunged as ordered by the Chair*) भी आते हैं, कुछ क्षण बैठते हैं और फिर वे चले जाते हैं, विदाई देते हैं। लेकिन एक भी सवाल का उत्तर नहीं देते।

(1400/YSH/RP)

सर, इससे पहले भी इस सदन में और इस संसद में बहुत से प्रधान मंत्री आए हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलिए। ... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सर, हम इस संसद की बात कर रहे हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप संसद के निर्णय पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सर, हम इस संसद की बात कर रहे हैं। इस संसद के इतिहास की बात कर रहे हैं। इस संसद के इतिहास में बहुत से प्रधान मंत्री आए हैं। सभी प्रधान मंत्रियों ने अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन हम पहली बार एक ऐसे... अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, यह गलत है।

... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) ... (व्यवधान) अभी तो शुरुआत हुई है। आप धैर्य रखिए। दो घंटे से हम आपकी बातें सुन रहे हैं, अब आप भी सुनने का धैर्य रखिए... (व्यवधान) हम दो घंटे से बैठे हुए हैं। अब हमारी बारी है। आप सुनने का धैर्य रखिए... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप नीतियों पर, कार्यक्रमों पर कितनी भी तीखी आलोचना कीजिए, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि सदन के निर्णयों पर ऊँगली मत उठाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सदन के निर्णयों पर ऊँगली नहीं उठा सकते हैं।

... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सर, मैं एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहता हूँ। रूल नम्बर 378 के अनुसार स्पीकर द्वारा हाउस में जो डिस्मिशन लिए जाते हैं, उस पर कोई भी चर्चा नहीं हो सकती है और कोई भी आरोप नहीं लग सकता है। रूल नम्बर 378 यही कहता है। आप रूल नम्बर 378 के अनुसार सारी स्पीच एक्सपंज करवाइए... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): भाजपा के दूसरे वक्ता ने देश के भूतपूर्व प्रधान मंत्री पर आरोप लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उनको रोका नहीं गया। महिलाओं पर आपत्तिजनक बातें की गईं, तब यहां पर उनको रोका नहीं गया। मैं आपके सामने बस तथ्य रख रहा हूँ... (व्यवधान) ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

माननीय अध्यक्ष : आप महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोल रहे हैं या संसद पर बोल रहे हैं?

... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: ये लोक सभा पर टिप्पणी कर रहे हैं और स्पीकर के लिए भी बोल रहे हैं। पीठ पर बोल रहे हैं... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) लोगों को भ्रमित करने के लिए भ्रम बहुत जरूरी है। इसमें तो ये माहिर हैं। यह सरकार तो इवेंट मैनेजमेंट में डॉक्टर है। लोग इवेंट मैनेजमेंट कहते हैं, लेकिन मैं अटेंशन मैनेजमेंट कहता हूँ। इन्होंने अटेंशन मैनेजमेंट में पीएचडी की है कि कैसे लोगों का ध्यान भटकाया जाए।

हम कहते हैं कि मणिपुर में प्रधान मंत्री जी क्यों नहीं गए, 190 लोगों की मृत्यु हुई, 50 हजार लोग बेघर हुए तो वे कहते हैं कि जी-20 देखिए। प्रधान मंत्री जी पेरिस में हैं तो वह देखिए। हम कहते हैं कि नोटबंदी में 100 लोगों की मृत्यु हुई तो इसका जिम्मेदार कौन है? वे कहते हैं कि पेट्टीएम का इश्तेहार आया है, उसमें मोदी जी का चेहरा है तो आप उसे देखिए। हम कहते हैं कि चाइना आज हमारी जमीन पर घुस आया है और चाइना लद्दाख में हमारे किसानों के साथ मुठभेड़ कर रहा है, ये कहते हैं कि आप देखिए कि मालद्वीव की तुलना में हम कितने ताकतवर हैं।

... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) हर वर्ष लगभग 10 हजार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। युवा कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं। महिलाएं कह रही हैं कि हम महंगाई से मर रही हैं। आज आर्थिक असमानता बढ़ रही है। गरीब और गरीब तथा अमीर और अमीर हो रहा है। आज हमारे देश के 10 प्रतिशत लोग 50 प्रतिशत धन सम्पत्ति के मालिक हैं और ये कहते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लार्जस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है तो ये लोगों की समस्याओं पर पर्दा डालने के लिए भ्रम का इस्तेमाल करते हैं। ये लोक शक्ति को कमजोर करने के लिए भ्रम का इस्तेमाल करते हैं।

(1405/RAJ/NKL)

आज ये लोगों को माया जाल में फंसा कर राजा को और ताकतवर बनाने का काम करते हैं। सर, प्रधान मंत्री जी एक साधारण घर से आते हैं, मैं उनका आदर करता हूँ। वे बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए हैं, लेकिन दुःख की बात यह है कि आज उन्होंने अपना सिंहासन इतनी ऊंचाई पर बना दिया है कि आज जमीन पर रहने वाले लोगों की समस्या उनके कानों तक नहीं पहुंचती है। उनको बेरोजगार युवाओं के आंसू दिखाई नहीं देते हैं। वे इतनी ऊंचाई पर हैं कि आज जब युवा कहता है कि हम शिक्षित हैं, लेकिन 25 वर्ष की आयु से कम जो ग्रैजुएट्स हैं, उनमें से लगभग 42.3 प्रतिशत ग्रैजुएट्स बेरोजगार हैं, ये उनके कानों तक नहीं पहुंचता है। आज हमारे युवा नौकरी की तलाश में अवैध रूप धारण करके अमेरिका जा रहे हैं। हम ने कुछ ही दिनों पहले देखा कि 303 लोग चार्टर प्लेन से निकारागुआ तक गए, क्योंकि वे रोजगार की तलाश में अमेरिका जाना चाहते थे। कुछ दिनों पहले 'डंकी' पिकचर आई थी। डंकी सिर्फ एक पिकचर नहीं है, बल्कि डंकी एक सच्चाई है। पिछले पांच वर्षों में सरकार ने खुद यह कबूल किया है कि अमेरिका में अवैध रूप से भारतीय नागरिकों का जाना बढ़ चुका है। वर्ष 2022-23 में लगभग 90 हजार भारतीय लोगों ने अवैध तरीके से अमेरिका में कभी कनाडा के बॉर्डर से, कभी मैक्सिको के बॉर्डर से घुसने की कोशिश की। वे कितने मजबूर होते हैं कि अपने परिवार को छोड़ कर, अपने घरों को छोड़ कर रोजगार की तलाश में कभी यू.एस. जाते हैं, तो कभी कनाडा जाते हैं और कभी अमेरिका जाते हैं। आज यह आर्थिक स्थिति है लेकिन ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं कि उनको यह नहीं दिखता है।

सर, बहुत दुःख की बात है कि मानव तस्करी बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आज आदिवासियों के गांवों में उत्तर-पूर्वांचल के गांवों में गरीब परिवारों का फायदा उठा कर मानव तस्करी करने वाले लोग जाते हैं और कहते हैं कि आप हमें अपनी बेटियों का दायित्व दो, अपने घर

की महिलाओं का दायित्व दो। आज मानव तस्करी करने वाले ये लोग उन बेटियों का शोषण करते हैं। आज वे उन महिलाओं का शोषण करते हैं। Human trafficking has become a major problem. यह human trafficking क्यों है, क्योंकि आज लोग गरीब और बेसहाय हैं। यह वास्तविक स्थिति है।

सर, आज हमारे सेना का जवान पूछ रहा है कि चार सालों बाद हमारा क्या होगा? अग्निवीर की योजना किसने बनाई है? हम कहां जाएंगे? यह नीति सेना के अंदर से नहीं आई है। बाहर का वह कौन विशेषज्ञ है, जिसने अग्निवीर की योजना बनाई है? आज ये बार-बार कहते हैं कि बाहर से छात्र-छात्राओं को बचाया है। हमने उन्हें बचाया, लेकिन उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, लेकिन सर क्या आपको पता है कि आज मेडिकल के छात्रों को पढ़ाई के लिए करोड़ों रुपए की फीस देनी पड़ती है। उनके पास करोड़ों रुपए नहीं हैं, इसलिए आज वे फिलीपींस, कजाकिस्तान, यूक्रेन, रशिया और चीन जाते हैं। क्योंकि यहां पर मेडिकल कॉलेज में करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं और वहां से लाखों रुपए में वे अपनी एमबीबीएस की डिग्री लेकर यहां आते हैं। यह वास्तविक स्थिति है।

आज महिलाएं पूछती हैं कि जब भी भारत की बेटी अन्याय के खिलाफ लड़ती है, तो वह क्यों अकेली लड़ती है, क्यों बिलकिस बानो अकेली लड़ती है? क्यों बिलकिस बानो के संबंध में एक विशेष राज्य सरकार उनके बलात्कारियों का पक्ष लेती है। महिला खिलाड़ी पूछती है कि मैं लड़ सकती हूँ, मैं लड़की हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई रहे। मैं क्यों अकेली पड़ गई हूँ? वे व्यक्ति कहां है? जब मैं पदक जीतती हूँ, तो वे मेरा स्वागत करते हैं। आज मैं दिल्ली की सड़कों पर धरना दे रही हूँ। आज मैं अकेली हूँ। क्यों आज बेटी अन्याय के खिलाफ अकेली है?

किसान पूछ रहा है कि आज हर किसान पर लगभग 70 हजार रुपए का कर्ज है। उनको एमएसपी की कानूनी सुरक्षा नहीं मिली। आज किसान देख रहा है कि उनको जो उचित मूल्य मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। किसान न्याय की मांग कर रहा है। आप लाभार्थी की बात करते हैं।

सर, आज भ्रष्टाचार ऐसा हो चुका है कि एक नया लाभार्थी टैक्स शुरू हो गया है। अगर आवास योजना का घर चाहिए तो पहले लाभार्थी टैक्स दो। अगर पीएम किसान में अपना नाम शामिल करना है, तो लाभार्थी टैक्स दो। अगर उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर चाहिए तो लाभार्थी टैक्स दो। यह वास्तविक स्थिति है। लेकिन इस स्थिति को लेकर कोई बात नहीं करते हैं।

(1410/KN/VR)

यहां पर कोई इनवेस्टिगेशन नहीं। पीएम किसान सम्पदा योजना में पहले 11 करोड़ लोगों को लाभ मिलता था, वह 11 करोड़ से 3 करोड़ क्यों हुए? वह संख्या क्यों घटी? वहां पर कितने सारे फर्जी लाभार्थी थे, क्या उस पर कोई इनवेस्टिगेशन हुआ? उस पर कोई इनवेस्टिगेशन नहीं। सारी चीजें भूल जाते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार गायब हो गया है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आपके लाभार्थियों के वितरण में हो रहा है।

सर, आज मैं खुश हूँ कि जनता जागरूक हुई है और विपक्ष आज जनता के इस जागरण का स्वागत करता है। आज़ादी की लड़ाई भी एक जन आंदोलन था और आज भी अगर राजतंत्र से आज़ादी पानी है तो विपक्ष देश की जनता के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। ... (*Expunged as ordered by the Chair*) को यह पसंद नहीं, ... (*Expunged as ordered by the Chair*) विपक्ष को कमजोर करना चाहता है। इनकम टैक्स के अफसर भेजते हैं, ईडी का अफसर हमारे पास आता है, सीबीआई का अफसर हमारे पास आता है। मैं ... (*Expunged as ordered by the Chair*) से यही कहना चाहता हूँ कि हम डरने वाले नहीं हैं। आप चाहे जितनी भी सरकार गिरा लो, आप चाहे जितनी भी सरकार का परिवर्तन कर लो। अगर बिहार में सरकार बनानी है तो रातों रात मुख्य मंत्री का इस्तीफा और रातों रात उनका शपथ ग्रहण होता है। लेकिन झारखंड में हमारे पास बल है, झारखंड की हमारे पास ताकत है। हमको 10 दिन का इंतजार करना पड़ता है, मतलब बिहार के लिए नियम अलग है और झारखंड के लिए नियम अलग है। इस प्रकार की बातें आज हम कर रहे हैं... (व्यवधान)

सर, अगर हम इनके खिलाफ लड़ें तो हमें जेल भेजा जाता है और अगर इनके साथ शामिल हो जाते हैं तो ... (*Expunged as ordered by the Chair*) बनाया जाता है। अगर इनके साथ हम लड़ें तो हम पर शारदा का टैक्स लगता है और इनके साथ हम जुड़ें तो ... (*Expunged as ordered by the Chair*) जाते हैं। यह वॉशिंग मशीन है। हम डरेंगे नहीं, हम अपना फर्ज निभाते रहेंगे। हम भारत को जोड़ेंगे, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। हम पिछड़े वर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जातिगत जनगणना की लड़ाई लड़ेंगे। हम अनुसूचित जाति, जनजाति, जिनके लिए आज केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में, केन्द्र सरकारों में लगभग हजारों की तादाद में पद खाली हैं, आज उन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में, केन्द्रीय सरकारों में अनुसूचित जाति, जनजाति का स्थान हो, उनको अपना हिस्सा मिले, हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे। हम उन युवाओं के लिए लड़ेंगे। लगभग डेढ़ लाख युवा, जिन्होंने सेना की भर्ती के लिए पूरी परीक्षा पार की, लेकिन आज भी वह सेना में भर्ती नहीं हुए। हम उनके मुआवजे के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम जम्मू कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ताकि उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा मिले, निर्वाचन दोबारा हो और लोकतंत्र की स्थापना वहां पर हो। हम आंध्र प्रदेश के लिए लड़ेंगे। For Andhra Pradesh, we gave a special category status. We promised them. Again repeatedly, the Prime Minister has been betraying the people of Andhra Pradesh and denying them the rightful special status. We, the Congress Party want special status for Andhra Pradesh.(*Interruptions*) हम असम के उन 6 समुदायों के लिए लड़ेंगे। जो अहोम, मोरन, मटॉक, कोच-राजवंशी, सूतिया आदिवासी हैं और जनजाति की मांग कर रहे हैं, हम उनके साथ रहेंगे। हम महिलाओं के लिए लड़ेंगे, जो महंगाई से राहत चाहती हैं। हम भारत के संविधान के लिए लड़ेंगे। सर, इस भारत के संविधान में 'हम' लिखा है। इसमें मैं नहीं लिखा है। इसमें कोई एक व्यक्ति की दिव्य शक्ति नहीं लिखी है। इसमें भारत की लोक शक्ति का उदाहरण है। इसमें लिखा है कि-

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता बढ़ाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे।

यह इस संविधान की प्रति है। क्योंकि देश किसी व्यक्ति की दिव्य शक्ति से नहीं, देश संविधान से बनता है। देश आम नागरिकों से बनता है, देशवासियों से देश बनता है। हम भारत के इस संविधान के लिए लड़ेंगे, हम वंसुधैव कुटुम्बकम् की संस्कृति के लिए लड़ेंगे, हम गंगा-जमुना की तहजीब के लिए लड़ेंगे।

सर, बहुत दुःख होता है। आपके पहले भी सरकारें थीं, आपके बाद भी सरकारें आएंगी। लेकिन शायद हमने पहली बार ऐसा देखा है कि भारतीय होने का गर्व सत्ता पक्ष सिर्फ सत्ता के मापदण्ड से देखती है। ... (*Expunged as ordered by the Chair*) यह कितनी अफसोस की बात है?... (व्यवधान) आप देख लीजिए। मैं रिकॉर्ड में डाल दूंगा... (व्यवधान) कितने अफसोस की बात है? लेकिन मैं... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं इसको देख लूंगा, हटा दूंगा।

... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सर, संयुक्त राष्ट्र में देश के विदेश मंत्री ने क्या कहा? मैं वह पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने कहा... (व्यवधान)

(1415/VB/SAN)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इस सदन में प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं। हम कोई भी टिप्पणी करें या कोई भी बात कहें, तो बिना प्रमाणित तथ्यों के सदन में न कहें। सदन की गरिमा बनाकर रखनी चाहिए।

... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर) : सर, हम आपका सम्मान करते हैं। आप मुझे भी जानते हैं। मैं कोई भी बात बिना तथ्य के और बिना सबूत के नहीं रखता हूँ। यह आपके प्रति मेरा आदर है।... (व्यवधान)

... (*Expunged as ordered by the Chair*) आपके ही भूतपूर्व विदेश मंत्री की बातें, जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कही थीं, के बारे में मैं कहना चाहूंगा। उन्होंने पाकिस्तान को संबोधित करते हुए कहा था कि 70 वर्षों के दौरान भारत में बहुत-से राजनीतिक दलों की सरकारें बनीं, लेकिन सभी ने विकास की गति को जारी रखा। हमने विश्व प्रसिद्ध इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाए, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाए और ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे बड़े अस्पताल बनाए, लेकिन आपने क्या बनाया? आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, टेररिस्ट कैम्पस बनाए। हमने स्कॉलर्स पैदा किए, इंजीनियर्स पैदा किए, डॉक्टर्स पैदा किए, लेकिन आपने क्या पैदा किया?

ये जो 70 वर्षों का विवरण दिया गया था, आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने विदेश मंत्री के पद पर रहते हुए, उन्होंने भारत की गरिमा को सुरक्षित रखा था। कितनी अफसोस की बात है कि आप वर्ष 2014 से पहले भारत के प्रति कोई गर्व ही महसूस नहीं करते हैं। सर, हम भारतीय होने का गर्व महसूस करते हैं। वर्ष 2014 से पहले और आज भी, जब हमारे पास सत्ता नहीं है, आज भी हम भारतीय होने का गर्व महसूस करते हैं और हमेशा हम गर्व महसूस करते रहेंगे।

ज्यादा समय न लेते हुए, अंत में बंकिम चन्द्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम् की कुछ पंक्तियाँ कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा।

“त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी,
कमला कमलदल विहारिणी,
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्,
नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम्,
सुजलाम् सुफलाम् मातरम्,
वन्दे मातरम्।”

भारत कब विकसित होगा, यह कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था या कोई विशेष व्यक्ति तय नहीं कर सकता। भारत तब विकसित होगा, जब संविधान के अनुसार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सबको मिलेगा। भारत तब विकसित होगा, जब विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सबको मिलेगी। भारत तब विकसित होगा, जब प्रतिष्ठा और अवसर की समता सबको मिलेगी। जब भारत का हर नागरिक ऐसा महसूस करेगा तब जाकर हम भारत के प्रति न्याय करेंगे।

अंत में, हम यही कहना चाहेंगे कि हम अपनी लड़ाई, भारत की लड़ाई, भारत जोड़ने की लड़ाई, भारत के आम नागरिकों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, हम डरेंगे नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बातों को समाप्त करता हूँ।

धन्यवाद।

(इति)

TEXT OF AMENDMENTS

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): I beg to move:

6. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the release of central funds for 100 days to job card holding workers in West Bengal."
7. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the release of fund for Pradhan Mantri Awas Yojana to the state of West Bengal."
8. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about making available the pesticides mentioned in Para 19 at cheaper rates in the interest of farmers."
9. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about bringing Tarakeshwar Temple under Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive (PRASAD)."
10. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about setting up of a Kendriya Vidyalaya in Chandrakona town of West Bengal."
11. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the need to provide central fund to build concrete bridge in Khanakul and Natibpur on urgent basis."
12. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about providing employment guarantee to unemployed persons."
13. That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the need to empower public representatives to review development schemes anywhere in their Parliamentary Constituency."

14. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the need to provide Central funds to install CCTV cameras in all Government offices and public places in Arambagh constituency of West Bengal."
15. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about fulfilling the promise of bringing back black money and giving each individual 15 lakh rupees."

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

36. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about a special package for eradication of poverty."
37. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about project scheme for control of price hike of essential commodities."
38. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the programme for protecting the farmers by providing adequate support price."
39. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about regarding reduction of price of petrol, diesel and cooking gas and disbursement of subsidy of cooking gas."
40. That at the end of the motion, the following be added, namely:-

“but regret that there is no mention in the Address about protecting the cashew industry and providing employment to and ensuring welfare of the cashew workers.”

41. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
“but regret that there is no mention in the Address about filling up of vacancies in government sector, public undertakings and railways and a scheme to reduce the rate of unemployment.”
42. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
“but regret that there is no mention in the Address about increasing the EPF pension to the minimum of Rs. 5000/- per month and to implement the Supreme Court judgement for higher pension.”
43. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
“but regret that there is no mention in the Address about extending the ESI benefit to Anganwadi workers, ASHA workers and other categories of workers in the unorganized sector and to increase the wage ceiling of employees for ESI benefit.”
44. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
“but regret that there is no mention in the Address about increasing the wages and taking welfare measures for ASHA workers and Anganwadi workers.”
45. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
“but regret that there is no mention in the Address about the programme/schemes for rehabilitation of minorities who have lost their houses and livelihood due to mob attack in Manipur and other parts of the country.”

1419 hours

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, with great respect to the hon. President of India, I would like to join with my other friends to thank her for her Address to both the Houses of Parliament on 31st January, 2024.

On behalf of DMK and my leader, *Thalapathi* M.K. Stalin, it is my profound duty to thank the hon. President of India for having addressed both the Houses because she is the face of 143 crore Indian nationals. At the same time, we cannot find fault with the subject-matters, which she has delivered, because it is a matter of Government policies as it is a comprehensive Government policy note which she has read in the House.

(1420/SNT/PC)

I cannot find fault with Madam. I have to thank her. But at the same time, I can definitely find fault with the policies of the Government. Time and again, we have to intervene in this Parliament for the omissions and commissions of the BJP rule for the past ten years whether it is the subject matter of youth of this country, common man, middle class, weaker section of the country, women and children, senior citizens, and so on. It is for that purpose only, we, the Members of Parliament are elected and are coming to the Parliament to discuss. When the ruling party goes wrong, it is for us to condemn and correct that.

Similarly, we have been demanding the policies and programmes for the development of our own State of Tamil Nadu whether it is pertaining to the exemption of NEET, demanding higher allocation to Tamil Nadu, demanding flood rehabilitation to Tamil Nadu, demanding AIIMS at Madurai, second phase Metro approval to continue and save the project, to increase the railway connectivity, fast moving trains from Madurai, Thanjavur, and Coimbatore, etc.

Sir, during the first and the third week of December 2023, Tamil Nadu has witnessed unprecedented floods and cyclone. It has surpassed 100 years of history. Chennai and three other surrounding districts experienced 45 centimetres of rainfall in a particular day. Thoothukudi, which Shrimati Kanimozhi represents, and three other surrounding districts have experienced more than 100 centimetres of rainfall in a particular day. It has never happened. It is unprecedented. More than two crore people of Tamil Nadu have suffered because of the unprecedented rain. They were starving for

weeks because there was no logistic approval. Only by boats things had to be moved, food had to be moved, water had to be moved. That is why they had suffered all that. Moreover, a lot of automobiles, cars, two-wheelers, and other vehicles have been immersed and still they are lying there. More than 8,000 tons of food grains were spoiled in the FCI godowns. Even now, it could not be relocated as the water has inundated everywhere.

The State Government asked financial support of Rs. 37,000 crore. What has happened? There is no relief, no reconstruction. My friend, Mr. Rajnath Singh had an aerial survey. Madam Nirmala Sitharaman had also went around Tuticorin and other four districts. Rajnath Singh ji has travelled here and there in Chennai. Then, they came back. Three Committees have been sent from the Government of India. What has happened? They have surveyed, they have assessed. What they have to give they know but they have not yet released even a single paisa. The Government of Tamil Nadu has asked for Rs. 37,000 crore. On 4th January, along with the CM's letter I met the Prime Minister of India personally. On 19th January, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu and myself went there and expressed the concerns about Tamil Nadu. The Prime Minister was very courteous and he had promised that he will do the needful immediately. What has happened? Nothing. On 13th January, an all-party delegation led by me met the hon. Home Minister of India.

(1425/AK/CS)

Finally, he has said and categorically promised that on or before 27th definitely he will help us. It was said that the relief and reconstruction fund will be given to Tamil Nadu on or before 27th of January. What is today's date? It is 2nd February and nothing has happened. Hence, the DMK and the Opposition calls it as a step-motherly attitude towards Tamil Nadu. The same thing the other man from Karnataka would have said that they are not getting enough allocation for South India. He should have said the same thing, but our Parliamentary Affairs Minister was casting aspersion on him and opposing him. It is not fair on the part of the Parliamentary Affairs Minister.

In addition, there is an insult to injury. What is that insult to injury? Five years back, our Prime Minister laid the foundation stone for AIIMS, Madurai in 2019. He has laid one brick. Nothing has happened over that brick. All the AIIMS that have been announced so far by the hon. Prime Minister of India in

2019 have come up and they are working and they are established. What has happened in Madurai? AIIMS, Madurai has not seen the light of the day. It is in ground zero. Only the compound wall is seen whenever we go there. So, it is a sad part. We want to express concern over this issue. Hence, we are saying that the Central Government is having step-motherly attitude towards Tamil Nadu. This is not fair on their part.

Are we in a federal setup or not? This is what I want to say about this issue. It is a Rs. 1,800 crore project, namely the AIIMS project. It would have been established long back just like other AIIMS establishments. They are spending Rs. 50 lakh crore in a Budget. Is it not possible to provide Rs. 300 crore to Rs. 400 crore every year to complete this project? If this was done, then by this time it would have been completed and established. One day after a deep slumber, the Health Minister came to the Parliament and to a Question he has answered that : "We have done it. 50 students have been admitted in Ramanathapuram College". Where is it? It is 120 kms. from Madurai. He says that the AIIMS is now working. Where is it working? It is in Ramanathapuram, which is 120 kms. from Madurai. Its head office is in Puducherry, which is 480 kms. away from Madurai. This is the state of affairs of things, which we were craving for years together. This is not fair on the part of the Union Government to just leave Tamil Nadu high and dry.

After a lapse of so many years I am asking this. What is happening with regard to the Sethusamudram Project? In 2005 the foundation stone was laid by Dr. Manmohan Singh Sir. The project was in progress. The court has given a stay in 2008 because of intervention of some case on communal basis. The entire India knows as to what has happened. Now, last year the Government of India itself has gone to the court saying that there is no man-made structure and they can go ahead with the project. What is happening? Nothing is happening. The project is not yet taken up. Even the Government of India is giving a lukewarm response. This is a project of Tamil dreams, that is dream of Tamil people. More than 160 years of Tamil dreams have not yet been made good as it has not been accomplished. It is a dream of Dr. Anna; it is a dream of Dr. Kalaingar Karunanidhi; and it is a dream of K. Kamraj. What has happened? Nothing is done. They are least bothered about Tamils and Tamil pride.

(1430/UB/IND)

The Government has renamed National Maritime Development Programme which was envisaged during my period when I was the Shipping Minister. More than 120 projects have been identified. During those times, each and every day, there would be a programme, progress, and development. What happened after the NDA Government came in? They just changed the name of National Maritime Development Programme to Sagarmala. What has happened to Sagarmala? It is without any link. Sagarmala is there in the eastern coast and in the western coast, but there is no link between the eastern and western coasts. If they want to fulfil the objective of Sagarmala, the link should be established. They are not going to do it. That is why Sagarmala's objective will not be achieved.

In para 7 of the President's Address, Madam President said, "This Parliament also enacted a law to grant citizenship to persecuted minorities from our neighbouring countries like Pakistan, Afghanistan and Bangladesh". All other communities have been permitted and they are getting citizenship whereas Muslim community is not getting the citizenship. Tamil minority from Sri Lanka is not getting citizenship. This is the state of affairs of the minorities.

Regarding Citizenship (Amendment) Act, the hon. Minister of State Mr. Shantanu said last week, "Within a week's time, I am going to implement". Where is the possibility? West Bengal is not inclined to implement CAA and Mamata Banerjee has already declared that. Dr. M. K. Stalin has already declared that he is not going to implement it in Tamil Nadu. Where is the possibility? Moreover, the other States are also not inclined to implement CAA in their States. But the hon. Minister of State simply said that within a week's time, he will do it. It is because of voting. With 13 Members of AIADMK in Rajya Sabha, the Bill has been passed. Without those 13 votes, this Bill would not have been passed. The ruling Party should understand the ground reality. Because of the ruling Party's friendship with AIADMK, the Bill has been passed. Now, it could not be passed. My leader, Dr. Stalin has collected two crore signatures in a signature campaign and sent them to the President of India not to approve CAA, but Madam President has not done it. He has also resolved in the State Assembly not to implement CAA. Despite that, the Central Government is going for it.

As per para 5 of the President's Address, Madam President said, "Last year, my Government has given Government jobs to lakhs of youths in mission mode". What has happened? In 2014 itself, the hon. Prime Minister of India came all the way to Chennai and declared that he was going to give 2 crore jobs every year. That is why Mr. Gogoi has asked what happened to the 20 crore jobs in ten years. Twenty crore jobs should have been provided by now. Not even a single job has been provided by him under this particular scheme. Moreover, second phase of metro project in Tamil Nadu is going on.

(1435/SRG/RV)

It is in progress without the help of the Central Government. We could not proceed because of want of money. What has happened? For metro projects, the Government of Tamil Nadu has written three to four times. He met the hon. Prime Minister twice or thrice. But in spite of that, the Government of India is not coming forward to help us. What has Madam President said in her President's Address? In para 15, Madam has said, 'the Metro facility, limited to only five cities, is now in 20 cities.' Government can boast of it as if they are doing it in 20 cities, but they are neglecting the Tamil Nadu projects. The second phase of Tamil Nadu metro project is lingering on. They are not helping us. This matter has to be looked into.

In para 11, Madam has talked about One Nation, One Tax. They have got slogans of that, 'One Nation, One Tax'. One tax means GST. For other things, they have provided GST. They have abolished all other taxes and put GST except on petroleum products. For diesel and petrol, GST is not there. Why? Government is mopping up money because of GST and because of other multiple taxes. They are not providing GST there. Even if they would have provided the higher slab of 28 per cent, the petrol and diesel prices would not have gone beyond Rs. 85. This is our demand that petroleum products should be provided with GST tax only.

They have put five per cent tax on LPG. There should be a zero tax on LPG. It is not correct on the part of the Union Government to sell an LPG cylinder at Rs. 900, whereas it was only Rs. 400 during the UPA regime,. It is not correct on the part of the Central Government.

Finally, I want to talk about Employees' Provident Fund Pension. They work till 70 years in the Government sector and after 70 years of age, they

retire. After the retirement, what is happening? They are getting a paltry amount of Rs. 1000 per month only as retirement pension. Even in Tamil Nadu, our own women household helps are getting Rs. 1000 per head every month. They are getting Rs. 1000 per month, whereas the industrial workers are only getting Rs. 1000 after serving for 15 or 20 years. This matter has to be dealt with immediately and they have to be given an increased pension of at least Rs. 3,000. This is my demand.

Finally, I want to say that many of the Governors in India think that there is a halo behind their head and they do not care about what is written in the Constitution. They do not know about the Constitution and they think that they are the ultimate of everything. This is not fair. Day before yesterday, on 31st January, Madam President has read out each and every syllable of the Address. However, Governors do not read it out. Moreover, they edit it and read it out. Recently one particular Governor has read out only the last line of the Governor's Address and came out. The worst part is that they are simply opposing the State Government much more than the Opposition in the particular State. The Opposition is used to do mudslinging on the elected Government. Crores and crores of public have given their mandate to the elected Government.

(1440/RCP/GG)

Whereas the elected Government is just belittled by the Governor. The Governor is making fun of it. Many times, he competes with the opposition to scold the party in power. This is not fair. So, if anybody, any Governor is doing some vicious act, Madam President should pull him up and see that he is terminated. This is my final demand.

Thank you very much, Sir.

(ends)

महिला और बाल विकास मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर, एक पूर्व वक्ता के बारे में, आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ। रूल 352 और 353 के संरक्षण में आपसे मेरे तीन निवेदन हैं।

एक – महामहिम राष्ट्रपति जी को पवित्र सैंगोल की छत्रछाया में आपने हम सबकी ओर से स्वागत किया। उनके उद्बोधन के लिए हम सब उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, किंतु सदन और महामहिम राष्ट्रपति जी के मध्य में जो पत्राचार है, निमंत्रण अथवा सदन को संबोधित करने वाली जितनी व्यवस्थाएं हैं, उस पर पूर्व वक्ता गौरव गोगोई जी ने जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि उन आपत्तिजनक टिप्पणियों को आप एक्सपंज करने की कृपा करें।

दूसरा – सर, बार-बार सदन की कार्यवाही और पीठ के द्वारा दिए गए जितने आदेश हैं, उनका जिस प्रकार से यहां पर उस सांसद ने अपनी राजनीतिक व्यवस्था के लिए दुरुपयोग किया, आपके बार-बार टोकने के बावजूद किया, वह भी आपत्तिजनक व्यवस्था है, जिसके लिए मेरा आपसे आग्रह है कि उसको भी आप एक्सपंज करें।

सर, मेरा मेरा तीसरा आग्रह है कि लोकतंत्र की यह गरिमा है कि प्रधान मंत्री पद पर हमारे राष्ट्र के नागरिक चुन कर एक व्यक्ति को विद्यमान करते हैं। उस पद के लिए, उस गरिमामयी पद के लिए ... (Not recorded) शब्द की जो उपाधि आज यहां पर, सदन के एक सदस्य ने इस्तेमाल की है, उसको भी आप एक्सपेंज करें। ... (व्यवधान)

मैं इतना कहना चाहूंगी कि उनका द्वेष नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो सकता है, लेकिन गरिमाविहीन टिप्पणी प्रधान मंत्री पद के लिए न हो। ... (व्यवधान) इससे संसद भी आहत होती है और वह वोटर भी, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुन कर अपने प्रतिनिधि को सदन में भेजता है। ... (व्यवधान)

सर, मेरा अंतिम निवेदन आपसे नियम 352 और 353 के संदर्भ में यह है कि बार-बार इस वक्ता ने कहा कि हमें इस बात की शर्म है कि हम हिंदुस्तानी हैं और इसकी अनुभूति हमें वर्ष 2014 से पहले नहीं थी। सर, मैं कहना चाहूंगी, मैं स्वयं इस सदन में साक्षी रही हूँ, इस सदन में एक ही सांसद था, जिसने भारत तेरे टुकड़े होने के वाक्य का समर्थन सदन से बाहर किया था। भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद ऐसा नहीं है, जिसने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी इस बात का गौरव न किया हो कि हम इस देश में जन्मे हैं और हम हिंदुस्तानी हैं। तो इस प्रकार का जो आक्षेप लगाया गया है, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसको एक्सपंज करें। ... (व्यवधान) ये अपनी राजनीति बाहर करते रहें, लेकिन राष्ट्रनीति का अपमान इस सदन में नहीं होगा। ... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सर, उस भाषण के शब्द, जो आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने दक्षिण कोरिया में इस्तेमाल किया है, उसका रिकॉर्ड आप देख लें।

माननीय अध्यक्ष : चलो छोड़ो।

डॉ. काकोली घोष दस्तीदारा

1443 hours

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Hon. Speaker, Sir, I stand here on behalf of All India Trinamool Congress in great reverence towards the speech of *Mahamahim* Rashtrapati Shrimati Droupadi Murmu. But I would like to ask a question also. Why is this the first time that she came here and not on the day that this grand building was inaugurated? What is the reason? Why was she not present, why was she not invited for the inauguration is a question.

1444 hours

(Shri N. K. Premachandran *in the Chair*)

The other question is this. As her speech commented a lot on the *nari shakti* here, we would like to say that when Nari Shakti Adhiniyam was passed by this House, there was a demand to increase the reservation beyond 30 per cent as my leader Mamata Banerjee has done in West Bengal without reservation being in force at that time. So here, when the Reservation Bill has been passed, it should cross that number.

At this juncture, even day before yesterday, women have been molested and killed in the North eastern Region of the country, in Manipur. Can we really say that *nari shakti* is being revered and *nari shakti* is being propagated or is given an equal opportunity in this country?

(1445/PS/MY)

I do not think so. Beyond that, Mahamahim Rashtrapati ji was talking about the Constitution. I would like to quote here that the fabric of our Constitution is being violated every day in the nation today. The nation is seeing an unforeseen betrayal to democracy, an indifference to respect for individual liberty and a deafness and blindness to the cries of the tormented. But we do not see any action being taken by this Government.

I take this opportunity to congratulate the scientists of this country, the scientists who successfully carried out the Chandrayan Mission and Aditya Mission. It is through their efforts that India became the first country to hoist its Flag on the Southern Pole of the Moon. It is the result of the hard work of the scientists -- nobody else, no politician -- who might have stayed away from many family reunions and might have given up on many nights of family life to take our country to this glory. In the same voice I would like say that a draconian notice is given by the National Medical Commission (NMC) to the doctors of service all over the country to act like bonded labours. They have to sign at 9 o'clock in the morning and sign at 4 o'clock in the morning. Now, doctors cannot be compared

to any other professionals, not even the people who are working so hard. We have the judicial system. We have the teaching system. We have advocates. They all have a time of working. But doctors can be called at the middle of the night, at 2 a.m., to treat a patient of arrhythmia or a patient having atrial fibrillation. If all the doctors of the country, every doctor of the country, put down their pens, or they do a pen-down or a stetho down so to say one day, then who is going to treat the emergency patients? When a doctor is called at the middle of the night to do a caesarean to save a mother and child, a mother who is suffering from pre-eclamptic toxemia, then the next morning he cannot be expected to be present in the hospital at 9 o'clock because he was working till 5 o'clock in the morning, between 2 a.m. and 5 a.m. So, I would like to request the Government that this NMC should not be allowed to bring this notice and serve it on the doctors. I oppose it completely. It has happened and the notice has reached the different hospitals of the country.

I would also like to bring to the notice here that in this country there is a demographic deficit. Nearly 44 per cent people who are seeking jobs are jobless. In the democracy, there is a shift of electoral autocracy. As far as the job market is concerned, in the last one fiscal, 135 million labour force was added which amounts to 450 million people looking for jobs. But there is no job market. There is no job. This is the first time possibly in Independent India that more than 45 per cent reverse migration is happening. People are going away from cities and towns towards villages looking for jobs in the farmland. But there also, the farming sector is being affected adversely by the increase in FDI. The farmers are also committing suicides. Farmers' suicides are rising so much. It is the report of the NCRB that the farmers' suicides are approximately rising to 11,290, one suicide per hour. This is a very serious note to be taken care of that we are not by the nari shakti and we are not standing by the farmers under the regime of this Government.

I quote the speech of the hon. Rashtrapati ji when she says, 'That this Government has made a contribution towards the wealth creators and believes in the private sector'.

(1450/SMN/CP)

Then, why is it that more than one lakh families who were engaged industrially in this country as wealth-creators have given up their citizenship of

this country and relocated to other countries? Is it in protest against the violation of human rights and respect to diversity in this country? It is a serious question.

Today, she quoted another thing. I quote her:-

“Forty-six per cent of the world’s total real time digital transactions took place in India.”

Now, this digital transaction is also opening a death trap. Due to these digital transactions, suicide rate among the adolescent and young adults is increasing so much. She said that Rs. 1200 crore transactions were done through Unified Payment Interface (UPI).

It has become the centre of the biggest UPI scam and the Government does not bother. How is that happening? It is happening because of the Apps. There are Apps which are being put up by one other country - I do not want to name the country - by a different country, a neighbouring country. There is no vigilance over those Apps. Due to this, there is a major rise in suicides and young people are falling into the trap by using those Apps and they are applying for loans. When they cannot repay the loans, they are committing suicides.

She talked about the high-speed trains. But what about the tracks? These tracks were laid during the British Raj. After that, the tracks have not been repaired. पटरी इतनी सड़ी हुई है कि जानलेवा दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हम इसके ऊपर वंदे भारत चलाएं या फास्ट ट्रेन्स चलाएं तो एक्सीडेंट्स होते रहेंगे और we will lose so many people. Without repairing the tracks, without laying new tracks, we should not be going in for these fast-moving trains.

Then, again, coronary stents, knee implants, cancer medicines, prices have been reduced. Maybe the Government is self-congratulatory on that. But they mention that more than 12 per cent increase in costs of many life saving drugs has happened which is making it very difficult for those patients who have to take medicines related to hypertension and medicines related to diabetes because diabetes is rampant in India. India might be called diabetic capital of the world. The prices of medicines have increased in the whole of the nation. The highest number of diabetic cases are in our country.

Mahamahim Rastrapati ji also talks about Nari Shakti again but women are paraded unclothed like we have seen in Manipur. They have been manhandled and nothing happened. This Government did not interfere in Manipur. Even day before yesterday, we have seen three people shot dead. Last month, we saw open fighting on the roads in Imphal. Business transaction is at its nadir in

Manipur and also in the other Eastern States. So, what is the Government doing about it? We would also like to point out that if we want the womenfolk to come forward further, their remuneration should be paid on time. Time and again I have mentioned it here and written personally to the hon. Minister of Education that the premier institutes are seeing their students, their research scholars going without pay. In places like Indian Institute of Technology, the researchers, the PhD scholars are not getting paid. That is not mentioned here.

The other thing is about the daily wage earners. It was decided that they would be given hundred days of work. But in the budgetary allocation of this very fiscal, their provision is only for 42 days. The total amount required would be Rs. 2.72 lakh crore but only Rs. 60,000 crore has been given. Why are the States not getting paid? In West Bengal, we have the hundred day workers who have not been paid for months together and they have worked. The statute is that they should be paid within 15 days after finishing the work. Now, months have turned up but they have not been paid.

(1455/SM/NK)

These people are being tortured familywise because they cannot run their home and hearth. The Government should sit up and take into cognisance the poor people of West Bengal who are suffering.

Farmers' deaths due to suicide, as per NCRB Report of 2022, are rising. The number was 11,290 in 2022. When you say that making farming more profitable is the intention of this Government, why is then FDI increasing? Foreign Direct Investment in farming sector in 2016-17 was 727.22 million dollars. In 2019-20, it was 904.70 million dollars. It shows that the farmers are not getting any benefit out of it because FDI is entering the farming sector also.

Then, we see that the Government talks about the grain storage plan. In 2022-23, crop produced in the country was 3,296.87 lakh tonnes. But the storage capacity of the country was only 145 MMT. So, we have the capacity to store only half of the grains we produce and the remaining half is rotting on the streets in rain and sun. So, we are not equipped to give respect to the produce of the farmers. The farmers are producing the crops by their own toil but they are not getting any help from the Government at all.

As far as Northeastern States are concerned, I do not know how this could be included in the speech. The Northeastern States have no development. There is no proper facility for their medical treatment; there is no proper facility for their

education. I myself have visited three to four of the seven sister States. Their condition is very pitiable. The children do not have schools to go to; women do not have proper facilities for healthcare. So, North-east is not something we can boast of. This should not have found the place here.

The renewable energy installed capacity has found the fourth place. It is congratulatory. But there is no mention about the grid conversion of renewable energy which is formed through the renewable sector.

We are saying here that previously we had seven AIIMS and 390 medical colleges, and now the number has increased to 16 AIIMS. But where are the faculties? I know very well, being a doctor myself and being in the teaching line myself, that this NMC's direction will further shrink the number of faculties. They are going to leave their jobs if NMC does not withdraw their draconian directions.

We do not have faculties. So, you should organise teachers, get them from abroad and pay them properly. The doctors are not paid properly in the country. The doctors are working throughout the day and night. When a doctor's telephones on the bedside table rings at 3 in the morning about a known patient who is getting pain in the chest, the doctor will not look at anything else. He will not think of anything else and he will just get up, take his car and go to the patient to perform cardiac resuscitation.

But the doctors are being underpaid. This NMC regulation is like an added tension for the doctors. So, more people will leave the job. There is no faculty. You are making college buildings. But where is the faculty to teach the students? Students with lot of dreams will get into the medical line to learn about medicines, to stand by patients, to treat them and to get them well. But there is no teacher. There is no infrastructure. The building is not the infrastructure in medical field. It is the equipment. In the medical infrastructure, we have to have the technicians who teach you as to how to put the Ryle's Tube in a patient.

(1500/RP/SK)

They should teach how to do a cannula and start the IV fluid. We do not even have that. So, the manpower and the infrastructure are lacking. Having building for AIMMS will not suffice.

Then, again, we talk about the historical places which are being renovated and then there are many sites which are being discussed to be upgraded. In my Constituency, there is a place called Chandraketugarh. This is supposed to be nearly 3000 years old and after repeated requests to this Government, the Central Government, for 10 years, nothing happened. Then, my Chief Minister, hon. Mamata Banerjee allotted funds by which we got a site museum made and we have executed certain things that we found were relics in Chandraketugarh. A small museum is working there. I worked very hard for almost 10 years to get this museum put up. But, the excavation has been stopped. This was either in the Gupta Period or in the Mauryan Period. It has a port city also as shown in the relics and important structures to prove that there was business through the rivers up to Europe. We found the seals and statues also. But, the excavation has been stopped in Chandraketugarh by ASI. If you say that they are doing a lot, then, the first thing they should do is to take up Chandraketugarh and declare it a heritage site or a world heritage site.

As they put forward arguments and Mahamahim Rashtrapati ji comes in and reads, I would like to say that the Government is really not doing justice to all segments of the people in the country like farmers, industrialists, students and naari shakti.

Thank you, Sir.

(ends)

1502 बजे

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): माननीय सभापति जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की चर्चा में भाग लेने का मौका दिया है।

सभापति जी, मैं आज डॉ. विजयकुमार हिना गावीत जी के प्रस्ताव के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की ओर से उपस्थित हुआ हूँ। कुछ समय पहले कांग्रेस के मित्र ने इस सदन के बारे में और संविधान के बारे में जो टिप्पणी की है, मैं उसका ब्रीफली जवाब देना चाहता हूँ और उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे मित्र ने माननीय प्रधान मंत्री जी के बारे में जो शब्द कहे और संसद की गरिमा के बारे में जो शब्द कहे, मैं उसकी सख्त आलोचना करता हूँ।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के बारे में बताना चाहता हूँ, वर्ष 2014 में पहली बार माननीय मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने और जब वह संसद भवन के द्वार पर गए तो वे संसद भवन के प्रति माथा टेककर सम्मान प्रदर्शित करके दाखिल हुए। मैं समझता हूँ कि आज तक किसी प्रधान मंत्री ने इस प्रकार से संसद भवन में माथा नहीं टेका।

अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, मैं गुजरात से सांसद हूँ। वर्ष 2010 में माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी जब तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब संविधान की धज्जियां उड़ रही थीं। उस समय उन्होंने सुरेंद्र नगर में संविधान की एक यात्रा निकाली थी। संविधान को हाथी की अंबारी पर रखकर माननीय प्रधान मंत्री जी ने उस यात्रा की अगुवाई की थी और मैं भी उसमें उपस्थित था। करीब दो किलोमीटर चलकर संविधान के प्रति आदर करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी हैं।

जहां तक संविधान की बात है, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि संविधान के रचियता, संविधान के शिल्पी बाबा साहब अम्बेडकर जी का अगर किसी ने सबसे ज्यादा अपमान किया है तो कांग्रेस पार्टी के मित्रों ने किया है। संविधान जहां स्वीकृत हुआ था, संसद भवन के सेंट्रल हॉल में, वहां बाबा साहब अम्बेडकर जी का तैल चित्र नहीं था। देश की इतनी बड़ी राजधानी में हर नेता के स्मारक और मेमोरियल थे लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का कोई मेमोरियल नहीं था।

(1505/KDS/NKL)

15 जनपथ पर बाबा साहब अम्बेडकर विश्व मेमोरियल की अगर किसी ने स्थापना की थी, अगर किसी ने उसका शिलान्यास किया था, अगर किसी ने उसका उद्घाटन किया था, तो वह हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी थे। इसी प्रकार 26, अलीपुर रोड, जहां बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपनी अंतिम सांस ली थी, वह बंगला एक निजी प्रॉपर्टी थी। अटल जी, तत्कालीन प्रधान मंत्री जी ने यह संकल्प लिया था कि बाबा साहब का हम यहां मेमोरियल बनाएंगे। इसके बाद उनकी सरकार चली गई। वह दायित्व नरेन्द्र भाई मोदी जी के पास आया और

आज उन्होंने 26 अलीपुर रोड पर संविधान पुस्तक के आकार के आर्किटेक्चर के तौर पर एक भव्य मेमोरियल बनाया है। कांग्रेस के मित्रों ने बाबा साहब का, जो उनकी दुहाई देते थे, हर पल अपमान किया था। आज इस सदन में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की चर्चा पर मैं यह बताना चाहता हूँ कि नए संसद भवन के कक्ष में एकत्र दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को 75 मिनट के अपने संबोधन में राष्ट्रपति जी ने पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में आतंकवाद व विस्तारवाद को मुंहतोड़ जवाब देते हुए हमारे सशस्त्र दिलों की सराहना की, उनकी सलामी की, इस हेतु मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।

माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा था कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कानून पेश किए हैं और संसद का दायित्व है कानून पारित करना, पॉलिसी को बनाना। जो कानून पास किए गए हैं, उनको मैं यदि गिनाऊं, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम की वजह से हमारी 50 प्रतिशत आबादी को विधान सभा व लोक सभा में प्रतिनिधित्व मिलेगा। यह काम भी हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जहां तक हमारी न्याय संहिता का सवाल है, तो मैं बताना चाहूंगा कि पहले गुलामी की मानसिकता के कारण न्याय पालिका के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का इंटेनशन किसी को क्रिमिनल डिक्लेयर करना था, लेकिन आज हमारी सरकार ने न्याय संहिता का पालन किया है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम संसद ने पारित किया है। जन विश्वास अधिनियम, जम्मू और कश्मीर में आरक्षण, खासकर ओबीसी के लिए आरक्षण संबंधी अधिनियम इसी संसद ने पारित किया है। जन विश्वास अधिनियम में विभिन्न कानूनों के तहत 183 प्रावधानों को अपराध विमुक्त कर दिया है। राष्ट्रपति जी ने इन्हें लागू करने में सहयोग देने के लिए हमारे सभी सांसदों की भी सराहना की थी। संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा था कि मोदी सरकार ने भारत में तीर्थ स्थानों और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर बहुत जोर दिया है और उन्होंने करके दिखाया है। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में करोड़ों देशवासियों की श्रद्धा के प्रतीक और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में अब वास्तविकता बन गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 22 जनवरी को प्रधान मंत्री जी के कर-कमलों से उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिससे हर भारतीय का सीना गौरव से चौड़ा हुआ। यह भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इस हेतु मैं पूरे देश की ओर से प्रधान मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद करता हूँ।

महोदय, जहां तक विकसित भारत की कल्पना है, प्रधान मंत्री जी की एक कल्पना रही है कि यह भव्य इमारत ज्ञान के चार मजबूत स्तंभों पर खड़ी की जाएगी और ये स्तंभ गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी शक्ति यानी महिला हैं। भारत की आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं, तो भारत आज आर्थिक विकास के 5वें पायदान पर आ गया है। इंग्लैंड को हटाकर हम 5वें पायदान पर आए हैं, जिन्होंने हम पर सालों तक राज किया था।

(1510/MK/VR)

यह हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। कुछ ही समय में भारत का विश्व में आर्थिक रूप से तीसरे पायदान पर आने की पूरी सत्यता है। आज भारत आर्थिक रूप से पूरी दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट की तरह जाना जाता है। राष्ट्रपति जी ने बताया कि भारत ने लगातार दो तिमाहियों में साढ़े सात प्रतिशत से अधिक विकास दर यानी की जीडीपी बनाए रखी है।

महोदय, भारत हाल के वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। आज भारत नाजुक पांच से परिवर्तित होकर शीर्ष पांच की इकोनॉमी बन गया है। यह हम सबके लिए गौरव का विषय है। इसके लिए मैं नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ।

पिछले 10 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आ गए हैं। मैंने देखा था, एक कांग्रेस की प्रधान मंत्री थीं, उन्होंने 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया था, लेकिन गरीबी नहीं हटी थी। अगर गरीबी हटाने के लिए किसी ने कार्य किया है, किसी ने धरातल पर कार्य किया है तो वह हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। पिछले 10 वर्षों में निर्यात 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 775 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। यह भारत का प्रभुत्व पूरे देश में और पूरे विश्व में लहरा रहा है। जहां तक विदेशी मुद्रा भंडार का सवाल है तो वह वर्तमान में 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। यह हम सबके लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश है। पहले हम मेड इन चाइना और मेड इन जापान देखते थे। मेक इन इंडिया की नीति के तहत आज भारत प्रोडक्शन में दुनिया में अक्वल स्थान पर जा रहा है। इससे पूरे देश में एक नया रोजगार मिलेगा। इसके लिए महामहिम ने हमारी सरकार को धन्यवाद दिया है। यह सफलता भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी की वजह से है।

डिजिटल इंडिया में भारत समग्र विश्व में अग्रसर रहा है। इसकी वजह से आज भारत में जीवन और व्यवसाय बहुत आसान हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी है, जो एक नये युग का डिजिटल बुनियादी ढांचा विकसित करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत इसमें अग्रसर रहे।

जहां तक मेडिकल का सवाल है, मैं स्वयं एक डॉक्टर हूँ, चाहे सिकल सेल एनीमिया हो, यह बीमारी हमारे आदिवासी भाइयों में पाई जाती है, इस सरकार ने मिशन मोड पर सिकल सेल एनीमिया को नेस्तनाबूद करने के लिए एक योजना बनाई है। मैं समझता हूँ कि यह हमारे गरीब और पिछले पायदान में बैठे हुए व्यक्तियों के लिए बहुत ही आशीर्वादरूपी योजना होगी।

जहां तक कोविड महामारी का सवाल है, कोविड महामारी के समय दुनिया के बड़े-बड़े देश, जिनका हेल्थकेयर स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत था, वे बिखर गए थे। उस समय हमारे यहां बहुत लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी जिस प्रकार से प्रधान मंत्री जी की अगुवाई में हमने उसका मुकाबला किया, मैं तो स्वयं डॉक्टर हूँ, मैंने देखा है कि वैक्सीन अगर कहीं से आती थी तो वह विदेश से आती थी, चाहे वह स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन हो। भारत में कोई वैक्सीन 20 साल के बाद, कोई वैक्सीन 25 साल के बाद और कोई वैक्सीन 40 साल के बाद आयी थी। मुझे बहुत फख्र होता है, मुझे बहुत गौरव महसूस होता है कि इस देश में बनी हुई वैक्सीन की वजह से आज भारत में हम सब लोग बिना मॉस्क के यहां बैठे हैं। यह सब हमारी सरकार की वजह से है और हमारे नरेन्द्र भाई मोदी जी की अगुवाई की वजह से है। हमारे यहां, हमारे देश में दो-दो वैक्सीन बनी हैं। जहां तक वैक्सीन इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, आज अमेरिका जैसे बड़े देश में भी 100 परसेंट लोगों को वैक्सीन का टीकाकरण नहीं किया गया है। मैं इस बात के लिए बहुत गौरव महसूस करता हूँ कि इतनी विविधता वाले देश में, चाहे मरूभूमि प्रदेश हो, पर्वतीय प्रदेश हो या दूर-सुदूर के प्रदेश हों, वहां भी जाकर दो-दो वैक्सीन देने का कार्य जो हमारे हेल्थ कर्मियों ने किया है, मैं समझता हूँ यह बहुत ही बड़ा कार्य किया है। इसके लिए मैं सरकार का बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूँ।

(1515/SJN/SAN)

हमने कोविड-19 की वैक्सीन बनाने का जो कार्य किया है, मैं समझता हूँ कि ऐसा कार्य 'न भूतो न भविष्यति' होता है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं इसके लिए गौरव महसूस करता हूँ और मैं हमारी सरकार का वंदन करता हूँ।

महोदय, जहां तक कृषि का सवाल है। कोविड-19 महामारी फैलने के बाद 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन प्रदान किया गया है। कल पेश हुए बजट में उस राशन को और पांच साल बढ़ाने की घोषणा की गई है। यह इतना बड़ा कार्य है। हमने देखा है कि जब महामारी फैलती है, तब जितने लोग उस महामारी से नहीं मरते हैं, बल्कि उससे ज्यादा लोग भूख की वजह से मरते हैं। तब इस सरकार ने लोगों को अन्न और राशन दिया है। उनके अधिकार का राशन दिया है, मैं इसके लिए सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

चाहे 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' हो या 'पीएम फसल बीमा योजना' हो, जिस प्रकार से सरकार के द्वारा कई योजनाओं के माध्यम से लोगों और किसानों के लिए कार्य किए गए हैं, वे क्राबिल-ए-तारीफ़ हैं। पिछले एक दशक में किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए इस सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं, ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके। भारत के किसान सरकार के साथ हैं। जहां भारत के रक्षा जगत का सवाल है, राष्ट्रपति जी ने कहा है कि पहली बार भारत के रक्षा बलों के लिए चीफ ऑफ़

डिफेंस स्टॉफ की नियुक्ति की गई है। चार दशकों से बहुप्रतिक्षित 'वन रैंक, वन पेंशन' लागू किया गया। पूर्व सैनिकों को लगभग एक लाख करोड़ रुपये का फायदा मिला है। यह सरकार के द्वारा किया गया है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं।

जहां तक शिक्षा का सवाल है, एससी और ओबीसी छात्रों का नामांकन करीबन 44 प्रतिशत बढ़ा है। जहां तक हमारे ट्राइबल स्टूडेंट्स का सवाल है, उनका नामांकन 65 प्रतिशत बढ़ा है। यह काम सरकार ने किया है। सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके 14,000 से अधिक 'पीएम एसएचआरआई' स्कूलों पर काम कर रही है। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है – 'आयुष्मान भारत योजना' है। मुझे पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह योजना गुजरात में चालू की थी। इस योजना को आगे बढ़ाते हुए आज पूरे देश में लगभग 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को उसका फायदा पहुंचा है। मैं गुजरात सरकार को बधाई देता हूँ, क्योंकि गुजरात सरकार ने प्रति परिवार 5 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रति परिवार कर दी है। मैं इसके लिए गुजरात सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जी-20 में अफ्रीकी संघ की स्थायी सदस्यता सुनिश्चित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी अगुआई में जो कार्य किया गया है, उसके लिए अफ्रीकन कंट्री प्रधानमंत्री जी का बहुत सम्मान करती हैं। सामाजिक न्याय पर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने ऐसी कई बातें अपने अभिभाषण में की हैं। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा। ये पंक्तियां सिर्फ मेरे हृदय में नहीं हैं, बल्कि ये पंक्तियां 140 करोड़ भारतवासियों के हृदयों में गूंज रही हैं। मैं आपके साथ उनको साझा करना चाहता हूँ – "सपने नहीं, हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी जी को चुनते हैं"। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।

(इति)

1519 hours

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Hon. Chairperson, Sir, I thank you very much for allowing me from YSR Congress Party, under the dynamic leadership of Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy *garu*, to participate in the discussion on Motion of Thanks on the hon. President's Address.

First of all, I congratulate the Government for its noteworthy achievements, including positive developments in Jammu and Kashmir, ensuring a safe and peaceful environment for its residents and the successful launch of the Aditya Mission, reaching a distance of 15 lakh kilometres away from the Earth.

(1520/SNT/SPS)

India's groundbreaking feat of placing its flag on the southern pole of the Moon and opening the space sector to start-ups is commendable for fostering innovation. I also commend the Government for steering India to become the fastest-growing major economy amidst a global crisis, maintaining a growth rate exceeding 7.5 per cent for two consecutive quarters.

However, I would like to take this opportunity to offer a few suggestions concerning the key points highlighted in the President's speech, particularly in relation to the role of Andhra Pradesh in the future of India's growth. The first point is regarding food and public distribution. I would like to mention about increasing coverage of ration cards under National Food Security Act, 2013. Commending the Government's commendable initiative to provide free ration to 80 crore people during the COVID-19 pandemic, along with the recent extension for five more years, there are critical issues regarding the coverage of the Centre's ration cards under the National Food Security Act, 2013 (NFSA) in Andhra Pradesh that need immediate attention.

The challenge of insufficient coverage under NFSA, 2013, in Andhra Pradesh, primarily due to relying on the 2011 Census for ration distribution has been discussed in various Centre-State meetings, pursued with the Department of Food and Public Distribution (DFPD) and NITI Aayog. The State has issued ration cards for rice and provided ration to over 56 lakh families, incurring a cost exceeding Rs. 5,527 crore. NITI Aayog recommends reallocating unutilised quota, urging prompt action from the Ministry of Statistics and Programme Implementation for a fresh Household Consumption

Expenditure Survey (HCES) and comprehensive examination by the DFPD. A revision in the methodology for identifying NFSA beneficiaries and a new Census are urgently requested, along with Government compensation for expenses incurred in extending benefits to those excluded by the Central Government. This is the demand from the State of Andhra Pradesh.

The second point, hon. Chairperson, Sir, is regarding climate change vulnerability. Climate change poses a significant threat to India, manifesting in disruptive weather events from El Nino to record-breaking heatwaves. This overarching concern impacts various facets of the country, including threat to food security, extreme weather events like cyclones and heatwaves. In light of the history of nearly 60 cyclones in the last five decades causing damages totalling around Rs. 87,000 crore, I urge the Government to institute a permanent Central fund to compensate cyclone victims in Andhra Pradesh. The financial support from this fund will be essential for annually rehabilitating victims, repairing infrastructure damages, and establishing climate-resilient infrastructure and communication networks to enhance emergency response capabilities.

Furthermore, the Finance Minister's announcement of Blue Economy 2.0 during the Interim Budget to promote climate-resilient activities and sustainable development in coastal areas brings hope that these efforts align effectively with climate challenges, ensuring adequate Central assistance for States like Andhra Pradesh.

Regarding health and family welfare, I would like to mention about high out-of-pocket spending on healthcare. Although Government spending on healthcare in India has increased since 2013-14, patients still bear nearly half of all health costs directly in regard to medicines, diagnosis, and other medical expenditures. In 2018-19, while 40.6 per cent of health spending was covered by the Government, 48.2 per cent still came from patients, according to the Economic Survey 2022-23. Thus, despite improvements in State's healthcare funding, the burden of healthcare costs on individuals remains substantial. On average, Indian families allocate 7.9 per cent of their entire annual household expenditure to healthcare, emphasising the ongoing challenge of high out-of-pocket health spending.

The Government's flagship program, Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY), has experienced lower actual spending compared to the proposed budget estimates.

(1525/AK/MM)

In the fiscal year 2022-2023, the scheme's actual spending was Rs. 6,185.80 crore although the proposed estimate for FY 2023-2024 was Rs. 7,200 crore.

Dr. YSR Aarogyasri Health Scheme, a Government-sponsored healthcare initiative in Andhra Pradesh on the other hand ensures universal health coverage for all its beneficiaries. It addresses primary care by offering free screening and outpatient consultations in health camps and network hospitals, eliminating additional out-of-pocket expenses for its beneficiaries. The scheme provides end-to-end cashless services for identified diseases under secondary and tertiary care through a network of service providers from both the Government and private sectors. The scheme encompasses a comprehensive range of 2,434 surgeries and therapies across 30 systems.

The Central Government's commitment to rewarding good performance must be appreciated. However, these suggestions can possibly make a more robust mechanism, which would in turn act as a more persuasive incentive for States to improve their performance in all service sectors, especially in the Aspirational Districts Programme.

The Aspirational Districts Programme has been pivotal to the development of 112 districts and changing the lives of almost 25 crore citizens. Among these districts is YSR Kadapa, which has also been given the title of one of the best-performing districts among those in the Programme, and Parvathipuram Manyam District, whose performance has been so stellar that it was entitled to receive an additional Rs. 3 crore allocation last year. Such efforts to reward developmental efforts must be lauded. It is important to bring up more performance-based incentives within the programme to benefit States that are showing strong signs of improvement such as the districts of Andhra Pradesh.

Lastly, before I conclude, I would like to mention about renewable energy. As regards solar and other forms of energy, the commitment shown towards rooftop solarisation is extremely important given the urgency with

which sustainable mediums of energy generation must be promoted. This change must also be driven forward by public institutions. In our State of Andhra Pradesh, the Andhra University at Visakhapatnam has already installed solar energy generation systems on all its buildings' rooftops and has shown an admirable commitment to the implementation of the Net Zero Energy Program. So, I would request the Central Government to ensure other public institutions also take up similar measures.

Lastly, from the State of Andhra Pradesh under the dynamic leadership of our hon. Chief Minister, Shri Y. S. Jaganmohan Reddy Garu, I would like to conclude by mentioning the significant role that Andhra Pradesh plays in Bharat's journey toward prosperity. The State excels in education accessibility, ease of doing business, leading marine exports, organic farming, and ongoing efforts in supporting farmers and empowering women. Addressing the longstanding demand for a Special Category Status and fulfilling all commitments outlined in the AP Reorganisation Act 2014 will further enhance Andhra Pradesh's contribution to the nation's progress. The Central Government's collaboration with Andhra Pradesh can be instrumental in advancing Bharat's overall development.

Before I conclude, from the State of Andhra Pradesh a Telugu orator, poet, novelist and social reformer Gurajada Apparao *garu* said:

*Desamunu preminchumanna
manchi annadi penchumanna
vatti matalu kattipettoy
gatti male talapettavoy.*

With these few words, I convey my thanks for the President's Address and I support all these achievements of the Central Government from the State of Andhra Pradesh. We need wholehearted and more support for the State of Andhra Pradesh. Thank you very much, Sir. Jai Hind!

(ends)

(1530/YSH/UB)

1530 बजे

*SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BERHAMPUR): Hon. Speaker, Sir, I am grateful for the kind opportunity given to me to speak on the Motion of thanks to the President's Address.

On behalf of my leader Naveen Patnaik and Party Biju Janata Dal, I express my gratitude to Hon. President for her magnificent speech. I am equally proud of the fact that hailing from a humble tribal family of Odisha she became the President of our country.

In her speech she had mentioned several freedom fighters and unsung heroes. She started her address with a quote from Odisha's great poet, social reformer and political activist, Shri Gopabandhu Das's famous poem: "*Mishu mora deha ei desha matire ...*" meaning "Let my body mingle with the dust of my motherland".

Respected Sir, you will be glad to know Odisha is in the midst of hosting the Global Odia Conference.

Our Hon. President in her speech has lauded the Aditya and Chandrayan missions of the Union Government and appreciated the contributions of our esteemed scientists. I too on behalf of BJD appreciate the superb contribution of our scientists.

The Hon. President has mentioned the great contribution of our freedom fighter Shri Birsa Munda. I would like to remind you that when my leader Shri Naveen Patnaik was the Union Minister of Steel he was instrumental in the installation of statue of Shri Birsa Munda in the august campus of our Parliament. Later as the Chief Minister of Odisha he ensured the construction of a world-class Birsa Munda stadium in the steel city of Rourkela.

In para 6 of her address the Hon. President mentioned the Naari Sakti Abhiyan. While speaking on the Motion of Thanks, I take this opportunity to humbly remind the august House that it was our great leader Shri Biju Patnaik who first initiated steps to reserve 33 per cent seats in Panchayats and Municipalities for women, much before the Parliament came out with such a proposal. Shri Biju Patnaik was the frontline leader of our country whose death

* Original in Odia.

received homages from Russia and Indonesia. Following his father's footsteps, my leader Shri Naveen Patnaik has proposed at least fifty percent reservation for women. The Odisha Assembly has already endorsed the national motion of 33 percent seats reservation for women in State Assemblies and Lok Sabha. We in Odisha, especially BJD, have been urging the Union Government for conferring the award of Bharat Ratna posthumously on Shri Biju Patnaik for his visionary views, which I am sorry to mention has not been considered yet. We renew that demand. BJD also demands installation of a statue of the late Shri Biju Patnaik in the Parliament House premises.

My state Odisha boasts the highest population of tribal/janajati people. We have demanded that about 169 communities be included in the list of tribals/janajatis. I request the Union Government to take initiatives to accept the list.

Similarly, tribal dialects like Kui, Ho, Mundari, Bhumij and Saura are included as tribal languages in the Constitution Schedule.

Respected Sir, estimated 10 lakh poor people depend on tendu leaves as a source of livelihood. Unfortunately, GST levied on tendu leaves has been increased from five percent to 18 percent. My leader and Chief Minister of Odisha Shri Naveen Patnaik has called for complete abolition of GST on tendu leaves. The Union Government should look into the matter urgently.

The Ayushman Bharat Yojana has long been implemented in Odisha under the Biju Swastha Kalyan Yojana. Except for the income tax payees, almost the rest of population have been included as beneficiaries. A sum of Rs.10 lakh for women and Rs.5 lakh for men has been granted under this Yojana.

Sir, Odisha awaits at least seven lakh houses under Pradhan Mantri Awas Yojana. For possibly political reasons, Odisha is yet to get those houses. The Union Government must expedite the matter.

A matter of considerable concern is the sorry state of National Highways in Odisha. The NH-55 linking Cuttack with Sambalpur is in a pathetic state reporting at least 100 to 150 deaths in road accidents per year. Similarly, NH-16 needs urgent attention for proper maintenance.

Sir, Odisha Assembly has passed a resolution for Rs.2,930 as minimum support price for paddy, which has not been implemented yet. We demand a

quick action from the Central Government.

The Hon. Odisha Assembly has passed a resolution to include the word Ahimsa in the Preamble of our Constitution. We demand faster initiatives in this respect.

Sir, our demand for the Odisha Legislative Council is still pending despite being unanimously passed by the Odisha Assembly. We demand due action in this regard by the Union Government.

The demand for Special Status to Odisha and other various special packages still await the Union Government's nod. This has been an all-party demand.

Sir, Odisha demands a Central University in Sundargarh, our most tribal populated district. Similarly, we demand sincere support from the Central Government for our Drink from the Tap scheme which has been keenly implemented by the Odisha Government.

The Hon. President in her speech has highlighted the various developmental schemes of the Union Government. I take this opportunity to assure the august House of the deep commitment Odisha has for honouring those various pro-people projects. I conclude my speech with the earnest faith that the Central Government would equally be considerate with regard to our demands.

Vande Utkal Janani. Jai Hind.

(ends)

(1535-1540/KN/RCP)

1544 बजे

श्री मलूक नागर (बिजनौर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए पार्टी की तरफ से और आपने मौका दिया, उसके लिए मैं आपको दोबारा धन्यवाद देता हूँ। मैं देश की पार्लियामेंट में महसूस करता हूँ कि वर्ष 1913 में कोलकाता में शुरू हुई, वर्ष 1920-21 में यहां आई और वर्ष 1947 के बाद अब भी दोनों तरफ से सुनने को मिलता है। लेफ्ट साइड पर, जो अच्छे-अच्छे काम करें, जिन कामों की गुंजाइश थी, जो और बेहतर हो सकते थे, उनका कहीं जिक्र नहीं होता। राइट साइड पर देखते हैं तो सारे उठकर कहते हैं कि यह कमी, वह कमी और अच्छे काम में भी कमी निकालते हैं। वर्ष 1913 का देश एक और देश था। वर्ष 1947 के समय एक और देश था तथा आज एक और देश है।

(1545/VB/PS)

देश या पूरा संसार जिस तरह तरक्की कर रहा है, मेरे हिसाब से, हमारी चर्चा भी उस तरह की होनी चाहिए। मैं अपने साथियों से यह प्रार्थना करना चाहता हूँ।

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कई चीजें ऐसी हैं, जहाँ गुंजाइश थी, जो और बेहतर हो सकती थी। कई चीजें ऐसी हैं, जो बहुत अच्छी हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख था कि देश में जो बॉर्डर के गाँव हैं, उनको पहले देश का आखिरी गाँव कहा जाता था। अब अगर देश का पहला गाँव कहा जाएगा, तो पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की बाउंड्री पर जितने भी गुर्जर मुसलमान हैं, जो अपने आप को ऐसा महसूस करते थे कि बगैर तनख्वाह लिये हुए, उग्रवादियों से, पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान के फौजियों से लड़ते थे, उनको कहीं न कहीं यह लगा कि देश की सरकार हमारे बारे में यह सोच रही है कि हम आखिरी गाँव नहीं हैं, हम पहला गाँव हैं। हम इसकी सराहना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, थैंक यू बोलते हैं।

मैं आपके माध्यम से, सरकार से इसमें एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार ने वहाँ इतना ध्यान दिया, तो वहाँ बाउंड्री पर बसे हुए जो लोग हैं, उनके लिए कॉलेज और स्कूलों की कमी है। वहाँ कॉलेज और स्कूलों को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए। वहाँ के जो लोग लड़ते हैं, उनको वेपन्स के लाइसेंस दिए जाएं। वहाँ पर फोर्स की चौकी बनाकर उनको सुविधा दी जाए। वहाँ पर, देश की बाउंड्री लाइन पर एक एसईजेड डिक्लेयर किया जाए, जिससे वहाँ के लोगों को स्वाभिमान के साथ रोजगार और शिक्षा मिल सके।

दूसरी बात टैक्स से संबंधित है। पहले कारपोरेट टैक्स 30 परसेंट लगता था, जिसे पिछले दिनों 22 परसेंट और 15 परसेंट कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से, इसके बारे में, सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। जो लोग 60 साल से ऊपर के हैं, खास करके 70 वर्ष पार करते ही उनकी स्थिति ठीक नहीं रहती है। इसलिए जिस तरह से, कारपोरेट टैक्स में छूट दी गई है, तो 60 साल से ऊपर के लोगों को भी टैक्स में छूट दी जाए। जब आगे का बजट आएगा, तो जो सात लाख रुपए टैक्स की सीमा है, उस स्लैब को भी बदलकर दस लाख रुपए किया जाए।

देश में जो कच्चा तेल है, जिसे देश की बड़ी कम्पनियाँ निकालती हैं। उस पर जो सेस या टैक्स लगता है, वह बहुत कम है। आम आदमी, जो तेल का इस्तेमाल करता है, चाहे ट्रैक्टर में इस्तेमाल करता हो या खेत में पानी देने के लिए इंजन में इस्तेमाल करता हो, चाहे दूसरी सवारियों में हो, गन्ने को ले जाने के लिए ट्रैक्टर की ट्रॉलियों के इस्तेमाल में हो, इसलिए उस पर जो सेस या टैक्स लगाया गया है, वह थोड़ा ज्यादा है। अगर एक ही चश्मे से देखकर दोनों में सेस या टैक्स कम लगाया जाता तो बहुत अच्छा होता।

अभी आगे आने वाले दिनों में चुनाव है। हमें तीन महीने में चुनाव में जाना है। सारी चीजों की महँगाई, खास करके कोरोना काल के बाद सारी चीजों की महँगाई बढ़ी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जो गन्ना किसान हैं, वे बहुत परेशान हैं। पिछले सात वर्षों में केवल एक बार 25 रुपए रेट बढ़ा है, एक बार केवल दस रुपए रेट बढ़ा है, अभी चार-पाँच दिन पहले 10 रुपए रेट बढ़ा है। जबकि अगर सात वर्षों की महँगाई जोड़ें, तो किसी साल में महँगाई लगभग 9 परसेंट, किसी साल लगभग 8 परसेंट और किसी साल लगभग 11 परसेंट बढ़ी है, जो टोटल लगभग 80 परसेंट के आसपास बैठती है। जो रेट साढ़े तीन सौ रुपए का था, अगर उसका 80 परसेंट भी लगाएं, तो लगभग तीन सौ रुपए वह रेट बैठता है। इस तरह से, वह तीन सौ के आसपास होता है। इसलिए गन्ने का रेट कम से कम साढ़े पाँच सौ रुपए जरूर कर देना चाहिए ताकि गन्ने का रेट बढ़िया हो और किसान खुशहाल हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि किसानों की आय डबल हो, उस पैमाने पर भी किसान लगभग उसके करीब पहुंच सके।

सर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के संबंध में, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जो छोटे-छोटे कारखाने वाले लोग हैं, जो छोटी कम्पनियों वाले लोग हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जो चीजें हैं, उन पर सरकार और ज्यादा ध्यान दे। इनको भी टैक्स में छूट मिले और कुछ इंसेंटिव मिले, जिससे वे जमीनीस्तर से ऊपर उठकर तरक्की कर सकें। इससे वे देश की तरक्की को आगे बढ़ाएंगे और देश की इकॉनमी को भी मजबूत करेंगे।

(1550/PC/SMN)

सर, मैं आज पूरे देश से एक बात कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और करीब-करीब 24 करोड़ लोग हैं। वर्ष 1953 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी, दिल्ली के पहले मुख्य मंत्री ने एक रैली में कहा था, वर्ष 1955 में बाबा अंबेडकर साहब ने एक रैली में कहा और वर्ष 1989 में श्री के. सी. त्यागी जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और वर्ष 2012 में बहन कुमारी मायावती जी ने एक प्रस्ताव पास करके भेजा कि यह बड़ा प्रदेश है, इसको चार हिस्सों में बांटा जाए, जिनकी 8.5 करोड़ के करीब जनसंख्या है। इन 8.5 करोड़ में से कम से कम आधे से ज्यादा जो प्रदेश हैं, वे छोटे-छोटे प्रदेश हैं, वे 8.5 करोड़ से भी कम की आबादी के हैं। अगर सरकार इसको भी आने वाले समय में कंसीडर करे, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश के सारे हिस्सों को बढ़िया तरीके से चलाया जा सकता है।

सर, अगर इसमें देर भी लगे, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हाई कोर्ट जाने के लिए इलाहबाद जाते हैं या लखनऊ जाते हैं। उनको बहुत परेशानी होती है। वे शाम को चलते हैं, अगले दिन पहुंचते हैं और रहने की भी उन्हें बड़ी दिक्कतें होती हैं। अतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासकर मेरठ में हाई कोर्ट की एक बेंच की स्थापना की जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा।

सर, मैं आखिर में एक बात कहकर अपनी बात का समापन करूंगा। माननीय प्रधान मंत्री जी की यह सोच है कि किसान की आय डबल की जाए। मैं उस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस बारे में पूरे वर्ल्ड में, देश में, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स में और बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज में बहुत खर्चा होता है। रिसर्च का एक अलग डिवीजन होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में किसान द्वारा फसल को कैसे हाई-टेक तरीके से किया जाए, कैसे बढ़िया फूल पैदा किए जाएं और कैसे बढ़िया फल-फ्रूट आदि पैदा किया जाएं, इसके लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खुले और किसानों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर भी मेरठ में बनाया जाए, जिससे किसान बढ़िया तरीके से अपनी खेती कर सके और रिसर्च करके जो रिपोर्ट आए, उसके आधार पर बढ़िया तरीके से किसान को सपोर्ट कर सके। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश भर का किसान खुशहाल रह सकेगा।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1552 बजे

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे (शिरूर) : सभापति महोदय, आपका धन्यवाद।

मैं महामहिम राष्ट्रपति जी अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक बहुत ही अच्छी बात अपने अभिभाषण में कही। वह बात थी – "राष्ट्र सर्वोपरि" लेकिन राष्ट्र बनता किन चीजों से है? राष्ट्र न सिर्फ इमारतों से बनता है, न सिर्फ पुलों से बनता है, न सिर्फ बजट के आंकड़ों से बनता है, न इन्फ्रास्ट्रक्चर से बनता है, राष्ट्र उसके देशवासियों से, उसके इंसानों से और उनके दिल में पनपते देशभक्ति के जज्बे से बनता है। इन देशवासियों की परिस्थिति क्या है? हर देशवासी चाहता है कि वह एक भयमुक्त वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करे, लेकिन मेरे चुनाव क्षेत्र में ऐसी परिस्थिति नहीं है। नेशनल वाइल्डलाइफ सर्वे की अगर हम रिपोर्ट देखें, तो मेरे चुनाव क्षेत्र में 400-500 लेपर्ड्स का अधिवास है। मेरे चुनाव क्षेत्र में दिन में श्री-फेज़ लाइट नहीं होती है, इसलिए रात में खेत को पानी देने के लिए जाना पड़ता है। आए दिन किसी न किसी पर लेपर्ड का हमला होता है। आज तक 18,000 मवेशियों का नुकसान हुआ है। 20-25 लोगों ने पिछले साल में अपनी जान गंवाई है। जुन्नार फॉरेस्ट विभाग ने महाराष्ट्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। जो इकलौता सॉल्युशन है, वह लेपर्ड रीप्रोडक्शन कंट्रोल का सॉल्युशन है। इसके लिए मैं नियमित रूप से मंत्रालय से भी गुजारिश कर रहा हूँ। मेरी यह गुजारिश है कि मंत्रालय इस पर संज्ञान ले और लेपर्ड रीप्रोडक्शन कंट्रोल करे और मेरे चुनाव क्षेत्र में दिन में श्री-फेज़ लाइट देने का निर्देश राज्य सरकार को पारित करे। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में गरीबों के लिए मकान की बात की, जो निश्चित ही सराहनीय है, लेकिन मेरे चुनाव क्षेत्र में डेढ़ से दो लाख लोग ऐसे हैं, जो रहते तो पक्के घरों में हैं, लेकिन उनके घर अनऑथोराइज्ड करार दिए जा रहे हैं और इसकी वजह दिग्घी एम्युनिशन डिपो की वजह से लगा हुआ रेड ज़ोन है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने कानूनों में सुधार की बात की और समय के साथ हर किसी को बदलना चाहिए, लेकिन अगर हम रेड ज़ोन की बात करें, तो जो कानून फॉलो हो रहा है, वह वर्ष 1903 का अंग्रेजों के जमाने का इंडियन डिफेंस एक्ट फॉलो हो रहा है, जिसके तहत रेड ज़ोन की मर्यादा दो हजार यार्ड सुनिश्चित की गई है। लेकिन वर्ष 1970 का जो स्टेक रेग्युलेशन है, स्टोरेज टेक्निकल एक्सप्लोसिव कमेटी का जो यूनाइटेड नेशंस का रेग्युलेशन है, वह हमारे देश ने अडॉप्ट किया है। उसके अनुसार 200 से 500 मीटर ही रेड ज़ोन की मर्यादा होनी चाहिए।

अतः जब हम कानूनों में सुधार की बात करते हैं, तो मेरी सरकार से यह गुजारिश है कि जो कानून हमने अडॉप्ट किया है, उस पर अमल किया जाए और 500 मीटर के आगे रेड ज़ोन की इस मर्यादा से देशवासियों को राहत दी जाए।

(1555/CS/SM)

महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात की और विकसित भारत के जो चार स्तम्भ हैं, उसमें उन्होंने किसानों का जिक्र भी किया, लेकिन वास्तविकता यह है कि पिछले 35-40 दिनों से अनियन के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लग चुकी है। अनियन एक्सपोर्ट, प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगने की वजह से मेरे महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों का 2 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस पाबंदी की वजह से पाकिस्तान के किसानों का भला हो रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का मार्केट हो, यूरोप का मार्केट हो, यह पूरा पाकिस्तान अनियन ग्राउंड फार्मर्स के हाथ में चला गया है और पाकिस्तान के किसानों को उनके प्याज का दाम मिल रहा है, लेकिन मेरे किसान को अपना प्याज 8 से 10 रुपये प्रति किलो के दाम पर बेचना पड़ रहा है। हमने सरकार से सुना था कि पाकिस्तान की कमर तोड़ देंगे, लेकिन इस निर्णय की वजह से पाकिस्तान के किसानों का भला हो रहा है, कमर मेरे किसानों की टूट रही

है। यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने किसानों की आय दोगुनी होने की बात की थी। मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ वर्ष 2013 में डीएपी के एक बैग की कीमत 560 रुपये थी। वर्ष 2024 में डीएपी के बैग की कीमत 1100 रुपये है। प्याज के लिए जो लागत की मजदूरी थी, उसकी कीमत 5 हजार रुपये थी, आज लागत की मजदूरी 11 हजार रुपये जाती है। वर्ष 2013 में प्याज 20 रुपये किलो बिक रहा था, आज प्याज 8 से 10 रुपये किलो बिक रहा है। वर्ष 2013 में सोयाबीन 6 हजार रुपये प्रति क्विंटल की दर पर बिक रहा था, आज सोयाबीन 4,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है। इस तरह से किसान की आय दोगुनी हुई या दो गुने से ज्यादा घट गई है। जब हम विकसित भारत का एक स्तम्भ किसानों को मानते हैं, मैं यह कहना चाहूँगा कि विकसित भारत यात्रा होती है, दिल्ली में ठंड बहुत है, यह किसी को बताना नहीं पड़ता है कि ठंड बहुत है। हम महसूस करते हैं कि ठंड बहुत है। जब विकसित भारत है तो यह बताना क्यों पड़ता है? मेरा किसान यह महसूस क्यों नहीं कर पाता कि यह विकसित भारत है और मेरी आय दोगुनी हुई है? यह मेरी दरखास्त है कि किसानों के बारे में गंभीरतापूर्वक यह विचार किया जाए, क्योंकि अगर उगाने वाला उगायेगा नहीं तो खाने वाला खायेगा क्या, यह सवाल है। अंत में, महामहिम राष्ट्रपति जी ने राम मंदिर के निर्माण की बात की थी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, हमारे रामलला जो विराजमान हुए हैं, उसके लिए मैं समूचे देश का अभिनन्दन करता हूँ और उसी के बारे में कुछ पंक्तियाँ कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा।

महोदय, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात आयी, तो किसी ने कहा कि बिना कलश के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी। किसी ने कहा कि बिना कलश के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी, किसी ने कहा जब चुनाव ही प्राण हो, तो सोचो कौन सी प्रतिष्ठा दाँव पर लगी होगी। लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप जन की बात मत सुनना, मन की बात करना। फिर भी खुश थे हम, फिर भी खुश थे हम, 500 साल का सपना जो पूरा हो रहा था, हमारे अंदर का हिन्दू भी पूरी तरह से जाग गया था। तो चल पड़े अयोध्या की ओर रामलला के दर्शन की आस लगाये, चल पड़े अयोध्या की ओर रामलला के दर्शन की आस लगाये, जो सामने नजारा देखा, वह देखकर दंग रह गए। वह तीन मंजिला, 400 खंभे, 32 सीढ़ियाँ, जय श्री राम का नारा लगाते हुए हम सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। रामलला से क्या गुहार लगाएँ, यह सोचने लगे। पहली सीढ़ी पर याद आई महँगाई। पहली सीढ़ी पर याद आई महँगाई, दूसरी पर देश में बढ़ती बेरोजगारी, तीसरी पर पत्रकारिता की चरण चुम्बकता, चौथी पर सेंट्रल एजेंसीज की संदिग्ध भूमिका। हर सीढ़ी पर कुछ न कुछ याद आ रहा था। हर सीढ़ी पर कुछ न कुछ याद आ रहा था, कहीं 15 लाख का जुमला, कहीं किसानों का आक्रोश था। कहीं महिला कुश्ती वीरों की वेदना थी, कहीं सालाना दो करोड़ रोजगार का वादा था, कहीं बढ़ती साम्प्रदायिकता थी तो कहीं चुनिन्दा पूँजीपतियों पर मेहरबान हमारी सरकार का चेहरा था।

(1600/IND/RP)

इस वास्तविकता के झंझोरने के बाद भी हम अंधभक्तों की तरह चलते गए। होश तो तब संभाला जब राम लल्ला के दर्शन हुए। हमें नतमस्तक देख राम लल्ला मुस्कुराते हुए बोले मैं कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। जितना इस मंदिर में हूँ, उतना ही तुम्हारे मन में रहूँगा लेकिन हमेशा याद रखना कि मैंने त्रेता युग में राम राज्य लाया था तुम कलयुग में जीते हो, जहां संविधान ने गणराज्य लाया है। धर्म समाज का किनारा जरूर है लेकिन देश एक बहती धारा है। किनारे को धारा के बीच में लाया तो प्रवाह अड़ जाता है, प्रगति के पथ से हट जाता है इसलिए धर्म का ठेकेदार नहीं पहरेदार बनना चाहिए। तुम रहो न रहो, वो रहे न रहे, ये देश रहना चाहिए। देश का संविधान रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। यह देश, देश रहना चाहिए। जय हिंद। धन्यवाद।

(इति)

1600 hours

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Thank you, Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President's Address.

Sir, it was indeed a very proud moment. कल बहुत गर्व महसूस हुआ था जब महामहिम राष्ट्रपति जी ने हम सबको संबोधित किया। एक आदिवासी होने के नाते मैं समझ सकता हूँ कि इसका क्या मतलब है। मैं अपनी बात दो-तीन मुद्दों पर रखना चाहता हूँ। हम आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी चीज जल, जंगल और जमीन होती है। फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 2023 पारित किया गया, उस समय हम शायद सस्पेंड थे या बाहर थे, जिसे बिना डिस्कशन के पारित किया गया है। पारसा ईस्ट एंड कांटा बासन कोल माइन्स फेज-2 एक्सटेंशन ऑफ कोल माइन्स हैं, इस अमेंडमेंट के द्वारा ऐसा हुआ, the Government and the developers can now acquire land for mining without any consent of local stakeholders for their business purposes.

1602 hours

(Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

The second thing is that they have redefined the definition of forest. I will quote some Supreme Court judgements. The first one is the 1997 Samata Judgement which said that no private party can do mining in schedule areas. There is a famous Niyamgiri Judgement which said that the allotment of lands should be completed first before the commencement of any public projects. Then we have the Godavaram Judgement which said that forest means all the forests naturally found and is not limited to notified forests. With this amendment in the Forest Conservation Act, now, they are mentioning about only notified forests. So, what will happen is that the judgements and other landscape, whatever is there, now, 50 to 75 per cent of country's forest areas cease to be existing. This particular amendment is diluting the Forest Rights Act and the Gram Sabha, the informed consent, and the local stakeholders. The Gram Sabha used to decide for what purpose the forest land will be diverted. That is also getting diluted. This is a very serious concern which will impact almost 700 million tribals across the country. We have also seen how it is happening after the new Government formed in Chhattisgarh. They are conducting fake Gram Sabha meetings. I will give you an example. We have Balda, Mali Parbat, and Hasdeo mines. First, the Government gave the mining control to the corporate houses and then they leave it to the State Government

to take care of tribal rights, land conflicts, and so on. If you have already given land, then, what is this all about? They are diluting all the judgements.

As far as the claims are concerned, 80 per cent claims of the forest dwellers have been rejected by the Central Government. I will give you an example. In the past as well, there used to be rejection. Before 2014, out of 308 million claims, only 54 per cent were rejected. But after 2014, if you look at the data, out of 2.7 lakh claims, around 79 per cent claims have been rejected. So, the land which was supposed to be given to the tribals through the Forest Rights Act, now, this is slowly going away. I will give you an example of the Nagarnar Steel Plant. It was conceived way back in 2015 by the Government. The Government gave them the mines in Bailadila for the welfare of Bastar tribal people under the pretext that these tribal people will get guaranteed jobs there. It was commissioned just before the elections. NMDC has 61 per cent stake but no one knows when the disinvestment will happen. Ultimately, this will be privatised. नगर नाल स्टील प्लांट का जो आइडिया था कि बस्तर के आदिवासी लोग वहां काम करेंगे, वह भी धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। आदिवासियों की जो मेन समस्या जल, जंगल, जमीन है, यह सरकार एक-एक ऐसे कानून लेकर आ रही है, जिससे हमारे अधिकार डाइल्यूट होते जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अवगत करना चाहता हूँ कि इसे रोकने की कड़ी आवश्यकता है।

(1605/NKL/RV)

Sir, in scheduled areas, there are a lot of people from scheduled caste community. I will talk about my areas, Rayagada and Koraput districts. वहां 20 प्रतिशत डोम्बो कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ये पहाड़ों पर भी रहते हैं। उन्हें डोंगरिया डोम्ब कहते हैं। जैसे डोंगरिया कोंध पी.वी.टी.जीज़. हैं, similarly, the Dongria Domb community stay in mountains. They belong to the Scheduled Caste community. इनकी मेन डिमांड यह है। It is not because they belong to Scheduled Caste community but because they live in scheduled areas, in mountains which basically have no access to mainstream life. This Dombo community has to be recognized as a vulnerable community, and its language, folklore and folk dance should also be recognized. Promotion of art, culture, custom and tradition of Dombo community is something which is the need of the day.

We need a special development council similar to that of the Scheduled Tribes for the Dombo community also, who are Scheduled Caste people. We need to have model residential schools in line with the Eklavya Model with 200-bedded hostel facilities. Apart from this, we should have employment

opportunities. When we have industries in mining areas, 90 per cent of the employment opportunities should be reserved for the local people, who belong to SC, ST and OBC communities.

Talking about the homestead land, the Scheduled Caste people are not getting the homestead land. प्रधान मंत्री आवास योजना से वे लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए उन्हें होमस्टेड लैंड की सुविधा भी प्रोवाइड करनी चाहिए। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में हम लोग आदिवासियों के साथ लैंड को डील कर रहे हैं, पर एक गैर-आदिवासी को 30 सालों का रेसिडेंट प्रूफ दिखाना पड़ता है, पर एस.सी. के जो विभिन्न लोग हैं, जो डोम्ब लोग हैं, इन्हें 3 साल के बदले उससे छूट दी जाए, क्योंकि अगर वे जंगलों में रहते हैं तो उन्हें उसका अधिकार मिलना चाहिए।

सर, जहां तक लोकल बॉडीज़ में उन्हें रिजर्वेशन मिलने की बात है तो अभी भी वहां पर शिड्यूल्ड एरियाज़ में एस.सी. लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। The most important thing for tribals is this. As a tribal, I do not have access to any financial institution. मुझे लोन नहीं मिलता है, न ही बिजनेस डेवलपमेंट के लिए लोन मिलता है, न पढ़ाई के लिए लोन मिलता है, न घर बनाने के लिए लोन मिलता है। वहां मेरी जगह है। I understand the importance of the fact that tribals should not be landless. But if I do not get access to finance, if I do not get access to loan system, how will I develop myself? I cannot mortgage my land, the Government does not want it, and I do not have access to the finance system. This was fine till some point of time. पर, अभी यह हो रहा है, उसी सेम जगह पर, the Government is encroaching our land, and that is the acquisition for Bharatmala Project, acquisition for mining projects and other large projects. So, this leaves us nowhere. At least, there should be some policy, there should be some discussion on how we can solve the issue. The State Government of Odisha came up with a policy stating that tribals can sell their land to non-tribals. We condemn it, we reject it. This is not the solution. The Tribes Advisory Council should sit and see what can be done in this regard. The Government should interfere in this regard so that we can mortgage our land with the banks. But if you just open the whole thing, and allow tribals to sell the land to non-tribals, this will create chaos. All the tribals will remain landless.

We need to have a national policy on Scheduled Tribes to give a framework for tribals for the overall development.

There have been increased attacks on Christian tribals throughout the country. If you look at the Bastar region of Chhattisgarh or Gunupur, Godari

and Chandrapur districts of Odisha, the Christian tribals are being attacked. मैं फिर से यह कहूंगा कि हम आदिवासी लोग धर्म के प्रहरी होते हैं। चाहे वे क्रिश्चियन हों, हिन्दू हों या दूसरी जाति के हों, पर हम लोग पहले ट्राइबल्स होते हैं। किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी को सुरक्षा प्रदान करने का काम सरकार का होता है। क्रिश्चियन ट्राइबल्स की हिफाज़त का काम भी माननीय प्रधान मंत्री जी का होना चाहिए।

सर, केंद्रीय पत्ता फॉरेस्ट प्रोजेक्ट होता है। हमारे आदिवासी लोग वनों में जाकर केंद्रीय पत्ते का संग्रहण करते हैं और उसे हम लोग बेचते हैं। That is our livelihood. This Central Government is so insensitive कि उस पर जो 5 प्रतिशत का जी.एस.टी. था, उसे बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया। सर, आपके माध्यम से हमारी यह डिमांड है कि इस जी.एस.टी. की दर को तत्काल हटाना चाहिए।

I will come back to some important projects in my constituency before I wrap it up. The Gunupur-Therubali rail line project was announced by the Government in 2017-18. It has been a long-pending demand. It is primarily a tribal dominated district. The RoR previously was minus three per cent; the revised RoR is now positive. Regarding this particular project, they had some discussion with the State Government in which it was discussed that the State Government will share the cost and give land free of cost. That is happening. But irrespective of that, the Central Government has to invest in this particular project which is the lifeline of Rayagada. This is pending for a long time. So, the completion of Rayagada rail division and Gunupur-Therubali line has to be done immediately.

(1610/VR/GG)

Sir, the State Government of Odisha has written to the Central Government that 180 communities should be given tribal status. We do not agree with this. If you give tribal status to everyone, where will the tribals go? There are some genuine communities which have to be taken care of. This can be ascertained through their anthropological details, primitive traits, socio-economic conditions, etc. Jhodia, Durva and Dora are such tribes which really deserve to be in the list of tribal communities. But if the State Government wants to include 180 to 200 tribes into the category of Scheduled Tribes, then the Central Government would not do anything. This is something which needs discussion between the Central Government and the State Government. इनको आपस में बैठ कर देखना चाहिए कि कौन एक्यूअली ट्राइबल है। आप सभी को ट्राइबल नहीं कर सकते हैं। पिछले सेशन में एक बिल आया था, वह हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल्स के लिए था, उसमें

आपने यह बताया कि कुछ लोग जो ट्राइबल कम्यूनिटी के हैं, उन्हें एसटी बना दो और बाकी लोग जो बच गए, जो एसटी नहीं बनना चाहते हैं, उनको एससी कैटेगरी दो। Scheduled Tribes and Scheduled Castes are quite different. Their primitive traits, distinctive culture, geographical isolation, and economic conditions are four points that define that a community is a tribal community. 180 ट्राइब्स को आप आदिवासी नहीं बना सकते हैं। तीन-चार जो मेन हैं, उनको आप बनाओ, बाकी भी आप देखो कि इनकी क्या एंथ्रोपॉलॉजिकल डिटेल्स हैं, ये एक्चुअली ट्राइबल्स हैं कि नहीं, उनकी संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है, उसके बाद यह करना पड़ेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की सैलरी बहुत कम है। हमारी राज्य सरकार उनसे वादा कर-कर के उनको सिर्फ ठग रही है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वे लोग बहुत परेशान हैं और बहुत मुसीबत में हैं। सर, हम आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि उनकी सैलरी कम से कम 20-25 हजार रुपये करनी चाहिए। जो हैल्पर्स हैं, उनकी सैलरी कम से कम 15 हजार रुपये करनी चाहिए। इसके साथ-साथ उनको पेंशन की सुविधा भी मिलनी चाहिए।

Koraput, Jeypore and Rayagada bypass is pending for a long time. We took a lot of trouble in getting this approved. लेकिन अभी यह लैण्ड एक्विजिशन में फंस गया है। हमारा यही अनुरोध होगा कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए।

सर, मैं अंत में पेंशन के बारे में कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में महिलाओं को 500 रुपये और बुजुर्ग महिलाओं को 750 रुपये दिए जाते हैं। सर, आज की तारीख में यह बहुत कम है। हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार इस पर कॉग्निजेंस ले कर इनकी पेंशन बढ़ा कर कम से कम तीन हजार रुपये महिलाओं के लिए और बुजुर्ग महिलाओं के लिए कम से कम 3500 रुपये की जाए। We should think of a broader minimum financial parity system. Universal basic income is a concept which has to be thought about. इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं कि सबकी एक बेसिक इनकम होनी चाहिए। इसके बारे में भी सोचना चाहिए।

इन्हीं बातों के साथ मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया का बहुत-बहुत धन्यवाद कर के अपने भाषण को यहीं विराम देता हूँ।

धन्यवाद।

(इति)

1613 बजे

श्री सुधीर गुप्ता (मन्दसौर): माननीय सभपति जी, मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा पर समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मन को बड़ी प्रसन्नता है कि जब राष्ट्रपति महोदया हमारे इस नए सदन में प्रवेश कर रही थीं, तब सैंगोल के साथ उनकी आगवानी की गई। बड़ी भव्यता थी, बड़ी सादगी थी और हम सबने आत्मीय रूप से स्वागत कर के मन को बड़ी प्रसन्नता दी है।

मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया के उन शब्दों को यहां दोहराना चाहता हूँ, जो उन्होंने अपने संबोधन के प्रारंभ में कहे। उन्होंने कहा कि – इस नए संसद भवन में यह मेरा पहला संबोधन है। आजादी के अमृतकाल के शुरुआत में यह भव्य भवन बना है। यहां एक भारत और श्रेष्ठ भारत की महक भी है। भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना भी है। इसमें हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सम्मान का प्रण भी है। साथ ही, 21वीं सदी के नए भारत के लिए नई परंपराओं के निर्माण का संकल्प भी है।

मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा और ऐसी नीतियां बनेंगी, जो आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत का निर्माण करेंगी, मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से यह संबोधन भारत की राजनीति में हम सब लोग, जो लाखों-लाख लोगों द्वारा चुन कर यहां आते हैं, उन पर एक बड़ा ही विश्वास है। राष्ट्रपति जी के मन में बड़ी आशाएं हैं कि अमृतकाल के इस दौर में यह भवन भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना का आधार बनते हुए लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे ले जाएगा।

(1615/MY/SAN)

माननीय सभापति जी, निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं कि मन के अंदर जो संकल्प और भाव होते हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदया ने उन संकल्पों को हम सब के सामने दोहराया और सरकार के किए कामों को गर्व से यहां कहा। निश्चित रूप से किसी सरकार के काम में अनुशासन एक महत्वपूर्ण परिधि होती है। हम जानते हैं कि जो वित्तीय असमानताएं देश के सामने रही हैं, उसको समानता की तरफ ले जाना एक बड़ा संकल्प था। तभी हम कहते हैं कि

अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला,
जिस दिये में जान होगी, वही दिया रह जाएगा।

भारत अपने वित्तीय एकीकरण के दौर में वित्तीय प्रबंधन को साधते हुए, वित्तीय संस्थाओं के बीच अनुशासित तरीके से आगे बढ़ा है। घरेलू वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुकूलता, कानूनी प्रतिबंधों को संज्ञान में लेना और वित्तीय प्रबंधन में सारे संस्थानों का उपयोग करना, यह हमारी बड़ी सफलता है। चाहे बीमा संस्थानों का उपयोग हो या बैंकों का, जनधन खातों के माध्यम से हमने एक दिव्य संदेश दिया। आजादी के बाद बैंकों का एकीकरण तो कर दिया गया था, मगर उसके पीछे विचार नहीं था। उसके पीछे एक अनुशासित कार्यप्रणाली को लेकर आगे चलने वाले ठोस व्यक्तित्व का अभाव था। आज नरेन्द्र मोदी जी के आह्वान पर वही बैंक, वही लोग, वही बिल्डिंग,

वहीं कंप्यूटर, मगर एक नया खाता न खोल सकने वाली बैंक 45 करोड़ लोगों को अपने उसी संसाधन के अंदर समाहित कर पाई, यह दुनिया के सामने अभूतपूर्व था। डिमोनेटाइजेशन का एक सधा हुआ संकल्प जिसके परिणाम आज देश ने देखे हैं। अगर हम इसको देखते हैं तो आईटीआर की संख्या जो 3 करोड़ के आसपास थी, आज 8 करोड़ की बड़ी संख्या का आधार बनाकर लोग अपने इस देश के वित्तीय विकास में योगदान देने के लिए एक अनुशासित वित्तीय प्रबंधन के कारण जुड़ पाए हैं।

हम जानते हैं कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जिस प्रक्रिया को आधार बनाने का आधार बनकर आगे बढ़ा है, जेम पोर्टल के माध्यम से गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेसमेंट हुआ है। उसमें अभूतपूर्व पारदर्शिता हम सबके सामने देखने को मिली है। कई लोग जीएसटी की बात को इधर-उधर की बातों में घुमाते हैं, लेकिन जब एक देश – एक कर को आधार बनाकर काम करने का महान संकल्प लिया था, आज 1,64,000 करोड़ रुपये का कर कलेक्शन, 1 करोड़ 40 लाख से अधिक लोग अपने-आप को इस वित्तीय कर प्रबंधन में जुड़कर और खुश होकर आगे बढ़े हैं। तब हम देख पाते हैं कि अगर वित्तीय प्रबंधन को अनुशासन के साँचे में लाकर ढाला गया तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे परिणाम सामने आते हैं। हम दुनिया के सामने 142वें रैंक पर खड़े थे, आज 63वें रैंक पर खड़े होकर हमने अपना आधार बढ़ाया है। उसके परिणाम भी देश को देखने को मिले हैं। आज अगर वाहनों की बिक्री देखें तो 21 करोड़ वाहन बिके हैं। यह आधार बताता है कि देश और आम जन के बीच में आर्थिक प्रबंधन बढ़े हैं। लोगों ने पर्यावरण को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से 12 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं। यानी देश के नेता अगर अपील करते हैं तो जनता के बीच में सर्वमान्यता से उसकी स्वीकार्यता बढ़ जाती है।

माननीय सभापति महोदय, यह सब जानते हैं कि वित्तीय प्रबंधनों के कारण ही एमएसपी का हम एक बड़ा व्यापक घेरा बना पाए हैं। हमने किसानों को उनके समर्थन मूल्यों की आवश्यकतानुसार भुगतान करने की प्रक्रिया को बहुत विस्तार दिया है। हमने किसानों को बीमा के माध्यम से एक विश्वसनीय व्यवस्था को सुदृढ़ ढाँचे में ढाल कर आगे बढ़ाया है। हमने सब्सिडी सेक्टर में बहुत बड़े विस्तार किए, ताकि कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में और आधार बन सके। हमने किसानों को सम्मान निधि के माध्यम से एक अनुशासित ढाँचे में ढाल कर 11 करोड़ से अधिक किसान भाइयों को हम अपने आप में जोड़ पाए हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह वित्तीय अनुशासन का ही परिणाम था कि अगर हम नीचे जाकर स्थानीय निकायों में देखें, शहरों के वित्तीय प्रबंधनों में देखें तो भारत सरकार के प्रबंधनों की झलक स्पष्ट रूप से गाँव-गाँव, गली-गली, डगर-डगर में हमको देखने को मिलती है।

(1620/CP/SNT)

चाहे वह फिफ्टीथ कमीशन का विषय हो, चाहे वह नरेगा का विषय हो, हम सब लोगों के विश्वास को आधार बनाकर काम कर पाए हैं। बैंकों के अंदर एक अविश्वास खड़ा था। लोग अपनी डिपोजिट्स को रखें या न रखें, इस प्रश्न पर खड़े थे। आज बैंकिंग ढाँचा सुदृढ़ हुआ है और बैंक एनपीए 4 प्रतिशत पर लाकर खड़ा किया है।

महोदय, हम जानते हैं कि वर्ष 2013-14 की जो शासन व्यवस्था थी, भारत की सेना, रिटायर्ड सैनिक सड़कों पर खड़े थे, वन रैंक, वन पेंशन की लंबे समय से उनकी मांग थी। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि वित्तीय अनुशासन का परिणाम है कि नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सुदृढ़ ढांचागत विकास हुआ है। आज एक लाख करोड़ से अधिक का भुगतान सिर्फ वन रैंक, वन पेंशन के हितग्राहियों को प्राप्त हुआ है। हम सब जानते हैं कि किस तरीके से भारत में औद्योगिक सुधार हुआ है। एमएसएमई सैक्टर के अंदर सुधार अभूतपूर्व है। यह भारत के युवाओं को उत्साहित कर रहा है, यह भारत के युवाओं के आगे बढ़ने के संकल्प को दृढ़ कर रहा है। 1 लाख से अधिक स्टार्ट अप्स देश में खड़े हो जाना, 1 लाख 60 हजार से अधिक कंपनीज का विकास और निर्माण हो जाना, शहद से लेकर खादी तक, खिलौने से लेकर रक्षा उत्पादनों तक का अगर निर्यात बढ़ जाता है तो हम गर्व से कह सकते हैं कि वित्तीय अनुशासन के जो फार्मूले देश के प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी ने जो हमको दिए हैं, उसका एक दृढ़ परिणाम है। हम सब जानते हैं कि वैक्सिनेशन प्रोग्राम जिस तरीके से देश में ढाला गया, मैं तो आग्रह करूंगा उन सभी विपक्षी संबोधन देने वाले ऐसे सांसद भाइयों से वे एक बार दी वैक्सिनेशन वार फिल्म अवश्य देख लें। उन्हें पता पड़ जाएगा कि वे कर क्या रहे थे?

उन्हें पता चल जाएगा कि देश में अनुशासनहीन व्यवस्थाएँ किस तरीके से भारतीय मनमानस को नीचे गिराने का काम कर रही थीं। आज वैक्सिनेशन वार पिक्चर देखने के बाद भारत के अंदर की व्यवस्थाएँ, उनके कुप्रबंधन और देश के लिए जूझने वाले उन लोगों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट होगा, जिन्होंने रात-दिन, अहर्निश परिश्रम करके और विशेषकर 70 प्रतिशत बहनों ने आईसीएमआर में अपनी जानें लगा दीं। उन्होंने अपने परिवार की चिंता न करते हुए, वैक्सिनेशन प्रोग्राम का एक ऐसा आधार खड़ा किया कि आज भारत दुनिया के सामने सिर ऊंचा करके कह सकता है कि यह बदला-बदला भारत है।

माननीय सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि वित्तीय प्रबंधनों के बहुत सारे क्षेत्रों में परिणाम आए हैं। हम यह भी जानते हैं कि क्षेत्रीय असमानताएँ और उसके कारण देश का विकास प्रभावित रहा है। नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश एकजुट होकर काम करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ा है। क्षेत्रीय असमानताओं के कारण हम सब जानते थे कि ब्रिटिश इंडिया ने जिस तरीके को एडॉप्ट किया था, क्षेत्र की असमानताएँ बनाने के कारण, उनको उनके उद्योगों को और उनकी स्वयं की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन करते हुए बाकी क्षेत्रों में विकास को जीरो करते हुए और देश के धन का दुरुपयोग करने का मौका मिला था। कांग्रेस ने भी, चूंकि आजादी के बाद देश उनके पास था और उनकी सोच में कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम जो ब्रिटिश आईएस अधिकारी थे, इटावा के कलेक्टर थे, जिन्होंने जिस पार्टी को आधार बनाया था, उस पार्टी के अंदर जो बीज प्रवाहित थे और ऐसी ही सोच लेकर इन्हें जब सरकार चलाने का मौका मिला, ये उसी ब्रिटिश सोच पर देश को चलाते रहे। हम क्षेत्रीय असमानताओं के कारण देश को एकजुट तरीके से विकसित नहीं कर पाए।

सभापति महोदय, हिंसक संघर्ष, विद्रोह, वामपंथी उग्रवाद और हरित क्रांति को कई क्षेत्रों से दूर रखना, यह एक दुष्परिणाम था। रेलों का विकास लक्षित नहीं था।

“मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है,
हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है।
डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में,
लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है।”

इसीलिए मोदी जी ने लड़कर अपने कदमों में पूरी प्रक्रिया को लाकर खड़ा किया है। बजट में हम सबने एक विकसित भारत को सबके सामने संकल्पित करने का प्रण लिया था, उसका परिणाम है कि क्षेत्रीय समानताओं में जो गिरावट थी, उसको सुदृढ़ तरीके से हम आगे ले जा पाए हैं, चाहे वह पूर्वोत्तर क्षेत्र का पर्यटन विकास हो या सीमाओं के रेलवे से लेकर और परियाजनाओं के विकास हों।
(1625/NK/AK)

क्षेत्रीय असमानताएं नार्थ ईस्ट के राज्यों के साथ-साथ गरीब जिलों में भी रही। आज 123 अकांक्षी जिलों को चिह्नित करके माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश को एक नई दिशा दी है। बेहतर स्टार्ट-अप्स, इको सिस्टम का विकास हुआ है। देश में कौशल उन्नयन का विकास हुआ है। पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए वृक्षारोपण से लेकर बांस प्रत्यारोपण का विकास हुआ है। देश के विकास को चिह्नित करते हुए किन-किन चीजों में गलतियां हुई हैं, देश ने आजादी के बाद से असमान विकास किया था, उसका दुष्परिणाम मेरे क्षेत्र ने भी झेला था।

आज दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे एक लाख करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, ऐसा रोड जो मेरे संसदीय क्षेत्र से जाता है जो ट्राइबल क्षेत्र के निकट से होते हुए निकलता है। क्षेत्रीय असमानताओं के कारण हमारे उस क्षेत्र का विकास असंभव था जिसे मोदी जी ने संभव करके बताया है। मेरा संसदीय क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, विकास की राह देखते-देखते 75 वर्ष बीत गए। मगर हम खुश हैं कि कल के बजट में 500 करोड़ रुपये रेलवे के विकास के लिए मेरे संसदीय क्षेत्र को मिला। मैं रेल मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने अभूतपूर्व विकास किया है। आज रेलों के विकास के कारण मेरा संसदीय क्षेत्र देश के मैप पर आकर खड़ा हुआ है। एनएचएआई से जुड़ने के कारण राष्ट्रीय परिदृश्य में मेरा संसदीय क्षेत्र सबसे पीछे था, वह आगे के क्रम में खड़ा हो गया है।

हमारे यहां कुछ फसल होती हैं जो वित्त मंत्रालय के अधीन रहती है। जिस तरीके से इस पर व्यापक ध्यान दिया गया है, 1 लाख से अधिक लोगों को अफीम की फसल से जुड़ने का एक बड़ा मौका मिला है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि यह वित्तीय प्रबंधन का कमाल था, चम्बल नदी हमारे मुहाने पर खड़ी थी। आज एक-एक इंच भूमि चम्बल के पानी से सिंचित होने के लिए आगे बढ़ गई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने विशेष प्रयत्न करते हुए चम्बल के पानी को एक-एक इंच भूमि पर सिंचित करने के लिए आगे बढ़ा दिया है। हजारों हेक्टेयर भूमि चम्बल के पानी से सिंचित होने के लिए आगे बढ़ गयी है। हम क्या-क्या गिनाएं?

मेरे संसदीय क्षेत्र में तीन मेडिकल कॉलेज खुल कर प्रारंभ हो चुके हैं। इस पर गर्व करने के अलावा उत्साहित होकर या उल्लासित होने के अलावा या धन्यवाद देने के अलावा कोई रास्ता

नहीं है। एक सैनिक स्कूल मेरे जैसे ग्रामीण, पिछड़े और गरीब जिले में खुलकर खड़ा होता है तो हम गर्व महसूस कर सकते हैं। दो सेन्ट्रल स्कूल खोले गए, पीएम-श्री स्कूल, मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल की श्रृंखला खड़ी हुई, तीन नर्सिंग कॉलेज भी मेरे संसदीय क्षेत्र में खोले गए। खेलो इंडिया के माध्यम से अच्छे ग्राउंड्स का विकास हुआ है।

न जाति की राजनीति करूंगा, यह दृढ़ इच्छा देश के प्रधान की है। न धर्म की राजनीति करूंगा, कैसे हो मेरे गांव का विकास, मैं उस रणनीति की बात करूंगा। जब देश का प्रधान जातिवाद से ऊपर, धर्म से ऊपर गरीबी को पैमाना बनाकर काम करता है। ये जातिवाद की दलदल में ले जाकर रोज वोटों की बात करते हैं, रोज एक-दूसरे को एक-दूसरे से उलझाने की बात करते हैं, तब देश के प्रधान के मुंह से हम विचार सुनने के लिए लालायित रहते हैं कि जातिवाद के दंश से माननीय मोदी जी कैसे निपटेंगे।

वह कहते हैं, मैंने 4 जातियां चिह्नित की हैं, जिनको विकास के क्रम में आगे ले जाना है। पहली जाति-कृषक, दूसरी जाति-महिला, तीसरी जाति-युवा और चौथी जाति-गरीब। जब इस आह्वान को हम अपने संसदीय क्षेत्र में जनता के बीच ले जाते हैं तो जनता भाव-विभोर हो जाती है। वह कहती है कि तमाम दलों ने हमें जातियों के दलदल में डाला है और आज हम जातियों से दूर रहते हुए विकास की बात करते हैं। गरीबी हटाने का नारा तो 1971 में लगा था। मनोज कुमार ने प्रभावित होकर एक पिक्चर भी बना दी थी, रोटी, कपड़ा और मकान। न रोटी मिली, न मकान का पता था, न कपड़े का पता था। गरीबी के दलदल में जूझता हुआ यह देश आज 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क राशन पहुंचाकर एक विश्वास प्राप्त कर चुका है।

(1630/SK/UB)

सभापति जी, मैं अपने संसदीय क्षेत्र में देखता हूँ, शहरों में, गांवों में झुग्गी-बस्तियां लगभग गायब हैं। शहरों की झुग्गी-बस्तियों में जबरदस्त सुधार हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनने के क्रम और विश्वास का क्रम बहुत बढ़ा है। जब माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी की विकसित भारत की संकल्पना की मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जाती है, तब लोगों के मन में अभूतपूर्व र्नेह जाग्रत होता है और लोग विश्वास के भाव से देखते हैं कि अब मेरा भी समय मैं देश को बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में विकसित भारत यात्रा के दौरान हाथ खड़े करवाकर पूछा कि गैस का चूल्हा किसे प्राप्त नहीं हुआ, तब लगभग एक-दो नाम सामने आए, जिनमें घर का विभाजन हुआ था। इनके अलावा और कोई हाथ खड़ा नहीं हुआ। सबके घर गैस चूल्हा पहुंच गया है। सड़कें गांव-गांव तक पहुंच गई हैं और स्कूलों की व्यवस्थाएं भी बनी हैं।

महोदय, एक समय था जब कुंओं से पानी लाना पड़ता था और पानी दूषित होता था। पांव से कीड़े निकलते थे। ग्रामीण भारत में एक-दो फीट सफेद रंग का कीड़ा पांव में होता था, जिसे देशी भाषा में वारा कहा जाता था, तड़प-तड़प कर निकाला जाता था। आज जब विकसित भारत बनने का दौर आया है और अब मैं अपने संसदीय क्षेत्र के गांव-गांव में चम्बल का पानी पहुंचते हुए अपनी आंखों से देख रहा हूँ। जब लोग घरों में रिश्ता बनाते थे और पहले जो बहुएं आती थीं उनको पीतल के तीन मटके उठाने पड़ते थे और बगल में एक मटका लेकर चलना पड़ता था। पानी के प्रबंधन में

धीरे-धीरे सुधार होता रहा लेकिन आखिरकार पानी घरों तक नहीं पहुंचा। माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अटल जी के नेतृत्व में जब शिक्षित भारत अभियान चला, भारत में हर एक बच्चे को पढ़ने का अधिकार मिला तब लड़कियां गांव में ब्याहने से पहले अपने पिता से पूछने लगीं कि जिस गांव में ब्याह रहे हो उस गांव में पानी तो नहीं लाना होगा। अब हम सभा में खड़े होकर कहते हैं कि पाइपलाइनों का जाल कई किलोमीटर तक बिछ रहा है, इसके साथ ही हम कहते हैं कि अगर नई बहू घर में आ रही है तो विश्वास से कह दो कि दिसंबर, 2024 में आपके घर में पीने का पानी टॉटी द्वारा चूल्हे पर उपलब्ध होगा। इस पर हजारों-सैंकड़ों की तादाद में महिलाएं भावुक होकर कहती हैं कि हमने ऐसा प्रबंधन जिंदगी में नहीं सोचा था।

हम जानते हैं कि देश के पूर्व प्रधान देश के लोगों के सामने कहते थे कि अगर मैं 100 रुपये भेजता हूं तो लोगों को 85 रुपये ही प्राप्त होते हैं। मैं ग्रामीण लोगों से पूछता हूं कि सरकार ने जितना पैसा भेजा है, तुम्हें कितना मिला है?

अब हम गर्व से कह सकते हैं कि 34 लाख करोड़ रुपये की बड़ी राशि डीबीटी से ट्रांसफर हुई। अगर इसका 15 प्रतिशत निकालें तो 5 लाख 10 हजार करोड़ रुपये ही पहुंचता, 28 लाख करोड़ रुपये तो घपले में ही चले जाते, 28 लाख करोड़ रुपये तो भ्रष्टाचार में ही चले जाते और 28 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार में लालायित होकर कई लोग न्याय यात्रा कर रहे हैं, कई लोग दीवाने बन रहे हैं कि 28 लाख करोड़ रुपये तो उनकी पॉकेट में मिलते। देश का पैसा बच गया और वह गरीब के घर चला गया। गरीब के घर खुशियों की बहार है और गरीब के घर के आंगन में खुशियों की रंगोली बनी है।

सभापति जी, हम देखते हैं कि किस तरीके से आजादी के बाद से हमें जाल में फंसाया गया। हम गांव में देखते हैं कि यूकेलिप्टस का पौधा लगा हुआ है, सुबबूल का पौधा लगा हुआ है। वृक्षारोपण के नाम पर गांव के लोग पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं कि इस पर फल कब आएगा? तब मैं कहता हूं कि यह तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बता पाएंगे क्योंकि यूकेलिप्टस का पौधा वही लाए थे, इस पर फल कब लगेगा?

सुबबूल लाकर खड़ा कर दिया, पहले बकरी फली खा लेती थी। अब बकरी दोनों पांव ऊपर करके खड़ी हो जाती है और कहती है, भैया, मेरी बबूल वाली फली कहां गई? मैंने कहा कि उस फली के बारे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बता पाएंगे। गायों के लिए गाजर घास कहां है? यह देश का कैसा विकास था? लेकिन आज नक्शा बदल रहा है।

हम जानते हैं कि किसानों को 2800-2900 रुपये में यूरिया खाद विदेशी बाजारों से लाकर देनी पड़ती है और 266-270 रुपये में उपलब्ध करवानी पड़ती है। भारत का फर्टीलाइजर सब्सिडी सेंक्टर बहुत घाटे में खड़ा है। देश के युवा, देश के वैज्ञानिक जब प्रयास करते हैं तो नेनो यूरिया, नेनो डीएपी जैसे प्रयास सामने आते हैं। जब नेनो यूरिया, नेनो डीएपी और पेस्टिसाइड्स की बातें करते हैं, हरित क्रांति के नाम पर जिन प्रदेशों का विकास हुआ, आज वहां कैंसर के मरीजों से भरी गाड़ियां चलती हैं।

(1635/KDS/SRG)

आज जब पेस्टिसाइड छींटने का अवसर या यूरिया को प्रतिबंधित करते हुए कितने गांवों में आवश्यकता थी, तब मिट्टी परीक्षण जैसा महान काम देश के अंदर खड़ा हुआ है। ड्रोन के द्वारा जब 'ड्रोन दीदियां' दवाई छींटने का काम करेंगी, तो गांवों के किसानों के अंदर बड़ी प्रसन्नता होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रसन्न होकर यह कह सकता हूँ कि आज देश में चाहे बात सेंगोल की हो, चाहे काशी-तमिल संगमम की हो, चाहे धारा 370 की हो, चाहे राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की हो, चाहे सेना के एकीकरण का विषय हो, चाहे अबूधाबी में बनने वाले मंदिर का विषय हो, चाहे दक्षिण ध्रुव पर तिरंगा फहराने का विषय हो, चाहे वैक्सीनेशन के निर्माण में लगे वैज्ञानिकों के प्रयासों का विषय हो, चाहे रक्षा उत्पादों के निर्माण में हम आगे बढ़ गए हों, चाहे नई शिक्षा की नीति के माध्यम से हम बच्चों को नई शिक्षा नीति से जोड़ पा रहे हों, चाहे गोल्ड का रिजर्व स्टॉक बढ़ा हो, आज देश में निर्यात करने वाली सामग्रियां 190 देशों को 7 हजार 500 से अधिक वस्तुओं का निर्यात करके हमने देश को आगे बढ़ाया है, तब हम विचार करते हैं। फार्मूला उनके भी पास था, शायद उन्होंने फार्मूला अपने दामाद को दिया और देश ने फार्मूला लाखों-करोड़ों युवाओं को दिया है। इसीलिए हम स्पष्ट रूप से यह कह सकते हैं कि प्रयास करने वाले सारे लोगों के मन के जो प्रयास हैं, वे ऐसे ही होते हैं, जैसे पानी पर तस्वीर बनाने से तस्वीर बन नहीं सकती, जैसे आलू से सोना बन नहीं सकता, वैसे ही सिर्फ ख्वाब देखने से तकदीर बन नहीं सकती और तस्वीर बदल नहीं सकती है।

महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ। इस आशा और विश्वास के साथ कि आजादी के स्वर्णिम काल से वर्ष 2047 तक का काल भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रेरणादायी रहेगा और माननीय राष्ट्रपति महोदय का यह संबोधन युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों के लिए आधार रहेगा। धन्यवाद।

(इति)

माननीय सभापति (श्री भर्तृहरि महताब) : धन्यवाद सुधीर जी, आपके इस स्पिरिटेड भाषण ने जरूर सभी को प्रभावित किया होगा।

1637 hours

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President's Address.

Sir, we all know that it is customary that a President's Address, though delivered by the hon. President, is basically the Government's policy which has been written by the Government and it is only through her that the Government's policy is expressed. To add more evidence to that, our hon. President being a Scheduled Tribe person has not been able to mention even a single word about the horrors which have happened in a North-Eastern State. If she had been given an opportunity, I am sure that she would have been wanting to say at least a word of consolation or a word of confidence to the local people over there. It is sad that this Government did not give her an opportunity to add even a single word or a single line to at least console the people of that region to make them feel that they are also a part of this country and they are not alienated from this country.

Sir, having clarified that, the President's Address had a lot of points about development, growth and GDP. This Government has consistently been comparing what has happened in the last ten years to the tenures prior to that. If you look at India, India is a very culturally rich country and it has a very long heritage. If you look at India even during the Mughal period, India was considered as one of the richest nations accounting for something like 25 per cent to 30 per cent of the world's GDP. But subsequently after the British rule, systematically the wealth of India had been siphoned off till the GDP of India came to around one per cent or two per cent of the world's GDP. So, after our Independence in 1947, in the next 44 years we had a very primitive way of looking at our economy. Those days the country was at a nascent stage when we had to make sure that the freedom that we had achieved in a peaceful way was protected. We were able to achieve our freedom because of the efforts of our great leaders like Mahatma Gandhi, Nehru and even Subhas Chandra Bose. But many countries were saying then that India would not remain free nation and soon it would soon disintegrate and collapse. Despite that, nation building was the primary motive for the next 40 years. During that period, we also had to make sure that we have enough agricultural produce, enough milk

produce etc. So, the Green Revolution and the White Revolution, everything was happening.

(1640/RCP/MK)

It was only from 1991 to 1996 – when Shri P.V. Narasimha Rao was the Prime Minister and the Finance Minister was former Prime Minister Dr. Manmohan Singh – that the economy of the country was opened up. If you see the growth of India since then, it has grown in a very successful and a very commendable way. If you look at the decadal growth from 1994, our GDP was about 300 billion dollars in 1994 and we had touched 700 billion dollars in 2004. That is about 130 per cent growth which means 13 per cent annual growth that happened during that tenure. Subsequently from 2004 to 2014, it went up from around 700 billion dollars to 2.1 trillion dollars. It was a very impressive 18 per cent annual growth. It was 180 per cent growth during that period. But if you look at what happened between 2014 and 2024, what was 2.1 trillion dollars has only reached 3.3 trillion dollars. I agree that there were big challenges like the pandemic and the war between Ukraine and Russia which set back the whole world. But despite that, our growth could have been a little bit more promising. The growth that has happened in the last 10 years is only about 60 per cent which annually is about six per cent.

In her Address the President had mentioned that the inflation which was eight per cent from 2004 to 2014 has been controlled and brought down to five per cent. The inflation is five per cent now. But you also have to understand that whenever such huge growth is happening, inflation also is bound to be higher. Also, this Government has mentioned that they have alleviated 25 crore people out of poverty. I congratulate the Government on this. But having said that, in the same note, they also say that 80 crore people have been provided free food. Eighty crore people is about 57 per cent of the total population. If you are saying that 80 crore people had to be fed during the pandemic, that is understandable. But now that the pandemic is over and we have recovered from it and we are back to normal, saying that we are continuing it for another five years, I find it paradoxical, contradictory. You have eliminated poverty, but at the same time you are saying that 80 crore people cannot afford to buy their own food. If this is the state of affairs, I really wonder which statement I should take as the true one.

Also, we were talking about the Citizenship (Amendment) Act. It is restricted only to three countries. As our Parliamentary floor leader Mr. T.R. Baalu has also mentioned, we have sadly forsaken the Sri Lankan Tamils. There are more than one lakh Sri Lankan Tamils who are in India for more than 40 years. These people have been here from 1983. They have had children over here. None of them are given any of the facilities of this country. We have kept them as refugees for the past 40 years. They have been denied certain educational opportunities.

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): The Citizenship (Amendment) Act was more on religious persecution.

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, this persecution was also religious and linguistic. You have to understand that Buddhism was the main religion in Sri Lanka. They had also said that non-Sinhalese speaking people should not be staying there. I am sure that you will be aware of the horrors they went through in 1983, the black July, the number of people who were murdered and tortured. Even subsequently, the horrors which have befallen them makes me shudder to even think about that. I was studying in 10th standard when this happened. I remember that as a 10th standard student, it was announced as a public holiday on the day these horrors happened. Usually, we enjoy whenever there is holiday. But on that day, every classmate of mine had tears listening to the horror stories which had been perpetrated on the Tamils in Sri Lanka. So, I request this Government to ensure that a suitable amendment be made. Sir, one lakh people are all living in camps over here. They all should be considered and citizenship should be given. Two Prime Ministers had signed an accord. Former Prime Ministers Madam Indira Gandhi and Mr. Rajiv Gandhi, both of them had signed an accord saying that citizenship will be given. They have been deprived of that and they have been living in very, very pathetic conditions despite our Tamil Nadu Government trying to do the best for their relief.

Also, this Government had come out with an announcement saying that the marriage age of girls should be fixed at 21.

(1645/PS/SJN)

Sir, I probably think that it is a commendable decision because that would reduce the incidents of maternal mortality, or infant mortality, or all those

things. But having said that, we have to understand that children are going to be finishing their Plus 2 at the age of 17 years. For the next four years, what are the parents going to be doing with the girls? So, taking this into consideration, our hon. Chief Minister of Tamil Nadu Mr. M.K. Stalin has brought in a new scheme where any girl student who finishes her Plus 2 and goes to college, she is incentivised by being given Rs. 1000 every month. This will encourage more and more women to go in for graduation. So, I think that the Government -- while having this kind of a law saying that marriage age is 21 years for women -- should also consider giving some kind of incentives so that these girls will be able to do something purposeful and be able to educate themselves, and even employment opportunities will be better for them.

Tamil Nadu has been a forerunner in many of the schemes. If you look at the noon meal scheme, it was initially started by our great leader Mr. Kamaraj and subsequently it has been refined and made better. This noon meal scheme has ensured that malnutrition among children is reduced. But despite that we found that children were going to schools only during lunch time because their parents say that as the lunch is being served at 1230 p.m., so you go at 1200 noon. To overcome that and also to ensure that adequate nutrition is provided, our hon. Chief Minister has also brought a breakfast scheme for school children in the primary schools up to fifth standard.

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): Mid-day meal scheme was started from Tamil Nadu.

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Yes, Sir. Mid-day meal was started from Tamil Nadu. I am aware of that. I told you that Mr. Kamaraj was the first person who had started it.

So, having been a forerunner on this mid-day meal scheme, I would request the Government to consider a similar programme, a breakfast scheme also for children. This will ensure that the students spend at least three to four hours in the schools and the students do not come only during the noon time and have their lunch and go back. If you see there are a lot of students in the schools whose mathematical skills and all those things are not up to the mark. This is what the study has shown. If this is implemented, I am sure that it will help them getting into schools.

Hon. Chairperson, Sir, this Government also claims that they are giving so much importance to Scheduled Caste students, Scheduled Tribe students, and OBC students for their education. But sadly, four days back, the University Grants Commission had come out with a circular saying that reservation of SCs, STs, and OBCs can be left if adequate number of students has not joined. That was the news which had come out. I do not know if this news is true or false. But I feel that this should not be implemented and it should be the Government's decision to ensure...

HON. CHAIRPERSON: The hon. Minister would like to clarify.

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य यूजीसी के चेयरमैन श्री जगदीश कुमार जी का नाम लेकर जिस न्यूज के बारे में कह रहे हैं, हमारे शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी ने एकदम क्लियर किया है कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जो सीट्स रिजर्व होंगी, उनको कोई अनरिजर्व नहीं कर सकता है। उन्होंने क्लियर किया है।

HON. CHAIRPERSON: You are the first person who got a response from the Government during the speech.

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): I thank the hon. Minister for it. I would also like to thank you for getting it clarified even as I was speaking. So as long as this news is false, I am very happy. I am sure that everybody in the country would be very happy with that decision.

Hon. Chairperson, Sir, in Tamil Nadu, we have also implemented a scheme where the BPL families will be provided with Rs. 1000 per month for bringing them out of their poverty. When we talk about BPL, the initial criteria was economic consideration for deciding as to which family belongs to Below Poverty Line family. It said that any person earning less than Rs. 27,000 per annum, which amounts to less than Rs. 2500 per month, belongs to the BPL category. But now they have come out with a new system where they call it as Multidimensional Poverty Index. We do not know as to what criteria they are using. They are using health criteria, education criteria and stuff like that.

Hon. Chairperson, Sir, in Tamil Nadu, we have implemented a scheme where women can travel free by bus. This will incentivise women and they will be able to have more savings. This Government speaks about farmers' welfare and women's welfare. I feel that bringing targeted policies like these, will

definitely help these women in empowering themselves and making sure that they are also economically better off.

HON. CHAIRPERSON: You can conclude now.

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, I am concluding in two minutes.

When coming to the Micro, Small and Medium Enterprises, there are 6.34 crore MSMEs. Of these, 6.3 crore are Micro Enterprises, which means that their investment is less than Rs. 1 crore. I request the Government to have a separate Ministry for these micro industries because 98 per cent of the MSMEs are only micro industries.

(1650/SMN/SPS)

Most of these are proprietorship concerns. This Government has given a tax rebate for corporates where they have reduced tax from 30 per cent to 23 per cent, whereas these proprietorships of micro industries end up still paying 30 per cent when they earn more than 15 lakhs because they have a turnover of upto rupees five crore.

Sir, regarding the infrastructure, everybody is talking about infrastructure but I have to say that India has still a long way to go when it comes to infrastructure. We need a huge dedicated rail network for cargo. We do not have that. The existing infrastructure is so poor that the number of accidents is actually alarming. I feel that when we are comparing ourselves with the rest of the world and saying that we are very great, we have to also see countries like Japan where they have had high speed rails and not a single incident of any casualty has ever been recorded in the last about fifty years. So, we have to take lessons from those kinds of countries to see how best we can improve ourselves.

I also want to speak about inland waterways. The Government has a proposal where Rs. 6 lakh crore was to be invested in the development of waterways, the National Waterways, especially in Tamil Nadu and Andhra connecting National Waterways-4. Despite repeatedly asking the Inland Waterways Authority, we have not been able to get any kind of response and whether even a DPR is made available or not. So, I request this Government to ensure that inland waterways are also developed.

When it comes to medical colleges, everybody was talking about how all the medical colleges have improved in the last ten years. I congratulate the Government on this but sadly, in Tamil Nadu in Madurai, for the last five years, this AIIMS college has not been constructed. Other colleges which were announced at the same time have all been commissioned and started functioning where students are studying and patients are being benefited. But here, the students are being sent to Ramanathapuram Government Medical College. It is very sad that the first few batches of students are going to pass out as AIIMS doctors without ever stepping into an AIIMS hospital in their life. It is very sad. I also wonder what will happen to the remaining students who are studying in the same college. There are hundred students who are already studying over there. Would they would be considered as AIIMS students?

Regarding the sports, the development of sports in this country is very important. We are very proud to see that more than hundred medals have been won in paralympic games, Asian Games and all those events. But if you see the allotment which is being made for the States for the development, Rs. 600 crore has been spent on Gujarat. While Haryana is the State which has bagged maximum number of medals, it was given a measly Rs. 60 crore. Tamil Nadu, of course, you know would have been given much less than that.

So, I request that this Government identify the talent and see how best these States are developing in sports depending on the number of people who are getting medals, and accordingly allocate funds to ensure that the right things are done.

Similarly, the Government has had a policy about Kendriya Vidyalaya schools. Kendriya Vidyalaya schools at one point of time were opened in Railway land. But now the Railways have come out with land guidelines which make it impossible for Railway lands to be utilized by Kendriya Vidyalaya schools. For the last three years I have approached both the Railway Minister and the HRD Minister but I have not been able to resolve this. Through you, I request for a place for a Kendriya Vidyalaya to be started in my Constituency of North Chennai.

Thank You very much.

(ends)

1653 hours

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, in the President's Address, the beginning of para one it is said that this new Parliament building will witness productive dialogue and policies. Okay, let us hope for the best. But within my experience about this House, especially in this era, I feel that her dream is not going to be a reality. As far as this Government is concerned, they are not for constructive discussion. What is happening here? I agree that Parliament is a forum for debate, discussion and things like that. But this Government is not for that. This is the only Government which took to crooked methods to deceive the elected representatives. This is a very serious thing.

Similarly, this is the only Government which adopted this kind of hate policies. They hate the critics; they silence the opponents; they even file criminal cases against them. How bad is that. In this great House, we have to witness very sharp criticisms. We must have tolerance for that. This zero percent tolerance is not at all welcome, Sir.
(1655/SM/MM)

What have we witnessed in the Parliament? I am raising a very, very important point. After Independence, this Government is the worst Government as far as the approach to the minorities are concerned. Kindly excuse my saying this. With due respect, I am saying this.

After 75 years of Independence, the minorities especially the Muslims had series of hellish experiences. I am very sorry to say this. India has never witnessed such an anti-minority Government. I humbly suggest that the Government should correct this mistake.

What should be our focus areas? These are youth power, women power, farmers and poor. But what is the reality? In India now, these categories are neglected like anything. Deprivation level is very much on higher side. In fact, you are not at all with the poor. You stand for big business houses, industrial magnets etc. What was your slogan? It was 'Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas'. But in

practice, you are digging ditches for them. It is nothing but some kind of lip exercise.

Sir, I would like to talk about one thing. You claim that this new Parliament building has been built during your tenure. Okay, it is good. When you are saying this thing very proudly, you have to realise one more thing about the pillars of democracy – Parliament, Executive, Judiciary and the fourth estate. What is happening regarding freedom of Press? This pillar has been narrowed down. It has been weakened due to your wrong policies. You must have an open mind.

Sir, our forefathers did a marvellous work for about three years in the Constituent Assembly and we have got the best Constitution. Unfortunately, that Constitution is now facing challenges. I humbly request that it needs to be corrected. After Independence, architects of new India did a lot of works for us. They made good institutions, classic institutions, national-level institutions. Unfortunately, what is happening now? You are spoiling all these things.

Now, the Treasury Benches are in a very celebrative mood. They are talking about Ram Madir. They are claiming credit for that. But I am telling you one thing. We have to realise that another kind of thing is going on. What is happening now? After Babri Masjid, Gyanvapi is now coming up. This kind of thing is taking place.

Recently, an 800-year old mosque at Mehrauli in Delhi has been demolished. What is happening? We must understand that this kind of incident gives a bad name for the entire nation. Our country was that of tolerance. We have to respect that. We have to respect our tradition. But this kind of things are going on.

Towards the end I would like to say that now the BJP leaders and the Ministers are saying that they are going to bring CAA and Common Civil Code. I would request you not to play with fire. When you introduced CAA earlier, there was a lot of pressure and agitation. If you bring this kind of thing again, you will open a floodgate.

A Government should be that of kindness; a Government should be that of positive kind of things. You unnecessarily are spreading hatred and things like that.

Sir, I would like to say you one thing. What do we expect from a Government? We are the citizens of this country whether we are Hindus or Muslims or Christians. We are born and brought up here. Do not take this kind of cruel step against the citizens of India especially against the Muslims.

I am not advocating for the Muslims. They are also citizens of this country. They have also made a tremendous contribution in the freedom struggle. They have done a lot of things for the country. I am sorry to say that they are being victimised. You have to put an end to that.

(1700/RP/YSH)

Sir, I would like to say that we really want peace and cordiality in the country. I hope, the Government will work for that with dedication. I hope that wisdom will prevail upon this Government.

Sir, with these few words, I conclude. Thank you very much.

(ends)

1700 बजे

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा समवेत सदन को दिए गए संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

माननीय सभापति जी, वर्ष 2014 में माननीय नरेन्द्र मोदी जी पहली बार देश के प्रधान मंत्री बने। उन्होंने अपने पहले ही संबोधन में अपनी सरकार का एजेंडा घोषित किया था। उन्होंने कहा था कि 'मेरी सरकार गरीबों को समर्पित होगी, मेरी सरकार गांवों, किसानों को समर्पित होगी, मेरी सरकार महिलाओं और नौजवानों को समर्पित होगी तथा मेरी सरकार उस प्रत्येक वंचित व्यक्ति को समर्पित होगी, जिसकी आज तक उपेक्षा की गई है।'

इस प्रकार की बातें देश पहले भी सुनता आया था। ये लोग बड़ी-बड़ी बातें कह देते थे। अभी मुझसे पूर्व हमारे एक वक्ता ने जब एक प्रधान मंत्री जी के गरीबी हटाओ वाले विषय की चर्चा की तो उस पर हमारे कांग्रेस के मित्रों ने नाराजगी जाहिर की, परंतु यह ऐतिहासिक सत्य है। उससे पहले भी इसी प्रकार के थोथे वायदे लोग करते थे और पतली गली से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग से निकलकर चले जाते थे। उनको कोई पकड़ता भी नहीं था। उसके कारण से देखा जाए तो पूरे देश में सम्पूर्ण संसदीय व्यवस्था, सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के प्रति एक प्रकार का अविश्वास फैल गया था कि ये नेता झूठे वायदे करेंगे, झूठे वायदे करके सरकार बनाएंगे और फिर निकल जाएंगे। हमारे लिए इनके मन में कोई दर्द नहीं है। ये हमारा काम नहीं करेंगे, लेकिन जब माननीय मोदी जी ने यह बात कही, उसके बाद से देश का चित्र बदलना शुरू हो गया। उन्होंने जब कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित रहेगी, मेरी सरकार गांवों, किसानों, महिलाओं, युवाओं तथा वंचितों को समर्पित रहेगी, उसके बाद से देश के अंदर निरंतर उस प्रकार की योजनाएं बनाई जाती रहीं, उनको लागू किया जाता रहा और उसका लाभ इन वर्गों तक पहुंचता रहा।

मैं उसकी बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि कई वक्ताओं ने उसकी चर्चा की है। मैं एक विषय 'जन धन खाते' का जरूर उल्लेख करना चाहता हूँ। गरीबी हटाओ का नारा लगाने वाले प्रधान मंत्री जी ने बैंकों को नेशनलाइज किया, लेकिन खाते नहीं खुले। गरीब आदमी बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता था। ये माननीय मोदी जी थे, जिन्होंने जिसकी जेब में एक पैसा भी नहीं था, उसका भी खाता खुलवाने का काम किया। इंकलूसिव इकोनॉमी का इससे श्रेष्ठ उदाहरण पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि 55 करोड़ खाते खुल चुके हैं। 38 लाख करोड़ रुपये डीबीटी के अंदर उन वर्गों तक पहुंच चुके हैं, जिन तक ये पहुंचने की संभावना नहीं थी।

खुद प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि मैं एक रुपया भेजता हूँ और 15 पैसे पहुंचते हैं। मैं हिसाब लगा रहा था कि यदि उनका शासन होता और यदि ये खाते तब खुल गए होते तो मुश्किल से साढ़े 5 लाख करोड़ पहुंचते और बाकी के लगभग 33 लाख करोड़ रुपये इन लोगों के बीच में चले जाते। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को 33 लाख करोड़ रुपये गंवाए जाने का बहुत बड़ा दुख है इसलिए वे पता नहीं किस-किस प्रकार की यात्राएं कर रहे हैं। वे सुन नहीं रहे हैं। वे यात्रा पर हैं। आप देखें कि चाहे उज्ज्वला योजना हो, मकान बनाने की बात हो, पानी पहुंचाने की बात हो,

बिजली पहुंचाने की बात हो, चूँकि मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं इनके आँकड़ों को दोहराना नहीं चाहता हूँ।

(1705/RAJ/NKL)

चार करोड़ मकान बनना, 11 करोड़ शौचालय बनना, 11 करोड़ घरों में जल पहुंचाना, 10 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शंस पहुंचाना, ये साधारण बातें नहीं हैं। मुझे ध्यान है कि माननीय अटल जी के पहले की जो सरकार थी, तो उस समय गैस कनेक्शंस प्राप्त करने के लिए लाइन लगती थी, गैस के सिलेंडर्स प्राप्त करने के लिए लाइन लगती थी। अटल जी की सरकार आई, तो वह लाइन खत्म हो गई। फिर यूपीए की सरकार आई, तो लाइन लगनी शुरू हो गई। यह स्थिति थी। सभी को इस बात का ध्यान होगा। जो परिवर्तन आया है, जो काम हुए हैं, उसके कारण से आज सत्ता प्रतिष्ठान के संबंध में देश के सामान्य जन के मन के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है। उनको लगता है कि मोदी जी कुछ कहते हैं, तो वह मोदी जी की दी हुई गारंटी है, वह गारंटी जरूर पूरी होगी। कठोर परिश्रम के साथ माननीय प्रधान मंत्री जी ने इन कामों को पूरा किया है। पिछले दस वर्षों के अंदर, एक दिन ज्यादा होता है, हमारे प्रधान मंत्री जी ने चौथाई दिन का अवकाश भी नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधान मंत्री नहीं हूँ। सत्ता उपभोग का विषय नहीं है, सत्ता सेवा का माध्यम है। उस नाते उन्होंने अखंड सेवा पिछले 10 वर्षों में की है। इसी कारण उनकी पक्की गारंटी की जो छवि है, आज यह देश में बनी है।

माननीय सभापति जी, माननीय मोदी जी की सरकार के लिए विकास कभी भी वोट का विषय नहीं रहा है। जिनके बारे में यह कहा जाता था कि शायद ये भाजपा को वोट नहीं देते हैं या कम वोट देते हैं। चाहे क्षेत्र हों, जातियां हों या धार्मिक गुप्स हों, हमने इस आधार पर कभी भी भेद नहीं किया। मैं आकांक्षी जिलों का उल्लेख जरूर करूंगा। उनके अंदर वोट बैंक का हिसाब नहीं था। देश में जो जिले विकास की यात्रा में पिछड़े हुए रह गए हैं, उन तक भी विकास समान रूप से पहुंचे, इसकी योजना माननीय मोदी जी ने बनाई है। उत्तर-पूर्व सीमांत प्रदेश है, उसकी रक्षा की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, वोट का हिसाब करके नहीं, बल्कि देश में उसकी एकात्मकता के भाव को सुदृढ़ करने के लिए वहां विकास की आवश्यकता थी। माननीय मोदी जी ने उन विषयों को पूरे दम-खम के साथ, पूरे विस्तार के साथ, डिटेल्ड योजना के साथ आगे बढ़ाया है। हमारे लिए विकास हमारी आस्था का विषय है। इसलिए हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस प्रकार की बात को लेकर चले हैं।

माननीय सभापति जी, मोदी जी की जो गारंटी है, यह केवल देश में ही नहीं है, बल्कि दुनिया के अंदर भी इसकी मान्यता है। कितने देशों में हमारे नागरिक फंस गए थे। इराक, कतर और यमन में नागरिक फंसे। एक-एक नागरिक को वहां से सुरक्षित निकालने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। अभी यूक्रेन और रूस का विषय ताजा है। तिरंगे की छाया में युद्ध विराम करा कर अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित वापस निकालना, यह माननीय मोदी जी की गारंटी का हिस्सा था। उसमें हमारे पड़ोसी देश के नागरिक भी निकल कर वापस आए। मोदी जी की गारंटी का प्रभाव सभी तरफ है।

आपको स्मरण होगा कि हमारे 41 श्रमिक उत्तराखंड में सुरंग के अंदर फंस गए थे। उनको निकालने में कई दिन लगे। लेकिन एक क्षण भी माननीय मोदी जी की दृष्टि से उनकी चिंता दूर नहीं हुई। आप भी उस वक्त के वक्तव्य को याद करेंगे। कई बार लगता था कि हमारे विपक्ष के कुछ नेता, कुछ लोग यह चाहते थे कि कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए कि हमें आलोचना करने का कुछ मौका मिल जाए, लेकिन सभी 41 श्रमिक सकुशल वहां से बाहर आए। यह मोदी जी की गारंटी का ही प्रभाव था। जब वे वहां से निकले तो उन्होंने कहा कि हमें भरोसा था, हम कठिनाई में थे, लेकिन जब मोदी जी हैं, तो हम जरूर सुरक्षित अपने घरों में पहुंच जाएंगे।

(1710/KN/VR)

अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कुछ बातें कही हैं। कांग्रेस भी सांप्रदायिकता को लेकर लगभग उन्हीं बातों को कहती रहती है। माननीय सभापति जी, मैं कुछ क्षण इस विषय पर जरूर कहना चाहूंगा। देश की राजनीति के अंदर कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान भ्रष्टाचार को लेकर है। प्रथम प्रधान मंत्री के समय से ही भ्रष्टाचार के मसले आते रहे और उनके अंदर वृद्धि होती रही। यूपीए के दो टर्म के कार्यकाल के अंदर 12 लाख करोड़ रुपये के घोटाले हुए, यह सारा देश जानता है और अर्थव्यवस्था खोखली हो चुकी थी। देश के अंदर एक प्रकार की निराशा व्यक्त हो गई थी। लेकिन उसके अलावा वोट बैंक की राजनीति का जो विषय है, यह कांग्रेस की बहुत ही घातक देन इस देश को है यानी किसी भी प्रकार से सांप्रदायिकता का आंचल इस कारण से उन्होंने ऐसा पकड़ा, जिसकी वजह से सारे के सारे देश के अंदर मन बंटे हैं, समाज बंटे हैं, देश बंटा है। यह स्थिति यहां पर आई है।

मेरा एक सवाल है। यह संसद है, हमारा सबसे बड़ा विचार-विमर्श का स्थान है। हमारे बहुत पूज्य गुरु सब के सम्मानित, सब के श्रद्धा के केन्द्र गुरु तेगबहादुर जी का दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर सिर विच्छेद कर दिया जाता है, इस कारण से कि वह एक धर्म विशेष को स्वीकार नहीं करते। हमारे दो साहिबजादों को, जरा कोई कल्पना करे, ईंट दर ईंट, ईंट दर ईंट लगा कर और यह कहते हुए कि इस्लाम स्वीकार करोगे, वे नहीं करते। उनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाता है। दुनिया के इतिहास में ऐसी घटना कहीं नहीं हुई होगी। मेरा निवेदन यह है कि जिन्होंने किया, उन्होंने किया, लेकिन उन लोगों को महिमा मंडित करने का काम यदि कोई दल, यदि कोई व्यक्ति करता है तो वह सांप्रदायिक है, वह किसी भी प्रकार से सर्वधर्म समभाव का पोषक नहीं है।

राम मंदिर का विषय आया। राम मंदिर का विषय सुलझ सकता था। राम आस्था का विषय है। लेकिन बहुसंख्यक समाज की आस्था का विचार न करते हुए केवल कानूनी झंझटों में उसे फंसाये रखना, यह इसलिए भी संभव हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति का दामन पकड़ रखा था। अब उसके बारे में विस्तार से कहने का समय भी नहीं है। लेकिन प्रथम प्रधान मंत्री जी के समय से जिस प्रकार का रुख उसके प्रति किया गया, वह सारा का सारा देश जानता है। मैं खुद आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ। आप देखें। सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय यदि कोई है, तो वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस है और वहीं से सब लोगों ने सीखा है। उस वक्त ये रेल मंत्री थे, मैं नाम नहीं लूंगा। भले ही यशस्वी रेल मंत्री थे और बिहार प्रांत के मुख्य मंत्री भी रहे।

उन्होंने यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। गोधरा में जो ट्रेन जला दी गई थी, उसमें निष्कर्ष निकाला कि अंदर स्टोव से आग लग गई थी, उस पर कोई हमला नहीं हुआ था यानी इस प्रकार की मनोवृत्ति थी। आपको ध्यान होगा, आप हमारे बहुत विद्वान सांसद हैं, सर्वश्रेष्ठ सांसद हैं। यूपीए के समय में ये लोग एक बिल लेकर आए थे— प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंसा उस बिल के अंदर इस प्रकार का प्रावधान था कि यदि कहीं अल्पसंख्यक वर्ग और बहुसंख्यक वर्ग में कोई विवाद हो जाए, अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति कंप्लेंट कर दे तो यह बहुसंख्यक वर्ग की जिम्मेदारी है कि अपने को निरापराध घोषित करे तथा उसका सारा खर्चा उसी को वहन करना पड़ेगा इत्यादि-इत्यादि। वोट बैंक की राजनीति के कारण से इस प्रकार के जो विषैले तत्व हैं, ये देश की राजनीति के अंदर आएंगे। मैं ऐसा समझता हूँ कि यदि हमको देश के अंदर सर्वधर्म समभाव को सही मायनों में स्थापित करना है तो सेक्युलरिज्म की जो मिथ्या परिभाषा है, सेक्युलरिज्म की जो विभाजक परिभाषा है, इससे हमें मुक्ति पानी पड़ेगी और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। राम मंदिर का निर्माण हुआ है। राम इस दृष्टि से हमारे आदर्श हैं। राम हमारे मार्गदर्शक हैं। जब राम वाल्मीकि भगवान को कहते हैं कि—

अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी॥

या फिर जब तुलसीदास जी कहते हैं—

सिय राम मय सब जग जानी; करहु प्रणाम जोरी जुग पानी।

ये दोनों बातें सब को साथ लेकर, हमारे देश की जो विविधता है, उसको साथ लेकर आगे चलने का रास्ता हमें दिखाती है, जो हमारा राम का मार्ग है। यह इस देश का मार्ग है। हम सब को साथ लेकर चलें, किसी ने कोई गलती की होगी, परंतु हमारे सब के पुरखे समान हैं। हम विविधताओं को समझें, विविधताओं का सम्मान करें। परंतु हमारे अंदर जो एकसूत्रता है, उसको भी हम आगे लेकर जाएं, तभी हम एक समर्थ देश का निर्माण कर सकेंगे, जिसका माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में निर्माण हो रहा है।

(1715/VB/SAN)

हमें विरासत पर गर्व भी हो, प्रगति भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी हो। गरीब, किसान, महिलाएं, युवा इन चारों वर्गों में, जिनमें सब लोग आ जाते हैं, इनकी उन्नति हो। इनके माध्यम से देश आगे बढ़े। विकसित भारत का जो संकल्प है, वह पूरा हो। वास्तव में, यही माननीय मोदी जी का सपना है, जिसको निरंतर आग्रहपूर्वक पूरा किया जाता रहा है।

माननीय सभापति जी, मैं यहाँ पर एक बात का जरूर उल्लेख करना चाहूँगा। 'नमो भारत' ट्रेन का उल्लेख हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि 'नमो भारत' ट्रेन, जो देश की ऐसी पहली ट्रेन है, वह दिल्ली से मेरठ के बीच की है। मैं इसके लिए विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनन्दन करता हूँ। मेरठ को लेकर किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ... (व्यवधान) मैं वही बता रहा हूँ। मेरा जो प्रथम कार्यकाल था, जब मैं पहली बार वर्ष 2009 में संसद में आया, मैं बराबर दिल्ली से मेरठ की कनेक्टिविटी की बात करता रहता था, मैं हाइवेज की बात करता रहता था। वर्ष 2013 के सितम्बर में, यह रेकॉर्ड है, एक स्टेटमेंट आया कि कुछ प्रायोरिटी की योजनाएं माननीय

प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्वीकृत की हैं और वे उनकी मॉनिटरिंग भी करेंगे। वे पूरी की जाएंगी। उनमें मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे भी था। मैंने संसद के अन्दर उनका धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा था कि मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा है, वह चुनावी घोषणा नहीं होगी। मैं मानता हूँ कि वर्ष 2014 के चुनाव तक यह पूरी तो नहीं हो सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसका शिलान्यास जरूर हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे तब मिला, जब माननीय मोदी जी की सरकार आई और आज मेरठ के चारों तरफ हाइवेज बन रहे हैं या बन चुके हैं। इसके साथ ही, यह एक नयी ट्रेन भी बन रही है। वास्तव में, यह जो विकसित भारत का चित्र है, वह पूरे देश में तो दिखायी देता ही है, इसके साथ ही यह मेरठ के संबंध में भी दिखायी देता है। माननीय सभापति जी, मैं और अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि आपकी ओर से भी कुछ-कुछ इशारा हो रहा है।

इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूँ, क्योंकि आप कहते रहते हैं कि मैं कुछ कविता वगैरह जरूर बोल दूँ।

माननीय सभापति (श्री भर्तृहरि महताब) : मैंने आपको कुछ इशारा नहीं किया, मैं बस स्माइल कर रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत ही जोश से बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

विकसित भारत का जो संकल्प है, मैं उसे कुछ पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूँ।

दसों दिशाओं में जाएं,

दल बादल सा छा जाए,

उमड़-धुमड़कर हर धरती को,

नन्दन वन सा शरसाएं।

यह विशेष रूप से मेरे विपक्षी मित्रों के लिए भी है।

ये मत समझो,

किसी क्षेत्र को खाली रह जाने देंगे,

दानवता की बेल विशैली,

कहीं नहीं छाने देंगे,

जहाँ कहीं लू झुलसाती,

अमृत रिमझिम बरसाये,

दसों दिशाओं में जाएं।

मैं समझता हूँ कि अमृत काल में इस अमृत को बरसाने का हमारा संकल्प है। वर्ष 2047 तक सब प्रकार से विकसित, आत्मनिर्भर और समर्थ भारत बनाने का हमारा संकल्प है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह संकल्प पूरा होगा। तीसरी बार पुनः वे प्रधानमंत्री बनेंगे। उनके नेतृत्व में हम लोग इस संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ेंगे।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1719 hours

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, first of all, I would say that the most unfortunate thing is that the hon. President's Address became a political statement and glorified the anti-people policies which have been adopted by the two Governments of 2014 and 2019. Actually, the realities are very much different from the speech.

Sir, the common people – the farmers, the workers, the students, the youth and the old - of this country are suffering very much due to the anti-people policies of this Government. Whatever promises they had made at the time of elections in 2014 and 2019, they are deviating from them now. They have already deviated from too many things. I can point out too many cases here. What is the price of petrol and diesel today? It has crossed Rs. 100. At the time of UPA regime, they had promised that they would reduce the price of petrol and diesel to below Rs. 50. Now, they are blaming the price of crude in the international market for it. At the time of UPA Government, they had said that it was the fault of Manmohan Singh Government, but now, they are not having any genuine answer and are saying that it depends upon price of crude in the international market.

(1720/SNT/PC)

It is the main violation of the promise of this Government. In the case of doubling of farmers' income policy, what happened to the farmers? Is this Government willing to address the people in the coming elections of 2024 with doubling of farmers' income policy? It has become a joke now.

In the case of job creation, this Government promised two crore jobs per year. According to that figure, it would have created 20 crore jobs. But we have not seen any kind of job creation by this Government. It is a violation of that promise. In the case of scholarships, the previous UPA Government initiated many scholarships for students, like Merit-cum-Means scholarship, pre-matric scholarship, special scholarships for

minority communities including the Maulana Azad Scholarship. Wherever the scholarships have been announced by the UPA Government, this Government has either reduced the amount or removed it completely. This is happening now-a-days.

In the case of minority community of this country, the anti-Christian attacks are increasing day-by-day. We have the experience of Manipur. What happened there? Hon. Prime Minister made no comment on the Manipur issue. More than 300 churches have been destroyed. The Government has not been able to stop the violence in Manipur. Last month in Madhya Pradesh, one Parish priest who is a Malayali and his name is Father Anil John had been arrested and remanded to jail. He was charged under the communal conventions. That means they are using that as a weapon against the Christian community of this country. It is a very sad thing and is the most unfortunate thing. In all the States wherever BJP is ruling, anti-Christian attacks are increasing day-by-day. In Kerala also, they are trying to please the Christian community. That is another thing we are facing politically. In this matter, I would demand certain things. The Dalit Christian community from our States are demanding reservation. They deserve that. Many of the marginalised community has been protected by the reservation policy of this Government. The previous UPA Government also protected so many communities, marginalised communities by reservation announcements and amendment of our Constitution. But even now, the Dalit Christian community has not been addressed or their demands have not been met. So, I demand the Dalit Christian community's reservation should be adopted by this Government.

Sir, now, I am coming to another point. The success stories of every Government depend upon the commitment and the hard work of the employees, especially the workers like Anganwadi workers, helpers, ASHA workers, and MGNREGS workers. Yesterday's budget also did not mention anything about our Anganwadi workers and ASHA workers.

So, I demand here that they should be recognised. They should get enough wages. At least, Rs. 25,000 per month should be given to them because they are doing much more than any other community to the nation. So, ASHA workers, Anganwadi workers, helpers, and MGNREGS workers should be recognised. That is our main demand.

1724 hours

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

I would like to urge upon this Government on another matter. This is related to human-animal conflict. This Government passed the amendment to the Wild Life (Protection) Act. But I would like to ask whether there is any effect of that amendment. I would like to know whether the farmer community or the common man is protected by this Wild Life (Protection) Act? Nothing is happening anywhere. Nothing is happening in our country. In Kerala, we are facing a crucial situation. Every day in day time, the cruel wild animals are coming out from the forest and attacking the people.

In my constituency Idukki, in the last ten years I have witnessed around 100 people have been killed or died by wild elephant attack. Last month, two poor labourers died by wild elephant attack. There is no remedy. So, my demand here is we have to adopt the policies in successive manner. The policies which are adopted or implemented in foreign countries, we have to implement here. The vermin list has been already excluded by this Government which is most unfortunate. I am demanding here that the vermin list should be reintroduced. We have to capture the vermin animals. There is no option.

(1725/AK/CS)

We have to adopt the culling policy for resisting the birth rate of animals like tiger, bear and other wild animals. They are passing through the villages and townships, and we are witnessing this nowadays all over Kerala. It is the most unfortunate thing.

As regards the promises made by this Government in the development sector for Kerala, Angamaly-Sabari Railway was there,

which was promised by the Vajpayee Government, but it has not been fulfilled. The responsibility for it was mainly vested with the Central Government and the State Government also. The State Government is not at all responding to whatever the Central Government is demanding from them. Earlier, they have committed 50 per cent share and that agreement is there. But the Central Government is again asking for 50 per cent share for Angamaly-Sabari Railway. In yesterday's Budget also Rs. 100 crore was allotted, which has not been utilized for the last one year. Again, an announcement has been made and it is asking for 50 per cent share from the State Government. But the State Government is not at all responding in the matter. Hence, both the Governments are not fulfilling their commitments to the people of Kerala.

In the case of the National Highway development, so many works are going on, but the case of 12 National Highway upgradation projects from the State of Kerala are kept pending and they are not being given the final sanction. The BJP Government during their first term had given the in-principle approval for 12 cases. In my Constituency also Vijayapuram-Oonnukal Road is there for which we are demanding the final sanction, but we are not getting the approval of the Ministry of Road Transport and Highways. This is an unfortunate thing.

This Government is deviating from all the promises made by them. They are making another goal post, which is the most unfortunate thing that the country is witnessing now. We are watching it. Hence, the President's Address became a political statement.

With these words, I am concluding my speech. Thank you, Sir.

(ends)

1727 बजे

श्री तेजस्वी सूर्या (बंगलौर दक्षिण): महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

Just when I am about to complete five years as a first-time Member of Parliament, I go back to reflecting the days of late 2013 and late 2014 when for the very first time many young people of my age then took to the streets in various protests across the country in the Anna Hazare led protests. देश में एक प्रकार से निराशा का माहौल था। रोज अखबार में बड़े-बड़े स्कैंडल्स, करप्शन स्कैम्स की न्यूज आती थीं। दिल्ली हो या मुंबई हो, अखबारों में रोज हम टेरेरिस्ट अटैक्स के बारे में देखते/पढ़ते थे। निर्भया का जो घोर रेप एपिसोड हुआ था, that had also shaken the conscience of the nation.

एक प्रकार से सरकार के प्रति और पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति ही एक विश्वासहीनता देश में पैदा हुई थी। उस प्रकार के एक निराशा के माहौल में नरेन्द्र मोदी जी जैसे एक रे ऑफ होप देश को मिला और मेरे जैसे करोड़ों-करोड़ नौजवान अपनी पूरी ताकत मोदी जी के पीछे लगाकर वर्ष 2014 में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को लेकर आए। आज पिछली 10 साल की जो व्यवस्था है, पिछले 10 साल में जो परिवर्तन हुआ है, जब हम उसका एक अवलोकन करते हैं, मुझे लगता है कि ये जो पिछले 10 साल हैं, ये देश के स्वर्णिम 10 साल हैं और अत्यंत अग्रणी स्थान पर ये 10 साल गिने जाते हैं।

(1730/UB/IND)

The last ten years have been the most transformative ten years, the decade of transformation in the country's political history. The kind of paradigm shift that the country's politics, society, and economy, has seen and witnessed in the last ten years is historic in every sense. That is why I feel that whenever the history of this Government and the hon. Prime Minister's legacy will be written, India's political history can be divided into two broad parts called 'Before Modi' and 'After Modi', मोदी से पहले का भारत और मोदी के बाद का भारत, क्योंकि इतना बड़ा बदलाव देश में पिछले 10 सालों में हुआ है।

सभापति जी, ऐसे तीन-चार बड़े-बड़े चेंजेज, जो देश में आए हैं, उनका ही जिक्र मैं आज के भाषण में करना चाहता हूँ। पहला चेंज यह आया है कि देश में जो ओवर ऑल माहौल था, वह डेस्पोडेंसी का था। देश में पूरा माहौल निराशा का था लेकिन आज देश आप्टिमिज्म के साथ, होप के साथ, कांफिडेंस के साथ उभरा है। Everyday we see and hear of new achievements of the country whether it is the achievement of Chandrayaan, our unprecedented medal tally in the Asian Games, our achievement in aerospace, or the achievements of our startups. Every single day, we are hearing stories

of achievements and success, and despondency has given way to hope and optimism. मोदी से पहले निराशा थी, मोदी के बाद आशा है। This is the change that Narendra Modi ji has brought to the country in the last ten years.

सभापति जी, इससे पहले भी देश में कई सरकारें आईं और कई सरकारें गईं लेकिन देश की जो बड़ी-बड़ी समस्याएं थीं, उनका समाधान नहीं हुआ क्योंकि देश में पॉलिटिकल कल्चर था कि जो भी समस्या है, उसका समाधान ढूंढने के बजाए उसे पोस्टपोन कर दिया जाए और सभी सरकारों ने ऐसा ही किया था। Maximum efforts of the Government earlier were to postpone the problems, not to resolve the problems. But one of the characteristic features of the Narendra Modi Government is that this is not a Government that has shied away from resolving decades and centuries old problems. This is a Government that does not believe in postponing problems, but this is a Government that believes in resolving the problems. This is the defining character of the Narendra Modi Government. There are multiple examples.

For almost seventy years, the country waited for a decisive action on Kashmir, on Article 370, but multiple Governments that came took no action and the country was literally bleeding by a thousand cuts. जो 70 साल से नहीं हुआ था, उसे इसी सरकार ने, इसी टर्म में आर्टिकल 370 को दुरुस्त करके 70 साल की समस्या का समाधान किया। लगभग 40 साल से अधिक समय से हमारे करोड़ों जवानों ने ओआरओपी का हक मांगा था। इस समस्या के समाधान को भी लगातार पोस्टपोन किया जा रहा था। इस 40 साल की ओआरओपी की समस्या का समाधान नरेन्द्र मोदी की सरकार ने करने का किया है। कारगिल युद्ध के समय के बाद से एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने की मांग देश में थी। लगभग 20 साल से यह मांग भी पोस्टपोन होती जा रही थी। सरकारें आईं, सरकारें गईं, but India's demand of a strong and coordinated Chief of Defence Staff, the creation of this institution, was not met. लेकिन इसका भी समाधान नरेन्द्र मोदी की सरकार के समय हुआ। आज मल्टीपल थिएटर्स में, मल्टीपल फ्रंट्स में कार्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ if India can now answer the external efforts and attacks, it is because we have created the institution of the Chief of Defence Staff. नॉर्थ-ईस्ट की भी समस्या थी। नागा एकोर्ड हो, बोडो के इश्यूज हों, मिजोरम के इश्यूज हों, मणिपुर के इश्यूज हों, बांग्लादेश से जुड़े लैंड एग्रीमेंट्स हों, ये इश्यूज 70-70 साल से पेंडिंग हैं।

(1735/RV/SRG)

आज नॉर्थ-ईस्ट के मैक्सिमम प्रदेशों में जो शांति आई है, इसका समाधान भी नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के समय में ही हुआ।

सभापति जी, इतना ही नहीं, यह तो 40 साल, 50 साल, 70 सालों की समस्या थी, जबकि 500 सालों से देश का भारतीय समाज, हिन्दू समाज अयोध्या के राम मन्दिर इश्यू का समाधान करने की प्रतीक्षा में था। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि हम सब के वोट की वजह से जो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार सत्ता में आई, तो इस सरकार के प्रयासों से 500 सालों की जो अपनी प्रतीक्षा थी, वह समाप्त हो गयी और अयोध्या में भव्य राम मन्दिर बन गया। So, this is a problem solving Government. मोदी जी के आने से पहले समस्या थी और मोदी जी के आने के बाद समाधान है। यह 'बिफोर मोदी' और 'आफ्टर मोदी' का फर्क है।

One of the biggest achievements of this Government is the fact that we have lifted 25 crore people out of poverty.

सभापति जी, यह जो अचीवमेंट है, अगर इसे हम ह्यूमन पॉपुलेशन के संदर्भ में देखें तो यह पता चलता है कि न यूरोप में, न चीन में, न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इतनी बड़ी आबादी को इतने कम समय में गरीबी से बाहर ले आने का काम विश्व के इतिहास में नहीं हुआ है और पहली बार जो हुआ है, वह मोदी जी के नेतृत्व में भारत में हुआ है।

सभापति महोदय, मुझसे पहले आप बोल रहे थे। आपने एक महत्वपूर्ण विषय को उठाया, जो फाइनेंशियल इन्क्लूजन के बारे में था। अपनी सरकार आने से पहले तक देश के मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के पास एक बैंक अकाउंट तक नहीं था। जब देश की जनता के पास एक बैंक अकाउंट भी नहीं होता है तो वह गरीबी से बाहर कैसे आ सकता है, देश की फॉर्मल इकोनॉमी के साथ वह कैसे जुड़ पाता है? पिछले दस सालों से 50 करोड़ से अधिक गरीबों को बैंक अकाउंट से जोड़ कर फॉर्मल इकोनॉमी के माध्यम से उनकी भलाई करने का और गरीबी से उन्हें मुक्ति दिलाने का काम नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है। When somebody gets connected to the banking system, it is very natural that they get introduced to a lot of other formal products also. देश में इंश्योरेंस का जो कवरेज था, जो परकोलेशन था, वह अत्यंत ही कम था। पर, जन-धन अकाउंट से लगभग 50 करोड़ जनता के जुड़ने के बाद आज देश में इंश्योरेंस का कवरेज भी ज्यादा हो चुका है। वह आयुष्मान भारत योजना हो सकती है, प्रधान मंत्री बीमा योजना हो सकती है या 20 रुपये में प्रधान मंत्री जी का जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस योजना मिल रही है, वह हो सकती है, ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को, जिसे देश के एलीट वर्ग 'टेकेन-फॉर-ग्रांटेड' मानते हैं, ऐसे कई सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को पहली बार देश के गरीबों तक पहुंचाने का काम अपनी सरकार ने किया है, नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है।

सभापति जी, मोदी जी ने अपने पहले कार्यकाल में ही, पिछले 70-75 सालों से जो कमियां थीं, उसका सुधार किया। मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में चाहे वह अनुच्छेद-370 हो, राम मन्दिर हो, या आज ही उत्तराखंड में यू.सी.सी. लागू करने का जो ड्राफ्ट प्रपोजल हमने पेश किया है, ऐसे

जो अपने कोर आइडियोलॉजिकल एजेंडा थे, उसे भी पूरा करने का काम किया गया। आने वाले दिनों में मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में विकसित भारत का फाउण्डेशन और एस्पिरेशनल ड्रीम्स को पूरा करने का काम यह सरकार करेगी। This is the massive change that the country's polity has seen in the last ten years.

(1740/GG/RCP)

इसलिए देश के युवा कह रहे हैं कि मोदी से पहले देश में गरीब थे, मोदी के बाद देश में समृद्धि है। Before Modi, there was poverty. After Modi, there is prosperity. This is the change the Modi Government has seen in the last 10 years.

सभापति जी, यह गरीब कल्याण रेवड़ी बांटने से नहीं हुआ है। यह गरीब कल्याण गरीबों को सरकार के ऊपर परावलंबित करने से नहीं हुआ है। देश के गरीबों को आत्मनिर्भर करने के लिए, स्वावलंबन करने के लिए नए तरीके के साथ मोदी जी ने काम किया है।

सभापति जी, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आपके माध्यम से देश का ध्यान भी इस विषय पर आकर्षित करना चाहता हूँ। मोदी जी के विज्ञान, मोदी सरकार की इकोनॉमिक एप्रोच और बाकी पार्टियों के एप्रोच में फर्क क्या है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो नई स्कीम प्रधान मंत्री सूर्योदय योजना मोदी जी ने लॉन्च की है, यह सबसे बड़ा उदाहरण है।

सभापति जी, हमने पिछले दो-तीन राज्यों के चुनावों में देखा है कि कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी तक चुनाव से पहले जनता से वादा करते हैं कि हम 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे। इस प्रकार से ये रेवड़ी बांटने का काम करते हैं और सरकार के ऊपर गरीबों को अवलंबित करने का काम वे लगातार कर रहे हैं। पर मोदी जी उनको अवलंबित नहीं करना चाहते, परावलंबी करना नहीं चाहते हैं, उनको स्वावलंबी करना चाहते हैं। इसलिए पीएम सूर्योदय योजना में गरीब के घर पर 16 रूफटॉप लगाने के लिए हम उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनको सब्सिडी देंगे, उनको ताकत देंगे। Not only that he can save 200 or 300 units of electricity so that 300 units of electricity will become free, but he can also earn additional money because of the solar rooftop. यह फर्क हमारी इकोनॉमिक एप्रोच में है। हम गरीब को गरीब रख कर, उनको वोट बैंक बना कर, पॉलिटिकल फायदा उठाने की सोच भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार नहीं रखती है। गरीब को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बना कर, उनको ताकत देने का काम पिछले दस सालों में हुआ है, इसलिए देश के युवा कह रहे हैं कि मोदी से पहले गरीब परावलंबी था, मोदी के बाद देश के गरीब स्वाभिमानी हैं, आत्मनिर्भर हैं। This is the difference between Before Modi and After Modi.

सभापति जी, इसके साथ-साथ देश के इतिहास में, लगभग पिछले 70 सालों में, मोदी से पहले देश में जो राजनीतिक परिभाषा सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को लेकर थी, वह इतनी परवर्टिड हो चुकी थी, उसमें इतनी एडल्ट्रेशन आ चुकी थी कि उसका जो मूलभूत विचार था, संविधान के जो मूलभूत विचार थे, वही एडल्ट्रेट हो चुके थे। The perverted discourse over the last six decades, by perverting and adulterating the very definitions of

secularism and socialism in the country, the country had to face two big losses. By a perverted definition of secularism, the country culturally lost a lot. By a perverted communication, commentary of socialism, the country lost economically.

सभापति जी, मैं एक-दो उदाहरण ही देना चाहता हूँ। आज़ाद होने के 70 सालों तक क्यों इतनी बड़ी संख्या में देश में गरीब थे? पिछली सरकारें क्या कर रही थीं? जितनी भी सरकारें आईं, वे वेल्थ क्रिएटर्स को, उद्यमशीलता को प्रोत्साहन ही नहीं कर दे थीं। अभी-अभी एक-दो महीने पहले इन्फोसिस के नारायण मूर्ति जी ने एक इंटरव्यू में बोला कि जब उन्होंने इन्फोसिस शुरू किया और जब उसके लिए उन्होंने यूएस से कंप्यूटर इंपोर्ट करने के लिए प्रयास किया तो सिर्फ कंप्यूटर्स इंपोर्ट करने के लिए उनको लगभग 50 बार दिल्ली आना पड़ा और अमेरिका से 50 कंप्यूटर इंपोर्ट करने के लिए तीन साल लगे।

(1745/MY/PS)

इस प्रकार की कंट्रोल्ड इकोनॉमी देश में इन लोगों ने जारी रखी थी। उसकी वजह से हमारे देश के युवा न तो उद्यमी बन सकते थे और न ही देश की इकोनॉमी इम्प्रूव हो सकती थी। इस प्रकार का एक shackling of the entrepreneurial spirit देश में हुआ था। आज मोदी जी के आने के बाद, for the first time, these fetters, shackles, and chains that had kept the entrepreneurial spirit of the country tied have been removed. तब अपने यहां 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स थे, लेकिन आज एक लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स देश में हैं। आज के स्टार्टअप्स देश को समृद्ध बनाने के काम में लगे हुए हैं।

सभापति जी, मैं आपके सामने और तीन-चार विषयों का उल्लेख करना चाहता हूँ। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में भी उल्लेख किए हैं। इस साल के बजट में सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये की धनराशि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए रखा है। This is making India future ready and future proof. आज पहली बार देश के युवाओं को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए इतनी बड़ी धनराशि का सपोर्ट मिल रहा है। पहले की जो सरकारें थीं, अगर वे इस प्रकार के सपोर्ट दिए होते तो India would have emerged already as a technological superpower in the world. Since they did not do it, in many areas India has to play catch up today. We are correcting that wrong and we are making that course correction - whether it is in artificial intelligence, whether it is in quantum computing, whether it is in any other emerging technology. India will be a world leader in the coming days because आज अपनी सरकार ने इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर दी है।

सभापति जी, सेक्युलरिज्म की परिभाषा भी देश में एक प्रकार का कल्चरल कॉन्फिडेंस कम करने का काम किया है। मैं दक्षिण भारत से आता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार एक नैरेटिव, विशेष रूप से पिछले दो-तीन सालों से देश में खड़ा किया गया कि दक्षिण भारत

अलग है, उत्तर भारत अलग है और दक्षिण भारत में हिन्दी इम्पोजिशन हो रहा है। इस प्रकार के कई सारे भ्रम फैलाने का काम विपक्ष कर रहा है।

सभापति जी, मैं एक और बात की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। कर्नाटक से एक एमपी थे। वह कांग्रेस पार्टी की तरफ से एमपी थे। कल उन्होंने दक्षिण भारत के नाम से एक राष्ट्र मांगने का काम भी किया। इससे बड़ा असम्मान इस सदन के प्रति क्या हो सकता है? Hon. Chairperson, Sir, I am astounded, I am ashamed that a sitting Member of Parliament has not only violated his oath but has also betrayed the true intention of the Congress Party by demanding a separate nationhood for the Southern States of India.

Hon. Chairperson, Sir, there are two things I want to bring to your attention. डीएमके के सदस्य और कांग्रेस के जो एमपीज साउथ से आते हैं, वे बार-बार हिन्दी इम्पोजिशन के बारे में बात रखते रहते हैं। अभी कार्ती जी भी हैं। He also keeps speaking about Hindi imposition. Hon. Chairperson, Sir, through you, I want to tell one thing to this august House. I come from Karnataka. My mother tongue is Kannada. I do not want any kind of Hindi imposition. If there is one Party that has resisted Hindi imposition, has been against imposition of any kind, and has always supported the vitality, diversity of various languages in India, it is my Party, the Bharatiya Janata Party. I want to give you one example from the Constituent Assembly.

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Now, please conclude.

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Hon. Chairperson, Sir, I will just take two more minutes because this is a very important issue.

Even yesterday there were Members of the DMK Party and Members of the Congress Party who created this argument about Hindi imposition.

(1750/SMN/CP)

When the debate was being held in the Constituent Assembly on what should be the official language of India, it was Shyama Prasad Mukherjee, who was the founder of the Bharatiya Jana Sangh, the earlier *avatar* of the Bharatiya Janata Party, who said this and I quote:

“Some of my friends spoke eloquently that a day might come when India shall have one language and one language only. Frankly speaking, I do not share that view and when I say so, I am not ignoring the essential need for creating that national unity which must be foundation stone in our future reconstruction. That

unity must be achieved by allowing those elements in the national life of our country which are today vital to function and function in dignity, harmony and self-respect. Today, it stands to the glory of India that we have so many languages from the North to the South, from the West to the East, each one of which in its own way has made contributions which have made Indian life and civilisation what it is today. If it is claimed by anyone that by passing an article in the Constitution of India, one language is going to be accepted by all by a process of coercion, I say, Sir, that will not be possible to achieve. Unity in diversity is India's keynote and must be achieved by a process of understanding and consent and for that, a proper atmosphere has to be created."

This was the position of the Jan Sangh and Shyama Prasad Mukherjee. This is still our position Karti ji. I will tell you why. I will tell you why it was your Party, the Congress Party, which was the original party of imposing Hindi in the Southern States.

Hon. Chairperson, Sir, in the last sixty years, the Congress Party got four opportunities to draft the country's National Education Policy and every time the Congress Party's National Education Policy came with a three-language formula. And what were these three language formulae? In all the non-Hindi speaking States, Hindi was made compulsory. Who made these policies? It was Jawaharlal Nehru, it was Indira Gandhi it was Rajiv Gandhi and it was not reviewed by Manmohan Singh. For the first time, through the National Education Policy of 2020, Narendra Modi Government has changed this compulsory Hindi policy and made study of any regional language of India possible. We have for the first time introduced provisions to study higher education in mother tongue.

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Now, please conclude.

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): We have made it compulsory to impart primary education in mother tongue. Karti ji, these are the facts that are staring at you and your party. So, please stop the bogey that the Bharatiya Janata Party is the Party that imposes Hindi. Stare at the facts that are staring at you. Acknowledge that it was your party that imposed Hindi coercively on the non-Hindi speaking States of the country.

Hon. Chairperson, Sir, I want to conclude only with one thing. पिछले 10 सालों में एक कल्चरल रिनेजान्स इस देश में हुआ है। इस कल्चरल रिनेजान्स ने देश के युवाओं में विशेष रूप में एक नया आत्मविश्वास जाग्रत किया है। In all walks of life, we are witnessing this new found self-confidence, especially the world is taking note of this. Today, India is not only exporting defence equipment; India is not only exporting automobile components; India is not only exporting electronic equipment; today India is also exporting good governance models to the world which the world is taking note of. For example, the world is taking note of how India managed Covid. The world is studying that model. The world is also looking at how India has set for itself and for its population a digital public infrastructure which is the best in the world. Many countries are drawing inspiration from this.

Not just that, even legislative techno-legal solutions like the ones that we have devised in the Data Protection Law are the ones that the world is taking inspiration from. मोदी जी से पहले, उनके प्रधान मंत्री बनने के पहले हम गुजरात मॉडल से देश में इंस्पिरेशन लेते थे। आज जब प्रधान मंत्री के रूप में मोदी जी काम कर रहे हैं, आज विश्व और अलग-अलग प्रदेश इंडिया मॉडल से प्रेरित हो रहे हैं, भारत से प्रेरित हो रहे हैं। This is the change that has taken place.

(1755/NK/SM)

Sir, I want to conclude with just one particular comment. कल जब निर्मला सीतारमन जी ने अपने बजट भाषण के कनक्लूजन में बोलीं कि जब जुलाई, 2024 में हम वापस आएंगे तो विस्तार रूप से बजट पेश करेंगे। It was an indication of our confidence. But the Opposition and its commentators inside and outside of the Parliament kept commenting that this is arrogance. यह एरोगेंस नहीं है, यह कॉन्फिडेंस है, यह कॉन्फिडेंस कहां से आता है, यह कॉन्फिडेंस यहां से आता है कि हमने डिलवर किया है, हमने जो कहा है वह किया है। We are confident because हमने 50 करोड़ जनधन खाते खोले हैं, हमें वापस आने का विश्वास इसलिए है क्योंकि हमने 11 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट कनस्ट्रक्शन पिछले 10 सालों में किए हैं। हम इसलिए कॉन्फिडेंट हैं कि देश में 43 करोड़ से ज्यादा मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन सैंक्शन्ड किए हैं। हम इसलिए कॉन्फिडेंट हैं कि हम 30 लाख से ज्यादा लोगों को डीबीटी के माध्यम से फायदा देकर देश का पैसा बचाया है। हम इसलिए कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को पहली बार एलपीजी कनेक्शन्स दिए गए हैं। हम इसलिए कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि देश में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पहली बार एक मकान दिलाने का काम किया है। हम इसलिए कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि देश में 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरियों वालों को 78 लाख से अधिक लोगों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभ दिए हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से देश के 15

करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर तक पहली बार नल से जल लाने का काम भी किया है इसलिए हम कॉन्फिडेंट हैं।

आज देश का युवा कह रहा है कि देश बदल चुका है और देश बदल रहा है। मोदी से पहले और मोदी के बाद देश बहुत बदल चुका है। मोदी से पहले सत्ता थी, मोदी के बाद सेवा है, मोदी से पहले समस्या थी, मोदी के बाद समाधान है, मोदी से पहले मलिनता थी, मोदी के बाद स्वच्छता है, मोदी से पहले विवाद था, मोदी के बाद विश्वास है, मोदी से पहले तम्बू था, मोदी के बाद भव्य मंदिर है, मोदी से पहले आतंक था, मोदी के बाद शांति है, मोदी से पहले गरीबी थी, मोदी के बाद समृद्धि है, मोदी से पहले बेरोजगारी थी, मोदी के बाद कौशल विकास है, मोदी से पहले अपराध था, मोदी के बाद सुरक्षा है। मोदी से पहले विभाजन था, मोदी के बाद एकता है, मोदी से पहले निराशा थी, मोदी के बाद आशा है, मोदी से पहले अव्यवस्था थी, मोदी के बाद व्यवस्था है, मोदी से पहले अन्याय था, मोदी के बाद न्याय है, मोदी से पहले तुष्टीकरण था, मोदी के बाद सबका साथ, सबका विकास है। मोदी से पहले परिवारवाद था, मोदी के बाद लोकतंत्र है, मोदी से पहले भय था, मोदी के बाद धैर्य है, मोदी से पहले परावलंबन था, मोदी के बाद आत्मनिर्भरता है, यह परिवर्तन भारत में पिछले 10 सालों में हुआ है। We are fully confident that the people of India and 140 crore Bharatiyas will bless the Prime Minister for a historic third term. I thank you for giving me this opportunity to speak and I thank the hon. President for this Address. Thank you.

(ends)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): माननीय सदस्यगण, अभी छह बजने वाले हैं, सदन की इजाजत हो तो दो घंटे के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: हां, बढ़ा दिया जाए।

1759 बजे

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): माननीय सभापति, आपको बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे सद्र-ए-जम्हूरिया के खुतबे पर बोलने का मौका दिया। मैं हस्ब-ए-आदत और हस्ब-ए-रिवायत की मुखालफत में खड़ा हूँ। सद्र-ए-जम्हूरिया के खुतबे को अगर आप देखेंगे तो पूरे खुतबे में लब्जे मुसलमान तो छोड़ दीजिए, लब्जे अकलियत भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि भारत में 14 फीसद मुसलमान हैं जो आबादी के लिहाज से 17 करोड़ हैं। पिछले दस सालों में नरेन्द्र मोदी की सरकार में वे अपने आपको गैर-यकीनी कैफियत में पाते हैं और सोचते हैं कि हमारी शिनाख्त को खतरा है, हमारे वजूद को खतरा है।

(1800/SK/RP)

मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जज़बात में आए बगैर कह रहा हूँ कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आपको ऐसे समझते हैं जैसे हिटलर के ज़माने में यहूदी अपने आपको समझते थे। मैं आपको चंद मिनट में बताता हूँ कि ऐसा क्यों समझते हैं।

सर, मिसाल के तौर पर आप खुतबा-ए-सदारत के हिस्से तहरीर का 32वां पैराग्राफ देखिए। ड्राप आउट रेट का जिक्र हुआ, स्कूलों में इन्द्राज और एनरोलमेंट का जिक्र हुआ। एसएसीज़ का नाम लिया गया, एसटीज़ का नाम लिया गया, ओबीसीज़ का नाम लिया गया, लफज़-ए-अकिलियत का नाम नहीं लिया गया, मुसलमान तो छोड़िए। इस मुल्क में सबसे ज्यादा ड्रापआउट अगर स्कूलों में है तो मुसलमानों में है, हायर एजुकेशन में सबसे कम एनरोलमेंट मुसलमानों का है। यह गवर्नमेंट का डेटा है कि मुसलमानों का स्टूडेंट ड्रापआउट 14 आशारिया 42 क्लास वन से शुरू होता है और क्लास-6 और क्लास-8 तक 10 आशारिया 76 तक पहुंचता है। यह सरकार का डेटा है यानी क्लास-1 से क्लास-6 और क्लास-8 तक यह हाल है। आपने इस बजट में क्या किया? प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को सिर्फ 9वीं क्लास तक महदूद कर दिया और पैसे कम कर दिए। वर्ष 2022-23 का बजट देखें, 5026 करोड़ रुपये दिए गए थे, जिसमें से सिर्फ 663 करोड़ रुपये इस्तेमाल हुए। एआईएसएचई का डेटा है कि हायर एजुकेशन में मुसलमानों का 8 आशारिया 5 ड्राप आउट रेट हो गया है। वर्ष 2020-21 में गवर्नमेंट का डेटा बता रहा है कि 1 लाख 80 हजार मुसलमान हायर एजुकेशन में नहीं हैं, लेकिन आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में 423 करोड़ रुपये को 326 करोड़ रुपये कर दिया, मौलाना आज़ाद फ़ैलोशिप को 45 करोड़ रुपये कर दिया और एनसीएम में बजट 44 करोड़ रुपये को 33 करोड़ रुपये कर दिया। आप बताइए कि सबसे ज्यादा जिस कम्युनिटी का हायर एजुकेशन में ड्रापआउट रेट है, उसके साथ आप यह बर्ताव कर रहे हैं।

सर, हम देख रहे हैं कि दस साल में इस सरकार ने गलत हुक्मरानी की, नफरतों को भड़काने की कोई हद नहीं छोड़ी, कोई हद नहीं छोड़ी गलतफहमियों को फैलाने की और कोई हद नहीं छोड़ी इस मुल्क के अवाम व नास को तरक करने की। इन दस सालों में हमने क्या देखा? जम्हूरियत हमारे वतन-ए-अज़ीज़ को बचाना बहुत जरूरी है। यह गरीबों और कमजोरों की बहुत बड़ी ताकत है। मगर, दस सालों में, साढ़े नौ सालों में क्या हुआ? एक शख्स को मज़बूत कर दिया गया, एक मज़हब को मज़बूत कर दिया गया, एक आइडियोलॉजी, एक नज़रिये को मज़बूत कर दिया गया, एक शिनाख्त

के सामने दूसरी शनाख्तों को मिटाने की कोशिश की गई। एक ज़बान को मज़बूत कर दिया गया, हमारी जम्हूरियत तो खोखली हो चुकी है। कोई भी हुकूमत और पार्टी सिर्फ़ ज़बर और इस्तसाल पर कायम नहीं रह सकती है।

सर, दूसरा प्वाइंट मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, सीएए के कानून के ताल्लुक एक मरकज़ी वज़ीर ने अख़बार में बयान दिया कि आठ दिन में करने वाले हैं। आप आठ दिन में करेंगे, आठ दिन में मुल्क के कोने-कोने में इतज़ाज़ शुरू होगा। आप सीएए को मज़हब से ख़त्म कर दीजिए, मज़हब से जोड़ेंगे तो आपका इरादा बुरा है। आपका भारत की अक्लियतों को, भारत के मुसलमानों और दलितों को परेशान करने का इरादा है।

सर, हम सीएए के खिलाफ़ क्यों हैं? क्योंकि सीमांचल के मुसलमानों को आप बांग्लादेशी कहते हैं। कोई मिनिस्टर मुझे कहता है कि घुसपैठिये हैं, रोहिंग्या हैं। सीएए को मज़हब से जोड़ना गलत था, इसे निकालिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ मैं अपने बचपने में जब हिस्ट्री पढ़ता था तो मैंने एक स्टेच्यु की फोटो देखी थी, प्रीस्ट किंग ऑफ़ मोहनजोदाड़ो। हमारे देश के प्रधान मंत्री, वतन-ए-अज़ीज़ के वज़ीर-ए-आज़म, ऐसा लगता है कि वैसे ही लग रहे हैं, प्रधान मंत्री नहीं हैं, बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ कि हमारे सद्र-ए-जम्हूरिया ने कहा था कि 22 जनवरी एक तारीखी दिन है। बिल्कुल तारीखी दिन है। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर, 1992 को रखी गई, 22 जनवरी की बुनियाद वर्ष 1986 में ताले खोलकर रखी गई, 22 जनवरी की बुनियाद जी.बी. पन्त ने रखी थी, इसलिए तारीखी दिन है।

(1805/KDS/NKL)

तारीखी-दिन इसलिए भी है, क्योंकि 16 दिसम्बर, 1992 को हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था। आप बताइए कि आज इस मुल्क में चाहे कोई सेक्युलर पार्टी हो या जो भी हो, सब सेक्युलर हैं, केवल बुरा मैं हूँ। किसी में भी हिम्मत नहीं है कि 6 दिसम्बर की बात की जाए और वह तारीखी-दिन इसलिए भी है कि इंसफ़ करने वालों में एक एनसीएलटी के चेयरमैन, एक गवर्नर और एक नामजदशुदा रुक्ने पार्लियामेंट बैठे हुए थे। आप बताएं कि मेरे पास बचा क्या है? बचा केवल आर्टिकल 32 है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वज़ीर-ए-आज़म पर ऐतमाद, भरोसा नहीं करते। वे बिल्कुल भरोसा नहीं करते, यह मैं खुलकर बता रहा हूँ। अगर आप आर्टिकल 32 का ड्यू प्रॉसेस ही ख़त्म कर देंगे, तो फिर मेरे पास क्या बचेगा? मैं तो यहां खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के बेबाक वकील श्री दुष्यंत दवे जी की तरह तो नहीं कह सकता। मुझे आज भी रूल ऑफ़ लॉ में भरोसा है। मुझे आज भी कानून पर, संविधान पर भरोसा है, मगर ड्यू प्रॉसेस तो फॉलो होना चाहिए, लेकिन वह फॉलो नहीं हो रहा है। एक तारीखी-दिन 22 जनवरी था, एक तारीखी-दिन 31 जनवरी था।

सर, रात के अंधेरे में अपील किए बग़ैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं। आप क्या पैगाम दे रहे हैं? 600 साल की मेहरौली मस्जिद को बग़ैर नोटिस दिए आपने डिमॉलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि भारत के प्रधान मंत्री और इनकी सरकार, भारत के मुसलमानों से उनकी सना को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे

छीनना चाह रहे हैं, वह मेरी मस्जिद है। आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए कि 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं? क्या आप हर मस्जिद को मुझसे छीन लेंगे? फिर मेरा वजूद क्या मायने रखता है, मेरा सना क्या मायने रखता है? रूल ऑफ लॉ क्या मायने रखता है? 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? आप उस पर कायम हैं या नहीं? आप 500 साल की बात करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि आप 500 साल पर मत जाइए, बौद्ध पर जाइए, जैनिज्म पर जाइए, शैविज्म पर जाइए। आप कहां रुकेंगे। इस देश को आजादी 1947 में मिली। डॉक्टर अम्बेडकर जी का बराबरी वाला संविधान मिला। उससे पहले तो राजा और रजवाड़े थे। जम्हूरियत नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, मगर आप उसकी जगह कह रहे हैं कि 500 साल बाद आगे क्या होगा, बताइए। अंग्रेजी में किसी ने कहा था-

“Civilization cannot be re-written by hatred. History cannot be corrected by demolition.”

आप यह नहीं कर सकते। मैं यह उम्मीद करता हूँ कि जब मौरिख तारीख लिखेगा। नरेंद्र मोदी जी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। वह यह तारीख लिखना चाहते हैं कि मैंने गांधी-अम्बेडकर के इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत के हमारे हिंदू भाई देश के प्रधान मंत्री की इस सोच को नाकाम करेंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है।

सर, नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है। नेबरहुड फर्स्ट में क्या हो रहा है? हम सोशल मीडिया के जरिए फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। मालदीव जैसा छोटा मुल्क हमें आंख दिखा रहा है। चीन की गोद में वह बैठ गया। हमारे लद्दाख में जो लोग जानवरों को लेकर घास चराने जाते हैं, वहां चीन की आर्मी उनको रोक रही है। बांग्लादेश चीन की गोद में बैठा हुआ है। आप गैलेंट्री अवार्ड दे रहे हैं, क्योंकि चीन बैठा हुआ है, तो भाई साहब, आपका बफर जोन गया कहां? नहीं मालूम, गायब हो गया बफर जोन।

सर, दूसरी बात, आप यह भी देख लीजिए कि यहां मैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। हम बोलते हैं India-Middle East-Europe Economic Corridor, कितना पैसा है, बताइए। वह नहीं बताया जाता। सबसे तकलीफदेह बात मेरे लिए यह है कि भारत यूनेस्को का इलेक्शन पाकिस्तान से हार गया। हम पाकिस्तान से हार गए। क्या यह आपकी फॉरेन पॉलिसी है? यूनेस्को के इलेक्शन में हम पाकिस्तान से हार गए। मामला, इजरायल, फिलिस्तीन, गाजा का आया। अक्टूबर में 10 हजार लोग मर गए। हमने यूएन में सीज फायर की तार्ईद नहीं की। दिसम्बर आया, 20 हजार मर गए, तो हमने तार्ईद कर दी, क्योंकि ग्लोबल साउथ को हमको फॉलो करना पड़ रहा है। भारत ग्लोबल साउथ को फॉलो कर रहा है, जो मेरे लिए तकलीफ की बात है। यह आपकी नाकामी का बहुत बड़ा सबूत है, इसीलिए हम बता रहे हैं कि यह सरकार की नाकामी है।

सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर आखिरी पॉइंट बोलना चाहूंगा। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। 1981 में एक्ट पास हुआ। हमारा लॉ ऑफिसर कोर्ट में कहता है कि मैं पार्लियामेंट के एक्ट को नहीं मानता। कैसे नहीं मानते? क्या नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट को नॉमिनेट किया या पार्लियामेंट ने नरेंद्र मोदी को प्रधान मंत्री बनाया है? आप 1981 के एक्ट को नहीं मानते। मुसलमानों की दो ही तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। आप की सरकार के दौर में 1 लाख 80 हजार मुसलमान हायर

एजुकेशन में निकल गए। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों से छीनना चाहते हैं। Theory of separation of powers में एकजीक्यूटिव हमको डिक्टेड करेगा। मेरी आवाज तो पार्लियामेंट है। अब मेरी आवाज के खिलाफ एकजीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट में बोलता है।

(1810/MK/VR)

आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इतनी नफरत क्यों है? वहां पर तो हिन्दू भाई भी पढ़ते हैं। यह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मामला है। मैं आपसे एक शेर कहकर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, आप भी उर्दू दां हैं। यह अहमद फराज़ का शेर है।

“मसीहाओं को जब भी आवाज दी है, पलट कर आ गए हर बार कातिल,
वहां क्या दादखाही, क्या गवाही, जहां हो मुंसिफ़ों के यार कातिल”

सर, मैं फिर से हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि अल्संख्यक समाज के बजट के स्कॉलरशिप को आप डिमांड ड्रिवेन कीजिए। भारत के प्रधान मंत्री प्रधान सेवक रहिए। आप कोई प्रिंस, किंग मत बन जाइए। आप जीतेंगे या कौन जीतेगा, यह देश तय करेगा। मगर याद रखिए 17 करोड़ मुसलमान आज गम और गुस्से में हैं। वे इस बात को महसूस कर रहे हैं कि प्रधान मंत्री को हमने वोट नहीं दिए, मगर हमारा प्रधान मंत्री है। आखिर यह प्रधान मंत्री 17 करोड़ मुसलमानों को, उनकी शिनाख्त को कैसे मिटा रहे हैं? कैसे उनको आप मार्जिनलाइज कर रहे हैं? इसीलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जो सेक्युलरिज्म है, उसको मैंने पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म नहीं माना। जो सेक्युलरिज्म संविधान में लिखा गया है, उसकी हिफ़ाजत करेंगे। मुल्क अहम है। वरना, आप याद रखिए, आप चुनाव जीतें या हारें, अगर आप 17 करोड़ जनता में गैर यकीनी कैफियत पैदा कर देंगे तो यह देश के हित में नहीं होगा। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस अदालत फॉलो करेगी। अगर अदालत एकतरफा फैसला करेगी तो गलत होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।

(इति)

1812 बजे

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): सभापति महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार के गौरवशाली दस वर्षों के कार्य का जो ब्यौरा प्रस्तुत किया है, उससे आज सारा देश गौरवान्वित है। गरीब, वंचित, पिछड़े, किसान, युवा और महिलाओं को केंद्र में रखकर सशक्त योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया है, जिससे न केवल सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर आमूल चूल सुधार हुआ है बल्कि करोड़ों देशवासियों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाकर उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास' के ध्येय पर चल रही मोदी सरकार समाज के हर वर्ग को उचित अवसर प्रदान करने में जुटी हुई है।

सभापति महोदय, सरकार की मुद्रा लोन योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट एवं मेक-इन-इंडिया योजनाएं अब ग्लोबल ब्रांड बन चुकी हैं। ऐसी योजनाओं के कारण आज भारत के युवाओं के स्टार्टअप्स की पूरे विश्व में धूम मची हुई है। आज भारत के एक लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं। उनमें से 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं। देश का युवा रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बना है।

सभापति महोदय, आज भारत की महिलाएं सशक्त भी हो रही हैं एवं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। भारत की नारी लड़ाकू विमान भी उड़ा रही है और व्यवसाय भी कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी स्वयं सहायता समूह बनाकर स्वरोजगार स्थापित कर रही हैं। यह गर्व का विषय है कि मुद्रा लोन योजना के 46 करोड़ लाभार्थियों में 30 करोड़ महिलाएं हैं।

सभापति महोदय, यह माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच एवं मजबूत निर्णय का ही परिणाम है कि वर्षों से लंबित महिला आरक्षण अधिनियम को इसी नये संसद भवन में पारित करके महिलाओं का वंदन एवं अभिनंदन किया गया है। अब वह दिन दूर नहीं जब 33 परसेंट महिला बहनें देश की संसद एवं राज्यों की विधान सभाओं में अपनी सक्रिय भागदारी निभाएंगी।

सभापति महोदय, आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से छः हजार रुपये प्रतिवर्ष की राशि सीधे किसानों के खाते में पहुंच रही है। एक दिन वह था जब प्रधान मंत्री कहा करते थे कि मैं एक रुपया भेजता हूँ तो नीचे जाते-जाते वह 15 पैसा रह जाता है।

(1815/SJN/SAN)

अगर आज मोदी सरकार डिजिटलीकरण के माध्यम से एक रुपया भेजती है, तो सीधे उनके खाते में एक रुपया ही पहुंचता है। अब तक किसान भाइयों को 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। एक समय था, जब यूरिया के लिए लाइन लगा करती थी। अब किसानों को नैनो यूरिया मिल रही है। पिछले 10 वर्षों में 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना', कृषि निर्यात की नीति, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र एवं 8,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाकर देश के अन्नदाता को मजबूत करने का कार्य किया गया है। आज किसानों को कृषि की उन्नत तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उनकी पैदावार भी बढ़ रही है और आमदनी भी बढ़ रही है।

माननीय सभापति जी, माननीय मोदी सरकार गरीब को गणेश मानकर कार्य कर रही है। ये सरकार आज 80 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क राशन प्रदान कर रही है। आज देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 4,10,00,000 परिवारों को पक्के मकान देने का काम हुआ है। 10 करोड़ लोगों को 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत गैस कनेक्शंस दिए गए हैं। पहली बार लगभग 11 करोड़ गरीब परिवारों के घरों में नल के द्वारा शुद्ध पानी दिया जा रहा है। देश में 11 करोड़ शौचालय बनाने का काम इस मोदी सरकार में ही हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया करते थे, आज मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए पिछले 10 वर्षों में पर्यटन क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम किया गया है। पर्यटन क्षेत्र में जो वृद्धि हो रही है, उससे भारत की साख बढ़ी है और दुनिया का हर व्यक्ति भारत को देखना, जानना एवं समझना चाहता है। घरेलू पर्यटन आज देश की अर्थव्यवस्था और युवाओं को रोजगार देने वाले एक बड़े सेक्टर के रूप में उभरकर सामने आया है। हाल ही में जिसका उदाहरण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लक्षद्वीप एवं गुलाबी नगरी जयपुर के दौरे को देखने से मिलता है।

माननीय सभापति महोदय, यह 'मेक इन इंडिया योजना' और 'पीएलआई योजना' का ही नतीजा है। पिछले 10 वर्षों में भारत हथियार के आयातक से हथियारों का निर्यातक बन गया है। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल एवं तेजस जैसे लड़ाकू विमानों का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। यह भारत की कुशल रक्षा नीति का ही परिणाम है कि आज विश्व की कोई भी ताकत भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती है। ये मोदी जी के सपनों का नया भारत है, जो अपने दुश्मन को घर में घुसकर मारता है।

माननीय सभापति जी, बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार ने लाल चौक से लेकर चन्द्रमा तक तिरंगा फहराने का काम किया है। आज विश्वपटल पर भी भारत की छवि उभर रही है और भारत पुनः विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। हम इस गति से आगे बढ़ रहे हैं, वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए कहते हैं कि "सपने नहीं, हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी जी को चुनते हैं"।

माननीय सभापति जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

(इति)

1819 hours

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Hon. Chairperson, Sir, before I come to the President's Address, I think I am duty-bound to allude to my young friend who referred to me when he spoke earlier. Co-incidentally, my young friend and I actually share our birthday. Unfortunately, he is not here to listen to me and I am sure that he will listen to me *via* social media. In his eagerness to please his leader, he actually ended up sounding like the leader of a fan club and not like an independent-minded Member of Parliament.

Sir, I was very glad that he reaffirmed that his party believes in unity in diversity and he referred to Shri Syama Prasad Mukherjee ji's speech in the Constituent Assembly. He said that the genesis of his political party comes from Shri Mukherjee and they believe in unity in diversity.

(1820/SNT/SPS)

But that is really not the reality of their actions. The ruling party in India today believes uniformity is unity. We in the Congress Party and in the Opposition will always fight to preserve the cultural, linguistic, and religious diversity of India. We will fight 'one this', 'one that' policy of this Government. There have been talks of one language, one religion, one kind of culture, now even one temple, one God, and even taking away the diverseness of our nation, which will always be resisted.

Sir, while the ruling party might have to please its leader and indulge in sycophancy, the reality of their India and the reality of what is actually happening is very, very different. Our hon. President was ceremoniously brought into this House with a parade, with a Sengol leading the way. The Sengol stands for righteousness and for great virtues. But this much vaunted Sengol has witnessed two events in this very House which have been unprecedented. There has been a criminal trespass in this House which this Sengol witnessed. Many of us were here in the House on 13th December when there were trespassers who jumped from the visitors' gallery. It was a grave failure of security, a grave failure of intelligence. Now, we are seeing the spectacle of it being turned into a political circus where that whole trial and the whole arrest is going to be turned into some sort of a political blame game. This Sengol also witnessed something very unprecedented. This Sengol which stands for righteousness, which stands for democracy, and which stands for great justice saw a spectacle of 146

Members being suspended from this House. This Sengol, unfortunately, if it is not meant to see these kinds of unprecedented events, is supposed to see justice and is supposed to see fairness. That is the Sengol which brought our President into this House.

Now, I refer to five references from our hon. President speech. The first reference is: "This is my first Address in this new Parliament building. This building resonates the resolve to respect our democratic and parliamentary traditions." These are very high-sounding words. But these high-sounding words did not find merit in inviting the President to inaugurate this House. This President had to wait for this day to come back and address this House whereas the President should have come here to inaugurate this House.

The second claim is this. The President said: "I appreciate all of you for having enacted the Nari Shakti Vandan Adhiniyam after a wait of three decades. This strengthens my Government's resolve for women-led development." Everybody knows the reality. Anybody who follows politics knows the reality that the women's reservation will only happen after the Census and after the Delimitation. It is just a mirage which this Government has put out in front of everybody, knowing that these two goal posts will never be met because the Census is something which has to happen after 2026 and then a delimitation which is going to be tremendously complicated if you are going to delimit constituencies according to population which means you will again penalise the southern States which have limited their population.

Sir, through you, I would like to tell a small statistic of this Government which keeps vaunting its commitment to Nari Shakti. The 17 BJP-NDA ruled States account for 60 per cent of all crimes against women. Seventy per cent of all rapes against women are committed in these States. So, this double engine *sarkar* which this Government keeps vaunting about is in fact a double-edged sword which is actually hurting the women in all these States.

I would come to the third claim from the President's speech. She said: "Today my Government is building modern infrastructure along the entire border. Be it terrorism or expansionism, our forces today are giving a befitting response." I think the Foreign Ministry and the Defence Ministry forgot to give a memo to the hon. President of India. They forgot to give her the Pentagon Report which is in public domain, which was filed in 2023, says: "Since the 2020 Galwan Valley

clash, the People's Liberation Army of China has been having a cozy continuous presence setting up their version of a scenic infrastructure along the Line of Actual Control." Till date, we have not had a categorical statement from the Government, be it the Prime Minister, be it the Home Minister, be it the Defence Minister, categorically saying what is actually happening on the Actual Line of Control which borders China and whether there have been incursions or not.

(1825/AK/MM)

Even recently, we saw a video where in Ladakh our shepherds were being prevented and chased away from the grazing land that belongs in our territory by the People's Liberation Army of China. They had been chasing them away from our land. This is the kind of reality, which is actually happening. But the President is being misled into believing that our borders are safe and we are creating infrastructure which is keeping intruders away.

There is another claim in the President's Address. It says: "My government has, for the first time, brought development to areas, which remained neglected for decades." I think somebody completely and conveniently forgot to mention to the President about the crisis which is happening in Manipur. There was not a single reference to the crisis that is happening in Manipur. There was not a single reference to the kind of ethnic strife which is happening in Manipur, but this Government was congratulating itself for developing areas which have been neglected for decades. This is happening right in front of our eyes. There is ethnic strife here. People are being killed even today, and this Government has been completely mute to that sad reality and is living in some sort of a Mayan Utopia.

The next claim of the President says: "Last year, my government has given government jobs to lakhs of youth in mission mode." This very Government in this very House to a Question had said that still 9.64 lakh vacancies are there in Government jobs. So, what jobs has this Government given to whom?

We have seen the spectacle of young men from Haryana, Uttar Pradesh and Bihar lining up to take up jobs in Israel and to go to the Israel border even though there is a war happening there. They are saying that it is better to work and die there rather than to die here without any work. This is a sad reality of the youth in India today. They are willing to go to conflict zones to get jobs because

there are no jobs here. But here, the Government is misleading the President into believing that job creation is actually happening here whereas the reality is that Indian youth are willing to go to strife areas to get jobs.

The next claim of the President is a slightly longer one. Indulge me please. It says: "After 75 years, the young generation relived that period of freedom struggle. Amrit Kalash containing soil from every village of the country were brought to Delhi. Over 2 lakh plaques were installed. More than 70,000 Amrit Sarovars were built. Construction of more than two lakh "Amrit Vatikas" was completed." These are all high in symbolism and very low in substance. Can this Government say how many IITs they have opened? Can this Government say how many IIMs they have opened? Even the much-vaunted AIIMS, medical colleges and hospitals that they said that they are opening, none of them have come about in reality.

For example, for the one in Madurai, the Bhoomi Pooja was done four years ago. I know that when you do Bhoomi Pooja you can do certain things very quickly. We have seen that with what happened now recently, but this Bhoomi Pooja for the medical college and hospital was done four years ago and still that is not ready. In fact, the medical students in AIIMS, Madurai are studying in Ramanathapuram. They will actually graduate from a college in Ramanathapuram, but their certificates will say that they graduated from AIIMS, Madurai. This is the reality of this Government. It is high on symbolism and low on substance. This has been the hallmark of this Government for the last five years.

As I conclude, this is probably the last speech many of us will be making in this august House in the 17th Lok Sabha, I want to thank you personally because most of the times I have spoken in this House you have been in the Chair. You are some sort of a lucky charm for me. I hope the same lucky charm continues for both of us in the next Lok Sabha as well.

But I only have one hope. When the next Lok Sabha is convened, I hope this Sengol will see the righteousness, virtuousness, justice and the democracy it deserves to see and not this acrimony, which has been the hallmark of this House. Thank you very much, Sir.

(ends)

1829 hours

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you very much, Sir. राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा में एनसीपी की तरफ से मुझे भाग लेने के लिए आपने वक्त दिया, इसके लिए मैं आपकी तहेदिल से आभारी हूँ।

सर, हम सारी स्पीचेज़ सुबह से सुन रहे हैं। पहली दो स्पीच सुनकर तो मुझे लगा कि बचपन में माँ बच्चों को कहानियां सुनाती है कि सब अच्छा है। एक परी आती है, वह सब अच्छा करके जाती है। वह एक स्टोरी होती है, लेकिन बच्चों को लगता है कि सचमुच कोई परी है, जो आकर सब कुछ ठीक करने वाली है। जैसे-जैसे बड़े होते हैं, तो पता चलता है कि इतनी आइडियलिस्टिक दुनिया नहीं है। शायद, ये ख्वाबों में रह रहे हैं। गवर्नेस एक कंटीन्यूटी है। हर सरकार कुछ तो अच्छा करती है।

(1830/YSH/UB)

ऐसा नहीं है कि सभी सरकारों का सब कुछ ही गलत है। अच्छा तो सभी करते हैं, लेकिन थोड़ी चीजें शायद वास्तविकता से दूर हैं। एक स्पीच का ड्राफ्ट आया है और सब वही पढ़ रहे हैं। There is nothing new even in the Budget Speech and in the hon. President's Address. ड्राफ्ट बिल्कुल सेम था। यह पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा बजट वाला है और कौन सा प्रेसिडेंट स्पीच है, क्योंकि हर स्पीच में 10 सालों का हिसाब है। उसमें पिछले साल का और इस साल का तो हिसाब है ही नहीं। इसमें इतनी सारी कंट्राडिक्शन है। जैसा कार्ती चिदम्बरम जी ने कहा है, it is high on symbolism and low on substance. Everything is optics and everything is an event. वह इवेंट खत्म हो जाता है और लोग भूल जाते हैं।

सभापति जी, आपको याद होगा कि जब यह सरकार आई थी, तब इस सरकार ने एक 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' शुरू की थी। उसका क्या हुआ?... (व्यवधान) मेरा मत अलग है। मैं आपको समझा सकती हूँ। जब आपके बोलने का समय आएगा, तब आप समझा दीजिएगा। मैंने 10 सालों से कहीं भी सांसद आदर्श ग्राम योजना को नहीं देखा। किसी एक-दो सांसदों की किताब दिख जाती है, लेकिन आगे क्या हुआ? शौचालय की बहुत बातें हुई हैं। शौचालय जरूर बने होंगे, लेकिन कितने ऑपरेशनल हैं, उसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। जब ये आए थे तो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था। इसमें सभी राज्य काम करते हैं, लेकिन उसका कहीं भी डेटा नहीं है। रेलवेज़ में बदलाव हुआ है। रेलवेज़ पहले से साफ हुई हैं। जो अच्छा है, उसे हम अच्छा बोलेंगे, लेकिन इस देश में कूड़ा-कचरा कम हुआ हो, ऐसा नहीं है। यह काम सिम्बलिज्म में होता है। Substance is really low. I am just being very pragmatic and I would like to be optimistic.

यह देश जितना आपका है, उतना हमारा भी है। इन्होंने महंगाई के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा है। महंगाई के डेटा के बारे में मैं बजट में विस्तार से बोलूंगी, लेकिन उस दिन जितने भी चैनल्स बजट को दिखा रहे थे और उनमें महिलाओं से पूछा जा रहा था कि आपको निर्मला सीतारमण जी से क्या चाहिए तो महिलाएं सिर्फ एक मांग कर रही थी कि महंगाई कम कर दीजिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए।

सर, आपने भी उस दिन टी.वी. देखा होगा। उसके बाद बेरोजगारी आती है। बेरोजगारी पर तो डेटा ही बोलता है, मुझे कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। दो करोड़ वगैरह और 15 लाख रुपये के जुमले के बारे में तो आप बोल-बोलकर थक गए हैं। नौकरियां तो मिल नहीं रही हैं। आज भी कितनी ही बड़ी कंपनीज़ हैं, जो 1000-1500 लोगों को निकाल रही हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। आप यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी-बड़ी कंपनी को देख लीजिए। उनकी फोर्स कम हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी तो कोई बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है।

मैं महाराष्ट्र राज्य से आती हूँ। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिन पर बहुत सीरियस चर्चा होनी चाहिए। आज उस राज्य में बहुत सारा अनरेस्ट है। मैं आपको गिनवाती हूँ कि किस-किस विषय पर आंदोलन चल रहे हैं। महाराष्ट्र में आरक्षण पर आंदोलन हो रहा है। वहाँ पर आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी बहिनें भी आंदोलन कर रही हैं। डॉक्टर्स आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। तलाठी की नौकरी का पेपर लीक हो गया तो उस पर आंदोलन चल रहा है। उसके बाद आपने महिला आरक्षण के लिए बोला तो उस पर आगे कुछ नहीं हुआ। आपने चैक तो साइन कर दिया, नाम भी लिख दिया, लेकिन उस पर डेट ही नहीं है तो कौन सी महिला के बारे में आप बोल रहे हैं। फिर से High on symbolism and low on substance की बात आ जाती है।

आपने प्रेसिडेंट महिला को बनाया, यह अच्छी बात है। हमें भी अच्छा लगा, जब एक महिला प्रेसिडेंट बनी, लेकिन उसके बाद महिला आरक्षण का क्या हुआ? हम यहीं पर ही तो बैठे थे। हमने दोनों हाथों से ताली मारी थी, लेकिन उसके बाद मेरे साथी मनीष तिवारी जी ने कहा कि सुप्रिया यह एक और जुमला है। इस पर डेट ही नहीं है। इसलिए यह इस साल तो नहीं हो रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र में दवाइयों में भी गड़बड़ चल रही है। उसके बाद मणिपुर के बारे में तो किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या हम इतने ज्यादा असंवेदनशील हो गए हैं? वहाँ पर इतनी प्रॉब्लम हो रही है। It is a boiling pot. Should we not discuss it? Is it not our moral duty to discuss it? We only talk about the good things and push everything under the carpet. Parliament is a very serious place to have these discussions. Even Jammu & Kashmir is doing much better. But has everything stopped? जम्मू में क्या हुआ? आपको याद होगा कि वहाँ पर दिसम्बर में कितना बड़ा अटैक हुआ था। So, this place is not just about jingoism. It is a very serious platform to have a discussion and give suggestions on self-improvement. These are a few issues that we need to discuss and we expect the hon. Prime Minister when he replies और अगर हमें विस्तार से इस बारे में सबकुछ समझाते तो we will also give good suggestions for the betterment of this country. That is how this democracy works. It is not only about using ICE. ICE मतलब बर्फ नहीं, ICE मतलब इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी है। पार्टियां तोड़ो, घर तोड़ो और अपनी पार्टी बनाओ। कांग्रेस मुक्त भारत करने वाले थे, लेकिन जितने कांग्रेस वाले कांग्रेस में नहीं रहे, उतने बीजेपी में दिखते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर राज्य में दिखते हैं। मुझे लगता था कि

कांग्रेस मुक्त मतलब कांग्रेस को खत्म कर देंगे। मुझे नहीं लगा था कि निगल जाएंगे और उनके यहां पर कांग्रेस के ही ज्यादा लोग होंगे।

(1835/RAJ/SRG)

यह तो कुछ और ही फॉर्मूला निकाल दिया। On a serious note, I would like to make some interventions. मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का अनुभव शेयर करूंगी।

सर, मैं बारामती निर्वाचन क्षेत्र से चुन कर आई हूँ। वहां सम्यक झाझर नाम का एक यंग लड़का है। उसकी एक दुकान है। मैं उसके साथ घूम रही थी, पता कर रही थी कि मार्केट में क्या चल रहा है? अनइम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, महंगाई, मिडल इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसका क्या हो रहा है? जो मिडल दुकानदार है, उसका क्या हो रहा है? उसको कैसे पैसे मिल रहे हैं? उसका बिजनेस कैसे ड्रॉप हो गया। उसका बिजनेस 25-30 टक्का कम हो रहा है। यह क्यों हो रहा है? मुझे यह समझ नहीं आया। मैं दुकान में गई थी और वह बोल रहा था कि उसके यहां दो-तीन साल पहले बहुत अच्छा चल रहा था because there was no rural distress. वहां शादी के कपड़े मिलते हैं। उसने कहा कि मेरा धंधा 30-40 टक्का धंधा कम हो गया है। क्योंकि there is rural distress. Where is the rural distress? सभी लोग छः हजार रुपए के बारे में कह रहे हैं। सर, उनको छः हजार रुपए हर साल मिलता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि it has not doubled his income. प्याज के बारे में अमोल कोल्हे जी ने कहा है, दूध और सोयाबिन का भी वही हाल है। आप पैन इंडिया देख लीजिए। It is a very serious issue. It is an agrarian crisis.

सर, यह समस्या छः हजार रुपए से हल नहीं होने वाली है। वे टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं क्या-क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये सिर्फ नैनो फर्टिलाइजर पर हैं, लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। किसान छोटा-सा चिप डाल देते हैं और मोबाइल से उससे पता चलता है कि खेतों में कितना पानी डालना है और कितना खाद डालना है। ये नैनो के बारे में कह रहे हैं, वह पीछे रह गया, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और आगे पहुंच गए, connect to farming. उससे बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जब तक उनको उत्पाद का भाव नहीं मिलेगा, तब तक उनकी इनकम डबल कैसे होगी?

आपने देखा कि प्याज की पॉलिसी को यूटर्न किया गया है। मैं पीयूष जी को बोल-बोल कर थक गई कि आप प्याज का एक्सपोर्ट नहीं रोकिए। इथेनॉल की पॉलिसी भी यूटर्न किया गया। थर्सडे को कहा गया कि इथेनॉल की बहुत अच्छी पॉलिसी करेंगे और फ्राईडे को बैन कर दिया गया। गन्ने के किसान का क्या होगा? उनका घर कैसे चलेगा? वे बच्चों की फीस देना चाहते हैं, दवाई लेना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। डबलिंग ऑफ फॉर्मर्स इनकम नहीं हुआ है। आप डेटा चेक कर लीजिए। We need to discuss this. We need to address this. ये प्रॉब्लम्स जिंगोइज्म से हल नहीं होने वाले हैं।

एस.पी.बघेल जी ने अपनी मां से संबंधित सिलेंडर की स्टोरी के बारे में बताया। वह बहुत अच्छी थी। उन्होंने उसे भोगा है। उनकी मां ने वह भोगा है। सिलेंडर आ गई, यह अच्छी बात है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बाद इंदापुर में झगड़ेवाड़ी नाम का एक गांव है। मैं हर गांव में घूमती हूँ। वहां मैना बाई

नाम की एक सीनियर लेडी थी। मैंने उनसे पूछा कि आपको सिलेंडर मिला तो उन्होंने कहा कि हां, मुझे सिलेंडर मिला। आप उसका क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि मैं उसे यूज नहीं करती हूं। मैना बाई आप उसे क्यों नहीं यूज करते है? उन्होंने कहा कि ताई, बहुत महंगा है। मुझे छः हजार रुपए मिलते हैं। अगर मैं एक हजार रुपए की सिलेंडर खरीदूंगी तो मैं क्या खाऊंगी और बच्चों को क्या खिलाऊंगी? आज आप यह मानों या न मानों। एस.पी. सिंह बघेल जी अपने भाषण में कह रहे थे कि महिलाओं का काम बहुत अच्छा चल रहा है। आप इंडिपेंडेंटली देख लीजिए। मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पता करिए कि कितने सिलेंडर्स रीफिल होते हैं। Regarding Ujjwala Yojana, the intent of the Government may be very good. I am not taking it away from the Government. लेकिन रीफिल कितने होते हैं? इनको यह कहने की आदत है कि पहले क्या हुआ? इस हिसाब से हमारे समय में सिलेंडर का भाव साढ़े चार सौ रुपए था और आज यह हजार रुपए का हो गया, तो महंगाई बढ़ी।

सर, आज आप आशा वर्कर्स की मीटिंग में चले जाइए। मैं खुद हर आशा वर्कर और आंगनवाड़ी सेविका, जब उनका आंदोलन चल रहा है, तो उनसे 10 बार मिल चुकी हूं। मैंने उनसे पूछा कि आप चूल्हे पर खाना पकाती हैं या सिलेंडर से खाना पकाती हैं। आधी महिलाओं ने कहा कि हम मिक्स करके खाना पकाते हैं क्योंकि हसबैंड भी काम करते हैं, तो दोनों की इनकम मिला कर काम करते हैं, तो काम चल जाता है। लेकिन जो महिला अकेली है, वह यह नहीं कर पाती है, क्योंकि महंगाई है, आप मानों या न मानों। आप यहां नहीं मान सकते हैं, तो घर जाकर भाभी जी से पूछ लीजिए आपको भाभी जी बता देंगी कि इस देश में कितनी महंगाई बढ़ी है। महंगाई का इश्यू है। एस पी बघेल जी जो कह रहे थे, वह ठीक है। उनका अनुभव बड़ा अच्छा होगा, लेकिन आज ग्राउंड रियलिटी वैसी नहीं है। सिलेंडर की दिक्कत है। Ujjwala Yojana has not done as well as the Government likes to claim.

मैं आयुष्मान भारत योजना के बारे में कहना चाहती हूं। Again I am not taking away from the intent of the Government. इंटेंट बहुत अच्छा होगा लेकिन इम्प्लिमेंट तो होना चाहिए। फिर जिंगोइज्म हो गया। आयुष्मान भारत के बारे में मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का 10 उदाहरण दे सकती हूं। आप फील्ड में बहुत जाते हैं। कितने लोगों के पास आयुष्मान भारत का कार्ड है? मैं एक उदाहरण देना चाहती हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पुरंदर है। वहां खड़द नाम का एक गांव है। मुझसे योगेश पाटिल मिलने आया था।

(1840/KN/RCP)

उसकी मदर को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। वह कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद आयुष्मान भारत के कार्ड को लेकर वह 10 जगह गया और वह कहीं नहीं चला। उसके बाद गांव के सब लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और उसका बिल भरा है। The scope needs to be increased. सिर्फ 10 हॉस्पिटल करने से कुछ होने वाला नहीं है। आंगनवाड़ी और आशा बहनों की आप जो मदद कर रहे हैं, वह अच्छी बात है और मैं उसका स्वागत करती हूं। लेकिन उसका स्कोप बढ़ना चाहिए। आप जो पेंशन देते हैं, उन महिलाओं की मांग है। आज सुबह क्वेश्चन ऑवर में एक क्वेश्चन था। उसमें सोशल

सिक्वोरिटी इंश्योरेंस के बारे में आज स्मृति ईरानी जी जवाब दे रही थी। उसमें मेरा एक सुझाव है कि अगर आप पेंशन दे रहे हैं तो हर्बैंड एंड वाइफ दोनों को दीजिए क्या होता है कि हमारी बहन का जब एक्सीडेंट होता है तो फैमिली को मिल जाता है, लेकिन अगर उसके पति का एक्सीडेंट हो तो उसको कुछ नहीं मिलता है। वह अकेली रह जाती है। This is a suggestion I am making to the Government. अगर आप आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को यह पेंशन दे रहे हैं तो जहां-जहां उनके पति हैं, फैमिली में दोनों का करवाइये। यदि दोनों में से किसी का भी अनफॉर्च्युनेटली एक्सीडेंट हो जाए तो वह औरत अकेली न रह जाए। That is my only suggestion to this Government. So, I will be really appreciating if they look at it.

दूसरा, ईपीएस-95 का विषय है। सर, वे आपको भी मिले होंगे। हेमा जी ने भी बहुत अच्छा लीड लिया था और उनसे मिलने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी को हेमा जी लेकर गई थी। मैं उनकी भी आभारी हूँ कि उन्होंने कोशिश की। But EPS 95 is a commitment which the BJP Government had given in 2013 before coming to power. आपको याद होगा कि अरुण जेटली जी उनसे मिले थे और अरुण जी ने वायदा भी किया था। उसके बाद अनफॉर्च्युनेटली अरुण जी अब हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन ईपीएस-95 के जो लोग हैं, उनको आज 700 रुपये भी नहीं मिलते हैं। उनके हक का पैसा है। वह कहां गया? सरकार के पास ही तो पड़ा था। उन्होंने विश्वास के नाते ईपीएस-95 दिया था। उसका क्या हुआ?

ये लोग रेलवे के बारे में इतना अच्छा बोलते हैं। आपको पता है कि इस देश के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए जो कंसेशन था, उसे कोविड के टाइम पर बंद किया था और आज तक वह चालू नहीं हो रहा है। उनको न पेंशन मिल रही है और न ही रेलवे का यह बेनिफिट मिल रहा है। वंदे भारत ट्रेन का क्या करेंगे? बस ट्रेन जोर-जोर से जा रही है और वंदे भारत की ऑक्युपेंसी कितनी है? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चार ट्रेन्स चलती हैं। Occupancy is negligible. I urge upon the hon. Railway Minister who is doing a very good job. आप वंदे भारत ट्रेन चलाइये, यह अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ गरीब रथ ट्रेन भी चलाइये। उनको और स्टॉपेज चाहिए। उनको लगता है कि बहुत एफिशिएंसी बढ़ रही है, लेकिन आप एफिशिएंसी किसके लिए बढ़ा रहे हैं? वह गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है। अगर वह स्कूल नहीं जा पाएगा, वह किसान नहीं जा पाएगा, उस लेबर के लिए ट्रेन वहां नहीं रुक रही है तो उस ट्रेन का क्या करेगा? बस देखता रह जाएगा कि वंदे भारत ट्रेन जा रही है। आप यह गरीब रथ ट्रेन नहीं बढ़ा पाएंगे।

हमारी मांग है कि आप स्टॉपेज को बढ़ाइये और गरीब रथ ट्रेन भी बढ़ाइये। यह देश गरीब देश है। मुझे एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होता है, मैं पिछले साल भी बोली थी, आज भी मैं वही बोल रही हूँ कि 80 करोड़ लोगों को आप खाना देते हैं। आप यहां बोल रहे हैं कि इतने सारे लोगों को आपने पॉवर्टी से बाहर कर दिया तो ये नंबर क्यों नहीं बदल रहा है? अगर आप 80 करोड़ लोगों को कंसिस्टेंटली अनाज दे रहे हैं then, nobody has come out of poverty. It is a contradiction. Who has got out of poverty then if you still have to feed them? So, there is something wrong in this number. The Government must clarify

where this contradiction is coming from. आप अनाज दे रहे हैं, वह अच्छी बात है। मैं उसका स्वागत करती हूँ। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि पॉवर्टी से बहुत सारे लोग बाहर आ गए हैं। It does not match. पिछली बार भी यही नंबर था। इस साल भी वही नंबर है। So, this is a contradiction. This Government is full of contradictions.

There is another major point. हमारे महाराष्ट्र में अब सबसे ज्यादा जो चल रहा है, मराठा, धनगड़, लिंगायत और मुस्लिम समाज के आरक्षण का विषय बहुत चल रहा है। वहां बहुत लड़ाई हो रही है। मेरे ख्याल से अभी आपके 200 एमएलएज हैं और यहां 300 एमपीज हैं। आप एक सेशन बुला कर अगर सरकार इन सब को न्याय देना चाहे, तो एक मिनट में कर सकती है, लेकिन कर नहीं रही है। फिर वही आंदोलन कर देता है, फिर उनको बुलाते हैं और कंट्राडिक्शन वहां भी है। This is again jingoism. उन्होंने मराठा समाज को दे दिया। फिर धनगड़ समाज को आपने क्यों नहीं दिया? मराठा समाज का जो जीआर निकला है, it is not getting implemented. सर्वे चल रहा है, सर्वे की डेडलाइन खत्म हो रही है और वह यहां तो आना ही चाहिए। It will need a Constitutional amendment. आरक्षण के मुद्दे ऐसे ही चलते रहेंगे और गांव-गांव में आंदोलन तथा मोर्चे लग रहे हैं।

(1845/PS/VB)

Who will address this issue? It is not as rosy as it looks. Every Government does good work. But you have to address major issues. So, these are some issues I will expect to get some clarity on. I am not saying, who will win? वह तो वोटर्स डिसाइड करते हैं, हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं। The voter is king. वे डिसाइड करेंगे कि अगले टाइम कौन कहाँ बैठेगा। But you have been very kind to us in the last five years. I am going to speak again on the Budget. So, there is one more chance for me to speak. But I appreciate all your patience. And I urge the hon. Government to be very empathetic. Leadership is not just about being affirmative. You have to be decisive which is appreciating. But you have to have empathy and you have to have compassion when you lead the country.

Thank you, Sir.

(ends)

1846 बजे

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिणी दिल्ली) : माननीय सभापति जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। सुप्रिया जी अपने दस मिनट के टाइम में 20 मिनट तक बोली हैं।

माननीय सभापति जी, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अभी मैं सुप्रिया जी को सुन रहा था। वे यहाँ पर राज्य के मामलों को डिस्कस कर रही थीं। दुर्भाग्य देखिए कि दस महीने पहले महाराष्ट्र में इनकी पार्टी ही सत्ता में बैठी थी। तब लोगों को पेंशन नहीं मिली। लोक सभा में ये कह रही हैं कि वहाँ वृद्धाओं को पेंशन नहीं मिली। आँगनवाड़ी स्टेट का मामला है। उन लोगों ने महाराष्ट्र में क्यों नहीं दिए? ये दस महीने पहले ही सत्ता में थीं। दस महीने बाद सब कुछ बिगड़ गया, सिलेंडर आदि सब बिगड़ गया। खैर, मैं अपने विषय पर आता हूँ।

माननीय सभापति जी, किसी भी देश की दशा और दिशा उस देश की सरकार की मानसिकता पर निर्भर करती है। आज 140 करोड़ देशवासियों का सौभाग्य है कि 50 वर्षों के कुशासन के बाद आज मोदी जी के कुशल प्रशासन को हम सब लोग देख रहे हैं। आज देश का उत्थान संभव हो पा रहा है। आज जो मोदी जी की सरकार है, इसकी सोच में एक नयापन है। इस नयेपन के कारण ही, वह नयापन क्या है? पहले एक सोच थी कि मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा परिवार ही हुआ करता था। उत्तर से दक्षिण तक सभी, अभी 'घमंडिया गठबंधन' के भी लोग हैं, अगर मैं सबको गिनवाऊँ, आप सभी दलों की सोच देख लें। नेशनल कांफ्रेंस में, शेख अब्दुल्ला, फारुख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी में, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, आरजेडी में, लालू यादव, तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव, जेएमएम में, शिबु सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी, टीएमसी में, ममता जी, अभिषेक जी और डीएमके में, करुणानिधि जी, स्टालिन जी, नाती दयानिधि मारन जी और बेटी कनिमोझी जी हैं, इनकी ये सोच रही है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी में, वे अभी कह रही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात की जा रही है। सुप्रिया जी, आप भी तो उसी टीम की हैं। माननीय पवार साहब भी तो कांग्रेस मुक्त करके ही गये हैं। कांग्रेस में, जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी और अब प्रियंका जी लांच की जा रही हैं। इस देश में और कोई है ही नहीं। ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, ये लोकतंत्र की बात करते हैं। दूसरी तरफ, इन सबसे अलग, आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ लोग ही मेरे परिवार के सदस्य हैं। शरद पवार साहब का मैं सम्मान करता हूँ। वरना शरद पवार जी और सुप्रिया जी हैं। सुप्रिया जी के बाद वे किसको लांच करेंगे, यह पता नहीं... (व्यवधान) यही कारण है कि पिछले दस वर्षों में... (व्यवधान) वह तो भतीजा है। वह बेटी नहीं है।... (व्यवधान) यही कारण है कि पिछले दस वर्षों में देश में एक ऐतिहासिक निर्णय, अभूतपूर्व विकास करने की तरफ देश आगे बढ़ रहा है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं- 'मेरे परिवारजनों।' यह माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है।

अखंड भारत की नींव रखने वाले बंगाल के सपूत सुभाष चन्द्र बोस जी, जिन्होंने अपनी सेना बनाकर गोरे अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए अपनी आर्मी का गठन किया था, नेशनल आर्मी का गठन किया था। पिछले 60 वर्षों में, इनमें से किसी को भी उनके बारे में सुध लेने की याद नहीं आयी। कर्तव्य पथ पर बंगाल के उस सपूत की प्रतिमा लगाकर सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया तो वह देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया। कांग्रेस की मानसिकता ऐसी रही कि पूरे के पूरे 60 वर्षों तक

एक ही खानदान की लांचिंग में लगे रहे। इतिहास के पन्नों में भी सुभाष चन्द्र बोस जी कहीं नहीं रहे। केवल वे एक ही खानदान को चमकाने में लगे रहे।

हमारे देश में, चार वर्गों के रूप में ही लोग हैं, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। इस देश को नॉर्दन, सदर्न में बांटने, सदर्न में हिन्दी इम्पोज कर रहे हैं, इस प्रकार से भारत तोड़ो वाले जो लोग घूम रहे हैं, वह इनके कारण से है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें विकास करना है। हमारे सामने चार ही जातियाँ हैं। वे महिलाएं हैं, युवा हैं, अन्नदाता हैं और गरीब लोग हैं।

(1850/PC/SMN)

सभापति महोदय, इतिहास साक्षी है कि देश में जब-जब यह क्रांति आई है, तब-तब उसका बिगुल युवाओं ने बजाया है। आज देश में 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है और 25 वर्ष से कम उम्र की आबादी हमारे देश में 50 परसेंट के लगभग है। प्रधान मंत्री की दूरदृष्टि के कारण अगर हम वर्ष 1857 की क्रांति की बात करें, तो उसमें हम धन सिंह कोतवाल, मंगल पांडे, झांसी की रानी, तात्या टोपे के नाम हैं। उसके बाद अगर हम अंग्रेजों के समय में आएँ, तो भगत सिंह जी, राज गुरु जी, सुखदेव जी, चंद्रशेखर आजाद जी, खुदीराम बोस जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, ऐसे वीरों के कारण ही देश आजाद हुआ था।

इसी के कारण माननीय प्रधान मंत्री जी की दूरदृष्टि की सोच है कि नौजवानों को हमारे देश के अंदर आगे बढ़ने के लिए स्पेस देना पड़ेगा। ये कुछ पंक्तियाँ हैं, जो लिखी जाती हैं, जिन्होंने कहा है –

तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है,
जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है।

यह सोचकर ही हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं, क्योंकि विकसित भारत का संकल्प इन्हीं युवाओं से संपूर्ण होगा। इन युवाओं की तरफ ध्यान देते हुए मोदी जी ने कहा है, अभी नव मतदाता सम्मेलन में भी उन्होंने आग्रह किया था कि जो आज की हमारी पीढ़ी है, 40 साल, 45 साल, 50 साल, जिन्होंने यह तंज झेला है, वह आज का जो 22 साल का नौजवान है, जिससे भारत विकसित होगा, उसको यह तंज झेलने की आवश्यकता नहीं होगी। युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के संकल्पबद्ध प्रधान मंत्री जी द्वारा अनेकों नीतियों का योजनाओं के माध्यम से युवा कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का काम इस सरकार में दस सालों में हुआ है।

सभापति जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसका उद्देश्य एजुकेशन के साथ इंप्लॉयमेंट, इंटरप्रेन्योरशिप और उसके बाद एक्सिलेंस है। यह जो नई एजुकेशन पॉलिसी, 2020 आई है और स्किल इंडिया के तहत 1,40,00,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने के बाद स्टार्ट-अप इंडिया से स्वरोजगार में वर्ष 2018 में 8,600 लोगों को रोजगार, जिन्होंने दूसरों को रोजगार देने का काम किया। वर्ष 2023 में स्टार्ट-अप इंडिया के माध्यम से 26,542 युवाओं को, जिन्होंने और भी लोगों को स्टार्ट-अप के तहत रोजगार देने का काम किया है।

सुप्रिया जी चली गईं। ये बोलते हैं, पत्थर फेंकते हैं और भाग जाते हैं। सुनते तो पता लगता कि बेरोजगारी देश में कितनी संख्या में कम हुई है? स्वनिधि योजना में 78,00,000 लोगों को 10,000 रुपए का लोन दिया गया। गरीब आदमी गांवों से शहरों की ओर इसलिए पलायन करता है कि उसके पास दो बीघा जमीन है, एक एकड़ जमीन है, गुजारा नहीं होगा, शहर की तरफ जाऊँ, बच्चों का लालन-पालन करना है। शहर की तरफ आए, तो रोजगार नहीं मिला। रोजगार करूँ, तो क्या करूँ? रेहड़ी, पटरी, खोमचा

लगाकर सब्जी बेचकर गुजारा करना, फ्रूट बेचना, चाय की दुकान लगाना, फेरी लगाना, लेकिन ये लगाने के लिए पैसा कहां से आए? दस-बीस हजार रुपए होते, तो गांव से शहर की तरफ क्यों आता? उनको साहूकारों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था।

हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री जी की गरीब आदमी का उत्थान कर के उसको ऊपर करने की सोच ही थी कि स्वनिधि योजना चलाकर 10,000 रुपए का लोन बगैर गारंटी के दिया गया। मोदी जी ने वर्ष 2014 में कहा था, पार्लियामेंट में पीएम बनने के बाद सेंट्रल हॉल में माननीय प्रधान मंत्री जी का पहला भाषण था कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार रहेगी। वर्ष 1971 की तरह यह नहीं कहा था कि गरीबी हटाओ, देश बचाओ और गरीबी आज तक चल रही है। गरीबों को समर्पित सरकार में स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए का लोन, बगैर गारंटी के, बगैर ब्याज के, एक साल तक गरीब आदमी को कोई ब्याज नहीं देना है, ऐसे 78 लाख लोगों को पिछले दो-तीन सालों में काम देने का काम हुआ।

इसी प्रकार से मुद्रा बैंक्स द्वारा 50,000 रुपए से लेकर 10,00,000 रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। उसमें 43 करोड़ जो लोन्स मंजूर हुए हैं, इसमें 23 लाख करोड़ रुपए नौजवानों को देने का काम हुआ है। मुझे लगता है, जैसे कहते हैं कि किसी की हरे में आँख फूट जाती है, तो उसको बाद में दुनिया हरी-हरी नजर आती है, सूखे में फूटती है, तो सूखी-सूखी नजर आती है। ये कहते हैं कि लोगों को रोजगार नहीं मिला, लेकिन 43 करोड़ लोन्स मंजूर हुए हैं। स्टार्ट-अप के माध्यम से 7,651 करोड़ लोन्स एससी / एसटी नौजवानों को देने का काम हुआ। हर ब्रांच एक लोन देती है। पिछले दस वर्षों में कई मेडिकल कॉलेजेज खोले गए हैं। अब गरीब का बेटा और बेटी भी एमबीबीएस करके डॉक्टर बनने के ख्वाब को लेकर आगे आती है। पहले अवसर नहीं मिलता था, जहां 60 सालों में 367 मेडिकल कॉलेजेज थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 643 हो गई। 103 सरकारी केंद्रीय विद्यालय खोलने का काम हुआ। अटल जी के नाम से दस हजार अटल टिकरिंग लैब्स खोले गए हैं, जिससे इनोवेशन्स को प्रोत्साहन मिला। एक करोड़ स्टूडेंट्स ने उसमें भाग लेने का काम किया है।

(1855/CS/SM)

खेलो इंडिया के माध्यम से स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। स्पोर्ट्स ही एक ऐसा इवेंट है, जिससे स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, चरित्र निर्माण, टीम वर्क की भावना लोगों के बीच में आती है। स्पोर्ट्स के माध्यम से जाति, धर्म से ऊपर उठकर एक सौहार्द की भावना का विकास होता है। जाति, धर्म एक तरफ रह जाता है, केवल राष्ट्रवाद की भावना रहती है। न जाति, न धर्म, न क्षेत्रवाद केवल राष्ट्रवाद नजर आता है। अगर सचिन तेंदुलकर कहीं भी सेंचुरी लगाता है, पूरे देश का एक-एक नौजवान ताली बजाता है। वह भूल जाता है कि यह दक्षिण का है या पश्चिम का है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इस सोच के कारण खेल को आगे बढ़ाने का काम हुआ, जिससे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आगे निकलकर आयी। इससे जनता में एक नयी चेतना जगी है।

महोदय, पिछले 4-5 साल के अंदर भारत की विश्व स्तर पर एक नयी पहचान बढ़ी है। देश भर में टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन को चिन्हित करने के बाद उन्हें सरकार के द्वारा सहायता दी जा रही है। हमारे देश में ऐसे लगभग 6 लाख के करीब स्पोर्ट्समैन को पैसा देकर उनके टैलेंट को उभारने का काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि कार्ती चिदम्बरम जी चले गए, उनके पिताजी ने वर्ष 2013 में स्पोर्ट्स का जो बजट पेश किया था, वह केवल 1219 करोड़ रुपये का था। मोदी साहब ने इसे बढ़ाकर लगभग 3400 करोड़ रुपये का कर दिया है। उन्होंने इसे लगभग तीन गुना से ज्यादा कर दिया है ताकि भारत के नौजवान को

अवसर मिले, उसे अपॉर्चुनिटी मिले। 'खेलो इंडिया' के नाम से अलग से एक हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। सितंबर 2014 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लॉच की गई और एक टास्क फोर्स का गठन किया। आज जो ये इतने मेडल्स आ रहे हैं, देश को यह जानकारी होनी चाहिए, उस टास्क फोर्स ने ओलंपिक 2020, ओलंपिक 2024, ओलंपिक 2028 को टारगेट करके कि परफॉरमेंस कैसे बढ़े, इस पर कार्य करना शुरू किया गया। खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट के अंतर्गत 3 हजार शॉर्ट लिस्टेड खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष 6 लाख 28 हजार रुपये अनुदान देने का काम हमारी मोदी सरकार ने किया है, क्योंकि खेल और स्पोर्ट्स में गरीब और सामान्य परिवार के बच्चे, गाँव के बच्चे ज्यादा निकलकर आते हैं। कबड्डी, खो-खो जैसे भारतीय खेलों को प्रोत्साहन दिया है और उन्हें आगे बढ़ाया है। इसी प्रकार से 29 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से फिट इंडिया कार्यक्रम लॉच किया गया था। जिससे शारीरिक व्यायाम और खेल के विषय में जन चेतना प्रारम्भ हो। अगर आप प्रतिदिन 45 मिनट व्यायाम करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। मैं वर्ष 2019 के फिट इंडिया मूवमेंट का उदाहरण हूँ। कोई भी मेरा फेसबुक अकाउंट चेक कर सकता है, पूरे कोरोना काल में मैं कभी घर नहीं बैठा। मैं लोगों की सेवा में जाता रहा, क्योंकि जो 45 मिनट का व्यायाम होता था, उसके कारण कोरोना कुछ नहीं कर पाया था। यह हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच रही है। आज भी मेरा फेसबुक इसका उदाहरण देगा। जो व्यवस्थाएं हम लोगों को दिया करते थे, उसकी फेसबुक पर रोज की डेट की हमारी पोस्ट होती थी। इस कार्यक्रम के अंदर फिट इंडिया यूथ क्लब सर्टिफिकेशन 15/08/2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉच किया गया। जहाँ देश के नौजवानों ने स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, चरित्र निर्माण के माध्यम से 47,133 युवा क्लब पंजीकृत किए। देश के नौजवानों का विश्वास मोदी जी के अंदर बना है। उसके बाद ओलंपिक के जो गेम्स हुए, उन्होंने इस बात को दिखा दिया कि भारत का युवा शक्तिशाली है। वह कुछ भी कर सकता है। कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग के अंदर, जो वर्ष 2019 में हुआ, 35 गोल्ड भारत के आए। पहले भारत टकटकी लगाए देखा करता था कि गोल्ड की लिस्ट में हमारा नाम होगा या नहीं होगा। इसी प्रकार से 21वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस गेम्स के अंदर तो कमाल ही हो गया। जितने भी टेबल टेनिस के हर आयु वर्ग के इवेंट हुए थे, हर किसी के अंदर गोल्ड भारत ने लिया था। इसी 'खेलो इंडिया' के कारण उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। अगर मैं स्पेशल ओलंपिक की बात करूँ तो कुल 368 मेडल भारत के आए। इसमें 85 गोल्ड, 154 सिल्वर और 129 ब्रॉज मेडल थे और 70 साल के बाद भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आया। ये कहते हैं कि आप ऐसा करते हो जैसे 10 साल में ही सब कुछ हुआ है, इससे पहले कुछ हुआ ही नहीं। इससे पहले हम कभी इस तरह से सोचते भी नहीं थे।

जब एक स्टेडियम का नाम गुजरात सरकार ने मोदी जी के नाम से रखा, तो इन्हें बड़ी तिलमिलाहट लग गई। गोगोई जी यहाँ नहीं हैं। अगर वे यहाँ पर होते तो मैं उनको बताता कि गोगोई जी थोड़ा पीछे जाकर देखिए, पूरे देश में एक ही खानदान के नाम से 19 स्टेडियम हैं। क्या इस देश में प्लेयर नहीं हुए, क्या इस देश में देशभक्त नहीं हुए, क्या इस देश में अच्छे पॉलिटिशियन नहीं हुए? इस देश के अंदर 650 ऐसी संस्थाएं हैं, जिनमें से 32 शैक्षिक संस्थाएं हैं, 4 अस्पताल, केवल राजीव गाँधी जी के नाम से देश में हैं, लेकिन इनको दर्द हो गया कि गुजरात सरकार ने मोदी जी के नाम से एक स्टेडियम का नाम कैसे रख दिया।

(1900/IND/RP)

महोदय, इसी प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में विल पॉवर पैदा हुई है और मजबूत सरकार बनी है। जब वर्ष 1984 में दंगे हुए थे, तब देश ने माना था कि देश में कोई विल पॉवर वाली सरकार बनाने की जरूरत है। सुप्रिया जी ने कहा कि यह एरोगेंसी है। यह एरोगेंसी नहीं है, यह विश्वास है। मुझे मालूम है कि मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूँ या 60 किलो वजन उठा सकता हूँ या 90 किलो वजन उठा सकता हूँ। यदि मैं इतना वजन उठा सकता हूँ तभी मैं कह सकता हूँ कि इतना वजन मेरे सिर पर रख दो और इतना वजन मैं उठाकर जाऊंगा। जिसके अंदर विश्वास ही नहीं होगा, वह क्या करेगा? दस साल में मोदी जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो 18-18 घंटे काम किया है, मंत्रियों से काम कराया है, यह सब उसका परिणाम है। भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण 500 साल से नहीं हुआ था। कितनी पीढ़ियां बीत गईं, किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई। अनुच्छेद 370 हटाया गया। आप आंकड़े देख लीजिए कि वहां कितनी हत्याएं होती थीं और आज जब एक आतंकवादी अटैक हो जाता है, तो उसे लेकर शोर मचाते रहते हैं। ओबीसी कमीशन, काका कालेलकर 30 मार्च, 1955 को जवाहर लाल नेहरू जी ने एक कमेटी बनाई। 44 से 50 परसेंट ओबीसी समाज देश में है, उन्हें उनका हक देने की ये कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए। मोदी जी ने कहा कि ओबीसी के लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। सरकारी क्षेत्र से लेकर हर क्षेत्र में उनके साथ न्याय हो और कमीशन में उनकी बात सुनने वाला होना चाहिए, इसलिए कांस्टीट्यूशन राइट देने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। ऐसे निर्णय लेने की विल पॉवर हमारी सरकार में है। जिसे हम सवर्ण जाति कहते हैं, क्या उनमें गरीब लोग नहीं हैं? क्या कभी इसके बारे में पिछली सरकारों ने सोचा? ऊंची जाति के अमीर लोगों का तो उत्थान हो रहा है, लेकिन गांव में गरीब सवर्णों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। मोदी साहब ने बगैर एससी, एसटी, ओबीसी के कोटे के आरक्षण को कम किए बिना 10 परसेंट आरक्षण देकर उच्च वर्ग के समाज के गरीब परिवारों को भी सम्मान देने का काम किया और उनके बच्चों का भी स्कूलों में एडमिशन हो और उनकी भी नौकरियां लगे, ऐसा काम मोदी जी की सरकार ने किया। इसके संबंध में देश में बहुत दुष्प्रचार किया गया कि मोदी जी आरएसएस के मैनडेट पर एससी, एसटी का आरक्षण खत्म करने जा रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में कहना चाहता हूँ। सुप्रिया जी चली गईं। सुप्रिया जी आप पढ़ी-लिखी हैं और अच्छे घराने की बेटी हैं। आप झोंपड़ी से निकल कर नहीं आई हैं। आपको मालूम है कि जब तक जनगणना नहीं होगी, डिलिमिटेशन नहीं होगा, तब तक किसी नई सीट पर नया आरक्षण कैसे लागू हो जाएगा? जनगणना वर्ष 2027 में होगी, तब 33 परसेंट आरक्षण महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत मिलेगा ही मिलेगा, इसमें गुमराह करने की क्या बात है? अब बेटियां पढ़ने लगी हैं और सब समझती हैं। बहनों को यह सम्मान देने का काम भी मोदी जी की सरकार ने किया है।

महोदय, मैं दक्षिणी दिल्ली से आता हूँ, जो पहले आउटर दिल्ली के नाम से जानी जाती थी। यह बहुत बैकवर्ड इलाका था। मैं वहाँ तुगलकाबाद गांव में पैदा हुआ हूँ। मैं हाउस के माध्यम से कहना चाहता हूँ और चैलेंज करता हूँ कि मैंने वहाँ विद्यार्थी परिषद से लेकर आज तक सामाजिक क्षेत्र में काम किया है। कभी कोई एमपी सोच नहीं सकता था, सरकारों की विल पॉवर नहीं थी कि वहाँ कोई विकास का काम करवाना है, लेकिन यह मोदी जी की विल पॉवर है कि वहाँ 885 एकड़ में बदरपुर-जैतपुर के अंदर एक ईको पार्क, जो एशिया में सबसे बड़ा पार्क है, बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी गए थे। इसी प्रकार से डीएनडी कालिंदी कुंज, जो दिल्ली में बौने दुर्योधन की सरकार चल रही है, उसने कह दिया कि हम अपना पैसा देंगे और सड़क बनाएंगे। गडकरी साहब ने कहा कि छोड़िए, मोदी सरकार ने बहुत पैसा दिया है इसलिए आप मुझे बताइए मैं सड़क को मुम्बई से मिला देता हूँ। चार हजार करोड़ रुपये की लागत से छह लाइन की रोड का जब वर्ष 2019 में उद्घाटन किया तो इन्होंने प्रचार किया कि ये तो केवल शगुफा छोड़ रहे हैं, लेकिन आज उस सड़क का 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

महोदय, आयुष्मान योजना के तहत हम अस्पतालों की बात करें। बदरपुर में 200 बेड के अस्पताल का मोदी जी ने उद्घाटन किया और वह तैयार भी हो गया है। इसी प्रकार वेस्ट टू एनर्जी प्लांट 345 करोड़ रुपये की लागत से जो कूड़े के ढेर दिल्ली में लगे रहते थे, उन्हें हटाने का काम हुआ। इसी प्रकार संगम विहार, साउथ दिल्ली में बिजली का कट रहता था और 24 घंटे तक बिजली नहीं आती थी। पीयूष गोयल जी एनर्जी मिनिस्टर और गडकरी जी वहाँ गए। 31400/200 केवीए का ट्रांसफार्मर 3100 करोड़ रुपये की लागत से बना। आज साउथ दिल्ली में एक मिनट भी लाइट नहीं जाती है। यह काम, यह विल पॉवर यदि आई है तो मोदी सरकार के समय आई है। ईएसडब्ल्यू फ्लैट्स 3024 झुग्गी वाले लोगों को देने का काम हुआ तो दो साल में झुग्गी वालों को मकान की चाबी देने का काम हुआ। इसी प्रकार से बदरपुर के अंदर, यदि मैं बात करूँ तो एरो सिटी एयरपोर्ट से लेकर तुगलकाबाद मेट्रो, केजरीवाल जी बोले कि मैं तो अपनी प्लानिंग बनाऊँगा, यह तो शीला जी का फोर्थ फेज था, मैं तो परमिशन नहीं दूँगा।

(1905/RV/NKL)

हरदीप पुरी जी ने कहा कि यह नहीं चलेगा, यह मोदी की सरकार है, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो अकेले केन्द्र सरकार 10,000 करोड़ रुपये देगी और अभी मेट्रो के उस चौथे चरण का काम तेजी के साथ चल रहा है। जहाँ तिगड़ी से लेकर अम्बेडकर नगर, खानपुर, लाल कुआँ, प्रह्लादपुर के लोग जाम में फँसा करते थे, वहाँ एक-डेढ़ साल में वह बनकर तैयार हो जाएगा।

महोदय, पहले मैं दिल्ली में एक एम.एल.ए. था। जब मैं एम.एल.ए. था तो एक हैंड पम्प लगाने के लिए, एक टॉयलेट बनाने के लिए तरले करने पड़ते थे। यह प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है।

सर, इसी प्रकार से रग्बी स्टेडियम की बात है। यहां नौजवान बच्चे खेलते थे। डीडीए की जमीन थी। बच्चे कहते थे कि अंकल, हमें किसी भी प्राइवेट संस्थान में जाने के बाद इसके लिए 40,000 रुपये देने पड़ते हैं। मैं वी.सी. साहब के पास गया। मैंने कहा कि मैं गृह मंत्री जी से बात करूं या आप करेंगे? वी.सी. साहब ने कहा कि बिधूड़ी जी, रग्बी स्टेडियम पूरे भारत में अभी तक कहीं नहीं है। राजीव गांधी जी इक्कीसवीं सदी की बात करते थे, लेकिन पहले रग्बी स्टेडियम के लिए लैंड एलॉट करके रग्बी मैदान बनाने का काम हमारी सरकार में मैदानगढ़ी में हुआ।

सर, 44 सालों तक देहात के क्षेत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई कॉलेज नहीं था। मैं वर्ष 2014-15 में उस समय के वी.सी. के पास गया। वे उसी विचारधारा के वी.सी. रहे होंगे। उन्होंने कहा कि बिधूड़ी जी, इस पर कैप लगा हुआ है, नया कॉलेज तो खुल ही नहीं सकता। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने शिक्षा मंत्री जी से यह कहा। उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं। उस वी.सी. की छुट्टी हुई, अगला वी.सी. आया, उन्होंने कहा कि इसमें कोई कैप नहीं है, हमारे पास बहुत पैसे हैं। आठ एकड़ जमीन एलॉट कराकर 80 करोड़ रुपये में फैसिलिटेशन सेन्टर तैयार हो गया और 200 करोड़ रुपये में कॉलेज बनाने की फाइल धर्मेन्द्र जी के पास पड़ी है, जिससे वहां कॉलेज का निर्माण होगा।

सर, बच्चों के खेलने के लिए द्वारका, बागडोला में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना। महिपालपुर में 188 करोड़ रुपये की लागत से पी.डब्ल्यू.डी. की सड़क बनी। पी.डब्ल्यू.डी. ने इसके लिए पैसे नहीं दिए। मैं हाउस में यह ऑन-द-रिकॉर्ड बोल रहा हूं। दिल्ली के मुख्य मंत्री ने इसके लिए मना कर दिया। हरदीप पुरी जी ने कहा कि बिधूड़ी, हमारे पास बहुत पैसे हैं, तुम चिंता मत करो। लोग बसंत कुंज, महरौली से होते हुए एयरपोर्ट जाते थे, वहां के पुल को 11 महीने में पूरा करने का काम किया गया।

सर, आज जेटली साहब नहीं हैं। वर्ष 2014 में यहां सरकार बन गयी। मैं एम.पी. बन गया। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। कांग्रेस की मुख्य मंत्री शीला जी ने वर्ष 2005 में इस बात के पत्थर लगाए थे कि हर दस किलोमीटर पर 200 बेड्स के अस्पताल बनेंगे। वहां पर अस्पताल नहीं थे। मैंने जेटली जी को यह कहा। जब इस सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया था, उस समय दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था। उस बजट में 50 लाख रुपये उसकी अर्नेस्ट मनी की घोषणा करके अस्पताल बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। अम्बेडकर नगर में गरीब लोग रहते हैं। वहां जे.जे. रिसेटलमेंट कॉलोनी है। हमने कहा कि वहां गरीबों के लिए अस्पताल चाहिए। अम्बेडकर नगर में एन.बी.सी.सी. कम्पनी के माध्यम से 200 बेड्स

का अस्पताल हमारी सरकार ने दिया। बाद में बौना दुर्याधन वर्ष 2015 में आ गया तो इसे उसका उद्घाटन करने का मौका मिल गया, लेकिन इसकी अगर किसी ने शुरुआत की तो मोदी जी की सरकार के माध्यम से अम्बेडकर नगर में 200 बेड्स का अस्पताल बना।

वहां गरीब लोगों की शादी के लिए कोई उत्सव पंडाल ही नहीं था। 6 करोड़ रुपये की लागत से अम्बेडकर नगर में उत्सव पंडाल बनाने का काम हुआ है।

सर, सबसे बड़ा काम दक्षिणी दिल्ली के लोगों के लिए हुआ है। वहां पाँच लाख लोगों को रोजगार मिलेंगे। अगर हमारे क्षेत्र के लोग और देशवासी माननीय प्रधान मंत्री जी के चरणों की धूल को पीएं तो भी कम पड़ेगा। इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, यशोभूमि, जो 25 करोड़ रुपये की लागत से बना है, यह दक्षिणी दिल्ली के पाँच लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेगा। यह हमारे दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र को मिला है।

सर, यशोभूमि की लागत के साथ-साथ मैं यह चीज आपको बताए बगैर नहीं रुकूंगा, इसके लिए आपको मुझे थोड़ा समय और देना पड़ेगा। सुप्रिया जी अभी बोल रही थीं, तो मैं प्वायंट लिख रहा था। सुप्रिया जी अभी कह रही थीं कि यहां पर कुछ नहीं हुआ है, क्या विकास हुआ है? सबने यह दोहरा दिया कि 78 एयरपोर्ट्स की जगह 149 एयरपोर्ट्स हो गए। लेकिन, हम इस बात को कैसे भूल जाएं कि यहां से आपके क्षेत्र मेरठ जाने में चार घंटे का समय लगा करता था। 70 सालों में 90 लाख किलोमीटर सड़क बनी थीं और मोदी जी के आने के बाद 1,40,000 किलोमीटर सड़कें पिछले सात सालों में देश में बनकर तैयार हुई हैं।

सर, मैंने आपके यहां के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से एल.एल.बी. की है। जब मैं गाड़ी में वहां जाता था तो मुझे चार घंटे का समय लगता था, पर अब एक-सवा घंटे में लोग मेरठ पहुंच जाते हैं। यह मोदी जी की देन है।

महोदय, यहां पर माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है, उसका समर्थन करते हुए मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो काम हुआ है, वह कल्पना से परे है और अगर तीसरी बार मोदी सरकार की बात करते हैं तो मोदी जी देशवासियों के भरोसे पर यह बात करते हैं। सीतारमण जी ने जो कहा है, वह हमने किया है। पेपर में हम जो लिख कर आए हैं, उसमें हमें विश्वास है कि हमारे पास मार्क्स आएंगे। जो लोग पेपर्स ही खाली छोड़ कर आएंगे, उन्हें संशय रहता है कि परीक्षा में फर्क चलेगा या नहीं चलेगा।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): आपने सी.सी.एस. यूनिवर्सिटी से पढ़ाई तो ठीक की है।

1909 बजे

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, पहली बात तो यह है कि जब हमारे ओडिशा की एक महिला, आदरणीय राष्ट्रपति जी सेंगोल के साथ इस भव्य सभा के अन्दर पधारीं, तो मेरा मन गदगद हो गया। उनसे मेरा काफी दिनों से परिचय है।

(1910/GG/VR)

जिस डिग्निटी से एक महिला सभा गृह में आती है, आप जहां पर बैठे हैं, वहां पर वे विराजीं और संबोधन करते हुए यह भी कहा कि मैं पहली बार इस भव्य भवन के अंदर आपको संबोधित करने के लिए आयी हूँ।

सोचिए, एक आदिवासी परिवार में जन्मी एक लड़की, मयूरभंज जिले के उप्रांत एरिया के आदिवासी गांव के परिवार में जन्मी लड़की, एजुकेशन के हिसाब से एक स्तर पर पहुंचीं और नौकरी भी की। फिर अपने पति के प्रोत्साहन से राजनीति में वे एक काउंसलर बनीं, एनएसी में, नोटिफाइड एरिया काउंसलर, रायरनपुर में और सौभाग्य से वे वहां डेप्युटी चेयरमैन भी बन गईं। उस समय उनसे मेरी मुलाकात हुई। यह करीब 40 साल पहले की बात है।

धीरे-धीरे जब वे राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ती गईं, उसके बाद वे ओडिशा में मंत्री बनीं, फिर उसके बाद राज्यपाल बनीं और आज वे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं। उनकी सादगी, जैसे पहले थीं, आज भी वह उसी तरह से बरकरार है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वे रांची के राजभवन से निकलीं, उसके बाद वे भुवनेश्वर में नहीं रहीं, शहर में नहीं रहीं, बल्कि वे अपने गांव में चली गईं और वहां पर वे उस समय एक स्कूल बना रही थीं। उस स्कूल को कैसे खड़ा किया जाए, इसी काम में जुटी रहीं। जिस दिन उनके पास खबर पहुंची कि आपको दिल्ली आना है और राष्ट्रपति के लिए आपको नॉमिनेशन करना है तो पहली चीज जो उन्होंने सुबह नहा कर की, सबसे पहले वे मंदिर गईं और मंदिर की साफ-सफाई खुद की, जो वे करती आईं थीं। उन्होंने पूजा भी की और जैसे शिव जी के सामने नंदी बैठते हैं, उनके कानों में कुछ कहा। जब मैं यहां दिल्ली में उनसे मिला, तब मैंने उनसे पूछा कि आपने नंदी के कानों में क्या कहा था? उन्होंने बताया कि मैंने कहा था कि देश की प्रगति हो। यही है उनकी मानसिकता और इसलिए उनकी सादगी आज भी बरकरार रही है। उनके जीवन में जो भी दुख आए हैं, उससे उन्होंने अपने परिवार और खुद को संभाला है। इस सिलसिले में कुछ और बातें मैं बाद में बताऊंगा, पर जो चीज उनके वक्तव्य में सबसे ज्यादा झलकी, वह है अयोध्या के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। पूरा देश, सिर्फ देश कहने से गलत होगा, पूरे विश्व ने उस नज़ारे को देखा और अपने को पवित्र भी माना कि हम अपने चक्षु से इस नज़ारे को देख पा रहे हैं। सिर्फ यह नहीं कि 500 सालों तक एक दबा हुआ अरमान हमारे मन में था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी दबा हुआ था, सिर्फ वह बात नहीं है। बात यह थी कि जिस समय प्रधान मंत्री जी ने साष्टांग प्रणिपात्र किया, उस समय मुझे लगा, आप सबको भी लगा होगा, आपको भी लगा होगा कि शायद मैं ही वहां साष्टांग प्रणिपात्र कर रहा हूँ। राष्ट्र के शासनाध्यक्ष के हिसाब से उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, पर इस देश के सारे नागरिक, जो वह दृश्य देख रहे थे, उनको लगा, कि हम वहां साष्टांग प्रणिपात्र रामलला जी के सामने कर रहे हैं। यह जो भावना देश में बनी और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं हुई। सबका समर्थन इसमें

था। सबका अनुराग इसमें था। यह सबसे बड़ी चीज है। वह ज़मीन विवादों में फंसी थी। पर जिस ढंग से इस मामले इसको निपटाया गया, सबकी अनुमति से, सहमति से, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ।

(1915/MY/SAN)

जिस ढंग से 22 जनवरी को प्राण-प्रतिष्ठा हुई है, वह भविष्य के लिए एक उदाहरण हो गया है। मैं दूसरी चीजों के बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा। परंतु एक चीज है, जिस पर अब तक यहां चर्चा नहीं हुई है। इसके बारे में मैं अभी बताना चाहता हूँ। वर्ष 2014 से आपको याद होगा कि फार्मर्स प्रोड्यूस को डेढ़ गुना रेट मिलेगा। उसका जो रेट है, उसको हम डेढ़ गुना करेंगे। हाल ही में एक रिपोर्ट निकली है। उस रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि पैडी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1455 रुपये है। अभी इसका एमएसपी 2184 रुपये है। यह ए-टू प्लस एफएल में आ जाता है। ए-टू का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और एफएल का मतलब फैमिली लेबर है। इन दोनों को मिलाकर 1.5 परसेंट आ जाता है। गेहूं 2 परसेंट तक आता है, जैसे इसका ए-टू प्लस एफएल 1128 रुपये हैं और इसका एमएसपी 2275 रुपये है। मेज में 1.5 परसेंट है। ज्वार में 1.5 परसेंट है। मूंग में 1.5 परसेंट है। तूर में 1.6 परसेंट है। इस चीज को अब देश हासिल कर चुका है। इसके बारे में पता नहीं बजट के समय कोई कहेगा कि नहीं कहेगा और 17वीं लोक सभा में चर्चा करने के लिए ज्यादा दिन भी नहीं हैं। मैंने सोचा कि इस बारे में जानकारी आ जानी चाहिए।

17वीं लोक सभा के कार्यकाल में एक और बड़ी चीज हुई। वह चीज यह है कि चार लेबर कोड्स को लॉ का स्वरूप दिया गया। वर्ष 2019 में कोड ऑन वेजेज पारित हुआ। वर्ष 2020 में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बना, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बना और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी भी बना। ये जो चार कोड्स बने हैं, करीब 37 लॉ को मिलाकर ये कोड्स बने हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज यह थी कि हमारी जितनी सारी लॉ बनी थीं, वे सारी ऑर्गनाइज्ड लेबर के ऊपर थीं। पहली बार ऑर्गनाइज्ड लेबर का स्ट्रेन्थ मैक्सिमम 9 करोड़ होगी। ये जो 48 करोड़ हैं, वे अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर के लोग हैं। अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर को हम लेबर लॉ के अधीन लाए हैं। आज सुबह इसमें एक प्रश्न भी था। उसमें आज सबसे बड़ी चीज आ रही है कि इस सरकार ने जो सबसे बड़ी चीज की, वह पेंशन स्कीम फॉर फार्मर्स एंड लेबरर्स है। इतनी सारे स्कीम्स इन्होंने यहां बनायी हैं। उसमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉएड पर्सन्स और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना बनी हैं। इसमें लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स सेल्फ एम्प्लॉएड पर्सन के लिए बना है। ये सारे लोग मुख्यतः अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। इसमें प्लेटफॉर्म वर्कर्स और ओला एवं उबेर टैक्सी ड्राइवर्स आते हैं। यह एक बड़ी चीज है, जिसे इस सरकार ने बनाया है।

यहाँ मैं एक और विषय पर बताना चाहता हूँ। यह हमारी इमरजिंग इकोनॉमी है। इमरजिंग इकोनॉमी में जिसे हम उभरता भारत कहते हैं, विकसित होने के लिए हमारे सामने काफी चैलेंजेज हैं। उन सारे चैलेंजेज को पिन प्वाइंट करके भारत सरकार उसका समाधान करने के लिए भी कोशिश कर रही है। वे काफी स्टेप्स भी ले रहे हैं। इसमें जो एक बड़ी चीज है, वह ईस्टर्न इंडिया के बारे में है। साउथ, वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया की तुलना में ईस्टर्न इंडिया काफी पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां इनवेस्टमेंट कैसे ज्यादा हो, वहां का आर्थिक विकास कैसे हो, इसके ऊपर अभी सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है।

(1920/CP/SNT)

इसमें मेरा राज्य ओडिशा भी लाभान्वित होगा।

एक और चीज के ऊपर मैं आपका और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर हम अपने पूर्वजों के महान बलिदानों को याद करते हैं और याद दिलाते भी हैं। यून तो सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए काफी कुछ कर रही है, परन्तु अभी भी काफी कुछ करना बाकी है। हाल ही में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि शासकीय नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के लिए आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं है? कोर्ट ने एक आवेदन पर यह पूछा है। बिहार, उत्तराखंड और हरियाणा राज्यों में शासकीय सेवाओं में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को दो से तीन प्रतिशत कोटा दिया गया है। यह हर एक राज्य में नहीं है। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में इस तरह का एक आवेदन आने के बाद और हाई कोर्ट मध्य प्रदेश सरकार को पूछने के बाद मैं यह चीज आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ क्योंकि हम कई सालों से इस बारे में अपने आवेदन सरकार को दे रहे हैं, विभिन्न प्रांत या राज्यों को भी दे रहे हैं। मेरा मानना है कि स्वतंत्रता सेनानियों ने पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ी, न कि किसी विशेष राज्य के लिए, इसलिए इनके साथ राज्य के स्तर पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि पूरे देश में शासकीय नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए।

मैं एक-दो चीजें और कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। एक चैलेंज है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में, आपको झेलना पड़ता है, मुझे वह सौभाग्य अब तक नहीं मिला कि जब आप चेयर पर बैठते हैं, हाउस डिस्टर्ब न हो, इसके लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ती है। यह डिस्टर्बेंस होता क्यों है? मेरे सेल्फ ज्ञान में जो है, मैं यही बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर डिस्टर्बेंस इसलिए होता है कि अपोजिशन चाहता है कि वह एक इश्यू रेज़ करे और ट्रेजरी बेंच की तरफ से बोला जाता है कि अभी नहीं। जैसा ब्रिटिश पार्लियामेंट में है, डेढ़ सौ दिन उनकी संसद साल भर में चलती है। बीस दिन अपोजिशन डे निरूपित हैं। अपोजिशन निर्धारित करता है कि क्या एजेंडा रहेगा, किस विषय पर चर्चा होगी, उस हिसाब से बीस दिन रखे जाते हैं। अगर इस तरह की कोई व्यवस्था हमारे यहां होगी, तो यह सारी जो डिस्टर्बेंस हमारे यहां हो रही है, वह नहीं होगी। जो लिस्ट ऑफ बिजनेस है, वह सरकार बनाती है। हमारे ऑनरेबल स्पीकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को चेयर करते हैं। वहां कुछ निर्णय होते हैं। जो लिस्ट ऑफ बिजनेस है, वह तय है, उसे सरकार बनाती है। अगर लिस्ट ऑफ बिजनेस में इस तरह की कोई व्यवस्था हो कि अपोजिशन भी उस लिस्ट ऑफ बिजनेस में अपना एजेंडा रखे, जिसको मान्यता सरकार की तरफ से भी दी जाए, तो यह डिस्टर्बेंस हम अवाइड कर सकते हैं। पार्लियामेंट सबका है। यही बात तो बार-बार कही जाती है कि पार्लियामेंट आपका है, हमारा है, सबका है, पर लिस्ट ऑफ बिजनेस बनाने में अपोजिशन को क्यों नहीं हम शामिल कर सकते हैं? मैं सोचता हूँ कि राष्ट्रपति जी के भाषण के अवसर पर, taking advantage of this discussion, मेरा यह सुझाव रहेगा कि इस बारे में सबको विचार करना चाहिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में सहमति बननी चाहिए।

वन नेशन, वन इलेक्शन के बारे में फॉर्मर प्रेसीडेंट मिस्टर कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। ऐसा नहीं है कि हम यहां चर्चा नहीं कर सकते हैं। एक कमेटी बनी है और शायद जल्दी ही उस

कमेटी की रिपोर्ट आएगी। यह इस देश के लिए एक आवश्यकता है। हमारी पार्टी वन नेशन, वन इलेक्शन के सपोर्ट में है।

(1925/NK/AK)

यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। मैंने पहले भी हाउस में इस बारे में कहा है। We are for one-nation-one-election. कुछ संशोधन हमारे संविधान में करने की आवश्यकता है, कुछ संशोधन यहां के रूल्स के बारे में भी करने की आवश्यकता है, कुछ संशोधन लोक प्रतिनिधि लॉ में भी करने हैं, यह देश की प्रगति के लिए आवश्यक है। मैं एक चीज आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, The latest Corruption Perception Index, which has been prepared recently by Transparency International suggests that corruption in public sector in India is an issue, and India's ranking is slipping to 93 out of 180 countries from 85 in 2022. कर्प्शन हमारे इलेक्शन प्रोसेस को पूरा खोखला कर रहा है। इस सिलसिले में यह जरूरी है। अंत में, मैं यही कहूंगा, राष्ट्रपति जी ओडिया में दो पंक्ति बोलीं और वह पंक्ति थी,

स्वराज्य-पथे जेते गाड़,
पूरु तहिं पड़ि मोर मांस हाड़

It means, let the potholes be filled with my flesh and bones so that my countrymen can proceed to achieve freedom. बंदीर आत्मकथा उन्होंने तब लिखी, जब वह जेल में थे। उस समय उन्होंने ये चीज लिखी थी। What type of selfless sacrifice he wanted to make, and that is how he could influence a large number of people.

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): बहुत ही प्रभावशाली पंक्तियां हैं।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Today, we bow our head in reverence to him. He is considered an epitome of Sanatan Dharma in our State. His statue is just placed on the entrance of Lord Jagannath Temple. Lord Jagannath Temple's Parikrama has been very beautifully constructed recently. It was inaugurated on 17th January by our Chief Minister, and it was his personal endeavour through which this Parikrama has come up. It has come up so well. We have seen Parikrama development at Ujjain, Kashi and in the Golden Temple. I would request you and all our Members to visit Puri and also see the Parikrama and also have a darshan of Lord Jagannath.

HON. CHAIRPERSON: I have been there. Sure.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): With these words, I conclude. Thank you very much, Sir.

(ends)

1928 hours

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Thank you Sir for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks to the hon. President's Address.

I join hands with all the colleagues who have spoken about the Motion of Thanks. The hon. President has spoken about North-East, especially the development of North-East during the present Government. I come from the North-East, but it is very unfortunate that the President fails to mention about the socio-ethnic and religious problems in the North-East in Manipur. In Manipur, for the last eight months there is no internet. Why is it so? It is because the Government does not want the people of India or rest of the world to know how they failed in Manipur.

The condition of 119 relief camps in Manipur is deplorable. When Manipur is affected, the whole of North-East is in problem. The border between India and rest of our neighbouring countries has been mishandled. Today, as I stand here, the North-East is full of drugs.

(1930/UB/SK)

Therefore, there is a rise in almost 70 per cent of drugs in the North-East and that is because of mishandling by the Government.

In Nagaland, almost ten years after signing the framework agreement between the Government and the stakeholders in Nagaland, there is no decision because of ego, lack of knowledge about the culture, language, and the history of Nagas. Nagas have a unique culture. They have a history. Therefore, this Government blindly signed an agreement without a conclusion. They know how to sign an agreement and how to mark it, but they do not know how to resolve the problems of Nagas. Therefore, the problem of Manipur and Nagaland is not resolved yet. The solution of the problem in the North-East is far from reality. Whatever is written in the President's Address by the present Government has misled the hon. President. I demand that the Government take the problem of Manipur and Nagaland seriously. Only then, there will be development for the people in the North-East.

The hon. President also talked about education in the North-East. She failed to mention the ambitions and aspirations of the people of Meghalaya. It had been decided unanimously by the Legislative Assembly of Meghalaya five years ago that Khasi language and Garo language should be listed in the Eighth Schedule of the Constitution of India. The BJP made a false promise during

election. Till date, that promise has not come to reality. The people of Meghalaya are still waiting and being fooled by the Central Government. I demand from the Government that Khasi language and Garo language be included in the Eighth Schedule which is the aspiration of the people. Then only the education for the people of North-East will get better. The Government should start the process as soon as possible.

This Government has been in power for the last ten years. I am a Christian. I could understand the insecurity among the Christians. At any time, whatever function happens, the Christians are at the receiving end. One of the issues, for example, in Manipur is that more than 300 churches have been demolished and more than 500 pastors, nuns and priests have been arrested in silly cases. This is the fate of the Christians. There is an increase of almost 200 per cent in harassment cases against the Christians in the last five years.

We always feel proud that Ram Mandir has been built and we joined the celebrations. But at the same time, people put flags in the churches and on top of the statue of Christ in many churches in India. It is an insult for the Christians. Christians are only 2.5 per cent in India but they have contributed a lot to capacity building, to education sector and to nation building in terms of education and social works but the way they have got the treatment from the Central Government and the respective State Government run by the BJP is really a harassment and they have faced social boycott in many incidents against the Christians. It is a concern for all of us. Therefore, I demand from the Government that the safety of the Christians and minorities should be taken care of. Until and unless we respect that every citizen has right to worship and right to live, I think the progress of India will be hampered.

(1935/SRG/KDS)

Sir, another very important thing is that the tribals, whether in the North-East or in any other part of India, feel insecure for their jobs being taken away. In my State of Meghalaya and in Manipur, they have demanded for Inner Line Permit. In Manipur, the Government has given the Inner Line Permit, whereas in Meghalaya, a consensus has been taken on the floor of the House by the Meghalaya State Legislative Assembly, but till date, no action, no decision has been taken by the Government of India. So, people of Meghalaya think that if they do not take a decision, I think they are not competent. Therefore, the youth of Meghalaya and the people of Meghalaya are losing faith in the Central

Government. So, I demand that a decision on this issue should be taken, so that the people's hopes and aspirations are fulfilled.

Another important issue which the hon. President has mentioned is about roads and connectivity in the North-East. On the National Highway No. 6 which connects between Assam and Meghalaya, as I am speaking today, almost every week on two or three days, there is a jam and blockage. Every week, at least one or two people die on the road because of accidents. The road is in a very deplorable condition. We have written to the hon. Minister. we met him. We requested him to expand it and widen the road, but no action has been taken. It has not even been repaired. Therefore, I think it is very important for the Central Government to take action on these issues. Until and unless we have proper connectivity, proper road and good conditions of the roads, we will not be able to develop. There should be proper connectivity with the Barak Valley especially going through the National Highway No. 6.

There is another important issue in the North-East which is drug abuse. As I said, because of the porous Border, there is an increase of almost 70 per cent in the last nine years in terms of drug abuse to our youth in the North-East. There is almost 6.34 per cent of consumption of drugs compared to only 2.06 per cent international average. So, three times of the people were falling prey to drugs because of unemployment, because of lack of development of the people of the North-East. Therefore, I suggest that a special law should be framed so that the people of the North-East and the youth of the North-East should be promoted, should be helped to solve the problems of the drug abuse. The important issues are unemployment and poverty. I come from a State with matriarchal society. I could see that many of the young people when they are unemployed, there are so many single women who take care of the family. The Government should have a policy to take care of the tribals who are not employed for taking care of their family and for the education of their children. I want to refer to Haryana story where the youths of Haryana want to go to Israel to get a job. So many people from the North-East also have that aspiration that they should get a job anywhere for their livelihood. Therefore, I request the Government to take note of this serious issue of employment of the people of North-East as well as the whole of India so that they can fulfil their promises during the elections.

Sir, thank you for giving me time. With these words, I conclude my speech.

(ends)

(1940/MK/RCP)

1940 बजे

श्री संतोष पान्डेय (राजनंदगाँव): सभापति महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर लाये गए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अभी मैं मेघालय के माननीय सांसद जी को सुन रहा था। मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि पूर्वोत्तर के उन प्रदेशों में कहा जाता था कि मिजो फॉर क्राइस्ट, मेघालय फॉर क्राइस्ट और अनेक प्रकार की बातें वहाँ से आती थीं। पूरे देश ने उसको सुना है और जानते हैं कि वहाँ स्थितियाँ किस प्रकार से थीं।

आज जब इस देश में राम की बात हो रही थी तो कुछ ऐसे ही लोग कहा करते थे कि हमें तो आमंत्रण नहीं मिला है। जब आमंत्रण मिल गया तो बहानेबाजी करने लगे। उसके बाद वे विमुख हो गए। इसके पहले भी वे कहते थे कि इसे धर्मशाला बना दो, इसे विद्यालय बना दो, इसे शौचालय बना दो, अनेक प्रकार की बातें कहने वाले लोग थे। आज यह बन गया। किसी कवि ने कहा था कि –

“तू पूछ, अवध से, राम कहाँ,
वृंदा बोलो, घनश्याम कहाँ,
ओ मगध! कहाँ मेरे अशोक,
वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ।”

किन्तु, अब राम आ गए हैं। वृंदा में भी आने वाले हैं। इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है, क्योंकि इस देश की पहचान यदि किसी से है तो वह गंगा, हिमालय, कृष्ण, शिव और राम से है। यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि राम भारत की आत्मा हैं, राम जीवन पद्धति हैं और राम भारत की पहचान हैं। राम जैसा पुत्र, राम जैसा भाई, राम जैसा राजा, राम ही आधार हैं और राम ही विचार हैं।

“जन जन के मन में राम रमे, हर प्राण-प्राण में सीता है,
कंकर कंकर शंकर इसका, हर श्वास श्वास में गीता है,
जीवन की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है,
यदि राम नहीं है श्वासों में, तो प्राणों का घट रीता है।”

यह भारत की पहचान है। यह सम्मान 500 वर्षों बाद मिला है। जिस प्रकार से सबके ऊपर, राजनीति के ऊपर राजदंड होता है, सेंगोल सामने-सामने और महामहिम राष्ट्रपति जी आईं और जिस प्रकार से वे बोलने के लिए खड़ी हुईं तो सम्माननीय प्रधान मंत्री जी को वह वाक्य याद आ गया- ‘नारी तू नारायणी’।

‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।’

वास्तव में नारी को सम्मान दिलाने का काम और एक लंबे समय बाद यदि कभी कहीं हुआ है तो वह माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में हुआ है। यह कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं यह कहना चाहूँगा कि नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में भी नारी शक्ति की झलक देखने को मिली। कदम से कदम मिलाकर चलती सामर्थ्य की झलक हम सबने देखी है। रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती की वह पंक्तियाँ याद आ जाती हैं-

‘गुमी हुई आज़ादी की कीमत हमने पहचानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी,
जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी,
यह तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनासी।’

इस प्रकार से माननीय मोदी जी की सरकार ने जल, थल, नभ और अंतरिक्ष, हर तरफ बेटियों की भूमिका का विस्तार किया है। हम सब जानते हैं कि महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता के मायने क्या हैं। महिलाओं की आर्थिक भागदारी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। आज लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुकी हैं। इन समूहों को 8 लाख करोड़ रुपये, बैंक लोन और 40 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। हमारी सरकार, माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार दो करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का अभियान चला रही है। ‘नमो ड्रोन दीदी’ के तहत समूहों को 15 हजार ड्रोन उपलब्ध कराने से आमूल चूल परिवर्तन आएगा। आज महिलाएं फाइटर पायलट हैं और नौसेना जहाज की कमांडिंग भी कर रही हैं। आज विश्व में हर क्षेत्र में हमारा देश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। विश्व में आज ऐसे उत्पादों की मांग विशेष रूप से है जो पर्यावरण के अनुकूल हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने ‘जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट’ पर बल दिया है। ग्रीन एनर्जी पर भी फोकस किया गया है। मेरे क्षेत्र में 100 मेगावाट का सोलर पार्क डोंगरगांव और डोंगरगढ़ विकास खंड में लग रहा है, जिसमें 10 साल तक बिजली जेनरेट होगी। उससे हम सीआरसीबी और रेलवे को बिजली देने वाले हैं।

सभापति महोदय, माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंता से अवगत हैं। इसकी झलक इस बात से मिलती है कि इसको रोकने के लिए कानून लाया जाएगा।

(1945/SJN/PS)

यह बात महामहिम राष्ट्रपति जी ने कही है कि देश में शिक्षा अधूरी छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी हो। उन्होंने उच्च शिक्षा में नामांकन में वृद्धि की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा था कि अनुसूचित जाति के छात्रों के पंजीकरण में लगभग 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के पंजीकरण में 65 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि और ओबीसी के छात्रों के पंजीकरण में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। स्कूली छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए केन्द्र सरकार 14,000 से ज्यादा ‘पीएम श्री विद्यालयों’ पर काम कर रही है। इनमें से 6,000 से अधिक स्कूलों में काम शुरू हो गया है। इसी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा और भारतीय भाषाओं में शिक्षा पर बल दिया गया है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून जैसे विषयों का शिक्षण भारतीय भाषाओं में शुरू किया गया है।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा है कि सभ्यताओं के कालखंड में ऐसे पड़ाव आते हैं, जो सदियों का भविष्य तय करते हैं। भारत के इतिहास में भी ऐसे अनेक पड़ाव आए हैं। जब पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची हुई है, ऐसे मुश्किल दौर में सरकार ने भारत को विश्वमित्र के रूप में स्थापित किया है। इसकी वजह से हम ग्लोबल साउथ की आवाज बन पाए हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने

कहा है कि पहले कूटनीति को दिल्ली के गलियारों तक ही सीमित रखा जाता था, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसमें बदलाव किया है। सरकार ने कूटनीति में जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की है। इसका जी-20 एक बेहतरीन मिसाल है।

“अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्”।

हम सबने जी-20 के समय इसकी भावना देखी है। खिलाड़ियों को सरकार की ओर से दी जा रही मदद अभूतपूर्व है। भारत बड़ी खेल शक्ति बनने के लिए अग्रसर है। मेरा राजनंदगांव क्षेत्र है, वह झांकी और हाकी के नाम से जाता है। वहां ध्यानचंद से लेकर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, उन सभी का वहां पदार्पण हुआ है। उन सबने वहां के मैदान में खेला है। कबड्डी और बास्केटबॉल में मेरे क्षेत्र को इस सरकार ने कई अकादमी दी हैं। मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

महोदय, हमारी अर्थव्यवस्था पहले सबसे नाजुक थी। वर्ष 2014 से पहले कहते थे, यदि इनका बस चले, तो ये कटोरा लेकर अंतरिक्ष में भी चले जाएंगे और वहां से भी कुछ बांधकर ले आएंगे। किंतु आज माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार द्वारा किए गए सुधारों की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की पहली पांच अर्थव्यवस्थाओं में आ गई है।

महोदय, इस सबके साथ ही साथ हमारी सरकार ने गरीबों की जो चिंता की है, वह तो अद्भुत है। हम सब जानते हैं कि गरीबों को सस्ता राशन मिलता रहे, उसके लिए हमारी सरकार ने पिछले दशक में लगभग 20 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इतना ही नहीं, एक जमाना था, जब कांग्रेस पार्टी के शासन काल में कनकी यानी चावल के टुकड़े और खंडे के लिए लाइन लगा करती थी, तब कहते थे कि -

“कभी वह दिन भी आएगा, जब हम सुराज देखेंगे,
दायरे हिन्द में फिर हिन्दियों का राज देखेंगे।
पेट में आएगी पेट भर रोटी,
वतन में दाने-दाने का न मोहताज देखेंगे”।

आज उसको दूर करने और गरीबों की चिंता करने का काम किया गया है। यदि किसी ने कोरोना काल में भी 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन देने का काम किया है, तो हमारी सरकार यानी माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अब इसे पांच वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है। इस पर और 11 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

हमारी सरकार ने चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, उन्होंने सभी क्षेत्रों में जो काम किए हैं, उसकी जितनी सराहना की जाए, वह कम है। माननाय प्रधानमंत्री जी की अगुआई पर हमारा देश, जो आज अग्रणी भूमिका निभा रहा है, वह द्रुत गति के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ और मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

(इति)

(1950/SPS/SMN)

1950 बजे

श्री अब्दुल खालेक (बारपेटा) : सभापति महोदय, मौका देने के लिए आपको और मेरी पार्टी को बहुत-बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर हिना गावित जी धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आई हैं, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता हूँ। मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहां नारी 'शक्ति वंदन अधिनियम' के बारे में कहा गया है, अगर नारी शक्ति को आगे लाना है, अगर महिलाओं को आरक्षण देना है तो इसमें डीलिटिमेशन की कोई जरूरत नहीं है। जैसे पंचायत और नगरपालिका में रिजर्वेशन है, लॉटरी होती है तो यहां भी लॉटरी हो सकती है और एक से शुरू कर सकते हैं, तीन से शुरू कर सकते हैं। यहां सीट बढ़ने और सीट टूटने की कोई बात नहीं है। ये लोग नारी शक्ति का सशक्तिकरण नहीं चाहते हैं, इसलिए वह जनगणना तक कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि वर्ष 2029 में होगा। यह होगा या नहीं होगा, उसका भी पता नहीं है।

महोदय, 'नारी शक्ति वंदन' कहते हैं, लेकिन हाथरस की बेटा को इंसाफ कैसे मिलेगा, राष्ट्रपति जी ने इसका जिक्र नहीं किया। राष्ट्रपति जी भी हेल्पलैस हैं, क्योंकि सरकार जो बनाकर देगी, वही बोलेंगी। अंकिता भण्डारी को इंसाफ कब मिलेगा, इसका जिक्र इस भाषण में नहीं हुआ है, कठुआ की आसिफा को कब इंसाफ मिलेगा, इसका जिक्र इस भाषण में नहीं हुआ है। हमारी कुश्ती गिरी है और जो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, उनको कब इंसाफ मिलेगा, राष्ट्रपति जी ने उसका उल्लेख नहीं किया है। ट्रिपल तलाक के बारे में कहा गया है, मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही गई, लेकिन बिलकिस बानो के जो रेपिस्ट थे, बिलकिस बानो की औलाद का जिन लोगों ने कत्ल किया था, उनको कौन सी सरकार ने रिहा किया था? जो इज्जत लूटते हैं, जो मुस्लिम महिला की इज्जत लूटते हैं, जब आप उनको रिहा करते हैं, तो क्या यह सशक्तिकरण है?

सभापति महोदय, सरकार सीएए के बारे में बोल रही है और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी बताया गया कि सीएए, यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू होगा। यह कानून कब अच्छा होगा? असम के लोग इसके खिलाफ हैं, देश के लोग इसके खिलाफ हैं। असम के बीटीएडी एरिया पर यह लागू नहीं होगा, हमारे तीन हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन पर यह लागू नहीं होगा। अगर यह हिल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए खराब है, बीटीएडी पार्ट के लिए खराब है तो यह सारे असम और नॉर्थ ईस्ट के लिए अच्छा नहीं हो सकता है।

सभापति महोदय, मैं नहीं चाहता हूँ कि दुनिया में किसी भी जगह पर हिन्दुओं के ऊपर अत्याचार हो, क्योंकि देश में मेजोरिटी हिन्दुओं की है। दुनिया में कहीं भी अत्याचार नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या हम अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं या नहीं उठाते

हैं? पाकिस्तान में जो परसिक्वूटेड होता है, तो वे उसके नागरिक हैं, यह दूसरी बात है, लेकिन बांग्लादेश, जिस देश को हम दोनों हाथों से सहायता दे रहे हैं, अफगानिस्तान को भी हमने सहायता दी थी और बांग्लादेश को आज भी सहायता दे रहे हैं। क्या बांग्लादेश से भी हिन्दू भागकर आएगा?

आपने अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा की है। ढाका शहर में ढाकेश्वरी मंदिर है। अगर सारा हिन्दू वहां से भागकर आएगा तो वहां उस मंदिर का घण्टा कौन बजाएगा और ढाकेश्वरी मंदिर में दीप कौन जलाएगा? हमें बांग्लादेश सरकार को कम्पेल करना चाहिए। वहां पर जो नॉन-मुस्लिम माइनोरिटी है, उन सब को सिक्योरिटी मिले, इसके लिए हमें बांग्लादेश की सरकार को कम्पेल करना चाहिए। वहां के हिन्दू को यहां लाकर नागरिकता देना, यह बुद्धि का काम नहीं है।

सभापति महोदय, इस नागरिकता कानून के साथ-साथ सरकार ने बोला है कि नॉर्थ ईस्ट में शांति आई है। 29 दिसंबर को उग्रवादी संगठन के कुछ लोगों के साथ सरकार ने समझौता किया, यह अच्छी बात है। उग्रवादी संगठन को मेन स्ट्रीम में लाना होगा, लेकिन किसको लाया गया? जो अरविंद राजखोवा और अनूप चेतिया हैं, जब पीवी नरसिंह राव जी प्रधान मंत्री थे और असम में हितेश्वर साइकिया जी मुख्य मंत्री थे, तब भी अरविंद राजखोवा और अनूप चेतिया डिस्कशन की टेबल पर आया था। उस समय के मुख्य मंत्री साइकिया जी ने इन लोगों को सोने की कलम दी थी। जब तक परेश बरुआ डिस्कशन टेबल पर नहीं आएगा, जिसके हाथ में बंदूक है, वह डिस्कशन की टेबल पर नहीं आएगा, तब तक यह समझौता कितना फ्रूटफुल होगा, यह कहना मुश्किल है। हमें समझौते के नाम पर अशांति नहीं फैलानी चाहिए।

सभापति महोदय, भाजपा राष्ट्रवाद की बात कहती है। ऐसा राष्ट्रवाद होना चाहिए, जिस राष्ट्रवाद से राष्ट्र मजबूत होगा। यह जो समझौता हुआ, उस समझौते में कहा गया कि हमारे जो चर एरियाज़ हैं, जो रिवर आइलैंड हैं, जब वहां नया चर निकलेगा, वह नया चर ऑटोमैटिकली गवर्नमेंट का खास लेन बन जाएगा, जो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वहां जो रिवर इरोजन की प्रॉब्लम है, जो कटौती की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से हमारे आर्थिक मुद्दे खराब हो रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, आर्थिक, सामाजिक और पॉलिटिकल समस्या हो रही है, लेकिन रिवर इरोजन कंट्रोल करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं।

(1955/MM/SM)

अब अगर नया चर निकलेगा तो जिसका जमीन पर अधिकार है, वह अधिकार नहीं रहेगा, यह बिल्कुल ठीक नहीं है।

असम में जो डिलिमिटेशन हुआ, वह संविधान की स्प्रिट पर नहीं हुआ। संविधान कहता है कि पॉप्युलेशन का ईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लेकिन ईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। भाजपा की राजनीति के लिए चुनाव आयोग ने वहां ऐसा-ऐसा किया, जिसका जियोग्राफिकल इंटिग्रेट नहीं है। अगर इंटिग्रेट है भी तो रोड कनेक्टिविटी नहीं है, रिवर से कनेक्टिड है।

भाजपा का एजेंडा, हमारे मुख्यमंत्री का एजेंडा जरूर पूरा हुआ, लेकिन लोगों का हित नहीं हुआ। इस समझौते में कहा गया कि आगे का डिलिमिटेशन भी ऐसा होगा, जो बिलकुल ठीक नहीं होगा। क्योंकि यह डिलिमिटेशन एज़ पर लॉ नहीं हुआ, यह डिलिमिटेशन एज़ पर संविधान नहीं हुआ, इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। सभापति महोदय, सिर्फ यही नहीं, असम में जो एनआरसी सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हुई। उस एनआरसी की लिस्ट में 19 लाख लोगों का नाम नहीं आया। उसके लिए आगे मैकेनिज्म नहीं बनाया गया है। अब सरकार बोल रही है कि इसका रिव्यू करेगी। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में यह हुआ था। उसके ऊपर अमित शाह जी ने सदन में भी कहा था कि एनआरसी अच्छा है और बाहर भी कहा था, लेकिन आज रिव्यू की बात बोल रहे हैं। सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार सोचती थी कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों का नाम ड्रॉप होगा, लेकिन वह नहीं हुआ और अब वह रिव्यू के बारे में कहते हैं। यह बिलकुल सही नहीं है।

सभापति महोदय, असम समझौते के क्लॉज़ नंबर 6 के लिए होम मिनिस्टरी ने एक कमेटी जस्टिस बिप्लब कुमार सरमा की लीडरशिप में बनायी थी। उस कमेटी ने एक रिपोर्ट बनायी थी, जिसे अमित शाह जी ने स्वीकार नहीं किया। होम मिनिस्टरी के किसी भी ऑफिसर ने रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। तब के मुख्यमंत्री ने लिया था, अब उस रिपोर्ट का क्या हाल है, यह किसी को नहीं पता। हमारे यहां कोच-राजबोंगशी नाम से एक कम्प्यूनिटी है, जिसको पश्चिम बंगाल में एसटी का दर्जा मिला हुआ है। मेघालय में कोच कम्प्यूनिटी को एसटी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन असम में वह ओबीसी है। उस कम्प्यूनिटी को कब एसटी का दर्जा मिलेगा?

हमारे यहां जो चाय बागान के लोग हैं। हमारे अर्जुन मुंडा जी ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, लेकिन वहां जो लोग मुंडा लिखते हैं, उनको एसटी का दर्जा नहीं मिलता है। इन लोगों को कब एसटी का दर्जा मिलेगा, इसका उल्लेख राष्ट्रपति जी के भाषण में नहीं है। हमारे वहां की दो कम्प्यूनिटीज़ गोरिया मुसलमान और देसी मुसलमान भी एसटी का दर्जा देने की डिमांड कर रहे हैं। इनको एसटी का दर्जा मिलेगा या नहीं, इसका भी उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है। सरकार ने चर्चा की और कुछ नये

एयरपोर्ट्स बनाए। यह अच्छी बात है। नये एयरपोर्ट्स होने चाहिए, लेकिन धुबरी-रूपसी में एक एयरपोर्ट बना। कुछ दिन तक वहां फ्लाइट्स गयी भी थीं, लेकिन अब यह बंद हो गया है। अगर आप एयरपोर्ट बनाते हैं और वहां से विमान नहीं चलते हैं तो फिर एयरपोर्ट बनाने का क्या फायदा है? सरकार को ऐसा करना चाहिए ताकि वहां से ज्यादा से ज्यादा विमान चले।

जम्मू-कश्मीर, आर्टिकल 370 – एक देश, एक कानून की बात करते हैं। लेकिन असम में उल्फा के साथ जो समझौता हुआ, उसमें कहा गया कि एक विधान सभा क्षेत्र के लोग दूसरे विधान सभा क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। जबकि जम्मू-कश्मीर में बाहर के लोगों को जमीन खरीदने का अधिकार दिया जा रहा है, लेकिन असम में आप कह रहे हैं कि एक विधान सभा क्षेत्र के लोग दूसरे विधान सभा क्षेत्र के इलेक्ट्रॉल रोल में नाम नहीं लिखवा सकते हैं। यह कैसा कानून होगा? कानून तो अभी तक नहीं बना है, लेकिन यह कैसी नीति होगी? यह नीति आपके मत के खिलाफ है। उस समझौते में यह भी कहा गया कि दो कांस्टिट्यूएन्सी में एक वोटर का नाम नहीं हो सकता है। यह कोई नयी बात नहीं है, यह लोकप्रतिनिधित्व आर्इन में भी नहीं है।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र यह सरकार बहुत करती है। सरदार जी ने क्या कहा था? जब मणिपुर जल रहा था तब प्रधानमंत्री को वहां जाने का टाइम नहीं मिला। मणिपुर के लिए एक मैसेज दिया और वह तीस मिनट का ही था, उससे ज्यादा का नहीं था। मणिपुर में अमन और शांति कायम हो, इसके लिए मैसेज नहीं दिया। मणिपुर वाली हालत पश्चिम बंगाल में होती, कर्नाटक में होती या किसी भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट में होती तो अभी तक राष्ट्रपति शासन लग गया होता, लेकिन मणिपुर में सरकार अभी भी बरकरार है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था – “Manpower without unity is not a strength unless it harmonised and united properly.”

इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

(इति)

(2000/YSH/RP)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): आज कुछ और माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं। यदि सभा की सहमति हो तो एक घंटे का समय और बढ़ा दिया जाए? क्या सदन की स्वीकृति है?

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ।

माननीय सभापति: धन्यवाद।

डॉ. डीएनवी सेंथिलकुमार जी।

2000 hours

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): *Vanakkam*, Sir, and thank you for giving me an opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President's Address.

We wholeheartedly welcome, Madam, President to the New Parliament Building to step in for the first time to deliver the President's Address. The Government's claim of witnessing the eradication of poverty on a massive scale is a distortion of reality that cannot be ignored. The boastful narrative conveniently sidesteps the grim fact that over 75 million Indians have plunged back into poverty, including a staggering one-third of India's 100 million strong middle class, erasing half a decade of hard-earned gains, according to estimates by Pew Research.

Sir, it is ironic that the Government chooses to rely on NITI Aayog's data, but let me shed light on how the Government is dismantling Indian federalism. The CEO of NITI Aayog revealed that the Fourteenth Finance Commission had recommended a 42 per cent share of Central Taxes for the States, but the Government wanted to keep it down to 33 per cent. This attitude is not good for Indian democracy.

Sir, the Government's narrative, resembling more of an election speech than a Presidential Address, paints a picture of a miraculous transformation since 2014.

The rushed implementation of the Goods and Services Tax (GST) dealt severe blows to businesses across the country. Far from the glowing picture, the Government portrays, unemployment soared to a 45-year high, reaching 6.1 per cent in 2017-18, according to the last official count. Instead of an era of unbridled progress, the past years have witnessed economic set-backs, policy missteps, and hardships for ordinary citizens. It is time to see through carefully crafted rhetoric and confront the harsh truth of the economic challenges faced by our nation. While the Presidential Speech claims credit for the Prime Minister Narendra's Government for introducing a 27 per cent reservation for OBCs in medical courses, the reality is different. This change only came after a Supreme Court Judgement, thanks to the relentless efforts of our leader, Chief Minister, M. K. Stalin. The DMK, under his leadership, filed the first PIL on this matter. The Government's commitment to social justice appears hollow in light

of these facts. It is crucial to recognize the genuine efforts of leaders like M. K. Stalin in championing the cause for OBC rights.

There is an erosion of India's parliamentary democracy under this Government. Over the past 10 years, India's vibrant democracy has faced significant challenges revealing an erosion of parliamentary values under the leadership of the Prime Minister's Government. Firstly, the trend of rushing Bills without adequate debate is alarming. The passing of contentious farm laws without a proper 'division' vote illustrates the adverse consequences of hasty decision-making, as evidenced by the prolonged farmer protests that lasted for 333 days and caused 600 deaths. This approach, coupled with a lack of thorough discussion and review in Parliamentary Committees, raises concerns about the impact on public life. According to analysis, while 71 per cent of the Bills were referred to Standing Committees during 2009-2014, only 16 per cent have been referred since 2019.

Sir, the Prime Minister's silence on the Manipur ethnic conflict is another notable omission, reflecting a lack of proactive engagement in resolving critical issues. The 17th Lok Sabha's historic low number of sittings, only 230 days so far, diminishes the time available for discussions and scrutiny of Bills. This challenges the very essence of parliamentary democracy. This Government is doing this purposely, restricting the time period of Sessions and rushing the Bills, where the autocratic BJP government had passed as many as 14 Bills in three days after suspending 146 MPs from both the Houses.

The absence of a Deputy-Speaker in the Lok Sabha for four years violates Constitutional norms, a position conventionally reserved for an Opposition Member.

(2005/RAJ/NKL)

This shows how the Government is violating the Constitution and strangulating the voice of the Opposition.

Even with a brute majority, Government's over-reliance on Ordinances, passing 76 through this route since 2014 and freezing of MPLADS funds amid the pandemic raise questions about adherence to parliamentary protocol and equitable distribution of resources for development. The reduced engagement of Prime Minister in parliamentary proceedings indicates a concerning trend, moving away from substantive leadership to mere presence.

Sir, the communal encroachment into parliamentary proceedings challenges the foundational principle of secularism, jeopardizing India's diverse and inclusive character.

The rushed nature of public notice, inviting suggestions on a proposed policy until 15th January violates the Pre-Legislative Consultation Policy, 2014 which prescribes a minimum of 30-days period for public input. This hurried approach undermines the principles of democratic governance.

Sir, as regards the Enforcement Directorate raids, through you, I would like to ask this Government to publish proper statistics as to members of which political party and of which State has the Enforcement Directorate raided. Once it comes into public domain, people would be aware of the work of the Government.

Sir, I will end my speech by paraphrasing a few sentences from Nehru's famous 'Tryst with Destiny' speech. It is called tryst with tyranny. Long years ago, we made a tryst with democracy, and now, the time looms when we must reckon with the spectre of tyranny. At the brink of a potential dark hour, if India elects the current regime in 2024, the dawn of oppression may cast shadows on the ideals we once held dear. As the world sleeps, India may awaken not to life and freedom but to a reality where the soul of the nation, once liberated, now finds itself shackled.

The ambition of those who fought for freedom may be overshadowed by the aspirations of a regime with autocratic tendencies. Wiping tears from every eye might transform into stifling dissent and curtailing individual liberties. As an age ends, the echoes of suppression may drown out the voice of democracy. Our labour and toil may no longer be directed towards the progress of a free nation, but instead, it could be employed to fortify the walls of authoritarian rule. The dreams we once held for India may be eclipsed by the harsh realities of a world witnessing the erosion of democratic values.

Thank you.

(ends)

2008 बजे

श्री संजय सेठ (राँची): जय जोहार, सभापति महोदय।

अभिभाषण में महामहिम द्रौपदी मुर्मू के उद्बोधन से देश में हो रहा है गुणगान
जनजातीय समाज की इस बेटी पर हम सब को है अभिमान
मोदी जैसे देवदूत ने दिखाई विकास की राह
उन्होंने किया है, अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह
मोदी की गारंटी ने बढ़ाया देश का मान
आज भारत का दुनिया में हो रहा है यशोगान
ऐसी है हमारी भारत भूमि, ऐसी है हमारी भारती भूमि।

हमें ये पंक्तियां राँची की एक बेटी पुष्पा सहाय ने अभी थोड़ी देर पहले भेजी है। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण के उपरांत धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया गया है, इसके लिए मैं आदरणीय अध्यक्ष जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। संसद के सभी साथियों को जोहार करता हूँ। यह हमारा सौभाग्य रहा कि आजादी के अमृतकाल में इस नई संसद और आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया वाले संसद भवन में हम सभी को जिनका उद्बोधन मिला, वे भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू-कान्हू और नीलांबर-पीतांबर जैसे वीर जनजातीय समुदाय, मनीषियों के समाज से आती हैं। निश्चित रूप से यह हम सभी के लिए गौरव की बात है कि महामहिम के रूप में जनजातीय समाज से आई हमारी अभिभावक का उद्बोधन हमें सुनने को मिला है। हम सभी को यह अवसर माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा प्रदान किया गया है। मैं प्रधान मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राज्यपाल रहीं। एक सौम्य, उदार, बड़ी बहन जैसा व्यवहार और साढ़े तीन करोड़ झारखंडवासियों के लिए यह सम्मान रहा। देश की आजादी के 70-72 सालों बाद जनजातीय समाज की एक महिला, जो ओड़िशा में एक शिक्षक होती थीं, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने उनको झारखंड का राज्यपाल बनाया। वह झारखंड की अभिभावक थीं। अब वह 140 करोड़ देशवासियों की प्रमुख और हम सब की आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं।

(2010/KN/VR)

आज हम सबसे पहले प्रधान मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं। हमारे दिलो-दिमाग में जो जीवंत हैं, जीवित हैं, गरीबों के मसीहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया, आज पूरा देश कृतज्ञता प्रकट करता है। ऐसे मसीहा, पिछड़ों के नायक, ऐसे अंत्योदय के नायक को भारत रत्न दिया गया। इसके लिए हम धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहेंगे। हम सब के अभिभावक, झारखंड के मसीहा करिया मुंडा, जिनको सम्मान देने का काम प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया, हम उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों ही हमारी दो बेटियों को पूर्णिमा महतो और चामी मुर्मू को पद्मश्री दिया गया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सिमोन उरांव राँची के बगल से आते हैं और उनको कोई जानता नहीं था। प्रधान मंत्री जी की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने पहाड़ काट कर सिंचाई के लिए नहर बनाई। ऐसे सिमोन उरांव को पद्मश्री दिया गया। छुटनी देवी ने डायन प्रथा के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाया और वह खुद डायन प्रथा से पीड़ित रही। ऐसी छुटनी देवी को भी पद्मश्री से नवाजा गया।

हमारे यहां एक कहावत है- 'जे नाची से बाची' मतलब जो नाचेगा वही बचेगा। रामदयाल मुंडा जी के ये शब्द थे। आज झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पूरे देश के आदिवासी भाई हमें सिखाते हैं कि मस्त रहो, प्रसन्न रहो। मुकुंद नायक, जो जनजाति से हैं, मधु मंसूरी गायक है, अशोक भगत जी का बड़ा नाम है, जिन्होंने गांव, गरीब, किसान के लिए इतना बड़ा काम किया। बलबीर दत्त आदि लोगों को पद्मश्री से नवाजा गया। हम आदरणीय प्रधान मंत्री जी का अभिनंदन, अभिवादन करते हैं।

सभापति महोदय, मोदी जी भारत के पहले प्रधान मंत्री हैं, जो 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी के गांव उलहातू गए। आज तक वहां कोई भी प्रधान मंत्री नहीं गये। यह आदिवासियों के प्रति प्रेम, देश के प्रति कृतज्ञता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर सिर्फ ट्राइबल नहीं, आदिवासी भाइयों ने नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों ने एक साथ भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई। यह प्रधान मंत्री जी की सोच है। जिन्होंने भारत की संस्कृति के लिए अपना बलिदान दिया, ऐसे साहिबजादों की याद में वीर बाल दिवस मनाया गया। यह प्रधान मंत्री जी की सोच है।

चिदम्बरम जी चले गए, वह कुछ कह रहे थे कि राम मंदिर तो बनाया, लेकिन एम्स नहीं बना, मेडिकल कॉलेज नहीं बना। मैं उनको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2014 तक देश में 7 एम्स और 390 से कम मेडिकल कॉलेज थे। दस वर्षों में 16 एम्स और 315 मेडिकल कॉलेज से ज्यादा स्थापित किए गए। 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए गए, एमबीबीएस की सीट्स को दुगुना किया गया। चिदम्बरम जी को जरा ज्ञान होना चाहिए।

अभी सुप्रिया दीदी बोल रही थी कि जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है, यह तो फ्लॉप योजना है। मैं आपके माध्यम से उनको जानकारी देना चाहता हूं कि वह रांची के जिला प्रशासन के पोर्टल पर चली जाएं और देख लें कि मेरे सांसद आदर्श ग्राम योजना की कितनी उपलब्धि हुई है? सांसद आदर्श ग्राम योजना में 723 योजनाएं थीं, जिनमें 445 योजनाएं पूर्ण हो गईं, 145 प्रगति पर हैं और 133 शुरू होने जा रही हैं। यह 61.54 प्रतिशत की उपलब्धि है। बोलने को तो बोल सकते हैं, लेकिन आपको आगे आना होगा। सांसद को आगे आना होगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना में आपको मेहनत करनी होगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि यह मोदी जी की गारंटी है, रांची में रातु एक बहुत बड़ा इलाका है, जो एक विधान सभा के रूप में है और लाखों लोग वहां रहते हैं। वहां लोग आवागमन से परेशान थे और जाम से परेशान थे। मैं प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और गडकरी जी को सैल्यूट करूंगा, जिन्होंने 550 करोड़ की लागत से झारखंड का पहला एलिवेटेड ब्रिज दिया। वह कम्पलीशन के स्तर पर है और तीन-चार महीने में वह कम्पलीट हो जाएगा।

(2015/VB/SAN)

झारखंड में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बना है। झारखंड को बने हुए 23 वर्ष हो गए। हमारे यहाँ कोई प्लांट नहीं था। हमारे यहाँ कूड़े का पहाड़ पड़ा रहता था। लाखों लोग कैसर और अस्थमा से पीड़ित होते थे। एक साल पहले, मैं आदरणीय हरदीप पुरी जी के पास गया और उन्हें बताया कि राँची राजधानी है। हमारे यहाँ कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट नहीं है। उन्होंने तुरंत 50 करोड़ रुपए की लागत से, गेल इंडिया के स्वच्छता मिशन से, तीन सौ मीट्रिक टन का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट दिया, जिसमें डेढ़ सौ मीट्रिक टन का प्लांट तैयार हो गया है। अगले हफ्ते हम उसका उद्घाटन कर देंगे। उस प्लांट में 5 हजार जीजीई सीएनजी गैस और 8 टन खाद बनेगी। यह है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी।

मैं एमएसएमई मिनिस्ट्री को धन्यवाद देना चाहूंगा। राँची में टुपुदाना एक इंडस्ट्रीयल सिटी है। वहाँ बहुत सारे उद्योग हैं। उनसे निकलने वाला जहरीला पानी खेतों में जाता था, उनका जहरीला पानी नालों में बहता था। वहाँ 35 करोड़ रुपए की लागत से सीपीटी प्लांट बनकर तैयार हो गया है। उसमें रोज़ाना 35 लाख लीटर पानी, जो उद्योगों से निकलेगा, वह स्वच्छ होकर पीने लायक बनेगा। यह है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी।

राँची में एक बहुत बड़ा तालाब है, उसका नाम है- विवेकानन्द सरोवर। वहाँ पर स्वामी विवेकानन्द जी की प्रतिमा लगी है। जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी ने उसे बनाया था। उस तालाब में ही शहर का गंदा पानी, अस्पतालों का गंदा पानी जाता था। वहाँ पर आठ करोड़ रुपए की लागत से एसटीपी प्लांट तैयार हो गया है और अगले हफ्ते हम उसका भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। राँची के नाले का पानी, सेवा सदन के नाले का पानी, जो विवेकानन्द सरोवर में जाएगा, जहाँ हजारों-लाखों की संख्या में छठ व्रत करने वाली हमारी दीदियाँ वहाँ अर्घ्य देती हैं, उनके लिए भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा उपहार है।

राँची से बोकारो के लिए एक्सप्रेस हाइवे बनाया गया। गडकरी जी ने आज से साल भर पहले हमसे पूछा था। उन्होंने कहा था कि संजय जी आप बताओ, धनबाद जाने में कितना समय लगता है? हमने कहा कि साढ़े चार-पाँच घंटे लग जाते हैं। उन्होंने कहा बोकारो जाने में कितना समय लगता है? मैंने कहा, दो-ढाई घंटे लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम पौने घंटे में पहुंचा दें तो। मैंने कहा कि गडकरी जी, आपने शेरशाह सूरी के नाम को बौना कर दिया है। आज वह धरातल पर उतर गया है। उस पर काम चल रहा है। अब हम लोग राँची से बोकारो दो-ढाई घंटे में नहीं पहुंचेंगे, बल्कि सिर्फ 40 से 45 मिनट में पहुंचेंगे। ये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी।

पिछले 60 साल में हमारे यहाँ रेलवे में जितना नहीं दिया गया, अश्विनी वैष्णव जी के एक साल के कार्यकाल में ही हमारे यहाँ दो हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स दिए गये। 450 करोड़ रुपए की लागत से राँची रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो रहा है। यह वर्ष 2025 तक तैयार हो जाएगा। 388 करोड़ रुपए की लागत से हटिया स्टेशन बन रहा है। पिस्का स्टेशन, जहाँ कुछ नहीं था, अब यह स्टेशन 90 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। वहाँ दो-दो नये प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं, नई रेल लाइंस बन गई हैं। अब अगले साल से वहाँ राजधानी एक्सप्रेस भी रुकनी शुरू होगी। 60 करोड़ रुपए की लागत से नामकुम स्टेशन, 80 करोड़ रुपए की लागत से टाटीसिलवई स्टेशन, 90 करोड़ रुपए की लागत से चांडिल स्टेशन बनाये जा रहे हैं। चुटिया एक बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ केताड़ी बगान में तीन-तीन गेट्स पड़ते हैं। वहाँ पर हजारों लोग जाम में फंसते हैं। हमने एक बार आग्रह किया, अभी अश्विनी वैष्णव जी राँची गये थे, उन्होंने कहा 45 दिनों के अन्दर रिपोर्ट दो और क्षेत्र की जनता जैसा चाहती है, वैसा ही फ्लाइओवर बनाओ। अब वह धरातल पर उतर गया है। यह है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का सपना और उस सपने का जमीन पर उतरना... (व्यवधान)

राँची से पटना, राँची से हावड़ा तक वंदे भारत ट्रेन्स दी गईं और अब राँची से बनारस वंदे भारत ट्रेन दी जा रही है। यह है प्रधानमंत्री जी का सपना।

बिरसा मुंडा एयरपोर्ट मिला। अभी चार दिन पहले बैठक हुई थी, हमने उस पर सिग्नेचर किया। एक सौ करोड़ रुपए की लागत से वहाँ विश्वस्तरीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी।

पिछले चार सालों में झारखंड को 55 हजार ट्रांसफॉर्मर मिले। झारखंड ऐसा प्रदेश है, जहाँ महीनों तक ट्रांसफॉर्मर नहीं लगता है। जब ट्रांसफॉर्मर लगता है, तो लोग कहते हैं, सांसद जी, आइए इसका उद्घाटन कर दीजिए, विधायक जी, आइए उद्घाटन कर दीजिए। झारखंड देश का पहला प्रदेश होगा, जहाँ ट्रांसफॉर्मर का उद्घाटन होता है। यह एक अजूबा प्रदेश है। फिर भी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 55 हजार ट्रांसफॉर्मर मिले। हर गांव के लिए दो-दो सौ बिजली के खम्भे मिले। सारे गांव का विद्युतीकरण हो गया।

(2020/PC/SNT)

चांडिल डैम और गेतलसूद डैम में फ्लोटिंग सोलर, चांडिल और सौंदा बस्ती में बड़ा अंडरपास, अमृत स्टेशन, जनजातीय संग्रहालय, जहां भगवान बिरसा मुंडा जेल में रहे। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जनजातीय संग्रहालय दिया और रांची का यह सौभाग्य रहा कि 600 किलोमीटर पीएमजेएसवाई की सड़क मिली। चाहे प्रधान मंत्री आवास योजना हो, लाइटहाउस हो, डीएमएफटी का फंड हो, इससे क्षेत्र का विकास हो रहा है। यह प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आशीर्वाद है।

एक तरफ प्रधान मंत्री जी दस लाख सरकारी नौकरियां दे रहे हैं और दूसरी तरफ झारखंड के अंदर क्या हो रहा है? झारखंड के अंदर अभी जेएसएससी की परीक्षा होनी थी। एक दिन पहले रात को उसका प्रश्न पत्र लीक हो गया। लोग बताते हैं, निशिकांत जी, आपको पता होगा। 25-25 लाख रुपए में वह प्रश्न पत्र बिका। 750 के आसपास परीक्षा केंद्र थे। हमारे जो युवा हैं, वे ट्रेन में थे, बसों में थे, ठंड में जा रहे थे, क्योंकि उन्हें परीक्षा देनी थी, लेकिन उस परीक्षा का पेपर लीक हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? झारखंड के मुख्य मंत्री जो अब जेल में हैं, किस आरोप में जेल में हैं? जमीन की लूट में, खनिजों की लूट में, उन्होंने झारखंड की जनता से वादा किया था कि हर साल पांच लाख नौकरियां देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं दावा करता हूँ कि इन चार सालों के अंदर पांच नौकरियां नहीं दीं और न ही बेरोजगारी भत्ता दिया। लेकिन देश के आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दस लाख सरकारी नौकरियां दीं।

सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि यह जो पेपर लीक हुआ है, उसके विरोध में छात्र आंदोलनरत हैं, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। इसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके बारे में हम सब बाद में बात करेंगे कि कैसे छात्रों के साथ हम न्याय कर सकें? गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी लिखते हैं। किसी का किडनी ट्रांसप्लांट होना है, किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट होना है, किसी को कैंसर है। कोई मरीज जब प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी लिखता है, तो 40 दिनों के अंदर अस्पताल को वह पैसा ट्रांसफर हो जाता है। यह प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सोच है कि गरीबों और मरीजों को उपचार के लिए पैसा दिया जाता है। आयुष्मान भारत, शौचालय, गैस कनेक्शन, जन धन खाता, प्रधान मंत्री आवास योजना, हर घर नल योजना आदि। जल जीवन मिशन के तहत दस हजार करोड़ रुपए चार साल पहले झारखंड की सरकार को दिए गए, लेकिन सिर्फ 3,300 करोड़ रुपए ही झारखंड की सरकार खर्च कर पाई, जो 33 प्रतिशत है। इस मन से कि जब वर्ष 2024 में हम वोट मांगने जाएंगे, तो पूछेंगे सांसद जी, कहां है पानी? इस सोच के साथ किया, लेकिन इनको पता नहीं झारखंड के ही नहीं, बल्कि पूरे देश के हृदय में प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी बसे हुए हैं।

पीएम किसान सम्मान, जन धन औषधि, गरीब कल्याण, स्वयं सहायता समूह, रेहड़ी-पटरी वाले, विश्वकर्मा योजना। अभी देवदूत के रूप में विश्वकर्मा योजना लाए हैं। कोई सुनार हो, कोई लोहार हो, कोई बढ़ई हो, आप कोई काम करते हों, गुड़िया बनाते हों, आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधान मंत्री श्री

नरेन्द्र मोदी जी ने एक लाख रुपए बिना किसी ठेपा के, बिना किसी कोलेट्रल के मिलेगा, वह भी पांच प्रतिशत ब्याज में, जिसके रीपेमेंट का समय 18 महीने का होगा। अगर रीपेमेंट ठीक हुआ, तो अगले वर्ष दो लाख रुपए मिलेंगे और उसके रीपेमेंट का समय 30 महीने का होगा। यह प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का सपना है कि समाज आत्मनिर्भर हो, परिवार आत्मनिर्भर हो और देश आत्मनिर्भर हो।

मैं प्रधान मंत्री जी के ड्रोन दीदी स्कीम के बारे में कहूंगा। एक ड्रोन की कीमत 12 लाख रुपए है, जिसमें 9 लाख रुपए भारत सरकार देगी और रेस्ट, वह जो समूह बनेगा, वह समूह देगा। हमने उज्ज्वला दीदी देखी, हमने जल सहिया देखा, अब ड्रोन दीदी है। ऐसी 15 हजार ड्रोन दीदीयां बनेंगी, जो किसानों को खेतों में यूरिया छिड़कने में मदद देगी, उनको आराम देगी, खेतों में ज्यादा पैसा खर्च न हो। यह प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सोच है। प्रधान मंत्री जी की सोच 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ' की है। यह उनकी गारंटी है। जितना देश की बेटियों के लिए उन्होंने काम किया है, चाहे शौचालय के रूप में हो, चाहे गैस चूल्हा, सिलेंडर के रूप में हो, चाहे आयुष्मान भारत के रूप में हो, प्रधान मंत्री जी ने देश की बेटियों को इतना दिया।

आज हम 70 हजार अमृत सरोवर, दो लाख से ज्यादा अमृत वाटिका के लिए कह सकते हैं। बोलने के लिए बहुत कुछ है, किंतु मैं अंत में यह कह सकता हूँ कि भगवान राम ने 500 साल इंतजार किया। कितना? पांच शताब्दी। किसलिए इंतजार किया? रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।

(2025/CS/AK)

भगवान राम ने इंतजार किया कि दुनिया के अंदर, इस सृष्टि में कोई तपस्वी पुरुष पैदा होगा, कोई ऐसा सच्चा पुरुष पैदा होगा, जिसके हाथों मैं अपने मंदिर का शिलान्यास और लोकार्पण कराऊंगा। देश और दुनिया ने प्रभु श्री राम मंदिर का लोकार्पण देखा। गाँव-गाँव, चाहे वह कोई भी इलाका हो, पूरा देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया उत्साहित थी। वह आनन्द मना रही थी। ऐसा दृश्य, लग रहा था कि प्रभु श्री राम 14 साल बाद वनवास काटकर अयोध्या लौट रहे हैं। ऐसा जश्र, ऐसी दीपावली पहली बार, देश ने दिन में राम नवमी मनायी, रात में दीपावली मनायी। मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ, 3.5 करोड़ झारखंडवासियों की ओर से मैं अभिनन्दन करना चाहता हूँ। मैं ऐसे देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। धन्यवाद।

(इति)

2026 बजे

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): महोदय, लोकतंत्र के इस नये मंदिर में आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा सदन में प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में दिया जाने वाला अभिभाषण सरकार के क्रियाकलाप, योजनाओं और लक्ष्य को रखकर दिया गया एक परिचयात्मक संबोधन होता है। इसी कड़ी में इस नये भवन में हमारी लोकतांत्रिक और संसदीय परम्परा के सम्मान का प्रण भी है। साथ ही 21वीं सदी के भारत के लिए नई परम्पराओं के निर्माण का संकल्प भी है। महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा अपने अभिभाषण में राष्ट्रहित में बनाई गई नीतियों पर सार्थक संवाद होने की बात कही गई है, जो आजादी के अमृत काल में विकसित भारत का निर्माण करेगी, लेकिन यह तभी सम्भव होगा जब इस लोकतंत्र में मन से संविधान में विश्वास रखने और संविधान को दिल से पूरे देश में जाति-पाति, धर्म, सम्प्रदाय, ऊँच-नीच, भेदभाव बिना लागू करना और उसके मुताबिक लोकतांत्रिक परम्पराओं का निर्वहन करना अनिवार्य किया जाना होगा।

महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि सरकार देश के संविधान को लागू होने के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में अमृतकाल और अनेक प्रकार के महोत्सव आयोजित कर अमृत महोत्सव का जश्न मना रही है। मैं इसका सम्मान करता हूँ, इसका स्वागत करता हूँ कि हमारे संविधान के प्रति आस्था और विश्वास बनाये रखने के लिए समय-समय पर देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में जो स्वतंत्रता सेनानी गुमनाम हैं, उनको याद किया जा रहा है।

महोदय, महामहिम राष्ट्रपति ने अमृत महोत्सव के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कर्तव्य पथ पर लगाए जाने की जानकारी दी है। साथ ही, साहिबजादों की याद में वीर बाल दिवस और भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया है। देश के विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया गया है। सरकार के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूँ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग रखना चाहता हूँ कि देश में बेजुबानों को आवाज, दलितों को सम्मान, पिछड़ों को अधिकार और आदिवासी तथा आर्थिक रूप से दबे-कुचले लोगों एवं अल्पसंख्यकों के हक और हुकूम की लड़ाई लड़ने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी के जन्मदिन को भी राष्ट्रीय स्तर पर दिवस घोषित किया जाता तो देश की एक बहुत बड़ी आबादी भी अपने राष्ट्रीय स्तर के महानायक को भी सम्मान मिलते हुए देखकर तन-मन-धन से उक्त दिवस पर इस अमृत काल के वर्षों में बढ़-चढ़कर भाग लेने तथा राष्ट्रहित में सेवा करने के लिए तत्पर होती।

महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि पिछले साल मेरी सरकार ने मिशन मोड में लाखों युवाओं को नौकरी दी है। मैं कहना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार सरकारी नौकरी पाने वालों की सूची न दे, लेकिन यदि आप केवल 50 हजार सरकारी नौकरियों के विज्ञापन को दिखा दें तो यह मान लिया जाएगा कि आपने लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, अन्यथा

यह भी एक चुनावी जुमला ही साबित होगा। आध्यात्मिक रूप से सदियों से प्रसिद्ध मेरठ में हस्तिनापुर का भी देश में विकसित हो रहे अन्य पर्यटन स्थलों की तर्ज पर विकास हो व बिजनौर में विदुर कुटी, जहाँ पर तमाम माननीय मंत्रीगण समय-समय पर जाते रहे हैं, उसका भी विकास हो।

(2030/IND/UB)

सभापति जी, इसके साथ ही अमानगढ़ और कालागढ़ जो पर्यटक स्थल हैं, मैं चाहता हूँ कि सरकार इन स्थानों को विकसित करके अच्छे पर्यटक स्थल का दर्जा दिलाना चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र में गुलदार की बहुत बड़ी समस्या है। गुलदारों ने तमाम मवेशियों को, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर सैकड़ों की तादाद में आक्रमण करके मारने का काम किया है। सरकार से मांग है कि वन क्षेत्र की तारबंदी की जाए और गुलदारों को पकड़ने के लिए बड़े-बड़े पिंजरे लगाए जाएं और साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाएं। पास के जो गांव वन क्षेत्र में आते हैं, वहां सरकार सोलर लाइट लगवाने की कृपा करे।

सभापति जी, मैं आपका ध्यान देश के विकास की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे साथी जो बिजनौर से सांसद हैं, मलूक नागर जी ने भी गन्ने के रेट के बारे में सरकार को अवगत कराने का काम किया है। गन्ने का रेट सात साल में मात्र तीन बार बढ़ा है। एक बार पच्चीस रुपये, फिर दस रुपये और इस बार भी दस रुपये बढ़ाने का काम किया है। यदि आप चाहते हैं कि किसान का हित हो, किसान की आमदनी दोगुनी हो तो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश में बनी थी। इससे पहले उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट 129 रुपये क्विंटल हुआ करता था लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने किसानों के दर्द को देखा और समझा कि यदि देश का किसान मजबूत होगा, तभी देश भी तरक्की करेगा। इसलिए बहन कुमारी मायावती ने 129 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ाकर 290 प्रति क्विंटल गन्ने का रेट कर दिया। इससे किसान मजबूत हुआ और जब किसान मजबूत होगा, तो निश्चित रूप से देश प्रगति की तरफ जाने का काम करेगा।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि किसान की आमदनी यदि आप दोगुनी करना चाहते हैं तो कृषि क्षेत्र में मशीनरी का रेट जो बढ़ा है, उसके हिसाब से किसान के गन्ने का रेट साढ़े पांच सौ रुपये प्रति क्विंटल करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा किसान मजबूत होगा।

महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।
श्रीमती लॉकेट चटर्जी।

2033 बजे

श्रीमती लॉकेट चटर्जी (हुगली): सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में बताया कि आज देश स्वर्णिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और हम सभी देशवासी इसके साक्षी हैं।

**“Abonatotbharotchahetomare,
esho Sudarshan Dhari murari
Nobinotantre, nobinomantre,
karo dikkhitotharot naro nari
Esho sudarshandharimurari”*

महोदय, हमारी संसदीय परम्परा में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सदैव महत्वपूर्ण रहा है लेकिन इस वर्ष महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हमारे लिए इस कारण भी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रहा है क्योंकि इस वर्ष आजादी के अमृत काल की शुरुआत में बनाए गए भारत के नए भव्य संसद भवन में राष्ट्रपति महोदय का यह पहला संबोधन था। उन्होंने खुशी जताई कि नई इमारत आजादी के अमृत काल के दौरान विकसित भारत के विकास को आकार देने वाली नीति को रचनात्मक संवाद की गवाह बनेगी। Atul Prasad ji had said:

**“Bharotabarjagotshabhaysreshthoasonolabe”*

महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अपने भाषण में बताया कि अमृत कलश अभियान के दौरान मेरी माटी, मेरा देश में पहले ही तीन करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने पंच प्रण की शपथ ली है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेता जी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा को कर्तव्य पथ पर इसी अमृत काल के उत्सव पर स्थापित किया गया। नेता जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।

**“Tomra amakeraktodao, amitomadershadhinatadebo’*

अमृत उत्सव के दौरान पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन जो, गुरु रबिन्द्र नाथ का प्राण है, जीवन है, पूरे बंगाली समाज की जान-प्राण है, वह वर्ल्ड हेरीटेज लिस्ट में शामिल किया गया। महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा आदिवासी वीर नायक बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का भी उल्लेख किया गया है।

(2035/RV/SRG)

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार गरीब के लिए समर्पित है। यह सरकार आज देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को फ्री में राशन देती है, लेकिन आज दुख की बात है कि पश्चिम बंगाल में इस राशन को लेकर भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। फेक राशन आई.डी. कार्ड्स बनाकर गरीब के अन्न की लूट होती है और बाहर उसकी कालाबाजारी होती है। अभी वहां के राशन मंत्री भी जेल में

* Original in Bengali.

हैं। आज प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 70 प्रतिशत आवास महिलाओं के नाम पर मिले हैं, लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल में प्रधान मंत्री आवास योजना को लेकर बहुत सारे घोटाले हुए। जिसका उस पर अधिकार है, उसे प्रधान मंत्री आवास योजना में घर नहीं मिलता है और जिसके पास तीन-चार मकान हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के पंचायत सदस्य हैं, नेता, मंत्री लोग हैं, उनके पास प्रधान मंत्री आवास योजना के तीन-चार घरों के पैसे जाते हैं। पश्चिम बंगाल में मनरेगा जैसी योजना के अन्दर 4,500 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। इसे राज्य सरकार ने अभी तक केन्द्र सरकार को नहीं दिया है, उलटा ये सभी लोगों को यहां लेकर आई और दिल्ली में आकर धरना दिया, नौटंकी की और बोलते हैं कि हमें केन्द्र सरकार पैसे नहीं देती है। जब तक हिसाब नहीं देंगे कि गरीबों का पैसा कहां दिया है, तब तक केन्द्र सरकार इन लोगों को पैसे नहीं देगी। ये गरीबों के पैसे की लूट करते हैं।

सभापति जी, जहां केन्द्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 12 करोड़ लोगों को शौचालय दिया है, वहीं बहुत दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि पश्चिम बंगाल में शौचालय को लेकर अभी तृणमूल सरकार 'कट मनी' लेती है।

सभापति जी, क्या आपने कभी यह देखा है कि ई.डी., सी.बी.आई. के अधिकारियों के ऊपर हमला हुआ हो? हमने पश्चिम बंगाल में यह देखा है। ई.डी., सी.बी.आई. के अधिकारी जब जांच करने के लिए जाते हैं तो हमने देखा है कि तृणमूल कांग्रेस के बहुत करीबी शेख शाहजहां के नेतृत्व में संदेशकाली में ई.डी. और सी.बी.आई. के लोगों के ऊपर हमले होते हैं। ई.डी., सी.बी.आई. के लोगों के सिर फाड़ दिए जाते हैं। ई.डी., सी.बी.आई. के लोग आज हॉस्पिटलाइज्ड हैं। शेख शाहजहां, जिसके नेतृत्व में यह हुआ है, वह अभी तक एक्सकॉन्डिंग है। अभी तक उसकी कोई खोज नहीं हुई है। तृणमूल कांग्रेस के सब लोग जानते हैं कि वह कहां पर है, पर पुलिस उसको खोज नहीं पा रही है।

*Sheikh Shajahan is under the protection of the Chief Minister; because politics of appeasement and 30 per cent vote politics are practiced in West Bengal.

महोदय, इसे सुनकर बहुत ताज्जुब लगेगा कि पश्चिम बंगाल सरकार की पूरी कैबिनेट अभी जेल में जा रही है। वहां के खाद्य मंत्री जेल में हैं, शिक्षा मंत्री जेल में हैं, शिक्षा का पूरा डिपार्टमेंट जेल में है। मुझे तो लगता है कि तृणमूल सरकार के कैबिनेट की बैठक अभी जेल में ही होगी। कल मुख्य मंत्री जी ने यह बोला कि अगर हमें जेल में भरेंगे तो हम जेल तोड़कर भाग जाएंगे। जेल कैसे तोड़ते हैं, अभी वे इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी हम सब लोग बोलते हैं और पश्चिम बंगाल की जनता बोलती है कि जो लोग जनता का पैसा लूटते हैं - *Catch the thieves and put them behind bars. लेकिन, मुख्य मंत्री अपनी सेना को, तृणमूल सरकार में जो लोग हैं, उनको सिखाती हैं कि जेल तोड़ो और जेल से भागो।

सभापति जी, पश्चिम बंगाल के टी.एम.सी. सांसद अभी सुबह में यह बोल रहे थे कि चन्द्रयान मिशन का क्रेडिट प्रधान मंत्री जी क्यों ले रहे हैं, साइंटिस्ट्स क्यों नहीं ले रहे हैं? हम 140

करोड़ जनता इसका क्रेडिट ले रहे हैं। चन्द्रयान का काम इस सरकार में हुआ। इस सरकार के इस काम का क्रेडिट 140 करोड़ जनता को मिल रहा है। इन्हें यह लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो भ्रष्टाचार होता है, उसका वे लाभ ले लें। पश्चिम बंगाल में जॉब्स की बात करते हुए वे कहते हैं कि पूरे देश में नौकरी नहीं दी गयी। हम हमारे क्षेत्र हुगली की बात करते हैं। हुगली में सिंगूर में टाटा ने नैनो कार प्रोजेक्ट लाया था। उन्होंने सिर्फ मुख्य मंत्री बनने के लिए किसानों के ऊपर बन्दूक रखकर टाटा के प्रोजेक्ट को हटाया और खेती को भी बंद कर दिया। अभी खेती भी नहीं है और इंडस्ट्री भी नहीं है। वह प्रोजेक्ट गुजरात में चला गया। गुजरात में बहुत सारे लोगों को उससे काम मिला, लेकिन पश्चिम बंगाल में कोई इंडस्ट्री नहीं है और कोई जॉब करने वाला नहीं है। इस केन्द्र सरकार ने पिछले दस वर्षों में 18.7 करोड़ लोगों को जॉब्स दिया है।

सभापति महोदय, हमारे यहां ग्रुप-बी, ग्रुप-सी, ग्रुप-डी के जॉब्स में भी नौकरी देने में भ्रष्टाचार होता है, पैसे लिए जाते हैं।

*People of West Bengal call them job thieves, sand thieves, stone thieves, cattle thieves and what not. West Bengal is expert in all kinds of theft and malpractices.

(2040/GG/RCP)

सभापति जी, सांसद जी सुबह बोल रहे थे कि पूरे देश में किसान आत्महत्या करते हैं। सभापति जी, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ किसानों को छह हजार रुपये की सम्मान निधि डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट के माध्यम से उसके अकाउंट में चली जाती है, इस बात का गुस्सा उनको है। क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, बीच में लूटने वाला कोई नहीं है, इसलिए उनको गुस्सा है और इसीलिए वे ऐसा बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में किसानों की फसल का कोई दाम नहीं मिलता है, इसलिए पश्चिम बंगाल में बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या की है। 1.75 लाख प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्र हमारी सरकार ने खोले हैं। 8 हजार किसान एफपीओ नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाए हैं। सभापति जी, किसानों पर और उनके विकास पर वे लोग बात करेंगे, जो फसलों के उत्पादन में से भी कट मनी लेते हैं। हमारे यहां एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें किसान मंडी में आया था और कट मनी के लिए पुलिस उसको धमकी दे रही थी।

सभापति जी, सांसद कह रहे थे कि इस सरकार में ट्रेन है, लेकिन ट्रेक नहीं है। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि 25,000 किलोमीटर ट्रेक हमारी सरकार द्वारा बिछाया गया है। अगर इस पर उनको विश्वास न हो तो वे स्वयं पैदल चल कर माप सकते हैं, ट्रेक मापो यात्रा कर सकते हैं।

सभापति जी, तीन दशक के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ, जिसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और नारी के लिए बजट में वित्त मंत्री जी ने महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। जैसे लखपति दीदी योजना का लक्ष्य, जो शुरूआत में दो करोड़ महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया था, उसे बढ़ा कर तीन करोड़ महिलाओं के लिए कर दिया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कृषि स्वयं सहायता समूह द्वारा निभाई गई भूमिका पर जोर दिया है, जिससे देश

भर में करोड़ों महिलाओं के जीवन पर प्रभाव पड़ा। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए नौ से 14 साल की बच्चियों को टीकाकरण किया गया है। साथ ही, आयुष्मान योजना का फायदा आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश की तीन करोड़ महिला किसानों के बैंक खातों में 54,000 करोड़ रुपये डाले गए हैं। सभापति जी, महिला सशक्तिकरण के लिए ये लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, अभी मणिपुर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन दो दिन पहले मालदा में दस साल की बच्ची के साथ जो हुआ है, उसके साथ अत्ययाचार कर के उसकी हत्या कर दी गई है। उस समय ममता बनर्जी मालदा में ही थीं, वे राजनीतिक समीकरण के लिए कांग्रेस के साथ क्या करेंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उस पर उनकी प्रायोरिटी थी, लेकिन उस बच्ची के लिए समय नहीं था। अभी उसकी डेड बॉडी पुलिस ने ढूंढी है। और ये बोल रहे थे कि मणिपुर में क्या हो रहा है। मालदा में एक वीडियो वायरल हुआ था, दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर के पुलिस के सामने घुमा रहे थे, लेकिन अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है।

Narendra Modi ji is considered a visionary and futuristic leader for several reasons. His emphasis on initiatives like Smart Cities, Digital India, Clean India reflects a forward-looking approach. Additionally, his focus on renewable energy, infrastructure development and efforts to strengthen India's global standing showcase a commitment to long-term progress and modernisation.

*Whenever a great soul comes, he brings with him opposition. Otherwise, there is no meaning of his arrival.

“हा रघुनंदन प्रान पिरीते। तुम्ह बिनु जिअत बहुत दिन बीते।।”

सर, 500 सालों की लड़ाई के बाद अयोध्या में रामलला आए हैं। उस पर मुख्य मंत्री जी बोलती हैं कि राम हैं, लेकिन सीता कहाँ हैं। अरे! रामलला अयोध्या में बाल रूप में आए हैं। सीता का भी मंदिर है। वे पश्चिम बंगाल में बोलती हैं कि नारी शक्ति को हम लोग सम्मान नहीं देते हैं। वहाँ पर सीता का भी मंदिर है, जानकी का भी मंदिर है, लेकिन रामलला बच्चे हैं, यह उनको समझ में नहीं आता है। सभापति जी, हम देशवासियों ने वे दिन देखे हैं, जब रामलला टेंट में थे और एक वर्ष में केवल सात वस्त्रों की अनुमति थी। परंतु आज हम सबके रामलला के तिलक भी रत्नों से जड़ित है। आज करोड़ों भारतीयों के आस्था के केंद्र, प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में आ चुके हैं। इसके लिए मैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके लोगों को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया है। प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि राम भारत हैं, राम भारत की आस्था, आधार, विचार, प्रतिष्ठा, महिमा, नेता और नीति हैं। राम शास्वत हैं। Rama is the ancient idol of the heroic ages, the embodiment of truth, of morality, the ideal son, the ideal husband, the ideal father, and, above all, the ideals all, the ideal king.

(2045/MY/PS)

पिछले 10 वर्षों में भारत ने अपने पूरे वैभव के साथ आर्थिक विकास और महिला सशक्तिकरण के मामले में आसमान छुआ है। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। मैं भारत को दुनिया का सबसे महान देश बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रयास के लिए उनका आभार व्यक्त करती हूं। इस अवसर पर मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी-

**“Shato beer, katonari, sarbochobharoto sheer, katodaan,
shato ban sarbosreshthobharot, prithibirboichitromoydesh,
bahu besheanekjudhho joy hashikannasheshe,
juktobharotmuktobharot, moder bharotmahan,
roibedesherjoygaan, pobitro moder Hindustan”*

(ends)

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Now, hon. Minister.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

48th Report

2046 hours

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND
MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, with your permission, I
beg to present the Forty-eighth Report of the Business Advisory Committee.

HON. CHAIRPERSON: Shri Jasbir Singh Gill ji. You have only four minutes to
speak.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव - जारी

2046 बजे

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): सर, धन्यवाद, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया।

सबसे पहले मैं पूरे देश को भव्य राम मंदिर के लिए बधाई देना चाहता हूँ। मैं यह भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि राम जी के दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे, जब तक आप सीता मइया जी, भगवान बाल्मिकी जी और लव-कुश जी के जन्मस्थान रामतीर्थ, अमृतसर नहीं जाएंगे। आपने अयोध्या में जितना वैभव मंदिर बनाया है, वैसा ही वैभव मंदिर हमारे रामतीर्थ में भी बना दीजिए, उसकी तरक्की करवा दीजिए। यह एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा।

सर, कल मैं जब राष्ट्रपति जी का भाषण सुन रहा था, उनका कहना था कि गरीब कल्याण देश का कल्याण है। मैं यही जानना चाहता हूँ कि आज इतनी महंगाई है, जो लोगों को मार रही है। आज किसान और मजदूर खुदकुशी पर उतर आए हैं। उनके ऊपर महंगाई का जो भार है, उसको कैसे उतारा जाएगा, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

सर, उन्होंने कहा कि *poor, women, and youth are the priority*. मगर आज हमारे यहां 8 परसेंट बेरोजगारी दर है। इसको कैसे दूर किया जाएगा? आज मैं देखता हूँ कि देश में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सेमी कंडक्टर कॉम्पलेक्स आ रहे हैं, आज बड़े-बड़े समिट हो रहे हैं, परंतु, जब मैं पंजाब की तरफ देखता हूँ तो मुझे वहां पर सूखा लगता है। देश के जो रिसोर्सेज हैं, देश का जो खजाना है, वह सभी देशवासियों का है। कृपया करके आप पंजाब की तरफ भी देखिए और वहां पर कुछ न कुछ जरूर दीजिए।

सर, रेलवे के 40 हजार कोचेज को आपने अपग्रेड करने की बात कही है। आज मैं देख रहा हूँ कि देश में बुलेट ट्रेन बन रहा है। यह अहमदाबाद से मुम्बई के लिए बन रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है, जब देश तरक्की करता है, परंतु हमारे पंजाब के दो छोटे-छोटे मिसिंग लिंक्स हैं। एक लिंक चंडीगढ़ से राजपुरा के लिए 18 किलोमीटर का है और दूसरा, पट्टी से फिरोजपुर के बीच में है। इसका सर्वे सहित सब कुछ हो चुका है। कृपया करके आप हमारा कल्याण करा दीजिए।

सर, अब मैं एविएशन सेक्टर के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आज हमारी एयरलाइन कंपनियाँ एक-एक हजार जहाजों की ऑर्डर दे रही हैं। हमारे यहां जेवर एयर पोर्ट बन रहा है। हमारे आईजीआई एयरपोर्ट पर टी-1, टी-2, टी-3 और टी-4 बन रहे हैं। दिल्ली का इतना विकास हो रहा है। परंतु, हमारे अमृतसर के साथ क्या बैर है? उसे दूर क्यों किया जा रहा है? हमारे यहां से तुर्कमेनिस्तान एयरलाइंस, उजबेकिस्तान एयरलाइंस कोविड से पहले चलती थीं। कृपया करके उन्हें चलाया जाए। कनाडा, अमेरिका और आस्ट्रेलिया के लिए हमें डायरेक्ट फ्लाइट्स दी जाएं।

सर, मैं पीएम साहब का विकसित भारत का विजन देखता हूँ। यह कितनी बड़ी बात है। आज मिडिल एशिया में इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ हमारा 10 हजार करोड़ रुपये का व्यापार होता है।

(2050/CP/SMN)

यह आज देश के बंदरगाहों से हो रहा है। आप या तो वहां से भी बंद कर दीजिए, नहीं तो वाघा और खालड़ा बार्डर खोलिए। वहां से व्यापार करेंगे, तो हमारी इकोनामी को थोड़ा फिलप मिलेगा।

आपने स्प्रिचुअल टूरिज्म की बहुत बड़ी बात कही। मेरे को भी खुशी हुई। दुनिया में दस स्थान जहां सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, अमृतसर गोल्डन टेम्पल है, वहीं पर दुर्गयाना मंदिर है, वहीं पर माता सीता जी, लव-कुश, वाल्मीकि जी का रामतीरथ है। कृपा करके उस शहर की तरक्की के लिए इसे दीजिए। हमें वहां थीम पार्क की बहुत जरूरत है।

सर, आपने बहुत से मेडिकल कॉलेजेज़ खोले हैं। मैंने भी बहुत खुशी के साथ लड्डू बांटे थे, जब मेरे क्षेत्र कपूरथला में प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेडिकल कॉलेज का ऐलान किया था। सर, उस पर काम शुरू करवा दीजिए। हमने जमीन दे दी है।

सर, मौलाना आजाद फैलोशिप माइनोरिटी स्टूडेंट्स को दी जाती थी। इसे वर्ष 2023 में बंद कर दिया गया। मगर उसमें यह कहा गया कि जो स्टूडेंट्स इसमें पहले से हैं, जब तक उनकी फैलोशिप कंप्लीट नहीं होती, उनको इसमें कंटीन्यू किया जाएगा। 6 महीने से उनकी फैलोशिप नहीं आ रही है। यूजीसी, जेआरएफ के साथ कनेक्ट करके आप इसका ऐलान कीजिए। जो दूसरी मेजोरिटी कम्युनिटी है, उनके लोगों को भी इसमें शामिल कीजिए। यह सभी को दीजिए।

सर, मिलेट हमारे प्रधान मंत्री जी का बहुत फेवरेट है। उन्होंने इस पर बहुत काम किया है। उन्होंने 2023 को मिलेट्स ईयर भी डिक्लेयर किया। पंजाब में इसे सबसे ज्यादा उगाया जा सकता है। 11 लाख हेक्टेअर पंजाब की कैपेसिटी है। यहां मार्केटिंग, एमएसपी और टेक्नोलॉजी दीजिए। जैसे हमने धान और कनक के गोदाम भरे हैं, हम मिलेट्स के भी गोदाम भरेंगे।

धन्यवाद, जय हिंद, जय पंजाब।

(इति)

2053 बजे

डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा (रोहतक): महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के अभिभाषण एवं धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और समर्थन व्यक्त करता हूँ। आजादी के अमृत काल में 25 साल का यह अमृत काल माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के आह्वान पर विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जिस तरह से माननीय राष्ट्रपति महोदया ने इस सम्पूर्ण वक्तव्य में इस दशक के लिए सबको दिशा देने वाला और देश के कोटि-कोटि जनों में वर्तमान सरकार की गरीब जन-कल्याण योजनाओं में विश्वास पैदा करने वाला यह अभिभाषण है।

सभापति जी, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे परम पूज्यनीय दादा जी एक बात कहते थे कि किसान का ध्यान किसान रख सकता है, व्यापारी का ध्यान व्यापारी रख सकता है, लेकिन गरीब की सेवा वही कर सकता है, जिसने गरीबी देखी हो। वही गरीब की सेवा कर सकता है और वह हैं हमारे माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी।

वर्ष 2014 से पहले जो व्यवस्थायें थीं, गरीबों के लिए, किसानों, मजदूरों के लिए, वे व्यवस्थायें चरमरा गई थीं। उन व्यवस्थाओं में सुधार करके माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने इस देश को एक नई दिशा दी है। देश के पूर्व प्रधान मंत्री यह कहते थे कि मैं अगर एक रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे गरीब आदमी तक पहुंचते हैं। उस बात में बदलाव हुआ है। आज अगर सौ रुपये भेजे जाते हैं, तो वह पैसा यूं का यूं ही गरीब के खाते में, किसान के खाते में पहुंचता है, महिलाओं के खाते में वह पैसा पहुंचता है, दलितों के खाते में वह पैसा पहुंचता है, बैकवर्ड भाइयों के खाते में वह पैसा पहुंचता है। इतनी बड़ी व्यवस्था का सुधार माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है।

एक और कांसेप्ट चला है, डबल इंजन की सरकार। लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ है, किसानों में, खेतिहर मजदूरों में, गरीबों में, दलितों में, बैकवर्ड भाइयों में, नौजवानों में, कर्मचारी-व्यापारी, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी और हमारे सैनिकों में, शहीदों के परिवारों में, महिलाओं में, बुजुर्गों में, हर कैटेगरी में डबल इंजन की सरकार पर एक विश्वास पैदा हुआ है।

(2055/NK/SM)

जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां गरीबों के जनकल्याण के लिए बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। जैसे, प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान योजना है, आयुष्मान योजना में पांच लाख रुपये की गारंटी है। इसमें हरियाणा सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चिरायु योजना दी है, उसमें पांच लाख रुपये तक बेनिफिट दिया है, जिस आदमी की आमदनी तीन लाख रुपये है, वह साल का मात्र पन्द्रह सौ रुपये देकर इस योजना का लाभ ले सकता है। यह कितना बड़ा कदम है। हरियाणा सरकार की स्वामित्व योजना है, लाल डोरे में गांव का जो गरीब आदमी रहता है, जिसके पास मकान तो था लेकिन उसके पास कोई मालिकाना हक नहीं था, वह मालिकाना हक किसने दिया? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामित्व योजना के जरिए दिया। लाल डोरे के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज थीं, उनका मालिकाना हक प्रधानमंत्री जी ने दिया।

मैं यह बताना चाहता हूँ, धारा 370 और 35ए दोनों धाराओं को खत्म करके देश के हरेक नागरिक को इस बात से जोड़ा कि उसमें उसका भी हिस्सा था। मैं रोहतक लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ। मैं वहां से सांसद नहीं होता या कोई दूसरी पार्टी का सांसद होता तो यहां वोटिंग हो रही होती। क्या धारा 370 और 35ए के हक में वह वोट डालता? मैं अपने रोहतक वासियों से कहता हूँ कि धारा 370 और

35ए जब खत्म हुए तो आप सभी का भी उसमें हिस्सा है। हरेक जाति के लोगों ने मुझे सांसद बनाकर यहां भेजा, उन सभी लोगों का हिस्सा है। आज देश विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था है। जब देश तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी तो हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, प्रत्येक नागरिक का उसमें हिस्सा हो, अपने कर्तव्यों का पालन करके हम अपने देश को आगे बढ़ाते रहें। 2014 से पहले का भारत देखें, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और घोटालों की सरकारें हुआ करती थीं। सारा बदलाव आज अगर किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। हरेक कैटेगरी में बदलाव किया है।

जय जवान जय किसान कहते हैं, हरियाणा में कहते हैं, जय जवान, जय किसान और जय पहलवान। पहलवान का मतलब स्पोर्ट्स से हैं, खिलाड़ियों से है, पहले कुश्ती और कबड्डी खेलते थे, लेकिन अब पहलवान का मतलब खिलाड़ी से है। हर घर में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर खिलाड़ियों को सम्मान निधि दी जाती है, हरियाणा से जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आता है, उसे 6 करोड़ रुपये दिया जाता है, इसी तरह से सिल्वर और ब्रॉज मेडल वालों को भी सम्मान निधि की राशि दी जाती है। हर घर में चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, हर घर में खेल का इतना प्रभाव बढ़ गया है कि आने वाले समय में हरियाणा में हरेक परिवार में एक लड़का या लड़की खिलाड़ी होगा। किसी न किसी खेल में वह आगे बढ़ेगा और हरियाणा का नाम रौशन करेगा। वर्ष 2047 का विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, उसमें हरियाणा का भी हिस्सा होगा, हरियाणा के खिलाड़ियों का भी हिस्सा होगा और हरियाणा के किसान का भी हिस्सा होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसानों की आय दोगुना करेंगे, उस दिशा में दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। हरियाणा में जीरी की फसल होती है। पहले एक एकड़ में 70 से 72 हजार रुपये जाता था, लेकिन इस बार 1 लाख 30-35 हजार रुपये प्रति एकड़ गया है। आप समझ सकते हैं कि हरियाणा किस तरह से किसानों के जरिए उन्नति कर रहा है।

(2100/SK/RP)

जो राम मंदिर की बात है, पांच सौ साल पुराना विषय था। यहां मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया। पांच सौ साल पुरानी समस्या का अगर किसी ने समाधान किया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया, एक नये युग की शुरुआत की, एक नई शुरुआत से देश आगे बढ़ रहा है।

2100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2047 का भारत हर तरीके से मजबूती के साथ हर कैटेगरी में विश्व गुरु होगा, विकसित भारत होगा। धन्यवाद। जय हिंद।

(इति)

माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 5 फरवरी, 2024 को प्रातः ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

2100 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 05 फरवरी 2024/16 माघ 1945 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।